



# भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ .

[आगरा विश्वविद्यालय के संशोधित पाठ्य-क्रमानुसार]

लेखक

बी० पी० जौहरी

प्रिंसिपल एण्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऐडुकेशन

आर० ई० आर्इ० टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

दयालबाग

एव

पी० डी० पाठक

लेक्चरर इन हिस्ट्री ऑफ ऐडुकेशन

आर० ई० आर्इ० टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

दयालबाग

विनोद पुस्तक मन्दिर

हॉस्पिटल रोड, आगरा

प्रकाशक  
विनोद पुस्तक मन्दिर  
हॉस्पिटल रोड भागला

[ सर्वाधिकार सुरक्षित ]  
प्रथम संस्करण १९६४  
मूल्य ₹ ५०

मुद्रक  
कलाग प्रिंटिंग प्रेस  
डॉ० रामेय रायव भाग  
भागला

## भूमिका

यह पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय के बी० टी० के सशोधित पाठ्य-क्रम के अनुसार लिखी गई है। इसके लेखन में पाठ्य-क्रम के अनोखेपन के कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पाठ्य-क्रम में यह निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि छात्रों को भारतीय गिज्ञा के इतिहास का किस समय से अध्ययन करना है। स्वतन्त्रता से पूर्व अति भ्रमोत्पादक शब्द हैं क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ने प्राचीनकाल से लेकर १९४७ तक स्वतन्त्रता का अनुभव नहीं किया। फिर गिज्ञा के समस्त इतिहास के लिए, जो अत्यधिक समीचीन अवधि में से होकर गुजरता है केवल ६ लेखों में निर्धारित किये गये हैं। क्या यह सम्भव है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय गिज्ञा के क्षय में जो परिवर्तन समय-समय पर हुये हैं, उनको ६ लेखों में समाप्त कर दिया जाय ? यदि पाठ्य-क्रम का उद्देश्य यह है कि छात्राध्यापकों को विभिन्न शिक्षा-पद्धतियों आयागों और समितियों के नाम बता दिये जायें—क्योंकि इससे अधिक ६ लेखों में नहीं हो सकेगा—तो उससे अध्ययन करने वाला का क्या हित होगा ? सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पाठ्य-क्रम को दो भागों में तो विभाजित कर दिया गया है पर इस बात का कहीं कोई ज़रा नहीं है कि जिस भाग में से कितने और कितने नम्बर के प्रश्न दिए जायेंगे। ऐसी स्थिति में वेयर-मेटर इस बात के लिये स्वतन्त्र है कि वह परीक्षा में कुछ भी पूछ ले। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर पुस्तक की रचना की गई है जिससे कि इसकी पढ़ने के बाद छात्र प्रत्येक प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो सके। हमने इस पुस्तक के अन्त में 'अपव्यय एवं अवरोधन' का एक अध्याय अपना आर से जोड़ दिया है क्योंकि यह बात सर्व विदित है कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या गिज्ञा में समा स्तरों पर है और किसी भी स्तर पर इसने सम्प्राप्त में प्रश्न दिया जा सकता है। हम श्री बाबुराम शर्मा के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को आगे बढ़ाया।

सम्भव गण्ड



## विषय सूची

### अध्याय १

#### बौद्ध शिक्षा

विषय-प्रवेश १, शिक्षा का तात्पर्य १, शिक्षा के उद्देश्य तथा आर्ग २, शिक्षा की व्यवस्था ३ शिक्षा के आधार मूल तत्व एवं विवेचन ४ ।

### अध्याय २

#### बौद्ध शिक्षा

विषय-प्रवेश ११, शिक्षा की व्यवस्था ११ सांस्कृतिक या प्राथमिक शिक्षा १२, उच्च शिक्षा १३, शिक्षा के आधारमूल तत्व एवं विवेचन १४, ब्राह्मणीय और बौद्ध शिक्षा की समानता १६, ब्राह्मणीय और बौद्ध शिक्षा की असमानता २१ ।

### अध्याय ३

#### मुस्लिम-कालीन शिक्षा

विषय-प्रवेश २४ मुस्लिम शासकों के समय में शिक्षा २५, शिक्षा के उद्देश्य २६ शिक्षा की व्यवस्था २७ शिक्षा के आधारमूल तत्व एवं विवेचन २८, श्री शिक्षा ३५ व्यावसायिक शिक्षा ३६ ।

## अध्याय ४

## ✓ आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ (मिशनरी प्रयास)

विषय प्रवेश ४० मिशनरिया के शिक्षा-कार्य ४१ चार्ल्स ग्रांट ४२  
१७६३ और १८१३ के आभा-पत्र ४३ १८१३ के बाद मिशनरी प्रयास ४३  
मिशन स्कुल की विशेषताएँ ४४।

## अध्याय ५

## ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य (१६००-१८३३)

विषय प्रवेश ४६ पसकता मदरमा ४७ बनारस संस्कृत कॉलेज ४७  
फोट विलियम बॉलेज ४८ १८१३ का आभा-पत्र ४८ कम्पनी की शिक्षा  
नीति (१८१३-३३) ४८।

## अध्याय ६

## प्राच्य-पाश्चात्य विवाद और निस्पन्दन सिद्धान्त

विषय प्रवेश ५ प्राच्यवादी ५० पाश्चात्यवादी ५१ मकानि का विवरण  
पत्र ५१ अटिच की स्वीकृति ५३ भारतीय शिक्षा को मकानि की देन ५०  
विवाद का जन्म ५४ निस्पन्दन सिद्धान्त ५५।

## अध्याय ७

## शिक्षा की प्रगति (१८३३-१८५३)

विषय प्रवेश ५८ भगान ५८ यमई ५९ मद्रास ६१ पश्चिमोत्तर प्रान्त  
६१ पंजाब ६२ उच्च शिक्षा ६२।

## अध्याय ८

## बुड का घोषणा-पत्र (१८५४)

विषय प्रवेश ६४ घोषणा पत्र की गिफारिहो ६४ घोषणा पत्र का  
मूल्यांकन ६७।

## अध्याय ९

## शिक्षा की प्रगति (१८५४-१८८२)

विषय प्रवेश ७१ प्राथमिक शिक्षा ७१ माध्यमिक शिक्षा ७३ उच्च  
शिक्षा ७४।

## अध्याय १०

## भारतीय शिक्षा-आयोग (१८८२-१८८३)

विषय प्रवेश ७५ आयोग का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य ७६ आयोग की सिफारिशों और सुझाव ७७ आयोग का मूल्यांकन ८० ।

## अध्याय ११

## शिक्षा की प्रगति (१८८२-१९०२)

विषय प्रवेश ८२ प्राथमिक शिक्षा ८२ माध्यमिक शिक्षा ८३ उच्च शिक्षा ८३ ।

## अध्याय १२

## लाइव कज न की शिक्षा-नीति (१८९९-१९०५)

विषय-प्रवेश ८५ शिक्षा-सम्मेलन ८६ शिक्षा-नीति सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव (१९०४) ८६ भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (१९०२) ८७ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (१९०४) ८८ विश्वविद्यालय अधिनियम का मूल्यांकन ८९ कज न और माध्यमिक शिक्षा ८९ कज न और प्राथमिक शिक्षा ९० भारतीय शिक्षा की कज न की देन ९० ।

## अध्याय १३

## राष्ट्रीय आन्दोलन का शिक्षा पर प्रभाव (१९०५-१९२१)

विषय प्रवेश ९२ राष्ट्रीय शिक्षा की माँग ९३ राष्ट्रीय शिक्षा की रूप-रत ९३ राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण ९४ ।

## अध्याय १४

## शिक्षा की प्रगति (१९०५-१९२१)

विषय-प्रवेश ९६ शिक्षा-नीति सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव (१९१३) ९६, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (१९१७) ९७ आयोग की सिफारिशों और सुझाव ९८ आयोग का मूल्यांकन ९९ उच्च शिक्षा १००, माध्यमिक शिक्षा १००, प्राथमिक शिक्षा १०१ प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य बनाने का प्रयास १०२ बटोना नरेश का प्रथम प्रयास १०२ गोयल का विधेयक १०२ अनिवार्य शिक्षा अधिनियम १०४ ।



## अध्याय १५

## शिक्षा की प्रगति (१९२१-१९३७)

विषय प्रवेश १०६ द्वैध-शासन की स्थापना १०६ हर्टिंग समिति (१९१९)  
१ ७ उच्च शिक्षा १०७ माध्यमिक शिक्षा १०८ प्राथमिक शिक्षा १०९।

## अध्याय १६

## शिक्षा की प्रगति (१९३७-१९४७)

विषय प्रवेश १११ केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-कार्य १११ केन्द्रीय शिक्षा  
सलाहकार बोर्ड ११२ केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय ११२ केन्द्रीय शिक्षा-सुचना  
कार्यालय ११२ विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग ११२ ऐक्ट एण्ड बुक रिपोर्टें  
(१९३७) ११२ सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव ११३ व्यावसायिक शिक्षा  
सम्बन्धी सुझाव ११३ उच्च शिक्षा ११४ माध्यमिक शिक्षा ११४, प्राथमिक  
शिक्षा ११४।

## अध्याय १७

## वैदिक शिक्षा

विषय प्रवेश ११७ महारमा गांधी के शिक्षा विषयक विचार ११७  
वैदिक शिक्षा का जन्म ११८ जातिर हसन समिति ११८ वैदिक शिक्षा  
की रूप रत्ना ११९ पाठ्य-क्रम ११९ अध्यापन विधि ११९ वैदिक शिक्षा क  
आधारभूत सिद्धान्त १२ वैदिक शिक्षा के उद्देश्य १२१ वैदिक शिक्षा की ✓  
विशेषताएँ १२२ वैदिक शिक्षा क दोष १२५।

## अध्याय १८

## सार्जेंट योजना, (१९४४)

विषय प्रवेश १२७ सार्जेंट योजना की सिफारिशें १२७ सार्जेंट योजना  
मूल्यांकन १३।

## अध्याय १९

## अग्रणी शिक्षा पद्धति का सिंहावलोकन

✓ विषय प्रवेश १३२ अग्रणी शिक्षा के लाभ १३२ अग्रणी शिक्षा की हानियाँ  
१३४ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास में असफलता १३५।

## अध्याय २०

## विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८-१९४९)

विषय-प्रवेश १३७ आयोग का गठन तथा सुझाव १३८, राष्ट्रीय अनु  
सूचीकरण का मूल्यांकन १४५।

## अध्याय २१

## माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-१९५३)

विषय प्रवेश १४६ आयोग के विचार एवं मुझाव १४७ उपसंहार १४३ ।

## अध्याय २२

## पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा

विषय प्रवेश १५४ प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा १५५ तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा १५७ तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा १६१ ।

## अध्याय २३

## नव भारत में शिक्षा (१९४७-६५)

विषय प्रवेश १६६ प्राथमिक शिक्षा १६६ बेसिक शिक्षा १७० माध्यमिक शिक्षा १७१ विद्वत्विद्यालय शिक्षा १७२, प्रायोगिक उच्च शिक्षा १७५ स्त्री शिक्षा १७५ विश्वविद्यालयों की शिक्षा १७६ ।

## अध्याय २४

## प्राथमिक शिक्षा

विषय प्रवेश १८१ समस्याएँ और उनके समाधान १८१ (१) सरकार की दायपूर्ण नीति १८२ (२) राजनीतिक कठिनाइयाँ १८४ (३) दीर्घपूरा शिक्षा प्रशासन १८५ (४) शिक्षकों का अभाव १८६ (५), शिक्षण का निम्न स्तर १८७ (६) धनाभाव १८८ (७) विद्यालय-स्थापन एवं विद्यालय भवन १८९ (८) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम १९० (९) अपभ्रष्ट एवं अवरोधन १९२ (१०) प्राकृतिक बाधाएँ १९३, (११) सामाजिक कुरीतियाँ १९४, (१२) भाषा १९५ ।

## अध्याय २५

## माध्यमिक शिक्षा

विषय प्रवेश १९७ माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप १९८ माध्यमिक शिक्षा का विकास १९८ समस्याएँ और उनके समाधान १९९ (१) उद्देश्यविहीनता १९९, (२) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम २०० (३) अनुशासनहीनता २०१ (४) अक्षयता की अवाधताय वृद्धि २०२ (५) शिक्षा का निम्न स्तर २०२ (६) दीर्घपूरा परा ११ प्रशासन २०६ (७) सामुदायिक जीवन का अभाव २०५

(८) अपव्यय एवं अवरोधन २०६ (९) संगठन २०७ (१०) माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध २०८ ।

### अध्याय २६

#### उच्च शिक्षा

विषय प्रवेश २१२ सामान्य उच्च शिक्षा की प्रगति २१२ व्यावसायिक उच्च शिक्षा की प्रगति २१३ समस्याएँ और उनके समाधान २१३ (१) उद्दयविहीनता २१३, ( ) अपव्यय २१५ (३) द्योतपूर्ण पाठ्य-क्रम २१६ (४) शिक्षा में विधिपट्टीकरण २१७ (५) मागप्रदहन एवं समुपदेशन का अभाव २१८ (६) शिक्षा का निम्न स्तर २१९ (७) शिक्षा का माध्यम, अग्रणी २२० (८) द्योतपूर्ण परीक्षा प्रणाली २२, (९) अनुशासनहीनता २२१ (१) छात्र समितियाँ २२२ ।

### अध्याय २७

#### समाज (ग्रौढ़) शिक्षा

ग्रौढ़ तथा समाज शिक्षा का इतिहास २२५ ग्रौढ़ अथवा समाज शिक्षा का स्थान एवं महत्व २३० ग्रौढ़ शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा २३२ ग्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा २ २ ग्रौढ़ शिक्षा तथा समाज शिक्षा में अन्तर २३३ समाज शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा २३३ समाज शिक्षा का पञ्चमुखी कार्य-क्रम २३५ समाज शिक्षा के सध्य २३६ समाज शिक्षा के उद्देश्य २३७ समाज शिक्षा की आवश्यकता २४१ समस्याएँ और उनके समाधान २४५ (१) निरक्षता २४६ पाठ्य-क्रम २४८ (३) शिक्षण-पद्धति २५२ (४) अध्यापकों का अभाव २५३ (५) उपयुक्त साहित्य २५५ (६) शिक्षा का साधन २५६ (७) घनाभाव २५७ (८) उत्तरदायित्व २५९ ।

### अध्याय २८

#### प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

विषय प्रवेश २६१ भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता २६२ प्राचीन भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा २६३ मुस्लिम काल में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा २६४ अंग्रेजी राज्य में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा २६५ स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा २६५ स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

२६८ स्वतंत्र भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा २७० आधुनिकतम  
गतिविधियाँ २७५ प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति ७२६,  
समस्याएँ और उनके समाधान ७७७ (१) अनुचित दृष्टिकोण २७७ (२)  
शिक्षालया का अभाव २७८ सर्वोच्च पाठ्यक्रम २७८ (४) शिक्षा का अनुपयुक्त  
माध्यम २७९ (५) प्रायोगिक शिक्षा का यून महत्व २८० (३) उपरान्त  
शिक्षा का अभाव २८०, (७) शिक्षा का अभाव २८१।

### अध्याय २९

#### अध्यापक शिक्षा

विषय प्रवेश २८३ प्राचीन भारत में अध्यापक शिक्षा २८४ मुस्लिमकाल  
में अध्यापक शिक्षा २८५, अध्यापक शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयास २८५ कुछ का  
घोषणा-पत्र एवं अध्यापक शिक्षा २८५ (१८४९ से १८७२ तक) अध्यापक  
शिक्षा २८६ १८-२ में अध्यापक शिक्षा की स्थिति २८७ अध्यापक शिक्षा की  
नियमित व्यवस्था २८८ शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१९०४)  
२८९ शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१९१३) २९० कलकत्ता  
विश्वविद्यालय आयोग और अध्यापक शिक्षा २९० हर्गिस समिति और अध्यापक  
शिक्षा २९० अध्यापक शिक्षा पर विहगम दृष्टिपात (१८८२ १९४७) २९१  
अध्यापक प्रशिक्षण की प्रगति (१९३१ ४१) २९१ स्वतंत्र भारत में प्रशिक्षण  
सुविधायें २९२ स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा का विस्तार २९३ अध्या  
पक-शिक्षा का विस्तार (१९४९ १९५८) २९४ वर्तमान प्रशिक्षण-संस्थाएँ  
२९४ पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र २९४ नार्मल या प्राथमिक प्रशिक्षण विद्या  
लय २९६ माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय २९८ प्रशिक्षण महाविद्यालय २९९  
शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थाएँ ३०१ विभिन्न प्रशिक्षण-न-द्र ३०१ समस्याएँ और  
उत्तरे समाधान ३०३ — १ प्रशिक्षण एवं स्कूल-कार्य की सम्बन्ध विहीनता  
३०४ २ सिद्धान्त पर अनुचित बल ३०५ ३ मानवीय पहलू की उपेक्षा ३०६  
४ स्वतंत्रता रहित वातावरण ३०८ ५ प्रशिक्षण के लिये व्यक्तियों का  
चुनाव ३०९ ६ चुनियादी एवं शर-चुनियादी पाठ्याभ्रमा की आवश्यकता ३१०  
उपसंहार ३११।

### अध्याय ३०

#### अपव्यय एवं अवरोधन

विषय प्रवेश ३१३ अपव्यय का अर्थ एवं परिभाषा ३१३ अवरोधन का  
अर्थ एवं परिभाषा ३१४ अपव्यय एवं अवरोधन-न्याय के दो पहलू ३१५

प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन ३१६ भाष्यमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन ३१७, विश्वविद्यालय शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन ३१८, अपव्यय और अवरोधन के कारण तथा उनके निवारण के उपाय ३१९, (१) दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ३१९ (२) दूषित वातावरण ३२० (३) प्रभाव होन शिक्षण-पद्धति ३२१ (४) दोषपूर्ण पाठ्य-क्रम ३२२ (५) दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली ३२३ (६) छात्रों की शारीरिक दुर्बलता ३२३, (७) अभिभावकों की अधिक्षा ३२४, आर्थिक कठिनाइयाँ ३२५, (८) सामाजिक कुरीतियाँ ३२७ ।

## वैदिक शिक्षा (Vedic Education)

### विषय प्रवेश

‘शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सम्पत्ता और सभ्यता के उत्थान के लिये अनिवार्य है। भारतवासियों ने शिक्षा के इस गहन महत्व को समझ लिया था। इसी के फलस्वरूप भारत के सुदूर असीत में भी शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था की गई थी। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने विद्यालय बन्धि साहित्य को सुरक्षित रखा और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक विचारों एवं विचारों को जन्म दिया जिन्हें इस देश का मस्तक आज भी यश और गौरव से उन्नत है।

### शिक्षा का तात्पर्य (Purpose of Education)

A S Altekar का कथन है— बर्हिष युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रज्ञा का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है।’  
(From the Vedic Age downwards the central conception of education of the Indians has been that it is a source of illumination giving us a correct lead in the various spheres of life )

‘सुभाषित रत्न सग्रह’ में यह कहा गया है कि एक मनुष्य ने भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो पर यदि उसमें अन्तर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ है और उसे अपने अध्ययन के फलस्वरूप अवश्य ही प्राप्त नहीं हुई है तो वह मूर्ख है। नेबल क्रियाशील मनुष्य ही वास्तव में शिक्षित है। शिक्षा उदर-पूति की समस्या को अवश्य हल करती है परन्तु वैदिक काल में शिक्षा को जीविका का साधन नहीं माना गया और जिन्होंने ऐसा मत व्यक्त किया उनकी घोर निन्दा की गई। सारांश में वैदिक काल में शिक्षा का साध्य अन्तर्ज्योति और शक्ति से था जिससे मानव के शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा आत्मिक बलों का समुचित विकास हो सकता था।

**शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श (Aims & Ideals of Education)**

वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों का विवेचन करते हुए Altekar ने लिखा है—‘ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का विकास नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक दृढता की उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार—प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे।’ ( *Infusion of a spirit of piety and religiousness, formation of character, development of personality, inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency, and preservation and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of Ancient Indian Education* )

१ **ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता**—वैदिक काल में शिक्षा बालक में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का समावेश करती थी। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था छात्रों द्वारा विभिन्न ऋतों का पालन नियमित सध्या एवं धार्मिक उत्सव का यही अभिप्राय था।

२ **चरित्र निर्माण**—इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों की पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेन होने थे। उनको अपने आचार्यों से सदाचार के उपदेश मिलते थे उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता था जिससे उनका चरित्रिक उत्थान हो और उनमें समस्त राष्ट्र की महात्मा विभूतियों के आदर्श बारम्बार उपस्थित किये जाते थे।

३ **व्यक्तित्व का विकास**—इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों में आत्म सम्मान की भावना का विकास, आत्म-विश्वास को प्रोत्साहन आत्म-सयम के

महत्त्व पर बल तथा न्याय और विवेक की शक्ति को जन्म देने की विधियाँ को अंगनाया जाता था।

४ नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन—शिक्षा ब्रह्मचारिणा में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना को भरती थी। उनको स्वायत्तपूर्ण जीवन व्यतीत न करने की शिक्षा दी जाती थी। शुल्क न मिलने पर भी वैदिक साहित्य का अध्यापन—उनका कर्तव्य बताया जाता था। उन्हें पुत्र पति तथा पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। उन्हें अपने धन से अतिथियों का सरकार एवं दुःस्थिती की सहायता करना आवश्यक था।

५ सामाजिक कुशलता की उन्नति—सामाजिक कुशलता की उन्नति और इसके फलस्वरूप मानव के सुख की वृद्धि के लिये विभिन्न शास्त्रों व्यवसायों तथा उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। छात्रों का मानसिक विकास करने के साथ-साथ उनको उस व्यवसाय की शिक्षा निश्चित रूप से दी जाती थी जिसे वे अपने भावी जीवन में अपनाना चाहते थे।

६ राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार—प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। प्रत्येक आर्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग को याद करता था। प्रत्येक ब्राह्मण वेदा को बख्ठस्य करता था। इन कार्यों से भारतीयों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था पर इनको करने से अपने पूर्वजों की संस्कृति एवं ज्ञान का संरक्षण तथा प्रसार करते थे। शिक्षा की व्यवस्था (Organization of Education)

वेदा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सुदूर अतीत में भी भारत में संगठित रूप से गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में कुछ इस प्रकार का संकेत मिलता है जिससे पाठशाला के समान किसी संस्था का अनुमान किया जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषद् से ज्ञात होता है कि बालक गुरु-गृह में रहकर विद्याभ्यास करते थे। वैदिक साहित्य में हम बात का उल्लेख मिलता है कि वैदिक युग में सप, परिषद् धरण मठ गुरुकुल तथा आश्रम स्थापित हो गये थे जहाँ गुरु व्यक्तिगत रूप से स्वयमेव शिक्षा को शिक्षा प्रदान करते थे। ग्रामों में प्राथमिक पाठशालायें भी थीं।

उपयुक्त सभी शिक्षा-संस्थायें सावाम (Residential) थीं और ब्राह्मण नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त थीं। इनमें छात्रों का प्रवेश एवं निश्चित आयु में होता था। प्रवेश के समय छात्रों को लिखने-पढ़ने और गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। प्राचीन भारत में श्वी, ६ठी (ईस्वी) छात्राश्रम तक समाज या



राज्य की ओर से शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक समय के समान सुसंगठित शिक्षा संस्थाओं का अभाव था। इस प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम बौद्ध विद्वानों द्वारा किया गया था।

वर्णिक युग तथा महाभारत-काल में वेद-पुराण व्याकरण ज्योतिष, वशेन, कला आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। इनके अतिरिक्त श्रम विभाजन पर आधारित समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार भी शिक्षा दी जाती थी। उदाहरणार्थ—ब्राह्मणों को धर्म-कर्म की दार्ष्टिक्य की मुद्रा विद्या और राजनीति की वश्या को वाणिज्य और कृषि-विज्ञान की तथा क्षत्रियों को विविध साधारण कलाओं और हस्त-काम की।

## शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ

(Basic Principles & Features of Education)

शिक्षा के जिन उद्देश्यों और आदर्शों का बलून पहलू किया जा चुका है, उनकी प्राप्ति के लिये बर्द्धि बाल के शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की एक विनिष्ट प्रणाली का निर्माण किया—जो साम्राज्य के पतन तथा समाज के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हुई और जिसने इन सहस्रों वर्षों के उपरान्त भी हमारे देश में शिक्षा की ज्योति को जलता हुआ रखा है। इस शिक्षा प्रणाली के निम्नांकित आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ थी —

१. उपनयन संस्कार—ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वश्य वर्ण का प्रत्येक बालक उपनयन-संस्कार के पश्चात् विद्याध्ययन का प्रारम्भ करता था। 'उपनयन' का दार्ष्टिक अर्थ है—पास ल जाना अर्थात् शिक्षा के लिए गुरु के पास पहुँचाना। उपनीत बालक को ही गुरु सावित्री मंत्र (गुरु मंत्र) का उपनयन कर दिया जाता और प्रारम्भ करता था। जिस प्रकार बिना वपतिस्मा के कोई ईसाई नहीं होता और बिना कलमा के मुसलमान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वर्णिक बाल में उपनयन-संस्कार को किए बिना कोई बालक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था।

२. विद्याध्ययन प्रारम्भ करने की आयु—बालक को किस आयु में विद्याध्ययन का प्रारम्भ करना चाहिए इस सम्बन्ध में बर्द्धि शास्त्रकारों में मतभेद है। मनु के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वश्य वर्ण का उपनयन सम्भार प्रमाण ८, ११ और १२ वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य के अनुसार बाल का प्रमाण ५ अनुसार किसी भी सुविधापूर्ण समय पर उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया जा सकता है परन्तु इस बात का परामर्श दिया गया है कि ब्राह्मण को अपने पाँचवें वर्ष में क्षत्रिय को छठे वर्ष में, और

वय का आठवें वर्ष में विद्याध्ययन का प्रारम्भ कर देना चाहिए। जिन छात्रों का निश्चिन् आधु म उपनयन संस्कार नहीं होता था वे सावित्री मंत्र को सीखने का अधिकारी नहीं रह जाते थे। दूदा का विद्याध्ययन का अधिकार नहीं था।

३ अध्ययन काल—वैदिक काल में यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि वेदा के अध्ययन के लिए अति दीर्घ काल की आवश्यकता है। भारद्वाज ने तान जन्मा में तीन वेदा का अध्ययन किया। इंद्र ने प्रजापति के शिष्य बनकर १०५ वर्ष तक विद्याध्ययन किया। वैदिक काल में सामान्य रूप से अध्ययन-काल १२ वर्ष का था। इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा गया है कि १२ वर्ष की अवधि जबतक एक वेद के अध्ययन के लिए है। यदि एक छात्र चारों वेदा का अध्ययन करता है तो उसे प्रत्येक वेद के अध्ययन में १२ वर्ष लगाने पड़ते थे। पर सभी छात्र चारों वेदों का अध्ययन नहीं करते थे। साहित्य तथा धर्म-शास्त्र के छात्र अपना अध्ययन १० वर्ष में समाप्त कर देते थे।

४ शिक्षा-सत्र—शिक्षा-सत्र की अवधि एक वर्ष में साढ़े चार या साढ़े पाँच मास की होती थी। साधारणतः विद्याध्ययन का कार्यक्रम प्रायण मास की पूर्णिमा का 'उषाश्रम' समारोह में प्रारम्भ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को 'धन' साम उत्सजनम् समारोह के साथ समाप्त होता था।

५ शिक्षण का समय—शिक्षण का कार्य जिस समय में कितने समय तक चलता था, इस सम्बन्ध में स्मृतियों विलुप्त मौन हैं। पर क्याकि वैदिक काल में मुद्रणालय बागज एवं समुद्री पुस्तकें नहीं थी अतः स्वाभाविक निष्कर्ष यहाँ निरसता है कि पठन-पाठन का सत्र कार्य आचार्य की देन पैर में होता था। सम्भवतः शिक्षण का कार्य प्रातः काल से मध्याह्न तक और फिर कुछ विश्राम तथा भोजनादि के उपरान्त सायंकाल तक चलता था। प्राचीन ऋषि की संस्कृत पाठशालाएँ कुछ समय पूर्व तक इसी प्रकार के कार्यक्रम का अनुसरण करती थी।

६ विद्यालय भवन—वैदिक काल में विद्यालय भवन विभिन्न प्रकार के थे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। शुन मौसम में अध्ययन-अध्यापन का कार्य शृंग के भीष होता था परन्तु वर्षा के समय शिक्षा प्रसार के आशयान का व्यवस्था अवश्य होगा। विहारा एक देवमलया में पड़ने वाले छात्रों के निष्क भवन घने हुए थे।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

७ गुरुकुल-प्रणाली—वर्दिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। छात्र अपने गुरु के पास अथवा किसी आश्रम में रहते थे। वहाँ रहकर छात्र ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरुकुल साधारणतः कोलाहल से दूर प्रकृति के सुन्दर वन में स्थित होते थे। परन्तु वे किसी गाँव या नगर के समीप अवस्थित होते थे जिससे उनमें निवास करने वाले छात्रों की अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

८ छात्र एवं उनका जीवन—छात्रों के खान-पान वस्त्र-भूषण आचार व्यवहार आदि के सम्बन्ध में निश्चित नियम थे—जिनका पालन करना अनिवार्य था। यथा—

(i) खान-पान—मनु ने लिखा है कि छात्रों को दिन में केवल दो बार भोजन करना चाहिए—एक बार प्रातःकाल और एक बार सायंकाल। इन दोनों भोजनों के मध्य में उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे अधिक भोजन से बचना चाहिए क्योंकि यह रोग का कारण तथा आध्यात्मिक उत्थिति में बाधक होता है। छात्रों को मांस मधु पान और वासा भोजन न खाने का आदेश था।

(ii) वेश-भूषण—छात्रों की वेश-भूषण निर्धारित थी। उपनयन के बाद पहिनी जान वाली मेखला विभिन्न जातियों के छात्रों के लिए विभिन्न वस्तु की बनी हुई थी। मनु के अनुसार ब्राह्मण की मेखला मूज घास की तन्त्रियों की तंतु की और वन्य की ऊन की बनी हुई होती थी। अपने शरीर के निम्न भाग को ढकने के लिए ब्राह्मण तन्त्रिय तथा वन्य छात्र क्रमशः खन रेसम और ऊन वस्त्रों के टुकड़ा का और ऊपरी भाग के लिये क्रमशः काले मृग चित्तीदार मृग एवं बकरे की खाल का प्रयोग करते थे। छात्र जिन ढण्डों को लेकर इधर उधर आते-जाते थे उन्हें उनको सड़ा परटना पड़ता था और वे बिना जले हुए देतने में सोम्य और भय उत्पादक नहीं हो सकते थे क्योंकि उनका प्रयोग केवल गुरुता के लिये किया जाता था। छात्रों को अर्जन सुगन्धि छाते तथा जूतों का प्रयोग मना था। वे अपने शरीर को किसी प्रकार भी सजा नहीं सकते थे। वस्त्र सँवारने की मनाही थी।

(iii) आचार-व्यवहार—छात्रों का जीवन पिपाद्याचार भयान्त्रि तथा आत्म संयम से पूर्ण होता था। उन्हें अपने जीवन की पवित्र रखने के लिये दोनों समय साध्या वल्गना एवं हवन करना पड़ता था। उन्हें गुरुजनों का आदर तथा सम्मान करना होता था। उन्हें बसत्य भाषण शालो-गमोज एवं पुण्यसंछोरी से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। उनका द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन नियम

जाने पर बस लिया जाता था। वे अपने पाम न तो धन रख सकते थे और न कोई वस्तु खरीद सकते थे। वे नृत्य संगीत तथा जुए का आनन्द नहीं ले सकते थे। वे स्त्रियों से आयर्यवृत्ता से अधिक बात नहीं कर सकते थे। उन्हें आत्म समय और काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्त रहने की शिक्षा दी जाती थी।

(iv) छात्रों की सावगी—प्रत्येक हिंदू छात्र को सादो आदतों की शिक्षा दी जाती थी। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं होता था कि वह किस कुल का है। धनवान तथा निधन—सभी परिवारों के बालकों को जीवन का एक ही ढंग अपना पड़ता था। महाभारत तथा रामायण में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि राजकुमारों को भी छात्र जीवन की उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जिनका सामना उनके निधन सहपाठी करते थे।

(v) छात्रों की दिनचर्या—छात्र पक्षियों के चहचहाहने से पूर्व उठते थे। नित्य प्रिया के बाद वे स्नान तथा सध्या करते थे। वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र प्रातः काल का अधिप्रास भाग हवन आदि करने में व्यतीत करते थे। उस समय में अथ विषयों के छात्र पुराने पाठों को दोहराते तथा नये पाठ को पढ़ते थे। दोपहर के समय वे भोजन करने के लिये अपना बाय समाप्त कर देते थे। कुछ समय के बाद वे फिर विद्याध्ययन में जुट जाते थे और सायंकाल तक इस कार्य में लगे रहते थे। सूर्यास्त के समय वे सध्या तथा हवन करने के बाद भोजन करते थे।

६ अध्यापकों के प्रति छात्रों के कर्तव्य—वैदिक काल में छात्रों के अध्यापकों के प्रति अनेक कर्तव्य थे। वे गुरु का स्थान राजा माता पिता एवं देवता से निम्न नहीं समझते थे और उनका हृदय से सम्मान करते थे। वे प्रातः काल गुरु से पूज उठ कर उसका अभिवादन करते थे और उससे नीचे आसन पर बैठते थे। वे आचार्य की प्रत्येक आज्ञा का गिरोषार्थ करते थे। पर यदि गुरु पर्माचरण से झुत हो जाता था तो वे उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं थे। वे गुरु की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। वे आचार्य के लिए प्रतिदिन निश्चित समय पर जल और दहीजन पट्टेबाज दे, उसके स्नान की व्यवस्था करते थे उसकी गृहस्थी के छोटे-मोटे काम करते थे और उसके घरों में कार्य करते थे।

१० छात्रों के प्रति अध्यापकों के कर्तव्य—वैदिक ऋषियों ने आचार्य को छात्र का 'मानस पिता' (Spiritual Father) कहा है। अतः वैदिक काल में आचार्य छात्रों के प्रति पुत्रवत् व्यवहार करते थे। अध्यापक का यह कर्तव्य

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

तो था ही कि वह अपने छात्र को ज्ञान प्रदान करे, परन्तु इसके अतिरिक्त उसके कुछ कर्तव्य और थे। वह अपने विद्यार्थियों के चरित्र का सदैव ध्यान रखता था। अतः वह उनका सलाहता था कि उन्हें किन आदतों का निर्माण और किन का त्याग करना चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य की उपरति किस प्रकार करनी चाहिए उन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और उन्हें कौन से व्यक्तियों से सम्पर्क रखना चाहिए। यदि कोई छात्र बीमार हो जाता था तो अध्यापक से समान उसकी चिकित्सा तथा सेवा करता था। चाराच में उसका पिता व समाज उसकी विद्यापियों का दायीरक मानसिक तथा आध्यात्मिक कर्तव्य था—अपने विद्यार्थियों का दायीरक मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास करना।

११ दण्ड—भारत की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था में दण्ड का स्थान तो था पर दायीरक दण्ड व सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्री एक मत के नहीं हैं। आपस्तम्ब ने लिखा है कि गुरु हठी छात्रा को अपने पास से दूर भेज दे या उनसे उपवास करावे। मनु का कथन है कि यदि छात्र अपराध करता है तो गुरु उसको रजु या पतली छड़ी से दण्ड दे सकता है। इसी प्रकार का मठ गौतम और विष्णु के द्वारा तथा महाभारत में व्यक्त किया गया है।

१२ निःशुल्क शिक्षा—ग्राह्यणों का कर्तव्य शिक्षा देना समझा जाता था। जब तक एक छात्र विद्या प्राप्त करता रहता था तब तक गुरु उससे किसी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता था। शिक्षा समाप्त होने पर छात्र का यह कर्तव्य था कि वह अपने गुरु को कुछ दसिया दे। F E Keay के अनुसार पत्नी विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य छात्र गुरु को इतनी दसिया नहीं दे पाता था जिस दसिया का उचित पारिवारिक कहा जा सके। मनु ने लिखा है कि छात्र दसिया के रूप में अपने गुरु को गाय अथवा अज्ञ इत्यादि कुछ भी दे सकता था।

१३ बाह्य नियंत्रण से मुक्ति—P N Prabhu ने लिखा है—यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य या सरकार अपना किसी राजनैतिक दल का नियन्त्रण नहीं था। राजा का यह कर्तव्य था कि वह इस बात को देखे कि विद्या पंडित विना किसी विघ्न-आपा व अध्यापन व कार्य में रत रहें। इसी प्रकार भारत में शिक्षा पर कोई जातीय प्रभाव नहीं था। (Education in ancient India was free from any external control like that of the State or Government or any party politics. It was one of the King's duties to see that the learned pundits pursued their

studies and their duty of imparting knowledge without interference from any source whatever. So also education did not suffer from any communal interest or prejudices in India")

१४ पाठ्य-क्रम—वैदिक काल में वेदा की शिक्षा के अतिरिक्त और भी अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। छात्रोग्य उपनिषद् तथा बृहदारण्यक उपनिषद् में जिन विषयों की सूची मिलती है वह इस प्रकार है—ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास अथवा पौराणिक कथाएँ, पुराण विद्या उपनिषद्, इत्योक्त सूत्र व्याख्यान अथवा आलोचना राशि (The Science of Numbers) दैव (The Science of Portents) निधि (The Science of Time), वाक्यवाक्य (Logic), वनिक शास्त्र दश विद्या (Etymology) ब्रह्म विद्या, सूत विद्या शास्त्र विद्या नक्षत्र-विद्या सर्प विद्या व्याकरण, ज्योतिष, कर्म्य (Ceremonial and Religious Practice)। इन विषयों के अतिरिक्त बीजगणित तथा औषधि विज्ञान के गिणत के भी अवसर सुलभ थे।

१५ शिक्षण विधि—शिक्षण विधि मौखिक थी और छात्रों का आचार्य द्वारा बतलाई गई सभी बातों को बटम्य करना होता था। प्रत्येक पाठ के प्रारम्भ में छात्र गुरु का चरण स्पर्श करते थे और उससे पाठ प्रारम्भ करने की प्रायश्चात करत थे। गुरु गम्भीर काली से मन्त्रों का उच्चारण करने से और छात्र उसका अनुसरण करते थे। गुरु उच्चारण करते गये मन्त्रों का व्याख्या भी करते थे। शिक्षण समाप्त होने पर छात्र गुरु के चरणों का स्पर्श करके विदा लेते थे।

१६ समावसतन उपदेश—जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करने पर सौन्ते थे तब आचार्य उनका समावसतन उपदेश देते थे। इसी उपदेश का दीक्षास्त भाषण (Convocation Address) कहा जाता है। समावसतन-उपदेश साहित्य तथा आगुर्वेद के स्मातका के लिये भिन्न थे।

१७ स्त्री शिक्षा—वैदिक काल में शिक्षा की अन्तिम विषयता यह थी कि स्त्रियों का शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। नारी शिक्षा अपने चरण उद्वेग पर थी। ब्रह्मचर्य व्रत से सम्पन्न शिक्षिता कन्या का ही पृथक् में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। समय की गति के साथ समाज में स्त्रियों का महत्त्व तथा इसके फलस्वरूप उनकी शिक्षा अधिकार कम होना पला गया। ऐसी दशा पूर्व २०० के लगभग हुआ। इस प्रकार अति प्राचीन काल से लेकर इस समय तक स्त्रियों की शिक्षा का नामप्रम प्रायः अवाध गति से चलता रहा। पालका के समान बालिकाएँ भी उपनयन ग्रहण करती थीं। यह शिक्षा

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

का प्रचलन था। शालिकाजा को साहित्य, नृत्य संगीत काव्य रचना वाद विवाद, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

उपसंहार

यदि कालीन शिक्षा-व्यवस्था के बिना प्रमुख तत्वों एवं विशेषताओं का उपयुक्त पक्तियों में विवेचन किया गया है उनसे यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि दीर्घ अतीत में हमारे देश में शिक्षा की अति सुन्दर व्यवस्था थी। शिक्षा का उद्देश्य था— व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना।” शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी मानसिक शक्तियों तथा क्षमताओं का विकास उसके लिए जीवन के अर्थ तथा महत्त्व की व्याख्या और उसे इहलोक तथा परलोक—दोनों में आत्मिक उन्नति करने में सहायता देती थी।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Give a critical estimate of the conception of teacher pupil relationship as it existed in the ancient Hindu educational system
2. Describe the salient features of the system of education prevailing in ancient India. To what extent are they discoverable in the present system?
3. It is said that education was a handmaid to religion in ancient India. How far do you agree with this view? How did religion influence educational theory and practice in ancient India?
4. "The educational system of a nation at any given period of its history is a faithful reflection of the social, political and economic conditions of the period." Explain this statement critically with reference to the system of education in ancient India.

## बौद्ध-शिक्षा (Buddhist Education)

### विषय प्रवेश

ईसा की छठी शताब्दी में भारत-भूमि पर महात्मा बुद्ध और धर्मोपदेशक महारामा बुद्ध का निवास था। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिये अष्ट मार्ग बताया। उन्होंने बौद्ध धर्म में चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया। उन्होंने वैदिक काल के देवी-देवताओं की उपासना नहीं की, पर आचरण पर अधिक बल दिया। उन्होंने एक नवीन शिक्षा-व्यवस्था को जन्म दिया जो वैदिक कालीन शिक्षा के समान होने हुए भी कुछ बातों में भिन्न थी। डाक्टर आर० ए० मुक्जर्जी (Dr R. K. Mukerji) के अनुसार उचित रूप से विचार किये जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिन्दू या ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। (Buddhist education rightly regarded is but a phase of the ancient Hindu or Brahmanical system of education')

### शिक्षा की व्यवस्था (Organization of Education)

बौद्ध धर्म का विकास संघा के रूप में हुआ था। अत्र बौद्ध गिणा के प्रमुख ब्रह्म संघ ही थे। केवल संघा में ही बौद्ध शिक्षा दी जाती थी



अन्य किसी स्थान पर नहीं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में केवल सभ न अमलों का ही धार्मिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती थी। अमलों के अनिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिक्षा देने का अधिकारी नहीं था। बौद्ध काल में ब्रह्म का स्थान समान से लिया था। अतः बौद्ध मठ की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा-पद्धति थी। डाक्टर आर० के० मुक्जर्जी (Dr R. K. Mookerji) ने लिखा है बौद्ध शिक्षा-पद्धति प्रामाण्य बौद्ध सभ की पद्धति है। जिस प्रकार वैदिक युग में ब्रह्म संस्कृति के केन्द्र में उसी प्रकार बौद्ध युग में सभ शिक्षा और विद्या का केन्द्र था। बौद्ध संसार में अपने सभा से पृथक् या स्वतन्त्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। सब प्रकार की शिक्षा—धार्मिक तथा लौकिक—अमलों के हाथ में थी। (The Buddhist system is practically that of the Buddhist order or Sangha Buddhist education and learning centred round monasteries as Vedic culture centred round the sacrifice. The Buddhist world did not offer any educational opportunities apart from or independently of its monasteries. All education sacred as well as secular was in the hands of the monks.)

## १ साधजनिक या प्राथमिक शिक्षा (Popular or Elementary Education)

हम आठक बयाआ से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में प्राथमिक शिक्षा की कमी व्यवस्था थी। इस शिक्षा के केन्द्र बौद्ध मठ थे। प्रारम्भ में यह शिक्षा केवल धार्मिक थी। पर कुछ समय के बाद सामाजिक शिक्षा भी दी जाने लगी। कारण यह था कि ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाली प्रतिद्वन्द्वा शिक्षा-संस्थाओं में दाना प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिये भी दाना प्रकार की शिक्षा का आयोजन हो। ऐसा करके ही शिक्षा पर स ब्राह्मणों के एक मात्र अधिकार को समाप्त किया जा सकता था। ग्राहिमान ने भारत आगमन के समय (३६६-४१४) बौद्ध मठों में केवल बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वालों की शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की।

हम चीनी यात्रियों ह्वेनसांग और आइत्सिंग के सत्रों में जो भारत में साठवीं शताब्दी में आये थे साधजनिक या प्राथमिक शिक्षा का उत्पन्न मिलता है। इन यात्रियों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा छ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती थी। छात्रों का छ माह तक सिद्धिरस्तु (Siddhirastu) नामक

वास्तव्यो पढ़नी पड़ती थी जिसमें ब्रह्मसूत्र के ४६ अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद छात्रों को पाँच विद्याओं—धर्म विद्या, शिष्यम्यान विद्या, चित्तिरमा विद्या, हेतु विद्या और अभ्यास विद्या का अध्ययन करना पड़ता था।

प्राथमिक शिक्षा के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध मठों में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस शिक्षा को न केवल बौद्ध भिक्षु वरन् गृहस्थ बौद्ध धर्मावलम्बी भी प्राप्त करने के अधिकारी थे। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है कि शिक्षा का माध्यम पामी भाषा थी, जो जन-साधारण के द्वारा बोली जाती थी, न कि संस्कृत जैसा कि ब्राह्मणों द्वारा मंचालित शिक्षा संस्थाओं में था।

## २ उच्च शिक्षा (Higher Education)

पाँच विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके प्राथमिक और सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता था। उसके बाद उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ होता था। इस शिक्षा के केंद्र भी बौद्ध मठ थे। उच्च शिक्षा में अध्ययन के विविध विषय और विशेषज्ञता (Specialization) का प्रबंध था। छात्र व्याकरण, धर्म, योतिष दर्शन औपधि विज्ञान आदि का अध्ययन करके इनमें से किसी में विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते थे। हूगनसांग के अनुसार उच्च शिक्षा में अत्रियात्मक और प्रियात्मक (Theoretical and Practical) शिक्षा के दोनों पहलुओं पर बल दिया जाता था। डा० ए० एस० अल्तेकर (A. S. Altekar) ने बौद्ध मठों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा की प्रशंसा में लिखा है 'मठा न अपनी उच्च शिक्षा की योग्यता से जहाँ अध्ययन करने के लिए कोरिया चीन तिब्बत और जावा ऐसे सुदूर देशों से छात्र आकर्षित होते थे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की ऊँचा उठा लिया।' ('The monasteries raised the international status of India by the efficiency of their higher education, which attracted students from distant countries like Korea, China, Tibet and Java')

उच्च शिक्षा के केंद्रों में मानसू, वाताभी, विप्रमणीस, जगन्त, ओदन्तपुरी, मिपिन्सा और नादिया विविध रूप से उत्सहनीय हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानसू विश्वविद्यालय को प्राप्त था। यह आधुनिक स्वरूप में राजगीर (बिहार में) से लगभग आठ मील दूर था। मन् ४५० ई० से लेकर लगभग ३५० वर्ष तक यह अपना प्रतिष्ठता का शिखर पर था। मूलान्ध्याय के भारत आगमन के समय इसमें लगभग ५,००० भिक्षु थे जिनमें से १००० के

ऊपर ४००० विद्यार्थियों की शिक्षा का भार था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय द्वार-पण्डित कहलाने वाला विद्वान् शिक्षक विश्वविद्यालय के द्वार पर बैठ कर छात्रों की कड़ी मौखिक परीक्षा लेता था। विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म जन धर्म घटिक धर्म कहा आकरण ज्योतिष, पुराणों दानशास्त्र और औषधि विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। समग्र ८०० वर्ष के बाद ज्ञान और विद्या से सब दिशाओं की आलोचित करने वाला भारतीय दर्शन कलाओं और सम्प्रदाय का यह केन्द्र सेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बन्धियार पिलजी के द्वारा धूल में मिटा दिया गया।

## शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ

(Basic Principles & Features of Education)

बौद्ध धर्मविस्तारियों ने अपने धार्मिक सिद्धान्तों और आदर्शों के प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा-पद्धति का अपनाया। हम इसके आधारभूत तत्वों और विशेषताओं का उल्लेख नीचे की पंक्तियों में कर रहे हैं —

१ विद्यार्थित्व (Studentship)—बौद्ध शिक्षा-संस्थाओं में सभी जातियाँ, पत्ने और बगैरे के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। केवल ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित था।

२ छात्रों का चुनाव—अप्रमिश्रित छात्रों का विद्याध्ययन के लिये चुनाव नहीं किया जाता था—(१) जिन्होंने अपने माता-पिता की आज्ञा नहीं ली हो (२) जिनको कोई वैदिक आदि गेग हो, (३) जो राजा की नौकरी करते हों, (४) जो डाकू रह चुके हों, (५) जो धन से भाग भागे हों (६) जिनको राज्य से किसी प्रकार का संबंध मिल चुका हो (७) जिनका कोई वर्ग भंग हो या जिनके शरीर का कोई भाग विकृत हो (८) दास और (९) नपुंसक।

३ विद्याभ्ययन प्रारम्भ करने की आयु—डा० एफ० ई० हेई (F. H. Healy) के अनुसार विद्याभ्ययन आरम्भ करने की आयु ८ वर्ष की थी। प्रवेश के बाद छात्र 'धम्मल' या 'सामनेर' (Samanera) या नव शिष्य कहलाता था। इस दशा में वह १२ वर्ष तक विद्याभ्यास करता था। २० वर्ष की आयु में वह भिक्षु के रूप में प्रवेश कर सकता था।

४ पम्बजा संस्कार—प्रवेश के समय पम्बजा संस्कार होता था। पम्बजा का अर्थ है—'बाहर जाना'। इस संस्कार का अर्थ था कि छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था। विनय पिटक (Vinaya Pitaka) में पम्बजा संस्कार का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है —

छात्र अपने सिर के बास मुड़ाता था वैसे वस्त्र धारण करता था मठ के भिक्षुओं के घरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पासती मारकर बठ जाता था । मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे तीन बार यह कहलवाता था—“बुद्ध धारण गच्छामि धम्म धारण गच्छामि सध धारण गच्छामि ।” इसके बाद उसे आगे सिखे १० आदेश दिये जाते थे—(१) जीव-हत्या न करना, (२) चारा न करना (३) अशुद्धता से दूर रहना (४) असत्य न बोलना, (५) मादक पदार्थों का प्रयोग न करना (६) व्रजित समय पर भोजन न करना, (७) वृत्त संगीत और तमाशों के पास न जाना (८) शृङ्गार की वस्तुओं (पुस्तकालाओं सुगंधिया आभूषणों आदि) का प्रयोग न करना (९) ऊँचे विस्तर पर न साना, और (१०) सोने या चाँदी का दान न लेना ।

५ उपसम्पदा—नवशिष्य १२ वर्ष तक अध्ययन करने के बाद २० वर्ष की आयु को प्राप्त होता था । उस आयु में वह उपसम्पदा संस्कार सम्पादित करके भिक्षु के रूप में सध में रह सकता था । पम्बजा के समान उपसम्पदा एक पक्षीय संस्कार नहीं था । उपसम्पदा संस्कार सध के वय से कम १० योग्य भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था । उनमें से एक धमण का परिचय कराता था । उसके बाद अन्य भिक्षु उससे प्रश्नों प्रश्न पूछते थे । उनसे उत्तर सुनने के बाद उपस्थित भिक्षु यह निश्चय करते थे कि नवशिष्य उपसम्पदा ग्रहण करने का अधिकारी है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपसम्पदा की प्रणाली जनतान्त्रिक थी । उपसम्पदा के बाद धमण पक्का भिक्षु और सध में रहने का अधिकारी हो जाता था । उसे आगे सिखे नियमों का पालन करना पड़ता था—(१) भोजन के लिये भिक्षा माँगना, (२) साधारण वस्त्र पहिनना (३) कुश के नीचे निवास करना (४) गो-मूत्र को औषधि के रूप में प्रयोग करना (५) स्त्री समागम, चोरी, जीव-हत्या और अलौकिक शक्तियाँ का दावा करने से दूर रहना ।

६ अध्ययन-काल—अध्ययन काल २२ वर्ष का था—१२ वर्ष पम्बजा का और १० वर्ष उपसम्पदा का । अध्ययन काल के वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर ३० वर्ष की आयु पर समाप्त होता था ।

७ छात्र जीवन सम्बन्धी नियम—बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता था—

(१) भिक्षाटन—छात्रों को प्रातः जल्दी उठना पड़ता था और फिर भिक्षाटन के लिये जाना पड़ता था । वे मोन रूप से भिक्षा माँगते थे बोलचाल नहीं । वे भिक्षा में केवल उतना ही भोजन माँग सकते थे, जितने की उनकी आवश्यकता होती थी ।

(11) भोजन—विद्यार्थियों का भोजन बहुत सादा और दिन में साधारणतः तीन बार होता था। रात्रि भोजन के लिए वे और उनके शिक्षक प्रायः कहीं न कहीं आमंत्रित रहते थे।

(12) वस्त्र—छात्रों को कम से कम वस्त्र पहिनने का आदेश था। उनके वस्त्र तीन होन थे अतः उनको "तिसिवरा" (Ticivara) कहा जाता था।

(13) स्नान—स्नान करने समय छात्रों को पानी में खेल करने और अपने शरीर को लकड़ी या दूसरे के शरीर से रगड़ने का निषेध था। पर वे हाथ से अपने शरीर को मल सकते थे।

(14) अनुशासन—अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता था। छात्र क्रूर-वृत्ति, पीड़ा और वृद्धा को हानि नहीं पहुँचा सकते थे सम्पत्ति नहीं रख सकते थे नैल-तमाने नहीं देख सकते थे शरीर को अलंकृत नहीं कर सकते थे और व्यर्थ की बातें नहीं कर सकते थे। इन नियमों का पालन न करने वालों को दण्ड दिया जाता था। कभी-कभी अनुशासनहीनता के कारण पूरे मध को दण्ड दिया जाता था। उसी सब समस्याओं को मध से निवृत्त दिया जाता था।

८. गुरु के प्रति छात्र के कर्त्तव्य—छात्र को अपने शिक्षक से पहिले उठ कर उसकी नीतों और हाथ-भुँह धोने के लिये पानी का प्रबंध करना पड़ता था। वह गुरु के बैठने का स्थान ठीक करता था भाँड़ लगाता था और समझे बनाने को साफ करता था। वह गुरु के साप भिंसा भाँगने जाता था और समझे झीटने से पहिले वापिस आकर गुरु के लिये जल और भोजन का प्रबंध करता था।

९. छात्र के प्रति गुरु के कर्त्तव्य—जिस प्रकार गुरु के प्रति छात्र के कर्त्तव्य थे उसी प्रकार छात्र के प्रति गुरु के भी कर्त्तव्य थे। गुरु का प्रमुख कर्त्तव्य यह था कि वह अपने शिष्य का मानसिक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शित करे। उसे अपने छात्र के लिये वस्त्र भिंसा पात्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना पड़ता था। शिष्य के बीमार होने पर गुरु उसकी सेवा सुधुपा करता था।

१०. गुरु-शिष्य सम्बन्ध—गुरु और शिष्य का सम्बन्ध स्नेहपूर्ण था। गुरु अपने शिष्य के समस्त साधन, निरन्तर अध्ययन निष्कर्षक चरित्र, और ब्रह्मचर्य के आत्म प्रत्युत्पन्न करता था। अनेक वर्षों तक निरन्तर साथ रहने के कारण गुरु और शिष्य में पारस्परिक घट्टा निर्भरता और प्रेम का विकास हो जाता था। डा० ए० एस० अल्टेकर (A. S. Altekar) के शब्दों में अपने गुरु के साथ शिष्य के सम्बन्ध का स्वरूप गुणानुसृत था। वे पारस्परिक

सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। "The relations between the novice and his teacher were filial in character; they were united together by mutual reverence, confidence and affection."

११ पाठ्य-क्रम—बौद्ध मठों में जो उच्च शिक्षा के केन्द्र थे, अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे—बौद्ध धर्म हिंदू धर्म जन धर्म दार्शनशास्त्र (Philosophy) प्रपञ्चसूत्र विद्या (Metaphysics), तर्क शास्त्र (Logic) सम्स्कृत, पाली नवग्रन्थ-शास्त्र विद्या (Astrology), सगोच विज्ञान (Astronomy), औषधि विज्ञान (Medicine) न्याय शास्त्र (Law) राज्य-व्यवस्था (Polity) और प्रशासन (Administration)।

१२ शिक्षण विधि—शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी। रटने पर धन दिया जाता था, पर रटने के छात्र को उसे याद की हुई बातों पर समझ बनाना पड़ता था। बाद विवाद तक बिदलेपण व्याख्या और स्पष्टीकरण की विधियाँ का भी प्रयोग किया जाता था। हुएन सांग (Hsuen Tsang) ने शिक्षण की अन्य विधियों के बारे में इस प्रकार लिखा है "शिक्षक पाठ्य-वस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को समझाने पर प्रवृत्ति करते हैं। वे उन्हें परिश्रम के लिये प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से उत्पत्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे विद्यार्थीय छात्रों का निर्देशित करते हैं और मन्द-बुद्धि विद्यार्थियों को ज्ञान के अर्जन के लिये उत्सुक करते हैं।" ("The teachers explain the general meaning and teach them the minutiae they rouse them to activity and skilfully win them to progress they instruct the inert and sharpen the dull.")

१३ शिक्षा का माध्यम—बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भारत के विभिन्न भागों से आने थे और विभिन्न भाषाएँ बोलते थे। छल्ला वाग्देव (Challa Vagdev) की एक कहानी के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी दो ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से उनके उपदेशों का सम्स्कृत में लिखने की आज्ञा माँगी। बुद्ध ने इसकी अस्वीकार करती हुई कहा 'ओ भिक्षुओ! मैं तुमसे प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हूँ।' परम्परागत शिक्षा का माध्यम—देव की प्रचलित भाषाएँ थी।

१४ स्त्री शिक्षा—बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्न है और भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का आदेश दिया गया है। परम्परागत मध्य

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

म स्त्रियों को स्थान नहीं दिया गया। कुछ समय के बाद बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजापति के आग्रह पर स्त्रियों को सघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जो स्त्रियाँ सघ में प्रवेश करती थीं उनको भिक्षुणी कहा जाता था। इनको भिक्षुओं के समान ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इनके मठ भिक्षुओं से अलग होते थे। संघ में प्रवेश करने की आज्ञा मिलने के कारण स्त्री शिक्षा का काफी विकास हुआ। डा० ए० एस० अल्टेकर (A S Altekar) के मतानुसार स्त्रियों के सघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की शिक्षा की बहुत काफी प्रोत्साहन दिया। ' ( 'The permission given to women to enter the Order gave a fairly good impetus to the cause of female education especially in aristocratic and commercial sections of society' ) पर हम इससे यह निष्कर्ष नहीं निरान सौा चाहिये कि स्त्री शिक्षा की बहुत प्रगति हुई। सघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों ने ही प्रवेश दिया। इन स्त्रियों की सख्या कम थी क्योंकि इनका प्रवेश भिक्षुओं की इच्छा पर आधारित था और वे साधारणतः सभी स्त्रियों को प्रवेश नहीं देते थे। जहाँ तक साधारण स्त्रियों की बात थी उनकी शिक्षा के लिये बौद्ध शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं था।

१५ व्यावसायिक शिक्षा—बौद्ध शिक्षा में प्रमुख स्थान धर्म का था। पर उस समय के बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई। भिक्षुओं और जनसाधारण को विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी।

महावाग (Mahavaagga) में भिक्षुओं के लिये बताई बुनाई और सिलाई के प्रशिक्षण का वर्णन है। उनको यह प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता था, जिससे कि वे अपने वस्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बौद्ध बालीन विहार स्तूप और अन्य उन युग की भवन निर्माण कला के प्रतीक हैं और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इन कला में उच्च क्रांति के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। भिक्षुओं को भी इन कला से अवगत होना पड़ता था जिससे कि वे विहारों के भवनों का निर्माण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकें। भवन निर्माण कला का अतिरिक्त भूतिका और चित्रकला का प्रशिक्षण भी भी सुन्दर व्यवस्था थी जैसा कि नासन्द और विप्रमशील विश्वविद्यालयों के भवन तथा अन्य सम्बन्धीन द्भागों से प्रकट होता है।

शुद्ध जीवन व्यतीत करने वालों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जीविका उपार्जन में सहायता देने के लिये विभिन्न उद्योगों की शिक्षा दी जाती

थी जैसे-लेखन गणना (Accountancy) रूपम (Drawing) कृषि वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन। मिलिन्द पन्था (Milinda Panha) में १६ सिप्पाओ (Sippas) या गिप्पा का उल्लेख है जो बौद्ध-काल में प्रचलित थे। इनमें से अग्रसिप्पिन की शिक्षा तससिला के कुछ उच्च सिप्पा-वेत्ता में दी जाती थी—हस्ति ज्ञान (Elephant Lore), इन्द्र जाल (Magic Charms) मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मन्त्र आशेट (Hunting) सब पशुओं की वीलियों समझने का ज्ञान पशुविद्या भविष्य इषण इन्द्रिय-सम्यग्धी सब प्रियात्रा को बरा में करने की कला शारीरिक स्वता का अर्थ और औपधि विज्ञान। ध्या इन विषयों में वे बसत एक का अध्ययन कर सकते थे। इस प्रकार जसा कि डा० कार के० मुक्जर्जी (Dr R. K. Mookerji) ने लिखा है यह स्पष्ट हो जाता है कि सिप्पात्रा या प्राथमिक तथा वज्ञानिक गिप्पा के ज्ञान की माँग सामान्य गिप्पा या घामिक अध्ययन की माँग से किसी प्रकार कम नहीं थी।"

( The demand for the knowledge of the Sippas or for technical and scientific education was not less keen than that for general education or religious studies )

### ब्राह्मणीय और बौद्ध-शिक्षा (Brahmanic & Buddhist Education)

#### समानता (Comparison)

डा० ए० एस० अल्टेकर (Dr A S Altekar) का कथन है "जहाँ तक सामान्य गिप्पा सिद्धान्त या कावप्रणाली का सम्बन्ध था हिन्दुओं और बौद्धों में कोई आधारभूत अंतर नहीं था। दोनों पद्धतियाँ व समान आदर्श थे और दोनों समान विधियाँ का अनुसरण करती थीं। ( There was no fundamental difference between Hindus and Buddhists as far as the general educational theory or practice was concerned Both systems had similar ideals and followed similar methods ) वस्तुतः बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने प्राचिन हिन्दू संस्थाओं का अनुकरण किया अब हम दोनों पद्धतियों की समानताओं पर विचार करेंगे।

(१) बौद्ध धर्म ने अपने भिक्षुओं का नियम ब्रह्मचर्य का अनेकानेक नियमों को अपनाया। ब्रह्मचारी का प्रथम वर्तमान निष्ठा माँगना था। बौद्ध धर्म 'भिक्षु' का अर्थ है 'भिक्षा माँगने वाला'। ब्रह्मचारी व समान भिक्षु की भी भिक्षा माँगनी पड़ती थी।



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

(२) ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित शिक्षा-पाठ्य शिक्षा माँगने की विधि भोजन करने बठने सोने केस कटवाने वस्त्र पुष्पमाला आ सुगन्धियो तैलों आदि विलास की वस्तुओं के सभी नियमों को बौद्ध धर्म ने अपने मिश्रणों के सिधे अपना लिया था।

(३) बौद्धों का 'अहिंसा' का सिद्धान्त ब्राह्मणीय है। ब्रह्मचारी को जुती हुई भूमि और पशु के ऊपर चरने का निषेध था जिससे कि वह जीव हुर्या न करे। यही कारण था कि मिश्र को वर्षाकाल में यात्रा करने की आज्ञा नहीं थी।

(४) ब्राह्मणीय पद्धति में 'संन्यासी' अपना घर छोड़ देता था और वृक्ष के नीचे निवास करता था। मिश्र को भी वृक्ष के नीचे निवास करने का आदेश था।

(५) बौद्ध धर्म धार्मिक पवित्रता पर उतना ही धन देता है जितना कि धार्मिक धर्म। वेदों के अनुसार धर्म व्यवहार में लाई जाने वाली वस्तु है। इसका सम्बन्ध ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार से अधिक है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का अभ्यास (The practice of Brahma)। शिक्षक को 'आचार्य' अथवा धर्म के आदेशों का पालन करने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति पुस्तकों के अध्ययन की अपेक्षा उचित आदतों पर अधिक बल देती है। बौद्ध शिक्षा-पद्धति में भी ऐसा ही है।

(६) ब्राह्मणीय शिक्षा-प्रणाली में छात्रों द्वारा उपवास रखने की विधि को बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने भी अपनाया।

(७) जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में उपनयन संस्कार सम्पादित किया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में 'पद्मजा संस्कार' का सम्पादन होता था। दोनों संस्कारों में छात्र को अपने माता पिता को छोड़कर गुरु के पास रहना पड़ता था।

(८) जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में विद्याध्ययन प्रारम्भ करने को आयु निश्चित थी उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा-पद्धति में भी थी।

(९) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में अध्ययन की ग्युनतम अवधि १२ वर्ष की थी। इतनी ही अवधि बौद्ध धर्म में नवविषय के सिधे थी।

(१०) जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी को ब्रह्मचारी की उपाधि दी गई थी उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में 'पद्मजा संस्कार' के बाद छात्र को 'सामनेर' की उपाधि दी गई थी।

(११) ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति के 'गुरु शिष्य सम्बन्ध' के प्रमुख विचारों को बौद्ध शिक्षा पद्धति में अपना लिया गया था।

असमानता (Contrast)

बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि सत्कार दुःखा और कष्टों से परिपूर्ण है और इसका त्याग करके ही एक व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अतः बौद्ध शिक्षा-पद्धति का आयोजन ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति से विभिन्न ढंग से किया गया। इन दोनों शिक्षा-पद्धतियों में पाई जाने वाली असमानताओं का चलन नीचे किया गया है।

(१) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति को शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली (Domestic System of Education) कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रणाली में शिक्षक का घर या परिवार छात्र का विद्यालय होता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध मठ की प्रणाली थी। इसमें परिवार का स्थान सभ या विहार में ले लिया था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा ने गुरु और शिष्य के पारिवारिक बन्धनों को नष्ट कर दिया।

(२) ब्राह्मणीय प्रणाली में शिक्षा का केन्द्र गुरु-गृह था। इसका विकास अनेक शिक्षा वाला शिक्षा-संस्था में नहीं हुआ। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की यह एक प्रमुख विशेषता थी। बौद्ध विहारों में अनेक शिक्षा अध्यापन का कार्य करते थे।

(३) बौद्ध विहारों में अनुलिन सम्पत्ति होती थी और वे धनी होते थे। हमें 'विनय पिटक' (Vinaya Pitaka) में जान पेश है कि विहारों का जीवन उनके बाह्य के जीवन से अधिक सुख और सुविधापूर्ण था। भिक्षुओं को भोजन का अभाव नहीं था और रोगग्रस्त होने पर उनका उपचार देना के गुरु प्रसिद्ध वचन जीवन (Jivaka) के द्वारा किया जाता था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अनेक अव्यक्त मनुष्यों ने सभ में प्रवेश से लिया। इन स्वरूप विहार सद्गुण और सद्गान के केन्द्र न रह गये। क्योंकि इन द्रष्टव्यों ने ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में प्रवेश नहीं किया इसलिए भारत में एक बार फिर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ।

(४) बौद्ध शिक्षा-पद्धति में गुरु शिष्य के सम्बन्ध होने अन्तर्गत थे जिनमें कि ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में थे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रथम शिक्षा प्रणाली में छात्र के ऊपर गुरु का अधिकार कम हुआ गया। विहार के सभी शिक्षा पूर्ण गुरुओं का उन्माद करते थे। यह एक गम्भीर प्रभाव शिक्षा का मया के द्वारा पारित किये जाते थे और गुरु शिष्यों का मतदान का समान अधिकार

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

प्राप्त था। इस प्रकार जब कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रजातान्त्रिक सिद्धांत (Democratic Principle) पर आधारित थी ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति का आधार एन स्वामिक सिद्धान्त (Monarchical Principle) था।

(५) उपसम्पदा सत्कार' दोनों शिक्षा-पद्धतियाँ के एक प्रमुख अन्तर की ओर संकेत करता है। ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में ब्राह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद घर लौट आता था विवाह करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसके विपरीत उपसम्पदा सत्कार के बाद भिक्षु को संसार से अपने सभी बंधनों को तोड़ देना पड़ता था और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और बौद्ध धर्म का उपदेश करने में अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने की शपथ लेनी पड़ती थी।

(६) बौद्ध संस्कृति का आधार व्यक्तिगत शिक्षा सम्बन्ध और गुरुओं तथा शिष्यों की आदर्श परम्परा थी। इसके विपरीत बौद्ध संस्कृति विद्यालय विहारी में स्थित शिक्षा-संस्थाओं के मध्य पर आधारित थी जिनमें अनेकों शिक्षक और विद्यार्थी रहते थे।

(७) दोनों पद्धतियों में भिक्षाटन की प्रथा थी। पर भिक्षा माँगने के ढंग में अन्तर था। ब्राह्मचारी बोलकर भिक्षा माँग सकता था पर भिक्षु को मौन रूप से भिक्षा माँगनी पड़ती थी।

(८) ब्राह्मणीय शिक्षा व समान बौद्ध शिक्षा दोनों पर आधारित नहीं थी और इसका शिक्षक ब्राह्मण नहीं थे। बल्कि वही ब्राह्मण अध्यापन का कार्य कर सकते थे जो बौद्ध धर्म को अङ्गीकार कर लेते थे। ब्राह्मणीय शिक्षा संस्थाओं के विपरीत बौद्ध शिक्षा संस्थाओं के द्वार प्रत्येक जाति के व्यक्तियों के लिये खुल हुए थे।

(९) ब्राह्मणीय पद्धति में प्रत्येक विद्यालय या आश्रम का स्वतंत्र अस्तित्व था। इसका अर्थ शिक्षा-संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। बौद्ध प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय आन्तरिक मामलों में स्वतंत्र होता था पर अन्य विद्यालयों व समान ढंगका सम्बन्ध रखे होता था।

(१०) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। बौद्ध विद्वानों में स्थित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम पानी और देवी भाषाएँ थीं।

(११) व्यावसायिक शिक्षा पर जितना बल ब्राह्मणों ने दिया उतना बौद्धों ने नहीं दिया।

## उपसंहार

भारत में बौद्ध धर्म ने पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म का ह्रास होना चला गया और कालान्तर में सुप्त हो गया। पर शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने प्रान्ति उत्पन्न कर दी। डा० एफ० ई० केई (Dr F E Keay) के अनुसार ब्राह्मणीय विद्यालयों ने एक मात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर मुलभ करने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जन सामान्य की शिक्षा की दृष्टि का कुछ विस्तार किया और उस मार्ग को प्रारम्भ किया जिसने कारण सावजनिक प्राथमिक विद्यालयों का विकास हुआ। ( In breaking down the monopoly of Brahmanic schools and offering the possibility of education to men of all castes Buddhism may have done something to extend amongst the people of India the desire for some popular education and to have stimulated a demand which led to the growth of the popular elementary schools

## UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Bring out some of the salient features of Brahmanical and Buddhist education Which of them in your opinion has stood the test of time ?
- 2 Buddhist education shows several radical departures from the Brahmanic. Discuss
- 3 Bring out the salient features of the Buddhist system of education
- 4 Give an account of the organization of the Buddhist education

## मुस्लिम-कालीन शिक्षा (Islamic Education)

### विषय प्रवेश

भारत की धार्मिक उन्नति तथा सम्पन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने ईसा की आठवीं शताब्दी में भारत पर अपने आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। मुहम्मद गोरी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने बारहवीं शताब्दी के अन्त में भारत में मुस्लिम राज्य का शिला-पात किया। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व यहाँ बौद्ध तथा ब्राह्मणीय शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था। परन्तु मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता के कारण उनका हिन्दू शिक्षा-केन्द्र नष्ट कर दिये गए और उनकी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया गया। इनके बादशाह भी प्राचीन एवं शुभ्यवस्थित संस्कृति पर आधारित तथा धर्म से प्रेरित भारतीय शिक्षा की धारा मुस्लिम प्रभाव से दूर स्थित स्थानों में अबाध गति से आगे बढ़ती रही। इसी के साथ-साथ जिन नगरों में मुसलमान विद्यालय स्थापना में निवास करते थे अथवा कोई मुसलमान शासक रहता था वहाँ उच्च शिक्षा की धारा भी जिसका प्रेरण स्रोत धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी—प्रवाहित होने लगी।

## मुस्लिम शासकों के समय में शिक्षा (Education Under Muslim Monarchs)

मुहम्मद साहब का एक उल्गा यह था 'दान में सोना देन की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना अच्छा है।' ("It is better to educate one's child than to give gold in charity") उनके अनुयायियों ने इस आदेश का अमल पासन किया और सत्तार के उन भागों में जहाँ उनका शासन था शिक्षा के क्षेत्र में सहायनीय कार्य किया। यूरोप के सबसे प्रथम विश्वविद्यालयों में से क़ोर्डोवा (Cordoba) में मुसलमानों द्वारा स्थापित किया जाने वाला विश्वविद्यालय था। भारत के इस्लाम से उठाने शिक्षा के प्रति यहाँ बड़ा रुचि नहीं व्यक्त था। इसका कारण बताते हुए टी. एन. सिक्वेरा (T. N. Siqueira) ने लिखा है "भारत की मुस्लिम विजय इस्लाम शिक्षा के उग्न अंधकारपूर्ण युग की समयवर्ती थी जब कि विद्यालयों ने सभ्यता के अपने विस्मृत आदर्शों को खो दिया था।" ("The Muslim conquest of India coincided with a dark age in Islamic education when the schools had lost their wider ideals of culture") फसल अक्षर के अतिरिक्त और किसी भी मुस्लिम शासक का उनके शिक्षा प्रयासों के लिए यथामान नहीं किया जा सकता है। मुहम्मद ग़ाज़ी के समय से भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल तक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उनका संक्षिप्त विवरण नीचे की पंक्तियों में दिया जा रहा है।

१ मुहम्मद ग़ोरी—सन् ११९२ ई० में मुहम्मद ग़ाज़ी ने अंतिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान का पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। उसने अजमेर का विजय किया और वहाँ के मस्जिदों को पुनर्बाद कर मस्जिदों और पाठशालाओं का पुनर्बाद कर मस्जिदों तथा मस्जिदों का निर्माण करवाया।

२ बालासन के शासन—ग़ोरी का मृत्यु के बाद उसका भाई कुतुबुद्दीन ने सन् १२०६ ई० में बालासन ग़ुल्ल सन्धाना। उसका सहायक बालासन ने नामन्द और विजयनगर के बीच विश्वविद्यालयों का पराजय किया जिससे हिन्दू शिक्षा की महान् क्षति पहुँची। पर कुतुबुद्दीन ने मस्जिदों बनवा कर जो धर्म और शिक्षा का बन्धनों मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उमर उसका पिछारी अन्तर्गत ने जिसमें मस्जिद-ए-मुबारक का स्थापना की। नागिरुद्दीन के प्रधान मन्त्री के रूप में अलतून ने एक मस्जिद का निर्माण किया और अपने स्थायी के नाम पर उसका नाम "नागिरुद्दीन" रखा। ग़ोरी में,

समी दास दासको—कुतुबुद्दीन अस्तमश रजिया नासिरुद्दीन और बलवन ने भवतयो और मदग्या का निर्माण करके मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया ।

३ दिल्ली का के शासक—सुलतान मुस्ताना के समान खिलजी मुस्ताना ने शिक्षा के प्रति कोई रबि व्यक्त नहीं की । अलाउद्दीन ने अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन द्वारा शिक्षा के काम के लिये दिये 'इनामा और बक्फो' (Gifts & Religious Endowments) को जम्त कर लिया । इतने पर भी उस 'हौज खास' से सम्बन्ध एक मदरसा बनवाने का यश प्राप्त है । उसके परवर्ती शासक—मुबारक शाह ने शिक्षा के लिये दिये गये 'इनामा और बक्फो' का वापिस कर दिया पर दुर्भाग्य से वह थोड़े ही समय राय कर सका ।

४ तुगलक बंश के शासक—सन् १३२५ ई० में अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान् मुहम्मद तुगलक सिंहासन पर आरुढ़ हुआ । ऐसे विद्वान् के शासन-काल में शिक्षा का तीव्र विकास होना अनिवार्य था । पर सन् १३२७ ई० में उसने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी का परिवर्तन करके अलि मदान् मूल्ता की । इससे दिल्ली में विद्वानों का पूर्ण अभाव हो गया और शिक्षा के केन्द्र के रूप में उसका नाम कुछ समय के लिए मिट गया । सम्भवतः शिक्षा की इस क्षति को पूर्ण करने के ही लिये मुहम्मद तुगलक ने सन् १३४६ ई० में दिल्ली में एक मदरसा बनवाया । उसके परवर्ती फिरोज तुगलक के समय में मुसलमानों की उच्च शिक्षा में स्थापनीय वृद्धि की । वह स्वयं शिक्षित था और शिक्षित व्यक्तियों को सरक्षण देता था । इतिहासकार फेरिश्ता (Ferishia) के अनुसार उसने ३० मदरसा का आधार गिना रखा । इनमें हौज-खास के पास मदरसे फिरोजशाही था । बामनघ म यह साक्षर विश्वविद्यालय था जिसमें शिक्षक और छात्र शाही मर्चे पर रहते थे । अपने समय का विद्वान् मोसना जलालुद्दीन कमी इसका प्रधानाचार्य था । फिरोज के समय में बवल दिल्ली में ३०० भवतय और मदरसे थे । डा० युसुफ हुसैन (Yusuf Hussain) के अनुसार फिरोज ने व्यावसायिक शिक्षा का भी व्यवस्था की । एन० एन० लॉ (N N Law) में लिखा है कि फिरोज तुगलक ने शिक्षा पर ३६ लाख टंके (मर्दान् ३६ लाख रुपये) व्यय किया । फिरोज की मृत्यु के बाद शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी । सन् १३६८ ई० में तमूर ने अपने आक्रमण के समय अपने मार्ग में स्थित सभी शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं का पुनः पुनरिष्ठ कर दिया ।

५ सयद और मोदी बंश के शासक—मयन और मोदी राजाओं ने सन् १६१४ ई० से सन् १६२६ ई० तक शासन किया । पर शिखन्दर सोनी के

मिवा क़िस्सा और न सिगा के लिये कुछ नहीं किया। स्वयं कवि और साहित्यकार होने के कारण मिनरर लोदी ने अपने राज्य के सब भाग में मन्तरमा की स्थापना की और उनमें अध्यापन का कार्य करने के लिये दूर दूर के स्थानों से योग्य शिक्षकों को आमंत्रित किया। उनमें द्वाग मधुरा और नरवर में स्थापित किये गये मदरसा में जानि और धम का भेद भाव किये बिना सभी वर्गों के छात्र विद्या का अजन कर सकते थे। इस प्रकार हिन्दुओं में फ़ारसी के अध्ययन की रीति उत्पन्न करने का श्रेय सिक्न्दर सानी को है।

६ मुघलों द्वारा भारत की विजय—सन् १५२६ ई० में मुघलान ने भारत को विजय करने में मुघल साम्राज्य की नींव डाली। उस समय देश के विभिन्न भागों में अनेक मन्तरम और मदरसे थे। यही हक़ बान की ओर संकेत कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि उस समय तक मुगलमान शासकों ने किसी निश्चित गिगा-नीति का अनुसरण नहीं किया था। सम्भवतः यही कारण था कि बाबर को यह शिक्षा देने का अवसर मिला कि भारत में अच्छी शिक्षा-मन्त्रालय नहीं थी। बात को कुछ भी हो शिक्षा की मुघल सम्राटों से अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हम विभिन्न मुघल सम्राटों की गिगा सम्बन्धी गतिविधियों पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं —

७ बाबर—बाबर प्रथम मुघल सम्राट था। वह अरबी फ़ारसी और तुर्की भाषाओं का विद्वान् था और उसे खिता से प्रेम था। उसने एक मन्त्री सय्यद मनवर धली की तयारीय के अनुसार बाहरत आम विभाग (Public-Works Department) का एक कर्तव्य यह था कि वह मन्तरमा और मन्तरमा के मन्तरा का निर्माण करवाये। दुर्भाग्य से ४८ वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी गिगा-सम्बन्धी सभी योजनाएँ अतूना रह गईं।

८ हुमायूँ—बाबर के पुत्र हुमायूँ को अध्ययन में इतना अधिक रुचि थी कि उसने नाम मदेय कुछ पुनी हुई पुस्तकों का संग्रह रक्खा था। उसने द्वारा दिल्ली में बनवाया गया मदरसे में गणित भूगोल और नक्षत्र विद्या के गिगाण का विशेष प्रचार था। उसने खिल्ला में एक पुस्तकालय का बनवाया था जिसमें दरजे से गिरने पर उसकी मृत्यु हुई थी। "निहामफ़ार जाफ़र (Jaffar) के अनुसार हुमायूँ के मन्तरमों में सम्बन्ध एक मदरसा था। भारत में हुमायूँ ने निर्माण के समय दोरगा न उनमें गिहामन पर आरम्भ फ़ार नारनीत में एक मदरसा स्थापित किया।



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

६ अकबर—अकबर के शासन-काल में मकतबा और मन्तरसा में दीजानी वाली शिक्षा ने नव युग में प्रवेश किया। उसने आगरा फ़ौजेदुर्ग-सीकरी गुजरात और अन्य स्थानों में मदरसे बनवाये। ये मदरसे साबास बे और इनका (Husain) का कचन हैं, उसके आदेश के अनुसार पाठ्य-क्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किये गये जैसे—तर्कशास्त्र गणित भूमिति रैखगणित नक्षत्र विद्या लेखाशास्त्र सावजनिक प्रशासन और कृषि। इस योजना ने देश की समस्त शिक्षा-व्यवस्था को मौलिक पक्ष दे दिया। (At his suggestion certain important subjects such as Logic Arithmetic Mensuration Geometry Astronomy Accountancy Public Administration and Agriculture were included in the course of studies. This scheme gave a secular bias to the entire educational system of the country.) उच्च शिक्षा के स्तर पर नीति शास्त्र (Ethics) गणित (Arithmetic) लेखाशास्त्र कृषि रैखगणित नक्षत्र विद्या अयशास्त्र पदार्थ शास्त्र (Physics) तर्कशास्त्र भौतिक विज्ञान (Natural Philosophy) और इतिहास के शिक्षण की व्यवस्था थी। मुस्लिम विद्याभिया को कुरान और हिंदू धात्रा की व्याकरण वेदांत और योग पर पातजनि की व्याख्या की शिक्षा दी जाती थी। राय द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं में अतिरिक्त अनेको व्यक्तिगत शिक्षालय भी थे जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत चित्रकारी, दर्शन और गणित की शिक्षा दी जाती थी। अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से प्रेरित होकर अकबर ने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में मकतबा और मदरसा में हिन्दू धात्रा का अध्ययन की व्यवस्था कर दी। हिन्दू बानव मुसममान सहको के साथ अध्ययन करन लगे और दोनों ने समान पाठ्य-क्रम का अनुसरण किया। क्योंकि अकबर का स्वयं दन्ता में दृष्टि थी इसलिए उसने कारखाना की स्थापना की जहाँ प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था।

१० जहाँगीर—अकबर ने जिस निश्चित शिक्षा नीति की स्थापना की थी उसका अनुसरण उसके पुत्र जहाँगीर ने नहीं किया। फिर भी वह अपने राज्य में शिक्षा की प्रगति को बनाये रहा। उसने यह नियम बना दिया था कि यदि किसी धनी मनुष्य या यात्री की मृत्यु हो जाय और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सम्पत्ति राय का अन्वयन या जाय और उसका प्रयोग मन्तरसा की स्थापना तथा मरगण क लिये किया जाय। ताराण जहाँ (Tarikh-e-Jahan) में अनुसार राजनिर्वाह पर बढते ही उसने उन मन्तरसा

की मरम्मत करवाई जिनमें २० वर्षों में पणियाँ एवं पशुआ का निवास था और उनको छात्रा तथा शिक्षकों से भर दिया।

११ ग़ाहज़री—निस्सन्देह ग़ाहज़री को सुन्दर इमारतों से प्रेम था पर उसने शिक्षा की उपेक्षा नहीं की। उसने विद्वानों और कवियों को पुरस्कार तथा वृत्तियाँ देकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सन् १६५० ई० में उसने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक मन्दिर स्थापित किया। उसने 'दास्तवका' नामक मन्दिर की, जो सम्बन्ध ही गया था मरम्मत करवाई। उसकी पुत्री जहाँनारा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद से सम्बन्ध एक मन्दिर बनवाया।

१२ औरंगजेब—यद्यपि औरंगजेब स्वयं बहुत शिक्षित था पर वह अपने पूर्वजों के समान हिन्दुओं के प्रति सहिष्णु नहीं था। अतः वह उनकी शिक्षा से वैमनस्य रखने लगा। सर जदुनाथ सरकार (Sir Jadu Nath Sarkar) के अनुसार उसने सन् १६६६ ई० में हिन्दू मन्दिरों और विद्यालयों को नष्ट कराने का आग्रह किया। पर इसके साथ-साथ उसने मुस्लिम शिक्षा को प्रत्येक प्रकार की सहायता दी। एच० जी० कीन (H G Keene) ने लिखा है—“उसने मुसलमानों के लिये अनेक मदतियाँ और मदरसों की स्थापना की। (He founded numberless colleges and schools for Muslims.) उसने नियम पर योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी। उसने गुजरात की पिछड़ी हुई योद्धा जाति को शिक्षित करने के लिये आर्थिक सहायता दी।

१३ उत्तरकालीन मुघल सम्राट—औरंगजेब के बाद आने वाले मुघल सम्राटों की शिक्षा-सम्बन्धी नीति प्रायः नगण्य थी। इस सम्बन्ध में डा० एफ० ई० कैड (Dr F E Keay) ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं—“औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुघल साम्राज्य का विलम्ब हीनता से समाप्त होने लगा और सम्राटों या मीर-सरकारों की व्यक्तियों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं की निर्मित करने और उन्हें धन सम्पन्न करने का प्रयास बहुत ही कम हो गया। (“After the death of Aurangzeb the glory of the Mughal Empire began rapidly to wane and the efforts made by Emperors or private individuals to erect and endow educational institutions became much more rare”)

१४ नादिरशाह का आक्रमण—सन् १७३० ई० में भारत पर किये जाने वाले नादिरशाह के आक्रमण ने हम देश की शिक्षा पर अति प्रबल कूटारोपाय किया। अनेक पशुआ के साथ जिनके नादिरशाह अपने साथ फारस को ले गया, वह साथी पुस्तकालय भी थे जिनमें अनेक मुघल सम्राटों ने अनेक शक्ति और परिश्रम से विभिन्न विषयों की पुस्तकें सङ्ग्रीत और असङ्गत किया था।

## शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)

भारत के प्रायः सभी मुस्लिम शासकों की अपनी आकांक्षाएँ परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताएँ थी और इन्हीं के अनुरूप उनके शासन काल में शिक्षा के उद्देश्य रहे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों में कुछ उदार और कुछ अनुदार थे। बल्लियार अलाउद्दीन फिरोज़ तथा औरंगज़ब ऐसे अनुदार शासकों का एक मात्र उद्देश्य हिन्दू मस्जिदें तथा शिक्षा को नष्ट करने उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा एवं सिद्धांतों का प्रसार करना था। इनके विपरीत अल्तमश मुहम्मद तुगलक अक्सर तथा शाहजहाँ ऐसे शिक्षा प्रेमी शासकों का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना और उसे प्रोत्साहन देना था। उद्देश्यों की इस विभिन्नता के बावजूद भी प्रायः सभी मुस्लिम शासकों इस्लाम का प्रचार करना अपना प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व समझते थे।

सारांश में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों को अधोनिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है —

१. ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना—मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य इस्लाम के बन्धों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना था। हजरत मुहम्मद ने ज्ञान का अमल बताया और प्रत्येक सच्चे मुसलमान से ज्ञानाब्जन की आशा व्यक्त की। उन्होंने धर्म तथा अधर्म और कर्तव्य तथा अकर्तव्य में अन्तर जानने के लिए अपने धर्म के अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

२. इस्लाम धर्म का प्रचार—मुस्लिम शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। मुसलमान अपने धर्म का प्रचार को सबाब (पुण्य) मानते हैं और उनका विश्वास है कि धर्म का प्रचार करने वाला ही पाखी होता है। भारत का मुस्लिम शासक ने धर्म प्रचार की अनक विधियाँ में शिक्षा को भी स्थान दिया और इसका द्वारा भारत में इस्लाम का पर्याप्त प्रचार किया। इस प्रकार धर्म का प्रचार इस्लाम का आधारभूत सिद्धान्तों से परिचित कराया जाता था। मदरसों में धर्म दर्शन साहित्य तथा इतिहास का रूप में इस्लाम का प्रचुर माध्यम प्रचार किया गया।

३. एक विनिष्ट नैतिकता का प्रचार—मुस्लिम शिक्षा का तीसरा उद्देश्य इस्लाम का अनुगार व्यक्तियों में एक विनिष्ट नैतिकता का प्रचार करना था। मुसलमानों की नैतिकता हिंदुओं की नैतिकता में पूर्णतः भिन्न थी। वे अपने साथ भिन्न नैतिक भावनाओं का साथ दे उन्हीं की शिक्षा के द्वारा भारतीय मुस्लिमों में जाग्रत करना चाहते थे।

४ मुस्लिम सिद्धान्तों कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रसार—  
मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य मुस्लिम सिद्धान्तों, कानूनों तथा सामाजिक  
प्रथाओं का प्रसार करना था जिससे अधिक से अधिक भारतीय इस्लाम से  
प्रभावित होकर उसके समस्त आत्म-समर्पण कर दें।

५ मुसलमानों को धर्म-परायण बनाना—मुस्लिम शिक्षा का पाँचवाँ  
उद्देश्य मुसलमानों को धर्म-परायण बनाना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये  
मक़बरा तथा मदरसे मस्जिदों के एक भाग में होने थे। इन मस्जिदों में सामू-  
हिक रूप से नमाज़ पढ़ी जाती थी जिससे व्यक्तियों में धर्म परायणता की  
भावना का समायोजन सरलता से किया जा सक।

६ सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति—मुस्लिम शिक्षा का छठा उद्देश्य  
सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति था। इस्लाम का आधार मानव की दो मूल  
प्रवृत्तियाँ—अर्थ एवं यौन पर आधारित रहा है। अतः इन दोनों की व्यवस्था  
शौकिक यमव की प्राप्ति मुस्लिम शिक्षा का एक प्रधान लक्ष्य रहा। जो  
व्यक्ति गिरित होने थे उन्हें मुसलमान शासक सिपहसालार काजी अथवा  
बजीर इत्यादि के पद पर नियुक्त कर देते थे। इस सोम का कमीश्रुत हाकर  
मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदुओं ने भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ  
कर दिया।

७ मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना—मुस्लिम शिक्षा का सातवाँ उद्देश्य  
हिंदुओं को मुस्लिम सम्यता संस्कृति तथा आदर्शों से रञ्जित कर भारत में  
मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना था। मुसलमान शासक इस बात से पूर्णतया  
परिचित थे कि इस देश की विनाश हिन्दू जनता के दृष्टिकोण की शिक्षा का  
द्वारा परिवर्तित करके ही मुस्लिम सम्यता तथा संस्कृति का उद्धार बनाया  
जा सकता है और इस प्रकार उन्हें मुस्लिम शासन के दृढ़ स्तम्भ बनाया जा  
सकता है। ग़ज़नाई धरमर के सामाजिक प्रयास इसा उद्देश्य की पूर्ति का  
सिध थे।

शिक्षा की व्यवस्था (Organization of Education)

मुस्लिम युग में शिक्षा की व्यवस्था मातृशाला और मदरसों में की गई थी।  
मक़बरा प्रारम्भिक शिक्षा और मक़बरे उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। ये मक़बरा तथा  
मक़बरे मापारगुज किमी मस्जिद में सम्मिलित होते थे। इनकी स्थापना मुस्लिम  
शासक। एवं पत्नी विद्या प्रमिता—दाना का द्वारा की गई था। इनका निर्माण  
यही पर होता था जहाँ शिक्षा अमोर उपराय का निवास होता था और  
मुसलमानों को शिक्षा प्रविष्ट होती था। इनसे सबसे अधिक सामाजिक होने

बाल उच्च वर्ग के मुसलमानों के छोटे बालक होते थे। जन-साधारण के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई सुलभ साधन नहीं था।

**प्रारम्भिक शिक्षा**—प्रारम्भिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब 'गुरु' से बना है जिसका अर्थ है—उसने सिखा। इस प्रकार मकतब यह स्थान है—जहाँ सिखना सिखाया जाता है। समस्त मुस्लिम बालकों से मकतबों में शिक्षा प्राप्त करने की आशा की जाती थी जिससे कि वे ऐतिहासिक धार्मिक कृत्यों में प्रयोग किए जाने वाले कारण के विविध भाषाओं से अवगत हो पायें। मकतब में प्रवेश के समय 'बिस्मिल्लाह' रसम सम्पन्न की जाती थी। यह रसम उम्र गमय सम्पन्न की जाती थी जब बालक ४ वर्ष ४ माह और ४ दिन का होता था।

मकतबों में ली जाने वाली शिक्षा का पाठ्य-क्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का था। Yusuf Husain ने लिखा है—'भाषा-शिक्षण-बालकों को सिखाना पढ़ाना तथा प्रारम्भिक गणित का ज्ञान कराया जाता था। मुन्दर लेख पर विशेष रूप में ध्यान दिया जाता था।' बालकों को कुरान की कुछ आयतें कठम्य करनी पड़ती थीं। जब छात्रों को लिपि का ज्ञान हो जाता था तब उनको फारसी भाषा और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 'गुलिस्ता' और 'बोस्ता' पढ़ाये जाते थे। इनके अतिरिक्त पगम्बरों की कथाएँ, मुस्लिम फकीरों की कहानियाँ तथा फारसी कवियों की कतिपय कवितायाँ का ज्ञान भी कराया जाता था। व्यावहारिक शिक्षा के अन्तर्गत हाथचीत व डग पत्र-लेखन अथवा अर्जुनचीतों पर ध्यान दिया जाता था।

मकतबों की शिक्षण विधि मौखिक थी। बालकों को 'कसमा' पढ़ना पड़ता था और कुरान की आयतें कठम्य करनी पड़ती थीं। एक कक्षा के समस्त छात्र उच्च स्वर से एक साथ बातकर पढ़ाई याद करते थे। लिखने के लिए तलियाँ का प्रयोग किया जाता था जिन पर बालक माटे सरपन्डे की कल्पना में लिखते थे। फिर उन्हें पतल कसम से कागज पर लिखने का अभ्यास कराया जाता था।

**उच्च शिक्षा**—मकतबों की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्र मदरसे में प्रविष्ट हुआ था। 'मदरसा' शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा का दरस 'पढ़ना' से हुई है, जिसका अर्थ है—'मापण देना।' इस प्रकार 'मदरसा' यह स्थान है जहाँ पर मापण लिये जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मदरसों की शिक्षण पद्धति व्याख्यानों पर आधारित थी। इन मदरसों में भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा होती थी।

मदरसा के अध्यापक छात्रों में स्वाध्याय की आदतों को प्रोत्साहित करते थे। प्रत्येक छात्र को अपने विषय से सम्बन्धित पाठ दे दिया जाता था और शिक्षकों द्वारा उसकी गठिनाइयों को हल करके उसकी प्रगति में योग दिया जाता था। बिजित्ता हस्त-कला, शिल्पनशास्त्र, संगीत आदि विषयों की प्रायोगिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए तक विधि का अनुसरण किया जाता था। गिन्या का माध्यम अरबी था।

## शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ

(Basic Principles & Features of Education)

मुसलमानों के आगमन से भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को पर्याप्त क्षति पहुँची। मुसलमानों ने उसका ध्वस्त करने में कोई कसर न छोड़ा रखी और उसका स्थान पर एक नवीन शिक्षा तथा शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया। उसके आधारभूत तत्त्व तथा विशेषताएँ निम्नांकित थी—

१ शिक्षा की प्रोत्साहन—मुस्लिम युग में गिन्या की राज्य द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भारत के मुस्लिम शासक ने साधारणतया शिक्षा में विशेष रुचि व्यक्त की। उनमें से अनेकों ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में मकतबा मन्दिर तथा पुस्तकालयों की स्थापना की। देश के घना-भाना व्यक्तियों ने शासकों के उपाहरण का अनुसरण किया। शासक तथा अमीर उमरावों द्वारा विद्वानों को अथवा साहित्यिक पुरुषों को सरस्वत प्रदान किया गया। छात्रों को प्रायः छात्रवृत्तियाँ (Scholarships) तथा शिष्य-वृत्तियाँ (Studentships) प्रदान की जाती थी। इन सब सुविधाओं के फलस्वरूप शिक्षा का प्रासनीय प्रसार हुआ।

२ शिक्षा की व्यापकता का अभाव—मुस्लिम युग में शिक्षा का प्रसार अल्प हुआ पर उसमें व्यापकता का अभाव था। मकतबों तथा मन्दिरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर व्यापक धार्मिक चट्टरणा की छाप लगी थी अतः हिन्दू जनता उनसे सामान्यित न हो सकी। शिक्षा की जो भी व्यवस्था थी वह केवल शहरों में उच्च तथा मध्य वर्गों के शासकों के लिये ही थी। पतित जन-साधारण का भावका के लिये जानाजान करने का कोई साधन नहीं था।

३ प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा—मुस्लिम शिक्षा-वर्गों में शिक्षा का माध्यम अरबी अथवा फारसी था। फलस्वरूप प्रांतीय भाषाओं का प्रगति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई। राजपूतों के लिये सामायित हिन्दुओं ने भी अपनी

भाषाभाषा की उपेक्षा करके अरबी तथा फारसी का अध्ययन किया। अकबर की उदार नीति के कारण हिन्दी का प्रासादन तो अवश्य प्राप्त हुआ परन्तु उसकी कोई विशेष प्रगति परिलक्षित न हुई। औरंगजेब ने उर्दू भाषा की प्रोत्साहित किया। इन दोनों मुगल शासकों के समय में जो परिवर्तन हुए उनका अरबी तथा फारसी पर कोई प्रभाव न पड़ा और इन दोनों भाषाओं का प्राधान्य बचा बचता रहा।

४ शिक्षा का सौर्जिक दृष्टिकोण—मुस्लिम शिक्षा में धार्मिकता का विशेष स्थान था, परन्तु इस्लाम धर्म में इस सोक की वास्तविकता पर विशेष बल दिये जाने के फलस्वरूप सौर्जिक जीवन ने भुलसलमाना का अवधिण साकृष्ट किया फलतः शिक्षा-क्षेत्र पर सौर्जिकता का व्यापक प्रभुत्व रहा। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का मुस्लिम शिक्षा में सर्वथा अभाव रहा। शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य सौर्जिक यज्ञ भुज तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति माना गया। अतः हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा का एक आधारभूत तत्त्व बौद्धिक विकास की अग्रहेतना करके वास निगेय की आवश्यकता माया की पूर्ति करना अनाष्ट था।

५ गुरु शिक्षा सम्बन्ध—मुस्लिम युग में शिक्षा के प्रति परिवर्तित दृष्टि कोण के फलस्वरूप गुरु भक्ति के उस महान् आदर्श का हास होने लगा जो प्राचीन भारत में था। औरंगजेब ने अपने गुरु मुत्ता साह सालेह की अज्ञातनास की भाषा देशर जा कठोर व्यवहार किया वह इस बात का उच्चतम उदाहरण है। फिर भी जसा जि Jallia ने लिखा है— सामारणतया समाज में गुरुओं का सम्मान होता था। विद्यार्थी उनका प्रति विनम्र तथा भक्तिपूर्ण होते थे। गुरु की सेवा करना और उसकी भाषा का पालन करना व अपना वक्तव्य समझत थे। त्रिन मन्त्रता में द्वात्रावासा की व्यवस्था था वहाँ गिदाश तथा विद्यार्थी एक साथ रहत थे। इस प्रकार एक दूमेरे में निवट सम्पर्क स्थापित हो जाता था और आत्मीयता की वृद्धि होती थी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपन गुरुओं से और भी निवट सम्पर्क रहता था क्वाकि अपने तिल्य में दक्षता प्राप्त करने के लिये छिल्य गिदाशों का तिल्यकार के साथ निरन्तर रचना आवश्यक था।

६ अनुशासन तथा दण्ड विधान—जसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है शिक्षागण छात्रा के पूज्य तथा श्रद्धा के पात्र थे। अतः अध्यापक के गम्भीर अनुशासन की समझा उपरिपन्न नहीं होती थी। फिर भी कुछ दण्डद्वल छात्र होते थे जिनकी विवृण मनोवृत्तियाँ का दमन करने के लिए दण्ड का प्रयोग किया जाता था। राज्य की आरंभ कोई दण्ड विधान निर्धारित न होने के

कारण निम्नक विद्याविधा को कोई भी दण्ड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। सामान्यतः दण्ड अति कठोर एवं निम्न थे। छात्रा का बेल कोड़े और धुँसे से शारीरिक दण्ड दिया जाता था। यदि कोई छात्र महान् अवलम्ब करता था तो उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ या गरदन पर ईंट या भारी लकड़ी रख दी जाती थी जिसे वह निश्चिन्त समय तक गिरा नहीं सकता था।

## स्त्री शिक्षा (Education of Women)

मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा का विशेष महत्त्व है। पर इस्लाम स्त्री-शिक्षा का नियेय नहीं करता है। इन दोनों विरोधी तत्वा ने नारी शिक्षा पर दो विभिन्न प्रभाव पड़े। बालकों के समान बालिकाओं को एर निर्दिष्ट आयु के बाद विद्याभ्यास में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाने का अधिकार नहीं है। शिक्षा का निषेध न होने के कारण अल्पे परिवारों की बालिकायें घर पर विद्याभ्यास कर सकती हैं। यही बातें मुस्लिम शासन-काल में भी थीं। साधारणतः छोटी आयु की बालिकायें मस्जिदों में पढ़ने के लिये जाती थीं। पर निम्न वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम पूर्ण करने के बाद या उच्चतम पढ़ाई ही समाप्त हो जाती थी। उनके लिये उच्च शिक्षा के अवसर कम थे। जहाँ तक धन सम्पन्न परिवारों की बालिकाओं का प्रश्न था, वे व्यक्तिगत रूप से अपने घरों पर शिक्षा से ज्ञान का अर्जन करती थीं। तुर्क अधिपति काल में राज परिवारों की बालिकायें व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करती थीं। हम 'तबक़ाते नसीरी (Tabqat-i-Nasiri) से ज्ञात होता है कि रजिया मुल्ताना ने न केवल उच्च शिक्षा करन् मुठ कौशल की भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।

बालिका व शासन ग्यामुद्दीन मुहम्मद ने शारंगपुर में बालिकाओं के लिये एक मक़रसे का निमायाम किया था। फ़रिदना (Fetishla) के अनुसार हमने बालिकाओं की मुख्य मंगीत सीता सुनना मशमल तैयार करना, बड़ंगीरी गुनारगारी मुहम्मदीय, तरंग बनाना पून बनाना, कुन्नी लहना और रणधोर की बनावें मिताई जाती थी। पर इस मक़रसे में धन व्यय करने में समर्थ व्यक्ति की बालिकायें ही अध्ययन कर सकती थी।

मुग़ल काल में राजकुमारियाँ या नियमित रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था थी। Majumdar Raychoudhary and Datta ने भारत इतिहास में लिखा है कि इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने वाला राजकुमारियों में से अनेक ने शिक्षा-जगत में अपना नाम अमर कर दिया। उदाहरणार्थ—बाबर की पुत्री गुलबदन बख़्श के हुमायूँ नामा की रचना की। हुमायूँ की भतीजी सलीमा



मुल्ताना ने फारसी भाषा में अनेकों कविताओं की रचना की। तूरजही, मुमताज महल, जहाँनारा जैदम और जेहुजिसा—फारसी और अरबी साहित्य की श्रेष्ठ विदुषियाँ थीं।

राजघराने और कुलीन वर्ग की बालिकाओं के अतिरिक्त मध्य वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा भी एक सामान्य बात थी। Dr Yusuf Husain ने लिखा है 'जिजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिये मकतबों की जहाँ अधिक आयु की स्त्रियाँ उनको कुरान मुलिस्ताँ मोम्नाँ और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थीं'। Dr Husain के मतानुसार निम्न व्यक्तियों की बालिकाओं के लिये भी पिता के अवसर थे। उन्होंने लिखा है, 'मध्य वर्ग के परिवारों का विधवा स्त्रियाँ अपने घरों में अपने पास-पड़ोस के निम्न व्यक्तियों की पुत्रियाँ के सामान्य व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देती थीं।' पर इस प्रकार की शिक्षा के अवसर बहुत कम थे।

### व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)

व्यावसायिक शिक्षा के प्रति दिल्ली के मुल्ताना और मुगल सम्राटों—दोनों ने पर्याप्त ध्यान दिया। फतुम्बरु मध्यकालीन भारत में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की सरलता था। यथा—

१ जीविका-सम्बन्धी शिक्षा (Vocational Education —Jaffar के अनुसार जीविका-सम्बन्धी शिक्षा कारखानों में दी जाती थी। वहाँ लड़के किसी गिल्दिकार के सिष्य बनकर विभिन्न कला-कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करते थे। मुहम्मद तुगलक ने अनेकों कारखानों की स्थापना की थी। ये कारखाने राज परिवार और सरकारी विभागों की भाँगी की पूर्ति करते थे। विराट तुगलक के समय में इन कारखानों में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था।

अबदर के समय में जीविका-सम्बन्धी शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। उमर शासन-काल में सब कारखाने दीवान मुयुनात' बड़े जान वाल सरकारी विभाग के अधीन थे। इन कारखानों में कई भाग होते थे और प्रत्येक में एक कला की शिक्षा दी जाती थी। Father Monserrate के अनुसार कुछ कलाएँ ये थी—चित्रकला, मूनार का काम कपड़ा बनाना, दरी और पर्दे बनाना तथा अस्त्र-संस्करण करना। Bernier ने कुछ और कलाओं का उल्लेख किया है जैसे—जोड़ाकारी दर्जी का काम जूत बनाना और मयमत संवार करना। जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में कारखाने प्रशिक्षण

देने व काम को यथावत् करने रहे। औरगजेव ने उनका और कोई विषय ध्यान नहीं दिया।

कारखाना के सम्बन्ध में अपने मत का व्यक्त करते हुए Dr Yusuf Husain ने लिखा है 'कारखाने केवल उत्पादन के साधन ही नहीं थे यरन् शिल्प छात्रत्व की प्रणाली के अनुसार युवकों को प्राविधिक और जीविका सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के बेग के रूप में भी कार्य करते थे। वे व्यवसाय को सीखाने के लिये किसी उम्माद के निष्पन्न बना दिये जाते थे और कुछ समय के बाद स्वयं दक्ष हो जाते थे।' (The *Aarkhanahs* were not only manufacturing agencies but also served as centres for technical and vocational training to young men by the system of apprenticeship. They were placed under a master-craftsman (*Ustad*) to learn the trade and in course of time became experts themselves')

सैनिक शिक्षा (Military Education)—हिंदू राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये मुस्लिम शासकों को निरन्तर युद्ध करने पड़े। ऐसी स्थिति में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य समझा गया। राजकुमारों को युद्ध-कला में दक्ष करने का प्रयास किया जाता था। मुस्लिम सैनिकों का भी सैनिक शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में सैनिक पाठ्यक्रम का विस्तार करके उसमें गोली चलाना और हाथियों पर युद्ध करना सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि सैनिक शिक्षा के लिये सैनिक विद्यालय नहीं थे। यह शिक्षा राज्य-सेना के सैनिकों द्वारा दी जाती थी।

३ औपचिक विज्ञान की शिक्षा (Medical Education)—औपचिक विज्ञान की शिक्षा उचित रूप से दत्त के लिये संस्कृत पुस्तिका का पारसी में अनुबाध किया गया। शिवन्दर नादी के समय में भुवह बिन खास छौ ने 'मशानुग शिखा ए सिफ-दरी' नामक पुस्तक की रचना की। संस्कृत पुस्तिका पर आधारित औपचिक विज्ञान की अन्य पुस्तकें थी—'दम्पूर उल प्रतिब्या' 'तलिक-ए-शरीफ' और 'मुहफ्फ-अल-मासिन'।

औपचिक विज्ञान की शिक्षा अनेक मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओं में दी जाती थी। रामपुर औपचिकों के प्रयोग की शिक्षा देने के लिये प्रसिद्ध था। अकबर द्वारा आगरा में स्थापित शिखे गये कुछ मस्जिदों में औपचिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी।

४ भवन निर्माण कला चित्ररत्न मृग-कला और संगीत का प्रशिक्षण (Training in Architecture Painting, Dancing and Music)—इन

बात क अनेका प्रमाण मिलते हैं कि मुस्लिम शासनकाल में भवन निर्माण कला चित्रकला नृत्य-कला और संगीत क प्रशिक्षण के लिये सुविधायें थी। इन कलाओं में प्रशिक्षण की विधि बग़ावत और परम्परागत थी। शिष्यों की धर पर या कारखाना में प्रशिक्षण दिया जाता था। ये सभी कलाएँ जनप्रिय थी और इनको राजाओं तथा अमीरों का सरक्षण प्राप्त था। तुर्क-अफ़ग़ान युग में प्रारम्भ की गई भवन निर्माण कला को मुग़लों ने चरम सीमा पर पहुँचाने का प्रयास किया। शाहजहाँ की भवन निर्माण कला बड़े पैमाने पर रत्नराशि थी। जहाँगीर चित्रा का अत्युत्तम पारखी था। खस्रू ने 'ख्वास' संगीत को स्थायी रूप दिया और कुछ राग रगिनियाँ का आविष्कार किया। अकबर कुशल संगीतज्ञ था और अति सुन्दर ढंग से नक्कारा बजा सकता था।

### उपसंहार

Yusuf Husain का कथन है— मध्यकालीन भारत की गिज्ञा पर आलोचनात्मक दृष्टिपात करने से यह बात निर्विवाद रूप से सत्य प्रतीत होती है कि उस युग की गिज्ञा प्रणाली में सचीलपन का अभाव था फ़मत यह अत्यधिक अनन्य तथा अनिर्माणकारी हो गई थी। ('Critically speaking the system of education in vogue in medieval India lacked resilience and had become much too rigid and non-creative') समय समय पर उसमें परिपक्व अवश्य किये गये पर वह अपन का समय की माँगा क अनुकूल बनाने में समर्थ न हुई। गिज्ञा का एक प्रमुख कसब्य है— व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना जिससे कि वह सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं क सम्बन्ध को समझ सके और तदनुसार अपने को समय तथा स्थान के अनुकूल बना सके। यह मानसिक प्रगति का लक्षण है और इसके अभाव में कोई भी मानव समुदाय उन्नति नहीं कर सकता है।

Yusuf Husain के मतानुसार— मध्यकालीन गिज्ञा प्रणाली का मुख्य दोष यह था कि उसमें छात्रों की परिणुष्ट निरीक्षण तथा व्यावहारिक निष्ण करने की क्षमता नहीं थी। वह अत्यधिक अनन्य निष्ण तथा पुस्तकीय थी। (The chief failing of the medieval system of education was that it was not sound adequate to enable its adherents to form habits of accurate observation and practical judgment. It was much too rigid sterile and bookish.)

किन्ती भी गिज्ञा प्रणाली की सर्वोत्तम कसोती यह है कि क्या यह व्यक्ति क अधिक तथा आप्पात्मिक अभ्युत्थान क लिय उगवा। छात्रों का पूर्ण विकास

करती है अथवा नहीं ? इस सच्य को ध्यान में रखते हुए Yusuf Husain ने लिखा है— यह कथन एक ऐतिहासिक सत्य है कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति में नवृत्त के गुणों का विकास करने में असफल रही और इस प्रकार वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तित्व की पूर्ति न कर सकी । ('It would be historically true to assert that the medieval system of education failed to impart the qualities of leadership and thus ensure the supply of outstanding personalities in the different walks of life')

सारास में, यह कह सकते हैं कि यदि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रचुर व्यक्तित्व का निर्माण करने की क्षमता होती तो सम्भवतः भारत का मानचित्र सात रंग से न रंगा गया होता ।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Give a brief account of the system of education that existed in India during the Muslim period of Indian history
- 2 Discuss briefly the progress of education under the Muslim rulers of India
- 3 Write a note on the organization of Muslim education
- 4 Write short notes on the following —
  - (a) Value of *Maktabas* as educational institutions,
  - (b) *Larkhanahs* as centres of vocational education,
  - (c) Aims of Muslim education
  - (d) Position of teacher and teacher pupil relationship

# आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ (Beginning of Modern Education) मिशनरी प्रयास (Missionary Efforts)

## विषय प्रवेश

औरंगज़ब की मृत्यु (१७७२ ई.) के उपरान्त देश में अज्ञाति और अराजकता फैल गई। इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर तीव्र झुटाराघात हुआ और उसकी बाया दिन प्रतिदिन जीर्ण और जबर होती चली गई। इसके विपरीत पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में धीमे से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बनपन लगी। इसका प्रमुख कारण भारत में यूरोप निवासियों का आगमन था। १७वीं शताब्दी में पुर्तगाली फ़तीही डच डेन और अंग्रेज़ अपनी अपनी व्यापारिक कम्पनियों का निर्माण करके भारत में व्यापार करने लगे थे। यूरोप के इन व्यापारियों के कुछ समय पश्चात् वहाँ के ईसाई मिशनरियाँ न इस दस्त में प्रवेश किया। इन मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य वहाँ के निवासियों में अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार करना था। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा को अपना साधन बनाया। अब उन्होंने शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित कीं और उनमें आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की। यही स भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास का आरम्भ होता है।

## मिशनरियों के शिक्षा कार्य (Educational Activities of the Missionaries)

१. पुतलासी—पुतलासी मिशनरिया ने गोआ डामन ऊयू कोचीन सहा दूगनी और चटगांव में प्रारम्भिक विद्यालय खोल। इनमें पुतलासी भाषा कुछ स्थानीय भाषाओं को छोड़-कर भारीगरी और कुयि गणित तथा रोमन कथोसिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन मिशनरिया ने उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। १५७५ ई० में बॉल में प्रथम जेसुइट (Jesuit) कनिज खोला गया। सेन्ट ऐन (St. Anne) नामक एक दूसरा कनिज बन्दोरा में स्थापित किया गया। गोआ बेसीन और कुछ अन्य स्थानों में भी कनिज खोले गए। इन कनिजों में लैटिन ईसाई धर्म तक गणित व्याकरण और संगीत की शिक्षा दी जाती थी।

२. कासीसी—कासीसीया ने अपनी कनिजों—पॉन्डिचेरी माहों यनाम भारीवत और चट्टनगर—में प्रारम्भिक विद्यालय खोले। इनके द्वारा सब भारतीय बच्चों के लिये खुल हुए थे। इनमें भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। ईसाई धर्म का शिक्षा अनिवार्य थी। इन मिशनरिया ने पॉन्डिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय भी खोला जिसमें कासीसीया और बम्पनी के भारतीय कर्मचारियों के बच्चों को कासीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी।

३. डच—डच मिशनरिया ने नागापट्टम और चिन्नमुरा में कुछ विद्यालय स्थापित किये। इनमें बम्पनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बच्चों की शिक्षा का प्रारम्भ था। पुतलासीया के समान डचों के मिर पर धर्म प्रचार का मूल संचार नाला था। अतः उन्होंने अपने विद्यालयों को धर्म प्रचार का केंद्र एवं स्थापन नहीं बनाया। डा० प्रिडे (Prideaux) के अनुसार डचों ने उच्च शिक्षा के लिये सहा में एक कनिज खोला था।

४. फ्रेंच—इन मिशनरिया ने प्रोटेस्टेंट डविड, त्रिचनापल्ली और तमिलोर में प्रारम्भिक विद्यालय तथा ट्रान्कबूर में अस्पतालों को खोला के लिये एक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया। वहाँ के प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रारम्भिक स्कूलों में नियुक्त किया जाता था। इन मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने स्थानीय भाषा की शिक्षा का माध्यम रखा। मुगलसालों में अपने धर्म प्रचार-कार्य में सहयोग पान के लिये उन्होंने उन बच्चों की शिक्षा का प्राथमिकता दी और उनके लिये प्रारम्भिक विद्यालय खोल।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

५ अग्रज—अग्रज मिशनरिया का प्रमुख कार्य क्षेत्र बंगाल था। उन्होंने बलकला और सीरामपुर में दान आश्रित शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित की। सीरामपुर के मिशनरिया के छान नेता थे—करे (Carey) वाड (Ward) और मार्शमन (Marshman)। उन्हें सीरामपुर त्रिमूर्ति (Serampore Trio) कहा जाता था। उन्होंने शिक्षा की अपेक्षा ईसाई धर्म के प्रसार पर अधिक बल दिया। १८८६ ई० में उन्होंने हिंदुओं व मुसलमानों के नाम संदेश (Addresses to Hindus and Muslims) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें मुहम्मद माहब को भूला पशुपुत्र बताया गया और हिंदू धर्म की निन्दा की गई। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में द्वन्द्व उत्पन्न हुआ कि उसे गान्ध कराने के लिए साईं मिनटो (Minto) ने मिशनरिया का प्रस जल कर लिया और उनको बन्दो करवा के बलकला भुला लिया।

मिशनरियों को बम्पनी की इस दमन-नीति से बहुत असन्तोष हुआ। भारत में इसका विरोध करने में अपने को असमर्थ पाकर उन्होंने अपने समर्थकों के द्वारा इंग्लैण्ड में आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन का नेता चार्ल्स ग्रांट था।

### चार्ल्स ग्रांट (Charles Grant)

चार्ल्स ग्रांट बम्पनी के कर्मचारी और व्यवसायी के रूप में भारत में रह चुका था। इंग्लैण्ड लौटने पर उसने ग्रेट ब्रिटेन की एसियाई प्रजा की सामाजिक दशा का निरीक्षण (Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain) नामक पुस्तिका लिखकर भारतवासियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। उसमें लिखा—अज्ञानता को दूर करने का वास्तविक उपचार ज्ञान का प्रसार है। हिन्दू इसीलिए अज्ञानी करते हैं क्योंकि वे अज्ञान हैं और उनका अज्ञानता को उचित प्रकार से बर्ना भी उनका समझ नहीं रहता गया है। उनको हमारे प्रकाश और ज्ञान का दिया जाना ही उनका सच्चा उपचार सिद्ध होगा। (The true cure of darkness is the introduction of light. The Hindoos err because they are ignorant and their errors have never been fairly laid before them. The communication of our light and knowledge to them would prove the best remedy for their disorders.)

भारतवासियों में ज्ञान का प्रसार करने के लिये ग्रांट ने अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का उपयुक्त माध्यम बताया। उसका कहना था कि योग्य शिक्षा से

अंग्रेजी साहित्य विज्ञान दर्शन और धर्म की शिक्षा पाकर भारतवासियों की विचारधारा परिवर्तित हो आयी। ग्रान्ट की प्रायः सभी बातों को मविष्य में मान लिया गया। वस्तुतः भारत में अग्रज्ज्ञा शिक्षा पद्धति की अग्रिम रूप रस्ता का निर्माण उसी ने किया। इसलिए उसको भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक (Father of Modern Education in India) कहा जाता है।

### १७६३ और १८१३ के आज्ञा पत्र (Charters of 1793 & 1813)

राष्ट्र के विचारों से ब्रिटिश लोकन्याय का सदस्य विल्बरफोर्स (Wilber force) अध्यक्ष प्रभावित हुआ। जब सन् १७६३ में कम्पनी का आज्ञा पत्र (Charter) पुनर्गोधन के लिये संसद में आया तब विल्बरफोर्स ने उसमें धर्म प्रचार पर आधारित शिक्षा सम्बन्धी एक धारा जोड़ने का प्रस्ताव किया। पर कम्पनी के मन्त्रियों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने हुए कहा— हिन्दुओं की अपने धर्म और नीतिवृत्तों की उत्तनी ही उत्तम प्रणाली जितनी कि अधिकांश सभ्यताओं की है और उनका धर्म-परिवर्तन का प्रयास करना या उनको अधिक ज्ञान देना पातकपूर्ण होगा। रांडल जेक्सन (Randle Jackson) का मत था— 'हमने अमेरिका के उपनिवेशों को अपनी भाषा का प्रसार करने का कारण तो लिया है अतः हम भारत में ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए।' ( We have lost our colonies in America by importing our education there we need not do so in India too )

सन् १८१३ में कम्पनी का आज्ञा-पत्र पुनर्गोधन के लिये पार्लियामेंट में आया। गम्भीर विचार विमर्श के पश्चात् उसमें एक नवीन धारा जोड़कर मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का स्वतन्त्रता दे दी गयी।

### १८१३ के बाद मिशनरी प्रयास (Missionary Efforts after 1813)

१८१३ के आज्ञा-पत्र ने मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता दे दी थी। तत्पश्चात् थोड़े ही समय में प्रायः समस्त देश में मिशनरियों का आगमन हुआ। उनका प्रमुख उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना एवं भारतवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करना था। शिक्षा का साधन बनाकर वे भारतीयों में सम्पर्क स्थापित कर सकते थे। उन्हें अपने धर्म प्रचार कार्य के लिए शिक्षित भागताओं की आवश्यकता भी थी। अतः मिशनरियों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करना आवश्यक हुआ गया। प्रारम्भ में उन्होंने देशी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाया और इन भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें, शब्द-कोशों, व्याकरणों आदि का रचना की। उनके इस कार्य ने भारत में शिक्षा प्रचार में महान् योग दिया।



## मिशन स्कूलों की विशेषताएँ (Features of Mission Schools)

मिशनरियों ने जो शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की उनमें से अधिकांश प्रारम्भिक स्कूल थे। इन स्कूलों की विशेषताएँ निम्नलिखित थी—

- १ शिक्षा का आधार धर्म था। अतः ईसाई धर्म के सिद्धांतों और बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य थी।
- २ पाठ्यक्रम विस्तृत था और उसमें अंग्रेजी स्थानीय भाषाएँ व्याकरण इतिहास तथा भूगोल सम्मिलित थे।
- ३ शिक्षा मौखिक रूप से नहीं दी जाती थी क्योंकि छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित करवा दी गई थीं।
- ४ अंग्रेजी का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य था।
- ५ शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएँ थी।
- ६ स्कूल नियमित रूप से चलते थे शिक्षा के घण्टे नियत थे और रविवार को अवकाश रहता था।
- ७ स्कूलों में कक्षा प्रणाली का प्रचलन था।
- ८ एक शिक्षक-प्रणाली (Single Teacher System) का स्थान बहु शिक्षक प्रणाली ने ले लिया था।
- ९ विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को आधुनिक ढंग पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी।
- १० वर्ष व लिंग में लिखित परीक्षा द्वारा छात्रों की योग्यता की जाँच करके उन्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेज दिया जाता था।

### उपसंहार

ऊपर जिन पाँचों मिशनरियों का बहान किया गया है, उनमें से अधिकांश का स्थान भारतीय शिक्षा व इतिहास में अति गौरवपूर्ण है। यह बताने इतना ही नहीं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया अपितु हमें यह भी कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था का सूत्रपात किया और भारत को भावी माध्यम-विधानों के समस्त शिक्षा का भार वहन करने का भाग्य उपस्थित किया। इन कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था—जन-साधारण में ज्ञान का प्रसार करना। यचना के आतङ्का से हिंदू शिक्षा-व्यवस्था की नींव डगमगा चुकी थी। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच पला भुस्सिम शिक्षा-व्यवस्था सामान्य जनता व ज्ञान-मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकी थी। इस शिक्षा में इन विदेशी मिशनरियों ने निःसुख शिक्षा की योजना बनाकर और

भारी सभ्यता से व्यक्तियों को ज्ञान का रसास्वादन कराकर पथ प्रदर्शक का कार्य किया ।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 "The beginnings of the present system of education in India can be traced to the efforts of the Christian Missionaries . Discuss.
- 2 Write a short essay on the educational activities of the early European settlers
- 3 The missionaries used education not as an end in itself but as a means to evangelization ' Elucidate

## ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-कार्य (Early Educational Activities of the E. I. Company) [1600-1833]

### विषय प्रवेश

इंग्लिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को ३१ दिसम्बर १६६० को इंग्लैण्ड की रानी ऐलिजाबेथ (Elizabeth) से पूर्वी देशों में साध व्यापार करने का आगमन (Charter) प्राप्त हुआ। कम्पनी के व्यापारियों ने १६११ में भारत भूमि पर मद्रास में तमिल स्थान पर पहिला कारखाना स्थापित किया। प्रारम्भ में कम्पनी का ध्यान व्यापार और धन-प्रसार पर केन्द्रित था। अतः उसने जन-साधारण की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि अपने कर्मचारियों और प्रोटेजेंटों की शिक्षा के लिये भाषाई और मूल्य में कुछ विद्यालय खोले। धीरे धीरे कम्पनी अपनी राजनैतिक सत्ता स्थापित करने लगी। १७१७ में स्पानी के युद्ध की विजय के बाद या अधिक निश्चित रूप से १७६५ में मद्रास राज्य आसम से बंगाल विहार और उड़ीसा की सीकानी प्राप्त करने के बाद भारत में कम्पनी का राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। अतः उल्लेखनीय कम्पनी यह अनुभव करने लगी कि उसे भारत में हिन्दू और

मुसलमान दासता के समान इस देश के निवासियों की शिक्षा के लिये कुछ करना है। अपनी शिक्षा-नीति को निर्धारित करने में कम्पनी का दो तत्वों से विशेष योग मिला। प्रथम 'रेगुलेटिंग एक्ट' (Regulating Act) के अनुसार बलवत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसके मायाघाशा को भारतवासियों के घम रीति रिवाज आदि से परिचित कराने के लिये शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। द्वितीय प्रभावशाली भारतवासियों के पुत्रों की राज-पदा पर आसीन करना जिससे कम्पनी को अपने मद-स्थापित राज्य को सुगम बनाने में उच्च वर्गों का विश्वास और सहयोग प्राप्त हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रख कर कम्पनी ने 'बलवत्ता मदरसा' और 'बनारस संस्कृत कलेज' का विधान्यास किया।

### कलकत्ता मदरसा

१७८० में कलकत्ता नगर के कुछ सचप्रतिष्ठ मुसलमानों ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) से प्रापना का कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये एक मदरसा स्थापित किया जाय। कून्वोतिंग हेस्टिंग्स को मुसलमानों का प्रमत्त करने के लिये इसमें अधिक अच्छा अवसर कौन-सा हो सकता था? अतः उसके आश्वानुसार अक्टूबर १७८० से 'कलकत्ता मदरसा' शिक्षा-कार्य में लग गया।

मदरसे के पाठ्य विषयों में पञ्च विज्ञान-शास्त्र, कुरान व घम सिद्धान्त वातून 'मोतिष' 'यामिनि' गणित 'तर्क' शास्त्र अलङ्कार-शास्त्र एवं व्याकरण मुख्य थे। शिक्षा-बान ७ वर्ष और शिक्षा का माध्यम अरबी था। शिष्टों के अनिवारित कुरान पढ़ाने के लिये एक छात्रिक और नमाज पढ़ने के लिये एक मुअज्जिन था। मुस्लिम प्रथा के अनुसार प्रापना एवं पूजा-नाथ के लिये मुद्रशर को अवकाश रहता था।

### बनारस संस्कृत कलेज

कलकत्ता मदरसा के समान बनारस संस्कृत कलेज की स्थापना का कारण भी राजनीतिक था। इस कलेज का विधान्यास १७११ में बनारस राज्य के रजिस्ट्रार जनधन दसन (Jonathan Duncan) ने किया था। त्रिम प्रकार कलकत्ता मदरसा में मुस्लिम धार्मिक सिद्धान्तों और वातूना की शिक्षा देकर मुसलमानों में बलवत्ता की अग्रज न्यायाधीशों की महायता देन के लिये तैयार किया जाता था, उसी प्रकार बनारस संस्कृत कलेज में हिन्दू मन्त्रियों की हिन्दू पद-शास्त्रों एवं वातूना की व्याख्या करने के लिये स्थापित किया जाता था।

कॉलेज के पाठ्य-विषयों में हिन्दू धार्मिक सिद्धांत तर्कशास्त्र, दशन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र गणित सङ्गीत इतिहास कविता और कानून सम्मिलित थे। कॉलेज का समस्त प्रबंध धर्मशास्त्रों के नियमों पर और शिक्षा मानव धर्म (Institutes of Manu) पर आधारित था।

### फोर्ट विलियम कॉलेज

इस कॉलेज की स्थापना १८०० में साउथ वेलेजली (Wellesley) ने बलकला में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कम्पनी के तत्त्व कर्मचारियों को हिन्दू और मुस्लिम कानून भारतीय इतिहास अरबी फारसी संस्कृत और भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसमें बङ्गला साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में अति महत्वपूर्ण योग दिया और उनसे सम्बंधित पुस्तकें प्रकाशित की।

### १८१३ का आज्ञा-पत्र (Charter of 1813)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आज्ञा-पत्र प्रत्येक १० साल के बाद पुनर्नियमित होता था। अतः जब यह आज्ञा पत्र १८१३ में पुनर्नियमित के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया तब उसमें एक नवीन धारा जोड़कर शिक्षा को कम्पनी का कर्तव्य बताया गया और कहा गया कि प्रति वर्ष कम से कम १ लाख रुपये भारतीय साहित्य व पुनर्नियमित एक विज्ञान के प्रसार में व्यय किया जाय। परन्तु धन की व्यय करने की विधि का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। परिणामतः शिक्षा के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कम्पनी के कर्मचारियों के दो दल बन गये। य दल प्राच्यवादी (Orientalists), और पश्चात्यवादी (Occidentalists) कहलाये।

### कम्पनी की शिक्षा-नीति (१८१३-३३) (Educational Policy of the Company 1813-33)

१८१३ के आज्ञा-पत्र के फलस्वरूप विवाद के उठ खड़े होने से इस बात में भारतीयों की सहायता करने के लिये किसी निश्चित नीति का अनुसरण नहीं किया गया। एलिफिन्स्टोन (Elphinstone) और मुनरो (Munro) भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हेरिडिंग और मंटो (Minto) व समर्थक तथा ब्रिटिश की 'सोच शिक्षा-मार्गदर्शक' अरबी फारसी और संस्कृत व प्रोस्ताहन एवं वाइन मधनी भाषा द्वारा उच्च वर्गों की शिक्षा के पक्ष में थे। कम्पनी के सभासदों की शिक्षा-नीति में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। १८१४ में उन्होंने प्राच्य शिक्षा-शैली एवं संस्कृत के अध्ययन पर बल दिया। १८२४ में पश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के प्रसार का प्रस्ताव दिया, १८२८ में मुनरो की

भारतीय भाषाओं द्वारा जन-शिक्षा की योजना स्वीकार की, और १८१० में इस कार्य पर अङ्गुठा लगा दिया। यदि वे अपनी शिक्षा-नीति का स्पष्टीकरण कर सके, तो कम्पनी के अधिकारियों का मतभेद समाप्त हो जाता और शिक्षा की प्रगति के लिये ठोस कदम उठाना सम्भव हो जाता। परन्तु हमका दोषारोपण सचासका पर करना उचित न होगा। वस्तुतः अपने कर्मचारियों की प्रत्येक शिक्षा-नीति का समयन एवं सञ्जन करके वे 'प्रयत्न एवं भ्रम' (Trial and Error) की साधारण विधि का प्रयोग कर रहे थे जिसे कि वे अन्त में एक उचित शिक्षा-नीति का प्रतिपान्न कर सकें।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Discuss briefly the educational policy of the East India Company between 1765 and 1833
- 2 Write short notes on the following—
  - (a) Calcutta Madarassah
  - (b) Banaras Sanskrit College and
  - (c) Fort William College
- 3 The Charter Act of 1813 forms a turning point in the history of Indian education. Discuss

## प्राच्य-पारचात्य विवाद और निस्त्यन्दन सिद्धान्त (Oriental Occidental Controversy & Downward Filtration Theory)

### प्रियम प्रवेश

हम विद्यार्थी अध्याय में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीयों की शिक्षा का सम्बन्ध में बम्बई के अधिकारियों में मतभेद था। इस प्रश्न को लेकर दो प्रमुख दल उत्पन्न हो गये थे—प्राच्यवादी (Orientalists) एवं पारचात्यवादी (Occidentalists or Anglicists)।

### प्राच्यवादी (Orientalists)

इस दल में बम्बई के पुराने अधिकारी थे। सर्वप्रथम वागेन हेस्टिग ने 'बसवत्ता मन्दिर' स्थापित करके प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्त किया था। इसी नीति के अनुसार डब्लू. न. 'बनारस संस्कृत बालिका' का निर्माण किया था। मिंटो ने भी इसी नीति का समर्थन किया था। बंगाल की 'सर्व शिक्षा-समिति' (General Committee of Public Instruction) ने प्राच्यवादी नीति के समर्थकों का बहुमत था। इनमें बङ्गाल के शिक्षा-सचिव एवं प्राच्यवादी एच. एच. एच. टी. प्रिन्सेप (H. T. Prinsep) तथा समिति के मंत्री

एच० एच० विल्सन (H H Wilson) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन् १८१३ के आभा-पत्र के अनुसार १ लाख रुपये की धन राशि को व्यय करने का अधिकार इसी समिति को प्राप्त था। समिति में प्राच्यवादी नीति के समर्थकों का बहुमत होने के कारण प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिये कॉलेज का निर्माण किया गया था। विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियाँ दी गई थी एवं प्राच्य भाषाओं के ग्रन्थ प्रकाशित किये गये थे। वस्तुतः कूटनीति-परराष्ट्र प्राच्यवादी सङ्घटित अरबी एवं फारसी पर आधारित शिक्षा देकर भारतीयों को जातियाँ एक धर्मों में विभक्त रखना चाहते थे जिससे कि नव निर्मित ब्रिटिश राज्य को सति न पहुँचे। प्रिन्सेप का मत था कि भारतीय अग्रजों भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विल्सन नहीं चाहता था कि भारतीय अग्रजों पढ़ कर उमय देखातियाँ के साथ कच्चे से कच्चा मिठावर एक घरायश में रहें। कुछ प्राच्यवादीयों का मत था कि पश्चात्य ज्ञान एवं विचारों के सम्पर्क में आने से प्राचीन भारतीय सङ्कटित नष्ट हो जायगी। उनका यह भी कहना था कि भारतीय साहित्य में ज्ञान की ऐसी अपार निधि है कि उसका अध्ययन यूरोप निवासियों के लिये भी आवश्यक है। इस प्रकार के तर्क देकर प्राच्यवादियों ने प्राचीन सङ्कटित साहित्य एवं शिक्षा का सुरक्षित रखना भारतीयों के लिये हितकर बताया।

#### पश्चात्यवादी (Occidentalists)

इस दल में बम्पनी के नवयुवक अधिकारी एवं मिशनरी सम्मिलित थे। उनका कथन था कि प्राच्य शिक्षा-पद्धति मरणासन्न है और उगता पुनर्जातित्व परना अभ्यस्त है। उनका मत था कि अरबी पारसी एवं सङ्कटित साहित्य में रुढ़िवादी एवं सङ्कुचित विचारों के अतिरिक्त बिना भी सामग्र्य ज्ञान की खोज करना व्यर्थ है। यूरोप में विज्ञान के अध्ययन के कारण औद्योगिक क्रांति हा रही थी और नवीन आविष्कार लिये जा रहे थे। अतः पश्चात्यवादी भारत की प्रगति के लिये अग्रजों शिक्षा द्वारा पश्चात्य विचारों के प्रसार के पक्ष में थे। इसमें भी एक राजनिति भाव था। अग्रजों को अपन व्यापारिक तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए बांग्लादेश की आवश्यकता थी। इस निम्न वर्ग के दिव्य व्यक्तियों को दृष्टिपूर्वक लेन साकर भारतीयों का निर्गुण करने तथा कर सना ही अपित विदेशपूर्ण बाय था।

#### मकाले का विवरण-पत्र (Macaulay's Minute)

जिस समय प्राच्य-पश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर रहा था उसी समय सार्जेंट मैकाले (Macaulay) १० जून १८३४ को गवर्नर-जनरल की



कौंसिल के कानून-सदस्य के रूप में भारत आया। वह अंग्रेजी का प्रकाण्ड विद्वान् था और अपने लेखों तथा व्याख्यानों से लोगों में जीवन का संचार कर देता था। वह उस युग की उपज था जब अग्रज अपने साहित्य एवं संस्कृति की सर्वेष्टक समझ कर विश्व विजय के लिये अपना अभियान प्रारम्भ कर चुके थे। इन्हीं विचारों से आत प्रीत भर्तृहरि ने भारत में पदार्पण किया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड बेंटिन्क (William Bentinck) ने उसे बंगाल 'लोक शिक्षा-समिति' का प्रधान नियुक्त किया और उससे १८१३ के आज्ञा पत्र की शिक्षा-सम्बन्धी धारा की व्याख्या करने में लिये तथा १ लाख रुपये की धन राशि को व्यय करने के विषय में कानूनी सलाह माँगी। २ फरवरी, १८३५ को मकलि ने अपना विवरण पत्र (Minute) गवर्नर-जनरल की कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस विवरण-पत्र में बर्तले ने प्राच्य साहित्य एवं शिक्षा का सङ्ग्रह तथा अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया। 'साहित्य' शब्द की व्याख्या करते हुए उसने लिखा कि इसका अर्थ 'अबद्ध साहित्य' से है न कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी के साहित्य से। इसी प्रकार भारतीय विद्वान् ने ऐसे विद्वान् का तात्पर्य है— 'जो लॉक (Locke) के दर्शन एवं मिल्टन (Milton) की कविता से परिचित हो।'।

इसके पश्चात् बर्तले ने शिक्षा के माध्यम के प्रश्न का लिया। उसने देशी भाषाओं का विषय में लिखा— भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान की कमी या अभाव है तथा वे इतनी अविश्वसित और गैरवास्तविक हैं कि जब तक उन्हें बाह्य मण्डल से सम्पर्क नहीं किया जायगा उनमें सुगमता न किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न का अनुवाद नहीं हो सकेगा।'

इस प्रकार बर्तले ने देशी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न वाद-विवाद से अलग कर दिया। तत्पश्चात् उसने संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं की अपेक्षा से तुलना करते हुए निम्नोक्त भाव में व्यक्त किया— 'एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। (A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia)'

बर्तले का प्रस्ताव था कि महत्त्व अरबी तथा फारसी में लिखे हुए कानूनों का अंग्रेजी में उद्घाटन (Code) बाध दी जाय। उनका कथन था कि केवल कानूनों की जानकारी के लिये महत्त्व अरबी तथा फारसी के शिक्षासूत्र पर धन व्यय करना भ्रमशून्य है। अब उसने प्रस्ताव किया कि उनसे विस्तृत बंद

कर दिया जाय । अंग्रजी भाषा की प्रशंसा में आकाश-पातान एक करते हुए उसने लिखा— यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है । जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विज्ञान ज्ञान भण्डार का प्राप्ति कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातिशा न रचा है ।" ( It stands pre eminent even among the languages of the West Whoever knows that language has ready access to all the vast intellectual wealth which all the wisest nations of the earth have created )

सारंग में मैकालि ने अपने विवरण पत्र में अंग्रजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया ।

### बेंटिन्क की स्वीकृति (Bentinck's Approval)

बेंटिन्क ने मैकालि के प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करके, १८१३ में प्रारम्भ होने वाले शिक्षा विचार का अन्त कर दिया । ७ मार्च १८३५ के आदेश-पत्र में बेंटिन्क ने शिक्षा-नीति की घोषणा की जिसकी रूप-रेखा इस प्रकार थी—

- १ ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है । इन सबसे हमी कार्य के लिये शिक्षा-सम्बन्धी समस्त धन राशि व्यय की जायगी ।
- २ प्राच्य शिक्षासिद्धांतों का बहिष्कार तथा उन्मूलन नहीं किया जायगा । उनके अभ्यास तथा छात्रों की पूर्णवृत्ति के लिये एक छात्रवृत्तियों की जाएगी ।
- ३ भविष्य में प्राच्य विद्या-सम्बन्धी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्राध्यान नहीं होगा क्योंकि इनमें अत्यधिक धन व्यय किया जा चुका है ।
- ४ इन गुणों से बचा हुआ समस्त धन भारतीयों में अंग्रजी भाषा के माध्यम द्वारा अंग्रजी साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करने में व्यय किया जायगा ।

भारत सरकार की यह प्रथम घोषणा थी जिसमें अंग्रजी की शिक्षा-नीति का स्पष्टीकरण और भारतीय शिक्षा के उद्देश्य साधन तथा माध्यम की स्थायी रूप प्रदान किया गया था ।

### भारतीय शिक्षा की मैकालि की देन (Macaulay's Contribution to Indian Education)

मैकालि के विवरण पत्र के अनुसार प्राच्य शिक्षा में विज्ञान-प्रति विषयों का निर्माण हो गया और बंगाली की स्थिति शिक्षा-नीति में स्थिरता का

गई। फिर भी मॅकॉले की अति कटु आलोचना की गई है। उसके सम्बंध में प्रमुख धारणाएँ निम्नलिखित हैं —

१—कुछ व्यक्तियों द्वारा मॅकॉले भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शन' (Torch bearer in the path of progress) माना जाता है। यह कथन एक प्रकार से असत्य ही है क्योंकि वह प्रथम व्यक्ति नहीं था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की ओर पहला कदम उठाया था। हम उस शिक्षा की आधुनिक संरचना का स्थापक तो मान सकते हैं, पर भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक नहीं।

२—कुछ लोग मॅकॉले पर भारतीय भाषाओं के अपमान एवं अवहेलना का दोषारोपण करते हैं। पर उस पर यह आरोप सगाना सबूत अनुचित है। लोक शिक्षा-समिति के प्रधान के रूप में उसने १८३६ की अपनी रिपोर्ट के अन्तर्गत कहा— हमें देशी भाषाओं के प्रोत्साहन एवं विकास में अत्यधिक रुचि है। हम समझते हैं कि देशी भाषाओं के साहित्य का विकास हमारा अन्तिम उद्देश्य है और हमारे सब प्रयास इस दिशा में लग जाने चाहिए।

३—कुछ व्यक्ति मॅकॉले का राजनैतिक अद्यान्ति का कारण मानते हैं। यह ऐसा आरोप है जिस पर सम्पूर्ण इङ्ग्लैण्ड गव्व कर सकता है। परन्तु इसका समस्त उत्तरदायित्व मॅकाल द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा की नीति पर नहीं रखा जा सकता है। इस नीति की अनुपस्थिति में भी राजनैतिक अद्यान्ति हो सकती थी।

४—मॅकॉले पर अन्तिम दोषारोपण यह है कि वह अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो 'रक्त और रंग में भारतीय हो पर पगल विचार आचरण और विन्यास में अंग्रेज हो'। ('A class of persons Indian in blood and colour but English in tastes in opinions in morals and in intellect') वास्तव्य सम्मता और संस्कृति का उपासक वर्ग का निर्माण करने वह भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को चिरस्थायी बनाना चाहता था। पर उसकी यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई।

उपरोक्त धारणाओं की विवक्षना के आधार पर हम निम्नलिखित कह सकते हैं कि मॅकॉले का सर पर मारा दोष मढ़ना उचित न होगा। वस्तुतः भारत उगता सदैव शूली रहेगा। उगने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार का समर्पण करने भारतीयों में राजनैतिक जागरण वधानिक चेतना और आर्थिक विचारधाराएँ प्रभुत्व की। इनका फलस्वरूप भारत ने सामान्यतः स्वतंत्रता का युग में प्रवेश किया। अब यदि हम यह कहें कि भारतीय शिक्षा का इतिहास में मॅकॉले का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है तो अनुचित न होगा।

## विवाद का अन्त (End of the Controversy)

जैसे ही साठ मिलियन ब्रिटिश ने १८३५ में त्याग-पत्र देकर स्वयं को लिये प्रस्थान किया प्राच्यवादियों ने सरकार के निणय के विरुद्ध आवाज उठाई। वे मैग्जि के विवरण पत्र और ब्रिटिश व आशा पत्र से असंतुष्ट थे और उन्होंने देशी भाषा के माध्यम गया कुछ अन्य बातों पर विवाद आरम्भ कर दिया। जब लॉर्ड ओकलैंड (Auckland) गवर्नर-जनरल नियुक्त होकर भारत पहुँचा, तब उसने स्थिति को पर्याप्त गम्भीर पाया। लगभग ४ वर्ष तक विभिन्न मतों का सतर्कता से अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वाद विवाद का आधारभूत कारण आर्थिक सहायता है। उसने विचार लिया कि यदि प्राच्यवादियों को शिक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिये कुछ अधिक धन दे दिया जाय तो वे शीघ्रतः मरणाशय बन कर देंगे। इस बात को दृष्टिगत कर सरकार उसने २४ नवम्बर १८३६ को अपना विवरण-पत्र प्रकाशित किया दोनों दलों की धन-सम्बन्धी माँगों को पूरा कर लिया और इस प्रकार १८३३ से आरम्भ होने वाले प्राच्य-वादवात्य विवाद को समाप्त कर दिया।

## ✓ नित्यन्दन सिद्धान्त (Downward Filtration Theory)

अर्थ—नित्यन्दन सिद्धान्त का अर्थ है यह कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाय और इन वर्गों से धीरे-धीरे शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। अरपर मेह्यू (Arthur Mayhew) के अनुसार जन-मन में शिक्षा ऊपर से धीरे-धीरे पहुँचना थी। बूँद-बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से सामान्यतः शिक्षा नीचे की ओर, जिससे कि वह कुछ समय में एक छोटी एक विनाश धारा में परिवर्तित होकर धीरे-धीरे मैदानों का सिंचन करे। (Education was to permeate the masses from above Drop by drop from the Himalayas of the Indian life useful information was to trickle downwards forming in time a broad and stately stream to irrigate the thirsty plains )

समर्थन—भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का इस सिद्धान्त में विश्वास था। वे समझते थे कि यदि इस देश के मूल्यों हिन्दुओं को ईसाई धर्म में दोषित कर दिया जायगा, तो निम्न वर्गों को इस धर्म को स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा क्योंकि इन वर्गों की व्यक्ति उच्च वर्ग के आशों का अनुसरण करते थे। बंगला के बर्मिगहाम्स में बर्मिहू के गवर्नर की कीर्ति के सम्मेलन, वार्डन (Warden) ने २३ नवम्बर १८२३ का भाव विवरण-पत्र में यह विचार इस सिद्धान्त की ओर संकेत किया था— जन-साधारण को दोषो-ही

शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा।" कम्पनी के सचिवों ने २६ सितम्बर १८३० के अपने आदेश-पत्र में मद्रास की सरकार को लिखा था— शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है, जब उच्च वर्गों के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाय, जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने दण्डीवासियों पर प्रभाव है।" मकाले ने इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए अपने विवरण-पत्र में लिखा था— हमारी इस शिक्षा द्वाारा एक ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त एक वर्ग में भारतीय होगा परन्तु पतन, विचार आचरण एवं विद्वत्ता में अग्रगण्य होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य होगा कि वे भारतीय भाषाओं को परिष्कृत तथा सम्पन्न करके उन्हें जनता तक नाम पहुँचाने का योग्य बनायें। सैड जॉन्सोन् ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और इसे सरकारी नीति के रूप में घोषित किया।

आधारभूत कारण—इस सिद्धान्त को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने के चार कारण थे। प्रथम ब्रिटिश सरकार को प्रारम्भ में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनको शिक्षित करके एक उच्च पद प्रदान करके राज्य का सुदृढ़ बनाया जाय। इससे लिये उच्च वर्ग की शिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी सोच-विचार नहीं। द्वितीय सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह सोच-विचार का भार अपने ऊपर न सकती। तृतीय अंग्रेजों माध्यम द्वारा उच्च वर्ग को शिक्षित करके और रहन-सहन तथा आचार विचार का परिवर्तित करके निम्न वर्गों को सरसता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता था। चतुर्थ, कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करके जन-साधारण को शिक्षा का भार उनके ऊपर छोड़ जा सकता था।

परिणाम—इस सिद्धान्त ने भारतीय शिक्षा का रूप निर्दिष्ट कर दिया। सरकारी नीति के रूप में इस अभिवारिका का प्रथम समर्थन प्राप्त हुआ और उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति होने लगी। सन् १८४४ में सार्द हार्डिज (Hardinge) की घोषणानुसार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्ति करना हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा की प्रगति और भी अधिक तेज हो गई। परन्तु सरकार ने जिस विचार से इस सिद्धान्त को अपनाया था उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। उच्च वर्ग को शिक्षित करके जन-साधारण तक ज्ञान को नहीं पहुँचाया जा सका, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च वर्ग पर आसीन हो जाते थे उनका जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त

करके एर ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया जो अनिश्चित निर्धन व्यक्तियों से अपने को घट्ट समझता था। यह कहना अनिश्चित्यपूर्ण न होगा कि हम वग के अनेकों व्यक्ति ब्रिटिश राज्य के स्वतन्त्र रूप से अपने दसवासियों के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रबल विरोध करते रहे।

## UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Write what you know about the Oriental-Occidental Controversy
- 2 Give a critical appraisal of Lord Macaulay's contribution to Indian education.
- 3 "Macaulay is a torch bearer in the path of progress. Do you agree? Give your arguments in favour of the view you hold
- 4 Write a short essay on the "Downward Filtration Theory

## शिक्षा की प्रगति (Progress of Education) [1833-1853]

### विषय-प्रवेश

सन् १८३३ तक बम्पनी की शिक्षा-नीति बिल्कुल अनिश्चित रही और भारतीय शिक्षा ने अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उठ खड़ा हुआ था उसका अन्त करने में लॉर्ड ऑक्सफ़ोर्ड ने अपनी नीति-चुनौती का परिणाम दिया। उसके बाद से शिक्षा का माग निश्चित हो गया और वह अवाध गति से अग्रसर होने लगी। भारत के विभिन्न प्रान्तों में शिक्षा-प्रसार के लिए अनेकों कार्य किये गये। हम इन पर नीचे दृष्टिपात कर रहे हैं।

### बंगाल

ब्रिटिश एवं ऑक्सफ़ोर्ड के शिक्षा-कार्य—ब्रिटिश ने अँग्रेजी का शिक्षा का माध्यम थापित करने बंगाल में अँग्रेजी का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। सन्त अँग्रेजी का शिक्षा देने के लिये विद्यालयों का तीव्रगति से निर्माण हुआ। ऑक्सफ़ोर्ड ने शिक्षा की आर विचार ध्यान दिया। उसने बंगाल प्रान्त को ६

माया म विभक्त किया और प्रायः प्रत्येक जिले में एक जिला विद्यालय स्थापित किया।

हार्डिज के गिरा-बाय—सन् १८६४ में साह हार्डिज (Hardinge) ने घोषणा की कि अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों की सरकार। नीकरिया में प्राथमिकता दी जायगी। फलतः अंग्रेजी के प्रचार एवं प्रसार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। उस समय प्राथमिक शिक्षा का पत्र प्रारम्भ हुआ गया था। अतः हार्डिज ने उसे प्रोत्साहित करने के लिये प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करवाया। परन्तु अंग्रेजी गिरा क अभाव में वे विद्यालय लोकप्रिय न बन सके।

डलहौसी के गिरा-बाय—साह डलहौसी (Dalhousie) विद्या प्रमी था। उसने प्राथमिक उच्च व्यावसायिक तथा नारी गिरा में अपनी रीति प्रदर्शित की। उसने अनुमान प्रणाली प्रारम्भ करके प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहित किया।

गिरा-परिषद् (Council of Education)—सन् १८४२ में लोक गिरा समिति की भग करके उसने स्थान पर गिरा-परिषद् की स्थापना की गई। इस परिषद् ने गिरा प्रचार की गिरा में सराहनीय कार्य किया। परिषद् ने सन् १८४३ में गिरा का पाठ्य-क्रम निश्चित करने पाठ्य-पुस्तक में सुधार किया। सन् १८४४ में विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति करके विद्यालयों की गिरा का भार उन्हें सौंप दिया। परिषद् ने प्राथमिक गिरा की ओर भी ध्यान दिया।

गिरा का माध्यम—इस काल में गिरा का माध्यम का प्रश्न अति विवादस्पद रहा। भारत सरकार अंग्रेजी का गिरा का माध्यम घोषित कर चुकी थी। ब० एम० बनर्जी (B. M. Banerji) एवं डा० बल्लान्तिन (Ballantyne) ऐसे विद्वानों ने देखा थापात्रा का पक्ष लिया परन्तु सरकार नानि क सामान जनकी दुष्ट न बला और अंग्रेजी की ही शिक्षा का माध्यम रखा गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् १८३३ से १८५३ तक बंगाल में अंग्रेजी गिरा का बालबाला रहा। भारतीयों की अंग्रेजी की ज्ञान पिपासा इनका अधिक हो गई थी कि अंग्रेजी विद्यालयों में प्रवेश देने वाले विद्यार्थियों को माध्यम

बम्बई भारतीय गिरा-समिति (Bombay Native Education Society)—इस समिति का निर्माण सन् १८२५ में हुआ। उसी समय से इस समिति गिरा के शत्रु में सराहनाय कार्य कर रही थी। सन् १८४० तक इन



सम्पूर्ण प्रान्त में ११५ जिला प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना की साथ ही ४ थप्राजी स्कूलों का भी निर्माण किया ।

राजकीय प्रयास—बम्बई सरकार ने सन् १८३७ में एल्फिंस्टन इन्स्टीट्यूट की स्थापना की । उसी वर्ष पूना संस्कृत कलेज में सभी जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अनुमति दे दी गई और मराठी की कक्षाएँ भी प्रारम्भ कर दी गई ।

शिक्षा-बोर्ड (Board of Education)—१८४४ में 'बम्बई भारतीय शिक्षा समिति' को भंग करके उसके स्थान पर शिक्षा-बोर्ड की स्थापना की गई । इस बोर्ड ने शिक्षा-कार्य में अग्रगण्य दक्षता का परिचय दिया । इसने सन् १८४२ में प्रान्त के समस्त विद्यालयों की गणना करवाई तथा एडम (Adam) की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया । प्रान्तीय शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड ने १८४२ में बम्बई को तीन भागों में विभक्त किया और शिक्षा की देख रेख के लिए प्रत्येक भाग में एक यूरोपियन निरीक्षक एवं एक भारतीय उप निरीक्षक की नियुक्ति की ।

शिक्षा का माध्यम—जिस समय बंगाल में प्राच्य तथा पारश्चात्य भाषाओं का विवाद चल रहा था उस समय बम्बई ने ऐसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम रख कर अपने साहित्य का परिचय दिया । पर दुर्भाग्यवश सन् १८४३ में सर ऐरस्किन पेरी (Sir Erskine Perry) शिक्षा-बोर्ड का सभापति नियुक्त हुआ । उसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए । इस पर बोर्ड में दो दल बन गये और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया । सन् १८४८ तक संघर्ष का रूप इतना उग्र हो गया कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा । सरकार ने यह निर्णय किया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए देशी भाषाओं का तथा उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी का माध्यम होगा । इस निर्णय से कोई भी दल संतुष्ट नहीं हुआ पर कुछ समय उपरान्त ही बंगाल की केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार को परामर्श दिया कि वह अपना ध्यान अंग्रेजी की शिक्षा पर केंद्रित करे । परिणामस्वरूप अंग्रेजी का प्रभाव में वृद्धि होने लगा ।

शिक्षा का प्रगति—ऐसी स्थिति में अंग्रेजी स्कूलों का नव निर्माण स्वाभाविक था । जनसंख्या के अनुसार अंग्रेजी स्कूलों का स्थापना हुई । अहमदाबाद में एक महिला विद्यालय के लिये आर्थिक सहायता का प्रबंध किया गया । १८५१ में पूना संस्कृत कॉलेज एवं पूना अंग्रेजी स्कूल का एक में मिला दिया गया । इस नवान शिक्षा संस्था का नाम 'पूना कॉलेज' रखा गया । इस

प्रकार १८३३ से १८५३ तक बम्बई में शिक्षा प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया।

### मद्रास

राजकीय प्रयास—सन् १८०० में कम्पनी के सचालका ने मद्रास के गवर्नर मुनरो का जन शिक्षा-योजना पर रोज सलाह दी थी और सिखाया कि प्रारम्भिक शिक्षा के स्थान में उच्च शिक्षा के लिये प्रयत्न किया जाय। ऐसी दशा में ऐसी विद्यालयों का जीवित रहना अशक्य था। उनका स्थान अग्रणी विद्यालय लेने लगे। सन् १८४१ में मद्रास नगर में एक हाई-स्कूल स्थापित किया गया। जनता निरन्तर अँग्रेजी की उच्च शिक्षा की माँग कर रही थी। अतः जनता को सान्त्वना देने के लिये सन् १८५२ में कनिज विभाग खोला गया। एल्फिन्स्टन ने जिस विश्वविद्यालय बोर्ड (University Board) का निर्माण किया था उसका नाम सन् १८४७ में बदल कर शिक्षा-बोर्ड कर दिया गया। इस बोर्ड का शिक्षा-सम्यथा व्यय के लिए १ लाख रुपये की धन राशि प्रदान की गई, जिससे दो अँग्रेजी स्कूल स्थापित किए गये।

### पश्चिमोत्तर प्रान्त

टामसन का निधन—सन् १८४५ में प्रान्त के गवर्नर जेम्स टामसन (James Thomason) ने अपने प्रान्त के समस्त जिनासीसा को आदेश दिया कि वे अपने जिलों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की जाँच करके अपनी रिपोर्ट भेजें। इन जाँच से उसे पता हुआ कि प्रान्त में केवल ३७ प्रतिशत लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। टामसन को शिक्षा में अभिगृहीत थी। अतः उसने जनसाधारण की शिक्षा को प्रोत्साहित एवं ऐसी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया। उसी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने ऐसी विद्यालयों को सहायित एवं विधित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। टामसन को आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है और इस रूप में भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसका नाम चिरस्मरणीय रहेगा।

टामसन की योजनाएँ—सन् १८४६ में टामसन ने बर्नार्डसूलर शिक्षा की संगठित करने के लिये केंद्रीय सरकार के समक्ष एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इस योजना में उसने प्रस्ताव किया कि २०० घराबान प्रत्येक ग्राम में एक स्कूल स्थापित किया जाय एक शिक्षा के केन्द्र के लिए जागीरें दो जायें। कम्पनी के संचालकों ने इस योजना में सतुष्ट न होकर टामसन से दूसरी योजना प्रस्तुत करने के लिये कहा। सन् १८४८ में टामसन ने अपनी द्वितीय योजना तैयार की, जिसे संचालकों ने स्वीकार कर लिया। इस योजना के अनुसार देशी

विद्यालयों का जीर्णोद्धार तथा प्रत्येक तहसील में आदर्श स्कूल का निर्माण हुआ।

**तहसीली स्कूल**—प्रत्येक तहसीली स्कूल में एक प्रधान अध्यापक होता था। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लिखना पढ़ना गणित ज्यामिति इतिहास एवं भूगोल थे। प्रत्येक जिले के स्कूलों के निरीक्षण के लिये एक विजिटर (Visitor) होता था। उसकी सहायता के लिए परगना विजिटर होते थे। इन विजिटर्स के कार्यों की देख भास के लिए एक विजिटर जनरल (Visitor General) होता था। तहसीली स्कूलों की इस योजना का प्रारम्भ २ जिला में हुआ—बरेली शाहजहाँपुर मनपुरी फर्रुखाबाद आगरा मथुरा अलीगढ़ तथा इटावा।

**हल्काबन्दी स्कूल**—देशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए टामसन ने यह आवश्यक समझा कि प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए सुलभ कर दी जाय। उन्हें अपने कार्य में मथुरा के जिसाधोग अलेक्जेंडर (Alexander) से सहायता मिली जिन्होंने 'हल्काबन्दी स्कूल प्रणाली' (Circle School System) के नाम से एक विस्तृत योजना १८५१ में बनाई थी। इन योजना के अनुसार कुछ ग्रामों को मिलाकर एक 'हल्का' या क्षेत्र बना दिया गया और उक्त एक प्रारम्भिक विद्यालय स्थापित किया गया। यह विद्यालय ऐसे स्थान पर होता था जहाँ से कोई भी ग्राम २ मील से अधिक दूर नहीं था। शीघ्र ही यह योजना आगरा एतद् इलाहाबाद बरेली मनपुरी तथा शाहजहाँपुर में फैल गई।

### पंजाब

पंजाब प्रान्त का निर्माण मई १८४६ में हुआ था। उस समय तक वहाँ शिक्षा की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। वहाँ बहुत समय से तीन प्रकार के स्कूल शिक्षा-काय में संलग्न थे—हिन्दू सिक्ख एवं मुसलमान। १८४६ में अमृतसर के निवासियों ने अग्रणी सीधने के लिए शक्ति इच्छा व्यक्त की। परिणामस्वरूप वहाँ के स्कूल में अग्रणी की शिक्षा का प्रवेश कर दिया गया। इसी प्रकार का एक स्कूल लाहौर में भी खोला गया। १८०७ में पश्चिमोत्तर प्रान्त की शिक्षा-योजना को पंजाब में भी लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समझ एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कमिश्नरी ने कुछ सुधारों के साथ यह प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

### उच्च शिक्षा

**पश्चिमोत्तर प्रान्त**—उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त की सरकार ने उच्च शिक्षा को धोर भी ध्यान दिया। १८१२ में आगरा में एक नार्मल स्कूल का निलागाम हुआ और उन्ही वर्ष 'मैन्ट्रि ऑफ़ कॉलेज', आगरा की स्थापना हुई। १८१० में

बरेली हाई-स्कूल एव १८५३ में बनामग के जयनारायण घोषाल स्कूल को कलिय बना दिया गया।

अप्य प्राप्त—अन्य प्रान्तों में भी कुछ राजकीय कॉलेजों का निर्माण किया गया। उदाहरणतः बङ्गाल में ढाका कॉलेज (१८४१) कृष्णनगर कॉलेज (१८४५) एव बरहामपुर कॉलेज (१८५३)। बम्बई एव मद्रास में भी कुछ कॉलेज स्थापित किए गए, पर उनकी संख्या अधिक नहीं थी। १८५७ में भारत में कॉलेजों की कुल संख्या ७३ थी जिनमें विज्ञान कॉलेज तथा व्यावसायिक शिक्षा देने वाले कॉलेज सम्मिलित थे।

### उपसंहार

सन् १८३३ में १८५३ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यवसाय, विज्ञान एव राज्य संगठन के कार्यों में व्यस्त रही। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके संचालकों तथा अधिकारियों को शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देने एवं उस पर पर्याप्त धन व्यय करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षा प्रसार का दिशा में जो भी राजकीय प्रयत्न किये गये वे इस देश की जनसंख्या का विद्यालसा तथा निवासियों का निरसाग्ना का देखने हुए सागर में कुछ बूंदों के समान थे। सन् १८५५ में जिन शिक्षा-संस्थाओं का प्रबंध कम्पनी कर रही थी, उनकी संख्या केवल १,४७४ थी और उनमें ६७,५९६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा शिक्षा पर दिया जाने वाला कुल व्यय सम्पूर्ण व्यय का १ प्रतिशत भी नहीं था। इस प्रकार इस काल में शिक्षा की प्रगति सतोषजनक नहीं हुई।

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. Write a brief account of the progress of education from 1833 to 1853
2. Describe briefly Thomason's plan for the development of mass education in the North Western Provinces.
3. 'James Thomason is regarded as the father of elementary education in India'. Discuss

८

## वुड का घोषणा-पत्र, १८५४ (Wood's Despatch 1854)

### विषय-प्रवेश

१८३३ में कम्पनी के आगुल चार्टर (Charter) के नवीनीकरण का अवसर आया। उस समय तब ब्रिटिश लोक-सभा यह अनुभव कर चुकी थी कि भारतीय शिक्षा की उपस्था करना उपयुक्त न होगा एक शिक्षा की एक स्थायी नीति प्रहण करना आवश्यक है। इन विचारों से प्रेरित होकर १६ जुलाई १८३४ को कम्पनी के सभासदों ने अपनी भारतीय शिक्षा-नीति की घोषणा की। उस समय Charles Wood कम्पनी के Board of Control का प्रधान था। अतः उसी के नाम पर कम्पनी का यह नया आदेश-पत्र, वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र (Wood's Education Despatch) कहा गया। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन उद-वास का बीगणेन किया।

### घोषणा पत्र की सिफारिशें

(Recommendations of the Despatch)

१ शिक्षा का उद्देश्य—शिक्षा के उद्देश्य को भारतवासियों तथा अंग्रेजी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। घोषणा-पत्र में यह

बात स्पष्ट कर दी गई कि शिक्षा द्वारा भारतीया की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करने के साथ ही ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना था जो राज्य को सुरक्षित बना सकें और विद्वांस के साथ राजपत्रों पर नियुक्त किए जा सकें ।

२ पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भाषाओं के साहित्य का ऐतिहासिक तथा कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया । इस प्रकार संस्कृत, अरबी एवं फारसी की उपयोगिता स्वीकार करके उन्हें पाठ्य-क्रम में स्थान दिया गया, परन्तु पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान का अध्ययन ही भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा गया ।

३ शिक्षा का माध्यम—घोषणा-पत्र में बताया गया कि देशी भाषाओं में पुस्तक का अभाव होने के कारण अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है । परन्तु यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अंग्रेजी का माध्यम केवल उन व्यक्तियों के लिए होगा जो इस भाषा का समुचित ज्ञान रखते हों एवं जो इसके द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें । अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होंगी ।

४ जन शिक्षा-विभाग की स्थापना—घोषणा-पत्र में आदेश दिया गया कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक जन शिक्षा विभाग (Department of Public Instruction) स्थापित किया जाय और उसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा-संचालक (Director of Public Instruction) हो । उसकी सहायता के लिए उप-शिक्षा-संचालक निरीक्षक (Inspector) तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त किए जायें ।

५ विन्धविद्यालयों की स्थापना—घोषणा पत्र में कहा गया कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कसबता बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मण्डल तथा अन्य स्थानों में विन्धविद्यालय स्थापित किए जायें । इन विन्धविद्यालयों का निर्माण लग्गन विन्धविद्यालय की आर्ग्य मान कर किया जाय ।

६ प्रक्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना—घोषणा-पत्र में समस्त भारत में प्रक्रमबद्ध विद्यालय (Graded Schools) की योजना पर बल दिया गया । इस योजना का स्पर्धोन्मुख करने हुए घोषणा-पत्र में अंकित किया गया कि शिक्षा का डीपा निम्नांकित प्रकार का होना चाहिए—

विन्धविद्यालय  
बालिक  
हाई स्कूल  
मिडिल स्कूल  
देशी प्रारम्भिक विद्यालय

७ जन शिक्षा प्रसार—घोषणा-पत्र में निम्न-उक्त सिद्धान्त के अनुसरण किए जाने पर असंतोष प्रकट किया गया और यह स्वीकार किया गया कि जन साधारण की शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई थी। अतः घोषणा पत्र में कहा गया कि जन-साधारण को व्यावहारिक एवं सामान्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों एवं प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाय। दक्षी विद्यालयों की प्रोत्साहित करने की नीति को आरंभ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

८ सहायता अनुदान पद्धति—जन शिक्षा प्रसार की योजना तो उत्तम थी परंतु उसे कार्यान्वित करने के लिए कम्पनी को अत्यधिक धन व्यय करना पड़ता। अतः घोषणा-पत्र में सहायता अनुदान (Grant in aid) का सुझाव दिया गया। घोषणा-पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रांतीय सरकारें इंग्लैण्ड की सहायता-अनुदान प्रणाली का अनुकरण करें और शिक्षकों के वेतन छात्रवृत्तियाँ पुस्तकालयों वाचनालयों प्रयोगशालाओं विज्ञान एवं कला बस्ताबा तथा भवन निर्माण आदि के लिए अलग-अलग अनुदान देने की व्यवस्था करें। अनुदान सब प्रकार के विद्यालयों को दिया जाय।

९ छात्रावासों का प्रशिक्षण—घोषणा पत्र द्वारा कम्पनी के सचिवों ने इच्छा व्यक्त की कि इंग्लैण्ड के उदाहरण पर भारत के प्रत्येक प्रांत में अति शीघ्र प्रशिक्षण विद्यालय निर्मित किए जायें। सचिवों ने यह भी आशा प्रकट की कि छात्रावासों की छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षण विभाग का उत्तम एवं आकर्षक बनाया जाय जिससे कि अन्य राजकीय विभागों में।

१० स्त्री-शिक्षा—घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के लिये धन देने वाले व्यक्तियों की गराहना की गई और आग्रह दिया गया कि उत्तमतापूर्ण नीति का अनुसरण करके उनको इस परम पुनीत कार्य के लिए अधिक प्रेरणा दी जाय। यह भी कहा गया कि स्त्री शिक्षा के विद्यालयों की सहायता अनुदान दिया जाय।

११ व्यावसायिक शिक्षा—घोषणा-पत्र में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) की ओर गौरव करने हुए लिखा गया कि ऐसे कर्मियों और स्कूलों का निर्माण किया जाय जिनमें भारतीय विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

१२ प्राच्य साहित्य एवं वैज्ञानिक भाषाओं को प्रोत्साहन—घोषणा-पत्र में प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई। यह सुझाव दिया गया कि पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की पुस्तकें का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाय। इसके अतिरिक्त दधी भाषाओं में पुस्तकें लिखी जायें और लेखकों को सुन्दर पुरस्कार दिय जायें।

### घोषणा-पत्र का मूल्यांकन (Critical Estimate of the Despatch)

बुद्ध का घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखेगा। इसने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के आवरण को चीर कर उसका नग्न रूप प्रकट किया एवं आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करके शिक्षा के भावी स्वरूप को निर्धारित किया। परन्तु इस घोषणा-पत्र की उपयोगिता के सम्बन्ध में गहरा मतभेद है। अतः हमें कुछ गुण-दोषों का सूक्ष्म विवेचन आवश्यक हो जाता है।

गुण —

- १ आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया। H. R. James ने इसे—'भारत में सर्वोच्च शिक्षा का महाविचार-पत्र' (Magna Charta of Education in India) कहा है।
- २ Lord Dalhousie के मतानुसार—आदेश पत्र में सम्पूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक इतना व्यापक एवं विस्तृत योजना था जिसे स्थानीय या केन्द्रीय सरकार द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। (It was a scheme of education for all India far wider and more comprehensive than the local or the Supreme Government could have even ventured to suggest.)
- ३ H. R. James के मतानुसार—'१८५४ के घोषणा-पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोद्दिष्ट स्थान है। जो कुछ हमें पूर्व हुआ वह इसी ओर संकेत करता है, और जो कुछ हमें बाद हुआ वह इससे निश्चय है। ('The Despatch of 1854 is the climax in the history of Indian education what goes before leads up to it what follows flows from it')



- ४ A N Basu ने अनुसार— यह घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा का दिलावार है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया। ('This Despatch is said to be the corner stone of Indian education. It is said to have laid the foundation of our present system of education.')
- ५ H V Hampton का कथन है—'१८५४ का घोषणा पत्र एक युग का अन्त करता है—शिक्षा के महान् अग्रदूतों के युग का। ('The Despatch of 1854 marks the end of an era—the age of the great educational pioneers.')

धीरे—

- १ आदेश-पत्र द्वारा विद्यालयों में धर्म निरपेक्ष लौकिक शिक्षा देने पर ध्यान दिया गया। परन्तु आदेश पत्र मिशन स्कूला में ही जाने वाली ईसाई धर्म की शिक्षा के प्रति निष्पक्ष नहीं रहा। आदेश-पत्र में कहा गया कि निरीक्षकों की उन धार्मिक सिद्धान्तों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिये जो किसी स्कूल में पढ़ाये जा रहे हों। यह भी निम्ना गया कि यह ठाक है कि मिशन स्कूला में बाइबिल पढ़ा जाती है और लोगो को उस पढ़ने की सुविधा है। साथ ही यह कोई छात्र कदा से बाहर शिक्षक से ईसाई धर्म के सम्बन्ध में अपनी राय का सामाधान करना चाहे तो हम कोई आपत्ति नहीं है।

शिक्षा का माध्यम धर्मही हो जाने से भारतीय विद्यार्थियों का विभिन्न विषयों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने में बर्हिनाई का अनुभव होने लगा। अतः जैसा कि A N Basu ने लिखा है— 'विद्यार्थियों ने सरल उपाय खोज निकाले। वे बिना समझे हुए विषय-वस्तु को रटत सभ। साथ ही उन्हें इस कार्य में सहायता देने के लिये बाजार में पुस्तक की टीकाओं तथा कृत्रिमों की बाढ़ आ गई।'

Short-cuts were devised Unintelligent memory work and cramming became the order of day, and notes flooded the educational bazar and intellectual market' इन सब का विद्यार्थियों की स्वतन्त्र विचार शक्ति पर अति हानि प्रभाव पड़ा।

१. शिक्षा की नवीन प्रणाली में परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि हो गया। विद्यार्थियों का ध्येय ज्ञान प्राप्ति न रहकर परीक्षा की पास करना हो गया।
४. आंग्ल-पत्रों द्वारा सहायता-अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों को मिल सकना था जो अपना भाषा ध्येय स्वयं वहन करें। इस ध्येय को लिये अंग्रेजी शिक्षा देने वाले विद्यालयों को तो सहायता प्राप्त हो जाता था पर इसी शिक्षा-अवस्थामा को नहीं मिलता था। फलतः शिक्षा उसी प्रकार असमस्त रह गई जहाँ कि यह पहल थी।
५. Sir Philip Hartog के मतानुसार, बुद्ध का घोषणा-पत्र भारत के कल्याण के लिये बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था। ( *As a result of Wood's Despatch an educational policy was evolved in the interests of India and to develop her intellectual resources* ) परन्तु R. P. Paranjpe ने इसका सङ्केत करते हुए लिखा है कि— उनका उद्देश्य यहाँ नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिये हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिये हो शिक्षा मातृश्रमिकों का रक्षण करने के लिये हो विशेष में ऐसी शिक्षा है जिसमें आवश्यकता एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों का हो। ( *The authors did not aim at education for leadership, education for the industrial regeneration of India education for the defence of the motherland, in short, education required by the people of a self-governing nation* )

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरणों के आधार पर निष्कर्ष होकर कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुद्ध का घोषणा-पत्र अजोड़ है। इसने भारतीय शिक्षा का बहुमुखी रूप प्रदान किया एक रूप का प्रदान की। इस घोषणा-पत्र के परिणामस्वरूप जनशिक्षा, मद्रास और बम्बई में विद्याविद्यालयों की नींव पड़ी सहायता-अनुदान प्रणाली प्रारम्भ की गई प्रत्येक प्रान्त में जन शिक्षा विभाग स्थापित हुए और सरकार शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने लगी। परन्तु इन सब प्रगतियों के बावजूद घोषणा-पत्र में व्यवहारिक मातृश्रमिकों के आदेश की कहीं कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह घोषणा-पत्र आधुनिक प्रमाण-पत्रों का विधान है जिसमें प्रमाण है, क्योंकि इन विभिन्न लोगों का उद्देश्य था और करने वाले हैं परम्परागत विद्याविद्यालय

आदर्श (Victorian Ideal) का प्रतिपादन किया। अतः कुछ के घोषणा-पत्र को 'भारतीय शिक्षा का महाधिकार-पत्र' कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता है। Nurullah and Naik ने उचित ही लिखा है— हमें उन अतिशयोक्ति-पूर्ण वाक्यों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने घोषणा-पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार-पत्र कहा है कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।' ( We cannot find any justification for the superlative terms in which some historians have described the Despatch, and even called it the Magna Charta of Indian Education ' )

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 What were the main recommendations of the Education Despatch of 1854 ?
- 2 "Wood's Despatch is called the Magna Charta of Indian Education Discuss
- 3 Whatever were the value of Wood's Despatch in 1854 it would be ridiculous to describe it as an Educational Charter in the year 1965 . How far do you agree with this statement ? Give reasons in support of your answer
- 4 What, in your opinion was the importance of Wood's Despatch ?

## शिक्षा की प्रगति

### Progress of Education (1854-1882)

#### विषय प्रवेश

मुद्रक पापणा पत्र के आधार पर ब्रह्मन्ती सरकार ने भारतीय शिक्षा का कार्य आरम्भ किया ही था और उसकी सभा सिरररिगा की कार्यम्वित भी न कर पाई थी कि १८५७ की घातित पुनः पुनः । फलतः भारतीय शिक्षा के माग में बड़ा बाधा पड़ी । १ नवम्बर १८५८ की भारत के वाइसरय लार्ड कैनिंग (Canning) ने इस प्रकार कहा ब्रह्मन्ती के शासन की समाप्ति और राना विक्टोरिया (Victoria) का भारत की सम्राज्ञी घोषित किया । उस समय से भारतीय इतिहास में विचाररिगा की घातितान प्रारम्भ हुआ । घातित के अनुप्राप्त ब्रह्मन्तीकरण से भारतीय शिक्षा की फलने पुनः न लिये निर्बाध अवसर मिला और उसकी प्रगति में प्रथमनीय अभिवृद्धि हुई ।

१ प्राथमिक शिक्षा (Government of India, 1854-1882)

लार्ड ओरलेण्ड ने निम्नलिखित शिक्षा की स्वीकार करने का शिक्षा की भारत में मुद्रक पापणा पत्र । इस नीति के अनुसार सरकार का ध्यान उच्च

वर्गों की उच्च शिक्षा पर केन्द्रित रहा। अतः प्राथमिक शिक्षा के लिये कोई प्रियारम्भक पग नहीं उठाया गया। १८५४ के घोषणा पत्र ने निस्पन्दन सिद्धान्त को अनुचित बताकर लोक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। परन्तु फिर भी प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुत्थान के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करती रही और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के प्रसार में धन व्यय करती रही। यद्यपि घोषणा-पत्र में प्राथमिक विद्यालयों की सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी परन्तु अनुदान सम्बन्धी नियम इस प्रकार के थे जिन्हें जनता निभा नहीं सकती थी। फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालय इस प्रणाली से विषाद साधन न उठा सक। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा के लिये जो प्रयास हुए उनका वर्णन निम्नांकित है —

**मद्रास—**इस प्रान्त में सरकारी स्कूलों की स्थापना के साथ-साथ सहायता अनुदान देकर प्राथमिक विद्यालयों को भी प्रोत्साहित किया गया। सहायता अनुदान का आधार विद्यालय का परीक्षा फल रहा गया था।

**बम्बई—**बम्बई प्रान्त में देशी विद्यालयों की विरोधी नीति का अनुसरण किया गया। फलस्वरूप उनका पतनपना असम्भव हो गया। सन् १८७० में वहाँ के शिक्षा-सचालक पिले (Peile) ने देशी पाठशालाओं को आर्थिक सहायता देने के लिये कुछ नियम बनाये पर वे निरर्थक सिद्ध हुए।

**बंगाल—**यहाँ की सरकार ने देशी विद्यालयों के पुनरुत्थान के लिये प्रयास भी कार्य किया। इस सम्बन्ध में प्रान्त के गवर्नर सर जॉर्ज कैम्पबेल (Sir George Campbell) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसकी योजना के अनुसार शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिये उनका वेतन बढ़ा दिया गया। सहायता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण सरकारी निरीक्षकों द्वारा किया जाता था। कैम्पबेल को आशा थी कि शिक्षकों के भोजन निवास स्थान आदि की व्यवस्था स्थानीय जनता करती रहेगी। परन्तु शीघ्र ही शिक्षावर्तों जाने लगे कि शिक्षकों की वेतन-वृद्धि के फलस्वरूप जनता ने शिक्षकों को दी जाने वाली सहायता में कमी कर दी है। फलस्वरूप शिक्षकों की वेतन वृद्धि की योजना को स्थगित करके परीक्षाफल के आधार पर सरकारी सहायता दी जाने लगी। परिणामस्वरूप देशी विद्यालयों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यहाँ यह कहना मुक्ति-मुक्त होगा कि बंगाल में हस्ताक्षरी स्कूलों की प्रथा प्रचलित थी।

**पश्चिमोत्तर प्रान्त—**बंगाल के समान पश्चिमोत्तर प्रान्त में भी हस्ताक्षरी स्कूलों की प्रणाली जारी रखी गई। साथ ही सर-सरकारी पाठशालाओं को भी सहायता अनुदान दिया गया।

**पञ्जाब—**पञ्जाब ने पश्चिमोत्तर प्रान्त के आदर्श का अनुकरण किया। इस शांत में एक शीर-सम्बन्धी विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक थी जिन्हें सरकार से किसी प्रकार का आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी।

**मध्य प्रदेश—**मध्य प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा के प्रकार के लिए बंगाल को अपना आदर्श माना और देशी या गालाभा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। परन्तु प्रान्त में देशी स्कूलों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण सरकार को बहुत से प्राथमिक विद्यालयों का सामंशिक बनाना पड़ा।

**असम—**असम १८७४ तक बंगाल का भाग रहा था। अतः यहाँ की प्राथमिक शिक्षा की नीति का आधार बंगाल का नीति ही था। इसलिए यहाँ देशी पाठ्यपुस्तिकाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इस प्रान्त में सरकारी स्कूलों की संख्या सब प्रान्तों से कम थी।

## २. माध्यमिक शिक्षा

१८५४ में लॉर्ड हार्डिज द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए अग्रणी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की बरीयता का जाने की घोषणा के फलस्वरूप अग्रणी शिक्षा के प्रकार की गति तब हो गई थी। सन् १८५४ के घोषणा-पत्र के आदेशानुसार प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना हुई जिन्होंने अग्रणी शिक्षा के संगठन में गम्भीर उपाय लिए। १८५६ के स्टैनली आदेश-पत्र (Lord Stanley's Despatch) ने सहायता-अनुदान की उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए सीमित कर दिया। इनका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होने लगा जिससे इस स्तर पर शिक्षा की भागीदारी उत्पन्न हुई। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्न के साथ-साथ भारतीय एवं मिशनरियाँ ने भी सराहनीय कार्य किया। परिणामस्वरूप १८८२ के अन्त तक माध्यमिक विद्यालय अबाध गति से बढ़े।

**राजकीय विद्यालय—**सन् १८५४ में राजकीय विद्यालयों की संख्या १६६ था जिनमें १८३५ स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। १८८२ में इन विद्यालयों की संख्या १३६३ और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ४४६०५ हो गई।

**मिशन विद्यालय—**सन् १८५० का प्रान्ति के माध्यमिक विद्यालयों के प्रति सरकार का रुझान बढ़ा हुआ था और था माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार में मिशनरियों का योग्य काम नहीं था। सम्पूर्ण भारत में ६८० मिशन स्कूल थे जिनमें से लगभग ४१८ पंजाब में ११८ पश्चिमोत्तर प्रान्त में १०४ तथा बंगाल में ४० विद्यालय थे।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

भारतीयों द्वारा संचालित विद्यालय—सन् १८१४ तक भारतीया न माध्यमिक शिक्षा की दशा में बहुत ही कम काम किया था। परन्तु १८८२ के अंत तक राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत होकर भारतीया ने अपने समस्त उपलब्ध साधना को विद्यालयों के निर्माण में जुटा दिया था। फलस्वरूप १८८२ में भारतीया द्वारा संचालित १३४१ माध्यमिक विद्यालय थे। इनमें से मद्रास में ६६८ बंगाल में ५८२ और शेष देश के अन्य भागों में थे।

### उच्च शिक्षा

सन् १८१४ से १८८२ तक माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या में इतनी भार्चर्यजनक वृद्धि हुई कि उनमें अध्ययन करने वाले ज्ञान के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया। उच्च शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का शिलारोपण करके किया गया।

विश्वविद्यालयों की स्थापना—भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का समय कुछ के घोषणा-पत्र की प्राप्ति है। इस देश के प्रशासकों ने आदेश-पत्र की आज्ञा शिरोधार्य करके उपयुक्त स्थानों पर विश्वविद्यालयों का निर्माण करने की योजना बनाई। इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक था परन्तु १८१७ में ही सरकार ने 'विश्वविद्यालय अधिनियम' (University Acts) पारित करके बसरता बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया। इन तीन विश्वविद्यालयों का अतिरिक्त १८८१ तक कोई अन्य विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया। १८८२ में पञ्जाब विश्वविद्यालय का आधार पिला रखा गया। कॉलेजों की स्थापना—भारतीय विश्वविद्यालयों का कार्य केवल परीक्षा देना था। उनमें शिक्षण का कार्य नहीं किया जाता था। यह कार्य विश्वविद्यालयों से भाग्यता प्राप्त कॉलेजों में होता था। इनके प्रति सरकार ने उदारता का परिचय दिया। फलतः कॉलेजों की संख्या में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई। १८१४ में सम्पूर्ण भारत में २१ कॉलेज थे। इनमें से १४ कॉलेज सरकारी और ६ मिशनरियों के थे। १८८२ में कॉलेजों की संख्या बढ़ कर ६२ हो गई।

## UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Trace the development of education in India from 1854 to 1882
- 2 Give a brief history of (a) Primary Education (b) Secondary Education and (c) Higher Education in India from 1854 to 1882

## भारतीय शिक्षा-आयोग (हन्टर कमीशन)

Indian Education Commission

(Hunter Commission)

[1882-1883]

### विषय प्रवेश

भारत-सरकार ने सिद्धान्त रूप में तो कुछ ही धारणा-एक में प्रतिपादित शिक्षा-नीति का अनुसरण किया परन्तु श्रियात्मक पक्ष बहुत-कुछ भिन्न हो उठाये। जगद्गुरुसाय—धोपणा पत्र की अवहेलना करके भारत-सरकार निम्नवत् सिद्धान्त पर चसनी रही और जनसाधारण की शिक्षा की ओर कोई ठोस काम नहीं उठाया। इस अवहेलना की जाँच की जानी थी। पर जाँच करना कौन ? भारत के सीमावर्त से इस देश की शिक्षा में कितनी रसत बात है गलतज्ञ व कुछ उत्साही निर्वाचनों ने भारत में शिक्षा की सामान्य समिति (General Council of Education in India) नामक एक संस्था स्थापित की थी। जब १८८२ में इल्लिंग वालिवावेन्ट में भारत के नए गवर्नर जनरल लार्ड रिपन (Lord Ripon) की नियुक्ति की, तब इस समस्या का कुछ समय का एक निष्कर्षण ने उगम भेंट की और भारतीय शिक्षा-नीति का जाँच करने का



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

प्राथमिक की। लार्ड रिपन ने उन्हें ऐसा करने का आश्वासन दिया। भारत पहुँचकर सा. रिपन ने ३ फरवरी १८८८ को गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी क सदस्य (Sir William Hunter) की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा-आयोग (Indian Education Commission) की नियुक्ति की। इसी आयोग को हन्टर कमीशन (Hunter Commission) भी कहा जाता है। इस आयोग में सर हन्टर व अतिरिक्त २० सदस्य थे। इनमें से ७ भारतीयों का प्रतिनिधि थे।

### आयोग का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य (Terms of Reference & Objectives of Commission)

जितने प्रस्ताव द्वारा आयोग की नियुक्ति की गई थी उसमें आयोग के उद्देश्यों की इन शर्तों में धारित किया गया था— कमीशन का कर्तव्य होगा विशेष रूप से इस बात की जाँच करना कि १८५४ के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है और ऐसे उपायों का सुझाव देना जो उस घोषणा-पत्र में निर्धारित नीति की उत्तरात्तर कार्यान्वित करने के हेतु कमीशन के मतानुसार राष्ट्रीय प्रतीत हों।

सतत प में कमीशन की अध्यात्मिकताओं की जाँच करने के लिये कहा गया था।—

- १ क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है ?
- २ प्रारम्भिक शिक्षा की क्या स्थिति है और उसके विकास के लिये क्या उपाय किये जान चाहिये ?
- ३ राजकीय विद्यालयों की क्या स्थिति है और भारतीय शिक्षा के लिये उनकी आवश्यकता है या नहीं ?
- ४ इस का शिक्षा-व्यवस्था में मिशन स्कूलों का क्या स्थान है ?
- ५ शिक्षा-क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों व प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिये ?

इस माह १८८८ मार्च १८८८ में आयोग ने ६० स अधिक पृष्ठों की एक पुस्तिका रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की।

## आयोग की सिफारिशें और सुझाव (Recommendations & Suggestions of the Commission)

अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भारतीय शिक्षा पर विह्वल दृष्टिपात करने के उपरान्त भावी शिक्षा प्रसार के लिये अनि महत्वपूर्ण सुझाव दिये और शिक्षा के प्रत्येक अङ्ग के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को संक्षेप में किया।

### १ प्राथमिक शिक्षा

आयोग का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा की जाँच करना था। अतः आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक अंग के सम्बन्ध में अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत कीं जिसका विवरण निम्नांकित है —

प्राथमिक शिक्षा की नीति—प्राथमिक शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिये न कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये एक साधन मात्र।
- २ प्राथमिक शिक्षा में ऐसे विषयों की स्थान देना चाहिये जो जन सामान्य के व्यावहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध हों।
- ३ प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होनी चाहिये।
- ४ प्राथमिक शिक्षा को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।
- ५ प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार को निम्न वर्गों पर नियुक्तियाँ करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिये जिन्हें शिक्षने-पढ़ने का सामान्य ज्ञान हो।

सङ्गठन—आयोग ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के सङ्गठन का कार्य नगरपालिकाओं (Municipal Boards) और जिला-परिषदों (District Boards) के हाथ में दे दिया। यह व्यवस्था करके सरकार को जन-साधारण को शिक्षित करने के भार से मुक्त कर दिया।

पाठ्य क्रम—आयोग ने पाठ्य-क्रम के सम्बन्ध में सभी प्रांतों को स्वतन्त्रता दे दी। वे अपनी परम्परा के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते थे। परन्तु आयोग ने कुछ धोवनोयोग विषयों को पाठ्य-क्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की जैसे— भौतिक विज्ञान, श्रम, चित्रादि।

**अध्यापकों का प्रशिक्षण**—हटर कमीशन ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सिफारिश की कि अध्यापकों को दोषित किया जाय और इस काम के लिये नार्मल स्कूल भोले जायें। प्राथमिक पाठशालाओं के निदेशों को दोषित करने के लिये कमीशन ने निम्नांकित सिफारिशें कीं—

१. प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाय जहाँ से वे समस्त प्राथमिक पाठशालाओं की स्थानीय भाषाओं की पूर्ति कर सकें। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम-से-कम एक नार्मल स्कूल की स्थापना की जाय।
२. नार्मल स्कूलों को सफल बनाने के लिये यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक निरीक्षक अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालय में रुचि ले और उनके गुणसम्पादन की व्यवस्था करे।
३. प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिये स्वीकृत धन राशि में से प्राग्भित्त विद्यालयों के निरीक्षण तथा नार्मल स्कूलों की स्थापना की उचित व्यवस्था की जाय।

**एक नमीशा**— भारतीय शिक्षा-आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रायः सभी अङ्गों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। आयोग की हार्दिक अभिलाषा थी कि भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देकर जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करे। प्राथमिक विद्यालयों की नगरपालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों को सौंपने से शिक्षासंस्था का बड़ा उपकार हुआ। कारण यह है कि शिक्षा काय को करने के लिये सरकार के पास समय नहीं था उसकी स्थानीय समस्याएँ सम्पादित कर सकती थीं। इस प्रकार जन-शिक्षा की समस्या के समाधान की आशा दृष्टिगोचर होने लगी।

## २. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने केवल दो बातों के विषय में अपने सुझाव दिये—(१) माध्यमिक शिक्षा में विस्तार करने के उपाय और (२) माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा को दूर करने की विधि।

शिक्षा प्रसार के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि सरकार माध्यमिक शिक्षा को मुख्य एवं बढ़िमान भारतीयों के हाथों में सौंपकर स्वयं उससे उत्तरदायित्व में मुक्त हो जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार सहायता-अनुदान प्रणाली का अनुसरण करे। यदि किसी क्षेत्र में अध्ययन की शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तरों की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो, तो उनका सहायता-अनुदान की प्रणाली पर स्थापित किया जाय। आयोग को विश्वास था

कि बुझात भारतीयों पर माध्यमिक शिक्षा का भार होने से उनकी प्रगति तीव्र हो जायगी और धीघ्र ही वह जनसाधारण की भाँति की प्रति बन सकेगी।

अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि यदि एक क्षेत्र की जनता इनकी धनी नहीं है कि वह महापता-अनुदान से माध्यमिक विद्यालय को चला सके तो क्या किया जाय ? इसके उत्तर में आयोग ने कहा कि ऐसे स्थान पर सरकार स्कूल का निर्माण कर सकती है। परन्तु आयोग ने इस बात पर बस दिया कि ऐसा स्कूल एक छिने में एक ही होना चाहिए। इस स्कूल की स्थापना के पश्चात् सरकार को माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का कार्य छिने के निवासियों पर छोड़ देना चाहिए। यदि वे चाहें तो अपने विद्यालयों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजकीय विद्यालयों में कम शुल्क ले सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा के लोगों को दूर करने की विधि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कमीशन ने लिखा है कि हाई स्कूल की शिक्षा को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय—(i) A Course एवं (ii) B Course। प्रथम कोस उन विद्यार्थियों के लिए हो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं। द्वितीय कोस अधिक व्यावहारिक हो और उनका उद्देश्य नवयुवकों को व्यावसायिक तथा अर्माहिलियर कार्यों के लिए तैयार करना हो।

एक समीक्षा—आयोग ने शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दिए परन्तु वे अत्यधिक निराशाजनक थे। आयोग ने हाई स्कूल के स्तर पर स्पाट रूप में अणुजी का पता दिया और मानुषाणा के विषय में सोच रहा। उसने मिडिल स्कूलों के लिए भी शिक्षा का कोई माध्यम निर्दिष्ट नहीं किया। आयोग की इन बुल-मुल सिफारिशों का परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

## ३. अध्यापकों का प्रशिक्षण

सन् १८८२ में भारत में केवल दो प्रशिक्षण विद्यालय थे—लाहौर और मद्रास में। आयोग ने प्रस्तावित प्रशिक्षण पर विचार कर संकल्प लिया और निम्नलिखित सिफारिशों की —

१. स्नातक (Graduates) का प्रशिक्षण प्राप्त करने निम्न पाठ्यपत्रों का पठनार्थापन की अपेक्षा कम होना चाहिए।
२. प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षा विज्ञान और प्रायोगिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाय।

## ४ उच्च शिक्षा

यद्यपि भारतीय शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा की जाँच करने का आदेश नहीं दिया गया था परन्तु फिर भी उसने कॉलेज की शिक्षा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

- १ कॉलेजों की सहायता अनुदान दते समय शिक्षकों की समस्या, कॉलेजों के व्यय उनकी आय क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय।
- २ आवश्यकता पड़ने पर कॉलेजों को भवन निर्माण, प्रर्निकर पुस्तकालय और शिक्षण-सामग्री के लिये बिनाप सहायता-अनुदान दिया जाय।
- ३ कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के विस्तृत पाठ्य क्रमांक सम्मिलित किया जाय जिससे कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें।
- ४ छात्रों के नैतिक स्तर को उँचा उठाने के लिये एक ऐसी पाठ्य पुस्तक की रचना की जाय जिसमें प्रकृति धर्म तथा मानव धर्म के सिद्धांतों की पूर्ण व्याख्या हो।
- ५ कॉलेजों के प्रधानाचार्य या अध्यापकों द्वारा एक ऐसी व्याख्यान माला जारी की जाय जिसमें विद्यार्थियों को मानव तथा नागरिक के कर्तव्य बताया जाय।

## ५ सहायता अनुदान-प्रणाली

बुध के घोषणा पत्र में प्रतिपादित सहायता अनुदान प्रणाली को भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित किया गया था परन्तु सभी प्रान्तों में इसका रूप भिन्न था। उदाहरणार्थ—बम्बई में परीक्षा-फल के अनुसार 'वेतन-प्रणाली' (Payment by Results System) मद्रास में 'वेतन अनुदान-प्रणाली' (Salary Grant System) तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त मध्य प्रान्त और कुछ सीमा तक गुजरात में 'नियत कालीन-प्रणाली' (Fixed Period System) का प्रचलन था। शिक्षा-आयोग ने इन सम्बन्धित प्रणालियों के गुण-दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिये।

## आयोग का मूल्यांकन

(Estimate of the Commission)

आयोग ने अपने अग्रम्य सुझाव स्वर भारतीय शिक्षा की एक निश्चित नीति का सूत्रपात किया। आयोग ने १८५४ के घोषणा-पत्र में शिक्षा के लिये

प्रतिपादित सिद्धान्तों की पूर्णता की ओर उन्होंने वे आधार पर १९०१-०२ तक भारतीयों की शिक्षा की योजना को कार्यन्विन किया गया। इसी आशय से Howell ने लिखा है—'भारत में ब्रिटिश शासन-काल में प्रथमतः शिक्षा की व्यवस्था हुई, फिर उन्नत एवं सफरता के साथ उमका विराय किया गया, तत्पश्चात् एक ऐसी प्रणाली का सूत्रपात किया गया जो कि भवभाव्य रूप से हानिकारक थी और अन्त में वह अपने यतमान स्तर पर रख दी गई।'।

आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा का प्रवाह तीव्र हो गया। निस्सन्देह देशी शिक्षा निष्प्राण हो चुकी थी परन्तु उससे न तो कोई व्ययित हुआ और न किसी ने उसके लिये अयुपात किया। इसने विपरीत सोचा ने अंग्रेजी स्कूलों तथा कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार देया। सम्पूर्ण देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल बिछ गया और ये विद्यालय निम्नस्तर से देशी पाठशालाओं से अधिक उत्तम थे। शिक्षा के विभिन्न अवयवों का सक्रिय विकास होने लगा। सरकारी अधिकारी तथा भारतीय, शिक्षा के लिए किए गये अपने प्रयागों से मुक्त और मनोप की भाँति सेने लगे।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोग व मुद्दाओं के फलस्वरूप शिक्षा का जो विकास प्रारम्भ हुआ उसमें कृटियाँ नहीं थी या उसमें प्रति किसी को कोई शिक्षामय नहीं थी। वस्तुतः शिक्षा में अनेक श्रेय स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगे थे। प्रथम इस शिक्षा ने भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में कोई योग नहीं दिया। द्वितीय शिक्षा के द्वार पराजित धन व्यय नहीं किया गया जिससे जन-आधारण की शिक्षा का योग नहीं हुआ। तृतीय, शिक्षा के द्वारा एक गले नवीन वर्ग का निर्माण हुआ जिसे नियत जनता से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। चतुर्थ शिक्षा प्राप्त करने व्यक्ति नगरों में नीरवियाँ करने लगे जिससे ग्रामीण जनता में उनका सम्बन्ध बिच्छू हो गया।

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. State and discuss the recommendations of the Hunter Commission of 1882 regarding either Primary Education or Higher Education
2. Summarize the chief recommendations of the Hunter Commission of 1882 on Secondary Education and trace their influence on the subsequent development of Secondary Education in India

## शिक्षा की प्रगति (Progress of Education) [1882 1902]

### विषय-प्रवेश

हम अध्याय १० में भारतीय शिक्षा-आयोग द्वारा शिक्षा के विभिन्न अङ्गों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का वर्णन कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकृत किया। फलस्वरूप शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। हम इन पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं।

### १ प्राथमिक शिक्षा

साठ रिपन ने इंग्लैण्ड की वाउण्टी कौंसिल्स का अनुकरण करके भारत में नगर-पालिकाओं एवं जिला-परिषदों का निर्माण किया था। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध इन स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। इस नवीन व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा की कुछ प्रगति अवश्य हुई पर उसकी सतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि सरकार ने स्थानीय संस्थाओं पर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व रतकर उमने अपना पीछा छुड़ाया। सरकार की उपेक्षा का

प्रमाण इस बात से मिलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर बिना जाने बासा राजकीय व्यय सन् १८८२ से १९०२ तक केवल १५ लाख रुपया बढ़ाया गया। इससे विपरीत, स्थानीय संस्थाओं ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में यथाशक्ति योग दिया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बिना जाने बात अपने व्यय को सन् १८८२ से १९०२ तक २२ लाख बढ़ा दिया। परन्तु स्थानीय संस्थाओं का अपना असमर्थताएँ थीं। फलस्वरूप इस अवधि में प्राथमिक विद्यालयों और उनके पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में विशेष वृद्धि न हो सकी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई।

## २ माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के विषय में हुटर कमीशन का सुझाव था कि सरकार हमकी व्यवस्था को वांछित प्रयामों पर छाड़ दे और स्वयं इसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाय। सरकार ने इस सुझाव का प्रतिकूल जवाब दिया और पूरे के समान माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में व्यस्त रही। फलन शिक्षा के इस क्षेत्र में प्रगति होनी स्वाभाविक थी। शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट विद्यालयों का सुव्यवस्था में विधितता न आने का और व उत्तरोत्तर समुन्नत हाथ चले गया। हमारे विपरीत सहायता-अनुदान से चलने वाले विद्यालयों की संख्या सम्पादन नहीं थी। उनके पास धन का अभाव था और वे अपने व्यय के लिए मुख्यतः शुल्क तथा चर्चों पर निर्भर रहते थे।

आयोग ने हाई-स्कूल की शिक्षा को अधिक सामान्य बनाने के विचार से उसे 'अ-बोर्ड' एवं 'क-बोर्ड' में विभाजित किया था। यद्यपि आयोग के इस सुझाव को स्वीकृत किया गया परन्तु इन विषयों का सार्वप्रदता प्राप्त न हो सकी। कारण यह था कि उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य—राजपद की प्राप्ति करना था। विद्यार्थियों का कुशाक 'क-बोर्ड' की ओर ही आकर्षित हो रहा था। फिर भी प्रांतीय सरकारों ने हाई स्कूल का पाठ्य-क्रम में जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा का प्रवेश करने उसको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया।

## ३ उच्च शिक्षा

भारतीय शिक्षा आयोग की विचारणा न अग्रगण्य रूप में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के विभाग में योग दिया। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए कनिष्ठा का निर्धारण आवश्यक हो गया। आयोग ने भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रत्याशा प्रदान की भी प्राप्ति दी किता था। विचारणा का विभाग होने के कारण आयोग ने भारतीयों



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

को ही बरीयता दी थी। फलतः भारतीयों ने मिशनरियों की अपेक्षाकृत अधिक कॉलेजों की स्थापना करके शिक्षा में अपनी अभिरुचि का प्रमाण दिया। सन् १९०२ में भारतीय ४२ कॉलेजों का संचालन कर रहे थे जबकि मिशनरियों के संचालन में केवल १७ कॉलेज चल रहे थे। सन् १८८२ में इलाहाबाद विश्व विद्यालय का निर्माण हुआ।

इस दौरान में १९ वीं सताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हो चुका था। राष्ट्रीय भावनाओं से भोज प्रोत उनको यह प्रणतया विदित हो चुका था कि भारत के नवयुवकों का चारित्रिक निर्माण भारतीयों द्वारा संचालित राष्ट्रीय विद्यालयों में ही किया जा सकता है। फलस्वरूप इस प्रकार के अनेकों विद्यालयों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ—सन् १८८० में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में फर्ग्युसन कॉलेज (Fergusson College) सन् १८८६ में स्वामी दयानन्द ने लाहौर में दयानन्द वैदिक कॉलेज और सन् १८९८ में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट (Annie Besant) ने बनारस में 'सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज' की स्थापना की।

इस अवधि में कॉलेजों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। पर अधिकांश कॉलेज भारतीयों द्वारा संचालित थे और उनके पास धन का अभाव था। फलतः शिक्षा का स्तर प्रमत्त गिरता चला गया। इसके बावजूद भी उच्च शिक्षा के विस्तार ने भारतीयों के ज्ञान भंडार में वृद्धि की और वे अपने देश की पराधीनता से मुक्त करने के लिये व्याकुल हो उठे।

## UNIVERSITY QUESTION

1 "The most significant achievement of the period from 1882 to 1902 was an unprecedented expansion of primary secondary and collegiate education." Do you agree with this view? If so give reasons and illustrate your answer with facts and figures

# लॉर्ड कर्जन की शिक्षा-नीति (Lord Curzon's Educational Policy) [1899—1905]

## विषय प्रवेश

जिस समय भारतीयों के अन्तर में अपना मातृश्रम की दासता की बेदियों को काट डालने की भावनाएँ उमड़ रही थी उस समय जनवरी १८९९ ई० में Lord Curzon ने गवर्नर-जनरल के रूप में इस देश में पदार्पण किया। A N Basu के मतानुसार— वह स्वभाव से उदार एवं स्नेहप्रधान व्यक्ति था और शिक्षा द्वारा बंदोबस्त शासन में विराम करने वाला बंदोबस्त साम्राज्यवादी था। वह कर्तव्यपूर्ण एवं कार्य प्रेमता का भी पुजारी था। ( By temperament he was a benevolent autocrat and by training a diehard Imperialist with implicit faith in a strong rule. He was also the archpriest of centralisation and efficiency ) वह धुरंधर शिक्षा, कुशल प्रशासन और शांतिपूर्ण सम्मति का परम भक्त था। उसका अर्थ कि वाम था कि दायिर्वाज जानिया का उदार चरम परस्पर सम्मति को अगाधार करने में ही ही गता है। आ शरीर अथवा का यह बलवत् है कि

वह प्राच्य जातियों का सम्म बनाने। इस प्रकार भारत में फैलती हुई राष्ट्रीयता की भावना ने विरोधी के रूप में कङ्गन ने इस देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में सम्हाला।

**शिमला शिक्षा-सम्मेलन, १९०१ (Simla Educational Conference 1901)**

कङ्गन को शिक्षा में विशेष अभिरुचि थी। जब भारत आने के कुछ समय उपरान्त ही उसने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। सन् १९०१ में उसने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें १५० प्रस्ताव पास किए गये जो शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव और कङ्गन की शिक्षा-नीति के आधार बने।

### शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, १९०४

(Government Resolution on Educational Policy, 1904)

११ मार्च, १९०४ का लार्ड कङ्गन ने अपनी शिक्षा नीति का एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में तत्कालीन भारतीय शिक्षा का दोषा का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। इनमें से अनेक दोष आज भी इस देश की शिक्षा में बलक बिन्दुओं के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया— सक्ष्मात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के दोष उर्वविदित हैं। ४ में से ४ गाँवाँ में स्कूल नहीं हैं। ४ बालिका में से ३ बिना शिक्षा प्राप्त किये बढ़ होत हैं और ४० में से केवल १ बालिका किसी प्रकार के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करती है।'

यद्यपि कङ्गन ने अपने प्रस्ताव में तत्कालीन भारतीय शिक्षा के गुण-दोषों का निरूपण विस्तृत ढंग किया था और शिक्षा प्रसार के लिये उसके सुझाव भी प्रगतनीय थे परन्तु जिस नीति का अनुसरण करके वह कार्य को सम्पादित करना चाहता था वह भारतीयों का पसन्द नहीं थी। A. N. Das ने लिखा है— यद्यपि रोग का निदान ठीक था परन्तु प्रस्तावित औषधि में तो उपयुक्त हो था और न सामर्थ्य ही। लार्ड कङ्गन ने जो बातें कहीं उनमें से बहुत या ठीक थी पर त्रिषु विधि से वह सुधार करना चाहता था उसके निहित भारतीयों के मस्तिष्क में गम्भीर उल्लेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझा कि इस सुधार काय में कोई गहरी राजनीतिक भाव छिपा हुई है।'

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, १६०२ (Indian Universities Commission 1902)

क़दम ने अपने शिक्षा के कार्य-क्रम में विश्वविद्यालयों के सुधार को अप्रिमता प्रदान की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने २७ जनवरी १६०२ को 'भारतीय विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति की।

आयोग के विषय—आयोग को आयोग के लिये निम्नलिखित विषय दिये गये—

१. ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की दशा एवं उनकी भाषा उन्नति की जाँच करना।
२. उनके विधान तथा कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
३. ऐसे सुझाव देना जिनसे विश्वविद्यालयों का शिक्षण-स्तर उठ सके और विद्या की उन्नति हो सके।

सिफारिशें एवं सुझाव—आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में घूमकर विद्या और उनकी अवस्था की सूखम छानबीन करवा लगेलग ६ माह पदचार एवं विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये और सिफारिशें की गई—

१. विश्वविद्यालयों के विधान में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय जिनसे शिक्षा कुछ भीषा तथा शिक्षण-भाग कर सकें।
२. विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति करें।
३. सीनेट एवं सिन्डिकेट का पुनर्गठन किया जाय।
४. सीनेट में बॉमजों एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा सुयोग्य विद्वानों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय।
५. बॉमजों की भाष्यता प्रदान करने के नियमों में अधिक बढ़ाई रखी जाय।
६. मान्यता प्राप्त बॉमजों का नियमित निरीक्षण किया जाय।
७. प्रत्येक बॉमज का प्रबंध एवं सङ्गठन समिति द्वारा किया जाय।
८. मेट्रोपुलिटन का स्तर उच्च किया जाय, इन्टरमीडियेट परीक्षा समाप्त कर दी जाय और बी० ए० का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाय।

आयोग का मूल्यांकन—उपरोक्त सुझावों में स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का उद्देश्य—विश्वविद्यालयों के सङ्गठन में आनुसन्तन पारिवर्तन करना नहीं था,

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

अपिषु प्रचलित प्रणाली को पुनर्जन्तुष्टि करके शक्तिशाली बनाना था। आयोग ने विश्वविद्यालयों को शिक्षा-केन्द्र बनाने का सुझाव नहीं दिया। उसके मतानुसार कॉलेज देश के प्रत्येक भाग में दूर-दूर तक फैले हुए थे। अतः उनको एकत्र करके विश्वविद्यालयों को शिक्षा-केन्द्र बनाना असम्भव था। शिक्षा शुल्क की निम्नतर दर निश्चित करने एवं तृतीय श्रेणी के कॉलेजों को तोड़ने का सुझाव देने के कारण आयोग ने भारतीयों की शत्रुता मोसल ली। ब्रिजन की सरकार ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया जो २१ मार्च १९०४ को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय—अधिनियम, १९०४ (Indian Universities Act 1904)

इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन कार्य-सत्र अधिकार और शासन आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए। ये परिवर्तन निम्नलिखित थे—

१. विश्वविद्यालयों में कार्य-सत्र को विस्तृत कर दिया गया। उन्हें परीक्षाएँ देने में अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करने का भी अधिकार दे दिया गया।
२. यह निश्चय कर दिया गया कि सीनेट के सदस्यों की निम्नतम संख्या ५० और उच्चतम १०० होगी और वे सदस्य अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल ५ वर्ष तक रहेंगे।
३. बम्बई जनसत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की सीनेटों के निर्वाचन सम्मेलनों की संख्या २० और अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेटों की संख्या १५ से अधिक नहीं होगी।
४. विश्वविद्यालयों के सिंडीकेटों को वास्तवी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
५. सरकार का सीनेट द्वारा बनाये हुए नियमों में संशोधन करने, उन्हें स्वीकृति देने तथा सीनेट द्वारा समय पर नियम न बनाए जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया।
६. विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता चाहने वाले कॉलेजों के लिये नियम बड़े कर दिए गए और सिंडीकेटों को मान्यता प्राप्त कॉलेजों को शिक्षण-सत्र का ऊँचा रखने के लिये उनका निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया।
७. गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों के प्राचार्य धन्यधिकार की सीमाएँ निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया।

## विश्वविद्यालय अधिनियम का मूल्यांकन (Critical Estimate of Indian Universities Act)

विश्वविद्यालय अधिनियम के सम्बन्ध में १८६६ विचारपाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। सरकार का कहना था कि इस अधिनियम से विश्वविद्यालयों का समस्त दोषों का निवारण हो जायगा और उच्च शिक्षा की ऐसी सुन्दर व्यवस्था हो जायगा कि उसकी प्रगति तत्काल हो जायगा। इसके विपरीत भारतीयों का मत था कि अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर सरकार का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जायगा और उसकी प्रगति रुक जायगी। परन्तु अधिनियम द्वारा न तो प्रथम बात सत्य सिद्ध हुई और न दूसरी असत्य। हाँ इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा को लाभ अधिक हुआ और हानि कम। विश्वविद्यालयों का संघासन पहिले से अधिक उत्तम रीति से किया जान लगा उनका संगठन बहुत-बहुत निर्दोष हो गया और उनका सोनेटा का सत्य सरकार का चाटुकार न होकर सुयोग्य और कृतब्यनिष्ठ व्यक्ति हान लगे। कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना हो गई। निरीक्षण की व्यवस्था होने के कारण शिक्षा का स्तर उच्च हो गया। जो कॉलेज इसमें सफलता न प्राप्त कर सके, उनका अन्त हो गया। शिक्षा का स्तर उच्च होने से विद्यार्थियों की योग्यता में वृद्धि हुई और वे विभिन्न विषयों में अपनी विद्वत्ता का परिचय देने लगे।

### कानून और माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले आधिकारिक विद्यालय भारतीयों द्वारा सञ्चालित थे। इनके पास शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिये धन का अभाव था। अतः विद्या प्रेमी कानून का ध्यान इनके सुधार का धार जाना आवश्यक था। उसने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति और उसका शिक्षण स्तर का ऊँचा उठान के लिये एक नवान नीति निर्धारित की। इसकी प्रमुख बातें निम्नांकित थी —

- १ सभी माध्यमिक विद्यालयों पर शिक्षा विभाग का नियन्त्रण रहेगा, चाहे उनका सहायता अनुदान मिलना हो या नहीं।
- २ कुछ निश्चित बातों का पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता (Recognition) प्राप्त होगा।
- ३ जो विद्यालय अपने छात्रों की मेट्रीकुलेशन का परीक्षा के लिये नवना चाहते हैं उन्हें अपने लिये विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- ४ माध्यम प्राप्त विद्यालय सहायता-अनुदान और राजकीय छात्रवृत्तियाँ को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- ५ किसी अमान्य (Unrecognised) विद्यालय का छात्र मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकता।
- ६ माध्यमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ ही निरीक्षणों की सम्प्राप्त वृद्धि की जाय और गैर-सरकारी स्कूलों को अधिक सहायता-अनुदान दिया जाय।

### बजट और प्राथमिक शिक्षा

बजट की प्राथमिक शिक्षा-नीति कुछ भिन्न थी। उच्च शिक्षा में तो वह बजट गुणात्मक (Qualitative) उन्नति चाहता था पर प्राथमिक शिक्षा में वह गुणात्मक तथा संख्यात्मक (Quantitative)—नौता प्रकार की वृद्धि चाहता था।

प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि करने के लिए बजट ने उनका उधारना पूर्वक अनावृत्त अनुदान (Non-recurring Grant) दिया। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान में वृद्धि कर दी। शिक्षा परिषद और नगरपालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का ३ भाग मिलने लगा जबकि वह अभी तक बजट १ मिलता था। बजट की इस नीति के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण करके प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की प्रामाण्य और नगरीय विद्यालयों के लिए विभिन्न पाठ्य-क्रम निर्धारित किए और सहायता अनुदान प्रणाली में सुधार किया।

### भारतीय शिक्षा को बजट की दृष्टि (Carzon's Contribution to Indian Education)

भारत आन थॉमस माइसराया ने सार्ज बजट का नाम प्रथम खोली में रखा जाया है। परन्तु पाठ्य-सम्पत्ति का कष्ट समर्थक और भारतीय संस्कृति को हेम समर्थन के कारण वह इस देश के निवासियों का स्नेह भाजन न बन सका। परन्तु तब भारतीय शिक्षा का सम्बन्ध है इसमें उसका योग की स्वीकार करना पड़ा। उसने शिक्षा के सभी अंगों का पुनर्गठन करने का मागीर्य प्रदान किया। शिक्षा सुधार के इस आन्दोलन का उसने इस दस्तावेज के प्रारम्भ

में सूत्रपात किया उसकी गति में आज सीढ़ी बना दृष्टिगोचर हो रही है। उसी का प्रेरणा के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की शिक्षा में मातृभाषाओं के साथ-साथ पाश्चात्य विज्ञानों को समाविष्ट करके शिक्षा की मज्जा निम्पति करने की अनवरत चेष्टाएँ की जा रही हैं।

आधुनिक भारत वजन की राष्ट्रीयता विराधा नीति को विस्मृत करके उसकी शिक्षा-सुधार सम्बन्धी सेवाओं की स्मृति को सावधानी से गंजा रहा है। डा० अमरनाथ झा के इन वचन में पूरा मर्यादा आभास मिलता है - 'आज जब कि अगणित सघर्षों की स्मृति जनोत्तम के गर्त में विनीत हो चुकी है सभी भारतीय उस महान् वायसरॉय की विवेकपूर्ण राज्य प्रभुता की प्रति अनुगृह्यमान हैं, जिसने हमारे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण तथा हमारे शिक्षा-मन्दिर का ऊँचा उठान का इतना प्रयास किया। अपने इन कार्यों के लिए उम्र आज भी स्मरण किया जाता है और भारतवासियों की अनन्त पीढ़ियाँ इन कार्यों के लिए उसका गुणगान करेंगी।' ( Now that the ashes of the numerous strifes are cold all Indians are grateful to the wise statesmanship of the Viceroy who did so much to preserve our ancient monuments and raise our educational standards. By these achievements he still lives and generations of Indians will bless him for them )

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. Write a short essay on Curzon's Contribution to Indian education
2. What services did Curzon render to the cause of Primary Education in India ?
3. Write short notes on the following —
  - (a) Simla Educational Conference 1901
  - (b) Indian Universities Commission 1902
  - (c) Indian Universities Act 1904 and
  - (d) Government Resolution on Educational Policy 1904



## राष्ट्रीय आन्दोलन का शिक्षा पर प्रभाव (Impact of National Movement on Education) [1905-1921]

### विषय-प्रवेश

बीसवीं शताब्दी के उषा-काल में राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय आत्मा को उसकी गहराई तक हिला दिया था। जन की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण परिस्थिति पहले से अधिक गम्भीर हो गई थी। भारतीयों के प्रति उसका उद्देश्य एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार ने उनकी क्रापाग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। देश के नेताओं ने अंग्रेजों के अमानुषिक व्यवहार और उनकी साम्राज्यवादी नीति का भूखाफोड़ करना प्रारम्भ किया। शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों की उस अर्थनीति की बहुत आलोचना की—जिसकी छाया में विदेशी भारत का दोषण कर रहे थे। भारतीय नवयुवक प्रान्तिकारी भावनाओं में खोल प्रोग्रेस के अनीत बमब की पुनर्स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। कुछ बर्मिष्ठ समाज-संस्था जनता का सन्देश दे रहे थे कि जब भारतीयों को अंग्रेजों के सामने मुक्ति पाना अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगे तभी देश अपने अनीत औरत की पुनर् प्राप्ति कर सकेगा। इन सब बातों का फलस्वरूप सन् १९०४ में राष्ट्रीय का आन्दोलन अपने चरम बिन्दु पर था।

ऐस समय में २० जुलाई १९०५ को मॉड कज़न की नौकरशाही ने पूर्णता पूर्ण एव निष्प्रयोजन नीति का पालन करके बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसकी मुनकर सम्पूर्ण बंगाल एक साथ उठ खड़ा हुआ और बांग्लेम न ७ अगस्त सन् १९०५ के बसकता-अधिवेशन में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। इस आन्दोलन के चार मुख्य भाग थे—(क) स्वराज्य की प्राप्ति (ख) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार (ग) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और (द) राष्ट्रीय शिक्षा की माँग।

### राष्ट्रीय शिक्षा की माँग

बंग भाग के शीघ्र बाद ही राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा और राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की गई। ज्यों ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन उत्पत्ता धारण करता गया त्यों-त्यों भारतीय शिक्षा के राष्ट्रीयकरण अथवा स्वदेशीकरण की माँग प्रबल होनी गई। ऐनी बेसेंट (Annie Besant) ने भारतीय शिक्षा के आत्मोपकरण की अत्यधिक विज्ञापन करने हुए कहा कि भारत का राष्ट्रीय जीवन एक राष्ट्रीय चरित्र को निबस बनाने का लिए भारतीय शिक्षा पर विदेशी प्रभुत्व से अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) ने भी जोरदार शब्दों में भारतीय शिक्षा का विदेशी स्वत्व को कटु आलोचना की।

### राष्ट्रीय शिक्षा की रूप रेखा (Outline of National Education)

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अन्तर्गत जिस राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की गई उसकी रूप रेखा निम्नांकित आधारभूत सिद्धान्तों पर निर्धारित की गई—

१. भारतीय नियंत्रण—राष्ट्रीय नेताओं ने माँग की कि शिक्षा को पूर्णतः भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए। ऐनी बेसेंट (Annie Besant) ने बल पूर्वक कहा—‘भारतीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय चार्मिक भावना में मराबोर होने हुए भी सामान्य मित्रता में पृथक् रहे और ध्यान का समस्त भक्ति ज्ञान एवं नविकता के भारतीय आत्माओं को उपस्थित करे।’

२. स्वदेश प्रेम की शिक्षा—प्रचलित शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। ऐसी शिक्षा प्रणाली का सबसे अनुपयुक्त टुहरापा गया। ऐनी बेसेंट (Annie Besant) ने कहा कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें स्वदेश प्रेम की भावना प्रकटित हो।

३. कार्य अनुकरण का धर्म—प्रचलित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसा बच्चा तैयार करना था जो भागीदार हो। हुए भाग्यदायक विचारों का हो। ऐसी शिक्षा प्रणाली को दोष-मुक्त बताया गया। अतः राष्ट्रीय नेताओं ने कहा

कि राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के समस्त भारतीय राष्ट्रीयता की विशेषताओं को रखे।

४ पाठ्यक्रम ज्ञान एवं विज्ञानों का अध्ययन—राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थकों ने अनुभव किया कि भारत का बाह्य देश से सम्पर्क स्थापित होना आवश्यक है। यह उमी देना सम्भव होगा जब पाठ्य-क्रम में पाठ्यक्रम ज्ञान एवं विज्ञानों को उचित स्थान दिया जायगा।

५ छात्रों के प्रभुत्व का अन्त—राष्ट्रीय शिक्षा में छात्रों का प्रभुत्व अवांछनीय है। छात्रों को न तो पाठ्यक्रम में प्रधानता दी जाय और न इसे शिक्षा का माध्यम ही रखा जाय। इनके विपरीत भारतीय भाषाओं को प्रभुत्व दी जाय।

६ व्यावसायिक शिक्षा पर अन्त—भारतीय जनमत इस पक्ष में था कि राष्ट्रीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को उचित स्थान दिया जाय। ऐसा करने में ही देश का व्यापक समस्या का समाधान होगा और जनता की निर्धनता से मुक्ति मिलेगी।

राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण (Construction of National Institutions)

सन् १९४४ में बंगाल विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में विरोध की लहर दौड़ गई। भारतीयों और विद्यार्थियों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिये सभाएँ की और जलूस निकाले। इन पर सरकार का दमन-चक्र प्रारम्भ हुआ। छात्रों को राजनीति से वृथका रहने के लिये आदेश दिया गया और इन भाषा का पालन न करने पर उनकी विद्यालयों से निकाल दिया जाने की धमकी दी गई। छात्रों ने इसका उत्तर स्वयं ही देकर दिया। इन अवसरों की शिक्षा का प्रयत्न करना राष्ट्रीय शिक्षा-समिति (Society for the Promotion of National Education) का सगठन किया गया। इस समिति ने बंगाल में राष्ट्रीय हाई स्कूलों का निर्माण किया। रासबिहारी घोष तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर के समुक्त प्रयास से कलकत्ता में एक 'नेशनल बोर्ड' स्थापित किया गया। कलकत्ता में एक 'टेक्निकल इन्स्टीट्यूट' का भी निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन एक अर्थ में भी दृष्टिगोचर हुआ। सन् १९४६ में रासबिहारी टैगोर ने दार्जिलिंग में एक प्रस्ताव पेश किया जो आज विश्व भारती के रूप में विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है। इसी समय के लगभग कार्य प्रतिनिधि सभा ने मुद्रांकन और दृष्टिकार में गुरुकुल स्थापित किया।

इस काल में भारत का बच्चा-बच्चा राष्ट्रीय शिक्षा की भावनाओं से सराबोर हो गया। ऐसा प्रतीत होता था माना नवनिर्मित राष्ट्रीय विद्यालयों में प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का पुनरुत्थान अनिवार्य रूप से होगा। परन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन धीरे-धीरे निमित्त पड़ता गया और १९११ में बंगाल विभाजन के अन्त के साथ वह भी समाप्त हो गया। कमकता का 'निदान बनेज' बन हो गया और अन्य विद्यालय भी विलीन हो गये।

१९२० में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन फिर प्रारम्भ हुआ। मॉन्टेग्यू चेलम्सफोर्ड योजना (Montagu-Chelmsford Reform) के मुद्दों से अमनुष्य और जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड से आतंकित भारतीयों ने अमहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया। १९२० में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने जनता से अपने बच्चा को स्कूलों और कॉलेजों से हटा लाने की और विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों को स्थापित करने की अपील की। गांधी जी की अपील स्पर्श न गई। तबही विद्यार्थियों ने विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। इस कार्य में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र अग्रणी रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण की माँग की पर उन्हें सफलता प्राप्त न हुई। इस आन्दोलन में भाग लाने के लिये जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय का बहिष्कार किया था उनकी नामियाँ मिलियाँ 'इस्लामिया' नामक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। यह विश्वविद्यालय सन् १९२५ में उठकर दिला जला गया। भारत के अन्य भागों में अलीगढ़ का अनुकरण किया गया और ४ माह से कम में ही बिहार विद्यापीठ बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तिलक महाशय विद्यापीठ काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ और अन्य प्रकार के अनेक राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई।

निकय—सन् १९२० का राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन अमहयोग आन्दोलन का एक अंग था। ४ फरवरी १९२२ को चौराचौरा नामक स्थान में गांधी जी को हिसा के प्रयोग का दुःख समाचार प्राप्त हुआ। फलस्वरूप उन्होंने अमहयोग आन्दोलन में हतासता स्वीकार कर लिया। इसका प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन पर भी पड़ा और उसमें शक्ति आ गया।

### UNIVERSITY QUESTION

- 1 Give an account of the impact of national movement on education between 1905 and 1921

## शिक्षा की प्रगति (Progress of Education) [1905-1921]

### विवरण प्रवेश

जिस समय देश में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन अपनी अन्तिम श्वास में रहा था उसी समय १२ दिसम्बर १९११ को मन्त्रालय द्वारा पंचम भारत में अभिलेख पधारें। उन्होंने भारतीयों की शिक्षा में अपना शक्ति को। ६ जनवरी १९१२ को कलकत्ता विश्वविद्यालय में जनता का अपना संदेश देते हुए उन्होंने कहा— मेरी यह इच्छा है कि सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का एक ताना बाना फैल जाय जहाँ से उद्योगों तथा कृषि और जीवन के सम्पूर्ण व्यवसायों में कुछ कर गिनाने वाले योग्य उपयोगी विद्वत्सनीय एवं साहसिक नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकलें।<sup>१</sup> इस संदेश के फलस्वरूप भारत-सरकार की अपनी शिक्षा-नीति स्पष्ट करना आवश्यक हो गया। उसने यह सन् १९१३ में सरकारी प्रस्ताव द्वारा किया।

शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारों प्रस्ताव १९१३, (Government Resolution on Educational Policy 1913)

इस प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत को निर्धारित किया गया एवं शिक्षा के विभिन्न अंगों के विषय में निर्धारित की गई।

आधारभूत मिडिल—१ शिक्षा-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाया जाय।

२ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व पाठ्य-क्रम की जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय।

३ भारत में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की व्यवस्था की जाय जिससे छात्रों का विज्ञान न जाना पड़े।

प्राथमिक शिक्षा-संस्थाओं के विचारों—१ पुनः प्राथमिक (Lower Primary) स्कूलों का अधिक विस्तार किया जाय।

२ उपयुक्त स्थानों पर उत्तर प्राथमिक (Upper Primary) स्कूलों की स्थापना की जाय।

३ शिक्षा-परिपक्व एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अधिक स्कूल खोले जाय।

४ मिडिल एवं माध्यमिक वर्गों के स्कूलों में सुधार किया जाय और उनकी संख्या में वृद्धि की जाय।

माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं के विचारों—१ राजकीय स्तरों की संख्या में वृद्धि न की जाय अपितु उनका आत्म-विकास व प्रवास किया जाय।

२ गैर-सरकारी स्तरों को उदारतापूर्वक सहायता-अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाय।

३ हाई स्कूल के पाठ्य-क्रम में वैज्ञानिक दृष्टि एवं विज्ञान ऐसी भाषा निबन्धन विषयों को सम्मिलित किया जाय।

४ छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान का शिक्षा दी जाय और उनके स्वास्थ्य निरीक्षण (Medical Examination) की व्यवस्था की जाय।

५ माध्यमिक शिक्षा के नियम 'स्कूल काइन्स परीक्षा' की व्यवस्था किसी संस्था द्वारा की जाय।

उच्च शिक्षा-संस्थाओं के विचारों—१ भारत में अभी बहुत समय तक परीक्षा विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी परन्तु उनकी प्राथमिक सीमाओं को निश्चित कर देना आवश्यक है।

२ विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय और प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।

३ विश्वविद्यालयों का कार्य बढा दिया है। अतः उन्हें हाई स्कूलों की माध्यमिक प्रदान करने के कार्य में युक्त कर दिया जाय।

- ४ ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जाय, जो शिक्षण कार्य करना चाहते हैं।

## कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (१९१७)

(Calcutta University Commission)

निर्मुक्ति का कारण—१९१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर आमुतोप मुरजी ने स्नातकोत्तर विभाग (Post-Graduate Department) खोला। वे चाहते थे कि इस विभाग के छात्रों के शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाय। इस बात की उपयुक्तता की जाँच करने के लिये सरकार ने १४ सितम्बर १९१७ को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डा० माइकेल सडलर (Michael Sadler) थे। अतः इसको 'सडलर कमिशन' (Sadler Commission) भी कहा जाता है।

जाँच का विषय—आयोग द्वारा जाँच का विषय था—कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकता की जाँच करना और उससे सम्बन्धित समस्याओं का रचनात्मक ढङ्ग से समाधान करने का सुझाव देना।

आयोग की सिफारिशों और सुझाव (Recommendations & Suggestions of the Commission)

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव—१ विश्वविद्यालय में उन्हीं छात्रों का प्रवेश दिया जाय जो इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों और बी० ए० का कोर्स तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाय।

२ इन्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक् कर दिया जाय। इन कक्षाओं की शिक्षा देने के लिए इन्टरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए जायें।

३ इन्टरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ हों।

४ 'प्रदेश प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा परिषद्' (Board of Secondary and Intermediate Education) की स्थापना की जाय। माध्यमिक विद्यालयों और इन्टरमीडिएट कॉलेजों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का भार इन परिषदों को सौंप दिया जाय।

कलकत्ता विश्वविद्यालय-सम्बन्धी सुझाव—१ छात्रों में पीछे ही एक भाषाएँ और शिक्षण (Residential & Teaching) विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

२. बसवत्ता नगर की गिन्ता-सम्पादा को इस प्रकार संगठित किया जाय कि एक वास्तविक गिन्ता-विविधविद्यालय का निर्माण हो जाय।
३. नगर के समीपवर्ती कमिजों का संगठन इस दृष्टि से किया जाय कि कुछ स्थानों पर नवीन विविधविद्यालयों की स्थापना हो जाए।

भारतीय विविधविद्यालय-सम्बन्धी सुझाव—१. विविधविद्यालयों पर सरकार का अधिक बढोतर नियन्त्रण अव्यापनीय है। अतः उन्हें अपि स्वतन्त्रता दी जाय।

२. 'पास कोर्स' (Pass Course) व अतिरिक्त 'ऑनर्स कोर्स' (Honours Course) का भी प्रबंध किया जाय। बी० ए० के कोर्स की अवधि ३ वर्षों की कर दी जाय।
३. विविधविद्यालयों में विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय तथा—व्यावसायिक शिक्षा इंजीनियरिंग अध्ययन भाषाएँ ब्राह्मण कृषि आदि।
४. उप-सुसंपत्ति का पद बनाना कर लिया जाय।
५. विद्यालयों व स्वायत्त की देस माल बनाने के लिए विविधविद्यालय में एक 'डाइरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग' नियुक्त किया जाय।

### आयोग का मूलमाद्दान (Critical Estimate of the Commission)

'बसवत्ता विविधविद्यालय आयोग' ने इस दशा की उच्च गिन्ता व शत्रु में स्तुत्य कार्य किया। यद्यपि इसकी नियुक्ति बसवत्ता विविधविद्यालय की जीव बनन व लिए हुई थी तथापि इसने समस्त भारतीय विविधविद्यालयों के सुधार के लिए सामान्य सुझाव दिए। सीमांतवर्ग सरकार व उनको स्वीकृत किया और उन्हें व आधार पर सभी विविधविद्यालयों में सुधार किए गए। यही कारण है कि इस आयोग का गिन्ता का महत्व अतिशय महत्त्व व लिए है। इसके सुझावों ने भारतीय विविधविद्यालयों की अव्यापनीय दशा से मुक्त किया और उन्हें एक नया जाना पहिना दिया। इसीसे सम्पादक व रक्षक अध्ययन तथा अनुसंधान के क्षेत्र बन गए। आयोग ने प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव दकर विविधविद्यालयों पर व्यवसायिक शिक्षा देने का उत्तरदायित्व रखा और इस प्रकार गिन्ता का वास्तविक जीवन व सम्बन्ध स्थापित कर दिया।



## उच्च शिक्षा (१९०५-१९२१)

नवीन विश्वविद्यालयों का निर्माण—१८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्माण के उपरांत ३० वर्ष तक कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया। परन्तु इस अवधि में कनिजों की संख्या १८५ हो गई। यह अनुभव किया जान लगा था कि इतने कनिजा का भार ५ विश्वविद्यालय—कलकत्ता, मद्रास, बम्बई पंजाब और इलाहाबाद-समालने में असमर्थ हैं अतः उनकी सहायता में वृद्धि की जानी आवश्यक है। १९१३ के सरकारी प्रस्ताव ने विश्वविद्यालयों के नव निर्माण पर जोर दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने भी इस दिशा में कार्य करने के लिए परामर्श दिया। फलस्वरूप १९१६ से १९२१ तक निम्न लिखित ७ नये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए—१ मसूर विश्वविद्यालय (१९१६) २ पटना विश्वविद्यालय (१९१७) ३ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (१९१७) ४ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (१९२०) ५ ढाका विश्वविद्यालय (१९२०) ६ सलनऊ विश्वविद्यालय (१९२०) ७ उत्तमानिया विश्वविद्यालय (१९१८)।

विश्वविद्यालयों का गिणन-कार्य—सरकारी सहायता अनुदान एवं व्यक्तिगत साधना से आर्थिक सहायता प्राप्त करके विश्वविद्यालयों दत्तचित होकर गिणन का कार्य करने लगे। इस काल में १२ विश्वविद्यालयों में से १ विश्वविद्यालय शिक्षण और सम्बन्धीकरण (Affiliation) का कार्य करता था ५ केवल गिणन का और दोष ६ सम्बन्धीकरण का। अन्तिम प्रकार के विश्वविद्यालय कुछ गिणन-कार्य भी करते थे जो निम्नांकित में से एक या उससे अधिक होता था—

- १ विश्वविद्यालय में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के भाषणों की व्यवस्था करना।
- २ विश्वविद्यालय में कुछ विविष्ट विषयों के गिणन का प्रबन्ध करना।
- ३ विश्वविद्यालय में मानव तथा म्नातजोत्तर कक्षाओं की चसना।

## माध्यमिक शिक्षा (१९०५-१९२१)

सन् १९०५ में १९२१ तक माध्यमिक शिक्षा की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण यह था कि सरकारी नौकरियों के द्वार अग्रणी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये खुल गए थे। छोटी दगा में छात्रों की संख्या में वृद्धि होना और तदनुसार शिक्षाओं की संख्या बढ़ना स्वाभाविक था। इस वृद्धि का दोन सन् १९१३ के सरकारी प्रस्तावों की भी प्राप्त है, जिन्होंने माध्यमिक

गिरी के विस्तार के सम्बन्ध में अनेकों बहुमूल्य सुझाव दिये थे। उनसे भा अधिक श्रेय राष्ट्रीय समाज-सेवा का लिया जाना चाहिये जिन्होंने गिरी प्रसार के कार्य में अपने को तन-मन से लगा दिया था।

**व्यावसायिक गिरी की व्यवस्था**—भारतीय गिरी अयोग की सिफारिशों के अनुसार करके विभिन्न प्रान्तों में हाई स्कूल के पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों का स्थान दिया गया था और स्कूल लीबिंग मटेरियल परीक्षा प्रारम्भ की गई थी। यह व्यवस्था इस अर्थ में भी सहायक रही गई। यद्यपि अधिकतर विद्यार्थी अब भी मेट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होते थे तथापि स्कूल लीबिंग मटेरियल प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या उनसे अधिक कम नहीं थी।

**अग्रणी गिरी में सुधार**—माध्यमिक स्कूलों का प्रमुख ध्येय—अग्रणी की गिरी देना ही था। इस काम में भा इस ध्येय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः अग्रणी के गिरी को अधिक प्रभावशाली बनाने के विचार से विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया।

**गिरी का माध्यम**—अग्रणी को अत्यधिक महत्त्व देने से भारतीय भाषाओं की गिरी का माध्यम न बनाया जा सका। मित्रता स्कूलों में गिरी का माध्यम मान्यता प्राप्त थी। पर हाई स्कूलों में गिरी का माध्यम अग्रणी ही था।

**एक टिप्पणी**—इस अवधि में माध्यमिक गिरी की सराहनीय प्रगति हुई। भा ही उसकी गुणवत्ता उन्नति की हुई। छात्रों की संख्या में भी आगामी गृही हुई। परन्तु माध्यमिक गिरी-सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का समाधान न हो सका। हाई स्कूलों में गिरी का माध्यम अग्रणी ही रहा और व्यावसायिक गिरी की गति-वृद्धि व्यवस्था नहीं की गई।

### प्राथमिक गिरी (१९०५-१९२१)

कठिन प्रथम कार्यवाही थी किन्तु मई १९०५ के सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक गिरी का विभाग करना—सरकार का एक प्रमुख कर्तव्य बताया। उसने प्राथमिक गिरी के विस्तार के साथ साथ उसका गुणवत्ता उन्नति की ओर भी ध्यान दिया। फरवरी १९११ तक प्राथमिक गिरी की प्रगति में बहुत तीव्रता रही। निम्नर १९११ में ग्रेजुएट बोर्ड परम्पू भारत सरकार और उन्होंने निम्नी दरबार में प्राथमिक गिरी पर ध्यान विज्ञान के विषये १० लाख रुपये का धन राशि प्रस्ताव करने का प्रावधान किया।

मई १९१३ के सरकारी प्रस्ताव में गुणवत्ता सरकारी या ध्यान प्राथमिक गिरी की सहायक शक्ति का अनेक गुणवत्ता उन्नति के आरम्भिक

था। वस्तुतः प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई मया सुझाव नहीं दिया गया। इन प्राथमिक शिक्षा में कोई प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। ही इतना अवश्य हुआ कि प्रस्ताव के सुझावों के परिणाम-स्वरूप १९१७ के अन्त तक संयुक्त प्रान्त बिहार आसाम पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रान्तों में शिक्षा परिषदा और स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्कुला का निर्माण किया गया। पर इन प्रयासों के बावजूद भी परिणाम अच्छे नहीं निकले।

### प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के प्रयास

#### बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास

महाराज सायाजीराव गायकवाड को अपनी प्रजा की शिक्षा में बहुत रुचि थी, फलतः मार्च १८९२ में उन्होंने एक रचनात्मक कदम उठाया। एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया गया कि अमरसो नगर के एक ताल्लुका के ६ ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। ७ से १२ वर्ष की आयु तक के सब बालक और ७ से १० वर्ष की आयु तक की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवम्बर १८९३ में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारम्भ किया गया और इसमें इतनी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई कि उपरान्त ताल्लुका के ५२ ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अमरसो में १५ वर्ष तक बिये जाने वाले दण्ड नशाने प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि सम्पूर्ण बड़ौदा राज्य के लिये प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य किया जाना उपयुक्त और वांछनीय होगा। अतः १९०६ में एक अधिनियम बनाकर राज्य के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

#### गोखले का विधेयक (Gokhale's Bill 1911)

राष्ट्रीय भावनाओं से सराबोर शिक्षा के मर्मज्ञ गोपाल कृष्ण गोखले बड़ौदा-नरेश के उत्कृष्ट उदाहरण से अनुप्राणित हुए। उन्होंने विचार किया कि जिस कार्य को आम के सीमित साधनों वाला एक छोटा-सा देशी राज्य सफलतापूर्वक कर चुका है उस कार्य को ब्रिटिश भारत में भी जिससे पास घन का अभाव नहीं है अवश्य सन्पादित किया जा सकता है। अतः उन्होंने भारत सरकार को इस विचार में त्रिधागोस करने का दृढ़ निश्चय किया।

गोखले का प्रस्ताव—कैबिनेट द्वारा समिति (Imperial Legislative Council) के सम्मुख करके मई १९१० की गोमम ने यह प्रस्ताव (Resolution) रखा—यह समिति गिराफि करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय और इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट प्रवृत्तियों का उपरिष्ठ करने के लिये सरकार।

और गैर-सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग द्वाारा ही नियुक्त किया जाय।" सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने का आदेशानुसार प्राप्त होने पर गोखले ने उसे आपसित से लिया। पर सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का निशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिये कुछ नहीं किया। इससे गोखले को बड़ी निराशा हुई।

गोखले का विधेयक—प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उन्मत्तता देखकर गोखले ने १६ मार्च १९११ को राष्ट्रीय धारा समा में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्गत विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया— हम विधेयक का उद्देश्य इस की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धान्त की प्रमत्त लागू करना है।" (The object of this Bill is to provide for the gradual introduction of the principle of compulsion into the Elementary Education System of the country") यह विधेयक गोखले के प्रस्ताव पर आधारित था और इसकी मुख्य मुख्य बातें अधोलिखित थीं —

१. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम को उन स्थानीय बाडों के क्षेत्रों में लागू किया जाय जहाँ के बच्चे का एक निश्चित प्रतिशत प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इस प्रतिशत का निर्दिष्ट करने का अधिकार गवर्नर-जनरल की परिषद को होगा।
२. स्थानीय बाडें सरकार को पूरा स्वायत्ति प्राप्त करके इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं।
३. स्थानीय बाडें इस अधिनियम को अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं।
४. प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय बाडें शिक्षा-कर (Education Cess) लगा सकते हैं।
५. अभिमर्दकों के लिये ६ से १० वर्ष तक का आयु के बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना अनिवार्य हो। यदि वे इस नियम का उल्लंघन करें तो उन्हें दण्ड दिया जाय।
६. कानूनन या बाधितशाला के लिये भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

- ७ जिस अभिभावक की आय १० रुपये मासिक से कम हो उससे शिक्षा मुक्त न लिया जाय।
- ८ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार स्थानीय बोर्डों और सरकार द्वारा वहन किया जाय। सरकार सम्पूर्ण व्यय का  $\frac{2}{3}$  भाग दे।
- १७ मार्च १९१२ को धारा-सभा में विधेयक पर वाद विवाद प्रारम्भ हुआ। दो दिन के भीषण सत्र के पश्चात् १९ मार्च १९१२ को इसे ११ वोटों के विरुद्ध ३८ वोटों से गिरा दिया गया।

## अनिवार्य शिक्षा-अधिनियम (Compulsory Education Acts)

राज्य सरकारों से प्रेरणा प्राप्त करके निम्नलिखित प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम बनाये गये —

पंजाब—१९१९—नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिये।

समुक्त प्रान्त—१९१९—नगरपालिका-क्षेत्रों में बालकों तथा बालिकाओं के लिये।

बंगाल—१९१९—नगरपालिका क्षेत्रों में बालकों के लिये।

बिहार व उड़ीसा—१९१९—नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिये।

बम्बई—यहाँ पब्लिक अधिनियम १९१८ में बना। यह बम्बई के अतिरिक्त अन्य सभी नगरपालिकाओं में लिये जा। सन् १९२० में बम्बई नगर के लिये अधिनियम बना। इसका अनुसार वहाँ के बालकों और बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

मध्य प्रान्त—१९२०—नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के लिये।

मद्रास—१९२०—नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के लिये।

## UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Give a historical review of the attempts for Compulsory Primary Education in India from 1906 to 1920 How far did these attempts succeed?

- 2 In spite of some defects it is universally admitted that the Calcutta University Commission wielded the greatest influence on university education in this country. Comment.
- 3 Write Short notes on the following —
- (a) Gokhale's Contribution to Primary Education
  - (b) Sadler Commission Report, and
  - (c) Government Resolution on Educational Policy 1913

## शिक्षा की प्रगति (Progress of Education) [1921-1937]

### विषय प्रवेश

सन् १९१४ में प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ। अग्य मित्त राष्ट्रा के साथ इंग्लैण्ड ने भी घोषित किया कि— यह युद्ध तसार का जनतन्त्रवाद व सिये सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लड़ा जा रहा है। इस घोषणा व परभाव महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीया ने जन-जन से इंग्लैण्ड की सहायता की। सन् १९१८ में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस बीच भारत-मन्त्री सार्ड मॉन्टेग्यू (Montagu) ने भारत के तरासीन गवर्नर-जनरल सार्ड चेम्सफोर्ड (Chelmsford) व साथ भारत का दौरा करके देश की राजनीति एवं वधानिक परिस्थिति का अध्ययन किया और जुलाई १९१८ में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (Montagu Chelmsford Report) प्रकाशित की।

इस रिपोर्ट की स्थापना (Establishment of Dyarchy)

उपयुक्त रिपोर्ट व आधार पर ब्रिटिश समदन १९१९ का भारत-सरकार अधिनियम (Government of India Act) पारित किया और १९२१ में

उसे कार्योन्मुख कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैधशासन प्रणाली (Dyarchy) अर्थात् दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रान्ता के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया— (१) सुरक्षित (Reserved) और (२) हस्तान्तरित (Transferred)। सरक्षित विषयों का प्रशासन नमचारी कर्म के हाथों में छोड़ा गया। ये नमचारी गवर्नर-जनरल एवं भारत में के माध्यम से ब्रिटिश सरकारों के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तान्तरित विषयों के प्रशासन, जन प्रिय मंत्रागण, प्रान्तीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। शिक्षा का हस्तान्तरित विषयों में स्थान दिया गया और उसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में छोड़ दिया गया।

### हार्टोग समिति (Hartog Committee, 1929)

इस शासन प्रणाली एवं असतत आधार वाली शामिल दुर्बल तथा अस्थिर-स्थिर प्रणाली सिद्ध हुई। क्योंकि उसका धार विरासत दिया और पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का भोग की। भारतीय अल्पसंख्यक प्रभावित हुए ब्रिटिश सरकारों ने ८ नवम्बर १९२७ का 'साइमन कमिशन' (Simon-Commission) की नियुक्ति की जिसका उद्देश्य (१९१६ की सुधार-योजना के अनुमति का विवरण करना था। इस समिति का नियुक्ति के समय भारत में राष्ट्रीय गिरावट का आभासन चल रहा था। अल्पसंख्यक ने भारतीय शिक्षा की जीव धरन के लिये एक सहायक समिति (Auxiliary Committee) की नियुक्ति की। इसका सम्पादन सर फिलिप हार्टोग (Philip Hartog) थे। उन्हीं के नाम से यह समिति हार्टोग समिति (Hartog Committee) के नाम से विख्यात है। समिति ने उत्कृष्टतम भारतीय शिक्षा के सभी अङ्गों का अध्ययन किया जिसका अन्त आग यथास्थान किया जायगा।

### उच्च शिक्षा (१९२१-१९३७)

विश्वविद्यालयों का निर्माण—१९११ के सरकारों-प्रस्ताव के अनुसार इस काल में ४ नवीन विश्वविद्यालयों का शिक्षा-व्यापक किया गया। ये विश्वविद्यालय थे—१ दिल्ली विश्वविद्यालय (१९१२) २ नागपुर विश्वविद्यालय (१९२३) ३ आंध्र विश्वविद्यालय (१९२६) ४ आगरा विश्वविद्यालय (१९२७) एवं ५ अमृतसर विश्वविद्यालय (१९२६)।

पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन—इस काल में पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। मद्रास विश्वविद्यालय ने विज्ञान के विभिन्न विषयों को उच्च शिक्षा के व्यवस्था के और अनुमोदन काय में प्रारम्भ किया। बम्बई विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर एवं प्रोफेसर शिक्षा प्रदान करने के



काय का शौगलेश किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शैक्षणिक बन गया। पञ्जाब विश्वविद्यालय ने 'विज्ञान व मानस कामों' को अधिक व्यापक बनाया।

**विश्वविद्यालय शिक्षा**—नवान विश्वविद्यालयों व निर्माण एवं पुरानों के पुनर्गठन तथा विस्तार व कारण उच्च शिक्षा की अधिक सुविधाएँ हो गई। फलस्वरूप छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा का व्यवस्था एवं यू० टी० सी (University-Training Corps) की स्थापना की गई। कलकत्ता छात्रों और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा (Military Science) को पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किया गया।

**हर्दाग समिति के सुझाव**—विश्वविद्यालय शिक्षा व सम्बंध में समिति ने निम्नांकित सुझाव दिये —

- १ शिक्षा की दृष्टि से एकात्मक विश्वविद्यालय सर्वोत्तम होते हैं। परन्तु भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्बंधक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता अभी पर्याप्त समय तक रहेगी।
- २ विश्वविद्यालयों व शिक्षा-स्तर का ऊँचा उठाना आवश्यक है।
- ३ विश्वविद्यालयों के प्रवेश-नियमों में कड़ाई की जाय।
- ४ मानस बीम व शिक्षण का प्रबन्ध किया जाय और इसको 'पास बोर्ड' से पुष्कल रखा जाय।
- ५ स्नातकों में बढ़ती हुई बेकारी का राक्षस क समय विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किया जाय।

### माध्यमिक शिक्षा (१९२१-१९३७)

१९२१ से १९३७ तक उच्च शिक्षा व क्षेत्र में जितनी अनकमुसी उन्नति परिलक्षित होती है, उतनी माध्यमिक शिक्षा व क्षेत्र में अवलोकित नहीं होती है। निम्नोक्त माध्यमिक विद्यालयों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय शिक्षा व आन्दोलन के फलस्वरूप प्रायः प्रत्येक बड़े प्रांत और राज्य में एक स्कूल बनने लगा। सन् १९३७ तक शिक्षा का माध्यम बड़ा रहा। पर उस वर्ष भारतीय भाषाओं का शिक्षा व माध्यम का पक्ष पर प्रतिक्रिया करने दिया गया। अध्यापकों की प्रशिक्षण की भार विचार ध्यान दिया गया।

हर्टाग समिति के सुझाव—समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ मिडिल स्कूल का पाठ्यक्रम मरुभिन है। अतः उसको विस्तृत किया जाय और उसमें ऐसे विषयों का स्थान दिया जाय जो छात्रों को घनायाजन में सहायता दें।
- २ हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यापारिक विषयों को सम्मिलित किया जाय।
- ३ मिडिल स्कूल का काम समाप्त करने के पश्चात् परीक्षा मन की व्यवस्था की जाय।
- ४ शिक्षा का स्तर केवल उठाने के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से व्यवस्था की जाय।
- ५ अध्यापकों के कर्मन एवं सेवा प्रतिक्रिया (Conditions of Service) का सुधार किया जाय।

### प्राथमिक शिक्षा (१९२१-१९३७)

भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस अवधि की सबसे प्रधान घटना प्राथमिक शिक्षा की तीव्र प्रगति है—जसा कि नीचे दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जाता है।

प्राथमिक शिक्षा अधिनियम—१९३७ तक निम्नलिखित प्राप्ति में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-नियम यो अधिनियम पारित किये गये —

बम्बई—१९२१—मध्यम प्राप्ति के आसपास तथा बालिकाओं के लिये।

असम—१९२६—ग्रामीण छात्रों के आसपास और बालिकाओं के लिये।

संयुक्त प्रान्त—१९२७—ग्रामीण छात्रों के आसपास तथा बालिकाओं के लिये।

बंगाल—१९३०—ग्रामीण छात्रों के आसपास तथा बालिकाओं के लिये।

हर्टाग समिति के सुझाव—समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में महान् आश्चर्य व्यक्त किया और यह निष्कर्ष पर पहुँची कि प्राथमिक शिक्षा का स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। समिति के अनुसार इसका प्रमुख कारण अप्रत्यक्ष (Wastage) एवं अवरोधन (Stagnation) थे।

अप्रत्यक्ष एवं अवरोधन—समिति ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक शिक्षासभा और छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हो रही है। कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा में अप्रत्यक्ष एवं अवरोधन अत्यधिक है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से

पूर्व बातचीत की किसी वक्ता में ने हटा लेना अपर्याप्त है। इस दशा में बालक को कुछ पोशा-बहुत पहना सिखना साख लेता है, उसे वह भूल जाता है और निरक्षर हो जाता है। साक्षरता का उद्देश्य सभी पुरा हो सकता है जब बालक कम से कम प्राथमिक शिक्षा का समाप्त कर लें। अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए समिति ने सिखा कि एक बच्चे का एक ही वक्ता में एक वर्ष से अधिक रहना 'अवरोधन' है।

हर्दय समिति के सुझाव—प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में समिति ने निम्नांकित सुझाव दिये—

- १ प्राथमिक विद्यालयों की सख्यात्मक वृद्धि पर ख़ोर न देकर गुणात्मक उन्नति पर बल दिया जाय।
- २ प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षा-अवधि ४ वर्ष होनी चाहिये और उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये।
- ३ विद्यालयों की निम्नतम वक्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय और उसमें होने वाले अपर्याप्त तथा अवरोधन को समाप्त करने के लिये हड़ प्रयास किया जाय।
- ४ विद्यालयों में ग्राम-मुधार का कार्य रखा जाय। उनमें सफाई, स्वास्थ्य आत्मविश्वास महत्कारिता आदि गुणों का विकास किया जाय और उन्हें सामान्य चिकित्सा मनोरंजन तथा प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र बनाया जाय।
- ५ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में सीधेपन न की जाय। जिस क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू की जानी है—उसका पहिल अध्ययन किया जाय और वहाँ के लिये एक उपयुक्त योजना तैयार की जाय।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Examine critically the main recommendations of the Hartog Committee regarding the improvements necessary in Primary Education.
- 2 What were the views of the Hartog Committee on 'wastage and stagnation in Primary Education? What measures did it suggest to overcome them?
- 3 Trace the growth of University Education in India from 1921 to 1937
- 4 Trace the development of Secondary Education in India from 1921 to 1937

## शिक्षा की प्रगति (Progress of Education) [1937-1947]

### विषय-प्रवेश

अपने स्वभावगत दोषा एवं भारतीय कांग्रेस के विरोध के परिणामस्वरूप इस सामन प्रणाली अक्षय्य मिट गई। कांग्रेस ने यह राष्ट्रीय मांग बुलन्द की कि भारत के लिए सीधे ही पूर्ण औद्योगिक स्वराज्य के आधार पर नविधान बनाने के लिये एक गोलमेड सम्मेलन (Round Table Conference) बुलाया जाय। सम्मेलन ने जो भी निश्चय किये वे भारतीय राष्ट्रीयता की दृष्टि में अत्यन्त असह्य प्रद थे। परन्तु इन्हीं निर्णयों के आधार पर सन् १९३५ का भारत-सरकार अधिनियम (Government of India Act) बनाया गया और अक्टूबर १९३७ में उसे प्रवर्तित कर दिया गया। इसने अनुसार प्रांतीय प्रशासन के क्षेत्र में स्वायत्तता की स्थापना हुई।

केन्द्रीय सरकार के गिना-बाय (१९३७-१९४७)

सन् १९३५ के अधिनियम ने गिना के बायों की दो स्पष्ट भागों में विभक्त कर दिया—केन्द्रीय एवं प्रांतीय। १९४६ में बनने वाली अन्तरिम सरकार (Interim Government) ने स. ७० जवाहरलाल नेहरू वाइसराय की कार्य

कारिणी मिति के उपसमापति नियुक्त हुए। उसी समय से केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया और विभिन्न समितियों तथा संस्थाओं का निर्माण किया गया जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थीं :—

### १. केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education)

इस बोर्ड की स्थापना १९२० में हुई थी। पर आर्थिक संकट के कारण इसने अस्तित्व का अन्त कर लिया गया था। १९३५ में इसको पुनर्जीवित किया गया। उसी समय से यह बोर्ड भारतीय शिक्षा के त्रि में विविध कार्यों का अति बुद्धिमत्ता से मन्वत्वन करना चला आ रहा है। अपने वार्षिक अधिवेशन में यह बोर्ड शिक्षा की प्रगति पर पुनर्विचार करता है और प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा प्रसार के सम्बन्ध में परामर्श देता है।

### २. केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय (Central Secretariate of Education)

इस सचिवालय का निर्माण १९४५ में हुआ और स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इसको मन्त्रालय (Ministry) का रूप प्रदान किया गया। केन्द्रीय सरकार के समस्त शिक्षा-कार्यों पर इसी का नियन्त्रण है और यही उनका नियोजन करता है।

### ३. केन्द्रीय शिक्षा-सूचना कार्यालय (Central Bureau of Education)

इस कार्यालय का प्रमुख कार्य—शिक्षा-सम्बन्धी तथ्यों तथा आँकड़ों को एकत्र करना और प्रान्तीय सरकारों एवं शिक्षा-संस्थाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है। यह भारतीय शिक्षा का विवरण एवं शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करता है।

### ४. विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग (University Grants Commission)

केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड की निष्कारिता के अनुसार इस आयोग का निर्माण १९४५ में किया गया। यह आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सामंजस्य रखता है, उनके लिये सहायता अनुदान की केन्द्रीय सरकार से निष्कारिता करता है और इस प्रकार लिये गये अनुदान की देखभाल करता है।

### एबट्ट एण्ड वुड रिपोर्ट, १९३७ (Abbott & Wood Report 1937)

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निष्कारिता के अनुसार एबट्ट व वुड मिति की नियुक्ति की गई। भारत-सरकार के निर्माण पर ये दोनों अध्येक्ष शिक्षा विधेय १९३६-३७ की शर्त श्रुति में भारत आये। समय के अभाव

के कारण उन्होंने केवल पत्रावलि लिखी और समुक्त प्रान्त का परिभ्रमण करके तत्कालीन शिक्षा की जाँच की और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट दो भागों में विभाजित है—(क) एस० एच० वुड (S H Wood) द्वारा लिखी गई सामान्य शिक्षा पर रिपोर्ट और (ख) ए० ऐबट (A Abbott) द्वारा लिखी गई व्यावसायिक शिक्षा पर रिपोर्ट। शिक्षा के इन भागों पर दिये गये सुझावों का विवरण निम्नांकित है —

### (क) सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव (Recommendations on General Education)

- १ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को विद्यार्थियों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा तियाजों पर आधारित किया जाय न कि पुस्तकों पर।
- २ निम्न-माध्यमिक (Lower Secondary) विद्यालयों में अंग्रेजी के अध्ययन पर बल दिया जाय।
- ३ हाई स्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय।
- ४ रचनात्मक हस्तकर्म की शिक्षा को सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय।

### (ख) व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव (Recommendations on Vocational Education)

- १ प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा का रूप वहाँ के उद्योगों, व्यापारों तथा परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाय।
- २ सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षाओं के माध्यम तथा अन्य विभिन्न हैं। अनेक दोनो प्रकार की शिक्षाओं के साथ पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था की जाय।
- ३ कुटीर उद्योग वर्गों में सघन हुए व्यक्तियों को उचित व्यावसायिक एवं व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाय।

- ४ उद्योग एवं व्यापार और उद्योग एवं शिक्षा में निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रत्येक प्रांत में 'व्यावसायिक शिक्षा परामर्शदात्री समिति' का संगठन किया जाय।
- ५ पूर्ण सामयिक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। ये विद्यालय दो प्रकार के होने चाहिए—(१) जूनियर कोलेजियल स्कूल, और (२) सीनियर कोलेजियल स्कूल।
- ६ जो व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं उनको शिक्षा देने के लिये 'अवकाशिक व्यावसायिक स्कूल' स्थापित किये जायें।
- ७ जिन औद्योगिक क्षेत्रों का जनसंख्या कम से कम ५० हजार हो, वहाँ जूनियर और सीनियर टेक्नीकल स्कूलों का निर्माण किया जाय।

### उच्च शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस अवधि में विश्वविद्यालय शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

शिक्षा विस्तार के कारण—१ माध्यमिक शिक्षा का विस्तार।

२ शिक्षा एवं विद्युद्दी जातियों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा।

३ युद्ध-कालीन समय में व्यावसायिक क्षेत्रों को व्यापार में अत्यधिक लाभ और उनका द्वारा उच्च शिक्षा के लिये दी गई उदार धन राशि।

४ युद्ध में शिक्षित व्यक्तियों की माँग में अभिवृद्धि।

नवीन विश्वविद्यालयों का निर्माण—इस काल में ४ विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ—१ आदमपुर विश्वविद्यालय (१९३७) २ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (१९४३) माधुर विश्वविद्यालय (१९४६), तथा ४ राजपुताना विश्वविद्यालय (१९४७)।

### माध्यमिक शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की तीव्र प्रगति हुई परन्तु वह पुरुषों का ही अपेक्षाकृत मात्र था।

शिक्षा की मध्य प्रगति के कारण—१ इस काल में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की गति में रीतिस्थ रहा। इसी प्रगतिप्रिया माध्यमिक शिक्षा पर होनी

स्वाभाविक थी। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र ही माध्यमिक स्कूल में प्रविष्ट हुए थे।

- २ विद्वत्-मुक्त के कारण जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कृटि हो गई थी। इस मेंहगाई का सबसे बुरा प्रभाव मध्य वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा था। उनका पास धन का अभाव था। अतः उनके लिये इससे अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था कि वे अपने बच्चों का विद्यालय जाने से रोक दें।
- ३ शिक्षकों का मेंहगाई देने के लिये मुश्किल में कृटि हो गई। साथ ही पुस्तकें, आदि का भी मूल्य बढ़ गया। ऐसी दशा में शिक्षा इतनी मेंहगी हो गई कि मायबे साधारण माध्यम वाले व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा से लाभ उठाना कठिन हो गया।

माध्यमिक शिक्षा की ध्वज विधेयताएँ—जब अवधि में प्रायः सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ हो गईं। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और अभ्यास सप्ताह की आरम्भ लगी। प्रांतीय सरकारों ने तकनीक और कृषि-हाई स्कूल खोले। पाठ्यक्रम की शिक्षा का भी प्रकाश किया गया। प्रविष्ट विद्यालयों की संख्या में कृटि हो गई। शिक्षकों अध्यापन-कार्य की भारी ज़ाबूत हुई।

### प्राथमिक शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस अवधि में काठमांडू मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिये पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने बिहार, बर्मा, मध्य प्रदेश, पंजाब, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सिन्धी में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य कर दिया।

प्राथमिक शिक्षा का विस्तार के लिये उन्होंने अन्य माध्यमों का भी प्रयोग किया। उन्होंने उन क्षमों में स्कूल खोले जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं थे। स्थानीय सरपंचों का अनिवार्य सहायता-अनुदान लिया जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में जाने वाले व्यय का भार वहन कर सकें। जिन स्थानों में माँग थी वहाँ अनिवार्य विद्यालय निर्मित किए। प्राथमिक स्कूलों में अक्षर शिक्षा की निपुणता की शिक्षा शिक्षा-कार्य दृष्टात् पूर्वक सम्पन्न किया जा सका।



## UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Summarize the views expressed by Messrs Abbott and Wood on the development of Vocational Education in this country
2. Give a brief account of the educational activities of the Central Government from 1937 to 1947
- 3 Describe the progress of Primary Secondary and University Education from 1917 to 1947

# बेसिक शिक्षा

## (Basic Education)

### वर्धा शिक्षा-योजना

### [Wardha Scheme of Education]

#### विषय प्रवेश

भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में 'बेसिक शिक्षा' का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अविनारनिगम् के अनुसार 'बेसिक शिक्षा' महात्मा गांधी द्वारा दिया गया अन्तिम और सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है।" ("The last and the most precious gift") देश को स्वतन्त्रता नितवाने तथा एक नवीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के प्रयास में महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्त्व को इसी प्रकार समझ लिया था।

महात्मा गांधी के शिक्षा-विषयक विचार—गम्भीर भारतीय शिक्षा के दोषों को देखकर महात्मा गांधी इन निष्कर्षों पर पहुँचे कि उससे देना तथा उसके निवारण का कल्याण होना असम्भव है। अतः उन्होंने हरिजन में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में जाने विचारों का आग करना प्रारम्भ किया जो

भारत के लिये उपयुक्त हो सकती था। २१ जुलाई १९३७ के हरिजन मंचाने अपने शिक्षा विषयक विचारों को अपोलिखित रूप में व्यक्त किया —

राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इन पिछड़े हुए हैं कि यदि हमने शिक्षा का यह कार्य-क्रम घन पर आधारित किया तो हम राष्ट्र के प्रति शिक्षा के अपने उत्तरदायित्वों को इस पीढ़ी में बाढ़ समय में निर्वाह करने की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः मैंने अपनी रचनात्मक योग्यता की क्षमता को सकट में डालकर यह प्रस्ताव करने का साहस किया है कि शिक्षा आत्म निर्भर होनी चाहिये। शिक्षा से मेरा अर्थ है—बच्चे एवं मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न आदि। यह तो अनन्त साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एवं स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तक्षिप्त शिक्षाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने योग्य बनाकर प्रारम्भ करना चाहता हूँ। इस प्रकार यदि राज्य विद्यालयों में निर्मित वस्तुओं की संख्या में उत्पन्न उत्पन्न न के तो प्रत्येक विद्यालय आत्म निर्भर बनाया जा सकता है।'

शैक्षिक शिक्षा का जन्म—गांधी जी के शिक्षा-विषयक विचारों ने देश में हलचल मचा दी। उस समय महाराष्ट्र का वर्षा मधे। वहाँ २२ और २३ अक्टूबर १९३७ को मारवाड़ हाईस्कूल की रजत जयन्ती का समारोह होने वाला था। इस अवसर पर भारत के विभिन्न भागों से शिक्षा विशेषज्ञ राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज-सुधारकों का आमंत्रित किया गया और 'असिक्त भारतवाय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन' जिस वर्षा शिक्षा-सम्मेलन' भी कहते हैं, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने शिक्षा विचारों के समक्ष अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार व्यक्त किये।

जाविर हुसैन समिति—सम्मेलन में जाविर हुसैन इस्तामिया दिल्ही के आचार्य डा० जाविर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस जाविर हुसैन समिति के नाम से पुकारा जाता है। इस समिति का उद्देश्य—वर्षा शिक्षा सम्मेलन में व्यक्त किए गये गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के अनुसार एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना था। इस समिति ने दिसम्बर १९३७ और अप्रैल १९३८ में दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट में वर्षा शिक्षा-सम्मेलन के आधारभूत सिद्धान्तों का विवरण तथा उत्तर प्रशिक्षण विचारों के संयोजन, प्रशासन एवं निरीक्षण और बगल जुलाई के विस्तृत पाठ्यक्रम इत्यादि का विवरण वर्णित किया।

द्वितीय रिपोर्ट में समस्त विषयों का पाठ्य क्रम एवं उनको आधारभूत हस्त तथा उत्पादक कार्य से सम्बन्धित करने का उपायों पर अपना मत प्रकट किया।

वैज्ञानिक शिक्षा योजना की रूप रेखा—१ यह शिक्षा ६ से १४ वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है।

२ शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा है।

सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किन्हीं आधारभूत कौशल (Basic Craft) से होता है।

४ चुन हुए कौशल की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बच्चों को उत्तम कौशल बना देना है और जो वस्तुएँ बनाना हैं उनको बचकर विद्यालय में व्यवस्था के कुछ माध्यमों की पूर्ति को जो सहायता है।

पाठ्य क्रम—वैज्ञानिक शिक्षा के पाठ्य क्रम में निम्नलिखित विषय होते हैं—

१ आधारभूत कौशल—अवलोकन आधारभूत कौशल में से कोई एक चुना जाता है—(क) कृषि (ख) कढ़ाई बुनाई (ग) लकड़ी का काम (घ) मिट्टी का काम (ङ) चमड़े का काम (च) मछली पालना (छ) पत्तों का काम एवं उद्योग कर्म (ज) बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान (झ) कोई अन्य कौशल, जिससे लिए स्थानीय तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों।

२ मातृ भाषा।

३ गणित।

४ सामाजिक अध्ययन—इतिहास भूगोल एवं नागरिक शास्त्र।

५ सामान्य विज्ञान—(अ) प्रकृति अध्ययन (ब) वनस्पति शास्त्र (ग) प्राणिशास्त्र, (ङ) रसायनशास्त्र (र) स्वास्थ्य विज्ञान (स) नक्षत्रों का ज्ञान (च) महान् वस्तुनिष्ठा एवं व्यवस्था की कठिनताएँ।

६ कला—रेखा चित्रण एवं संगीत आदि।

७ हिन्दी (जहाँ मातृ भाषा नहीं है)।

८ पारोक्षिक शिक्षा (व्यायाम एवं खेल-कूद)।

अव्यापन विधि—वैज्ञानिक शिक्षा में अध्ययन-विधि सामान्य शिक्षा-पद्धति से भिन्न है। वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली में अध्ययन का कार्य त्रिमासा एवं अनुभवा के माध्यम से किया जाता है। दूसरा यह कि शिक्षण विधि इसकी व्यावहारिक होती है कि बच्चे विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में अर्जित करते हैं। साथ ही उन्हें यह ज्ञान ज्ञान के समय में ही उपयोग में आता है।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

विस्तार रूप में शिक्षा अग्रलिखित प्रकार से प्रदान की जाती है—प्रथम कक्षा में बच्चों को अपनी मातृभाषा का मौखिक ज्ञान कराया जाता है। तदनंतर बच्चे पढ़ना और उससे बाद लिखना सीखते हैं। जिस समय वे लिखना सीखते हैं उस समय किसी आधारभूत शिल्प की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्या-ज्या बच्चे आगे की कक्षाओं में पहुँचते हैं, वे विभिन्न विषयों के ज्ञान का अजन करते हैं। परन्तु उनको इन विषयों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप से प्रदान न की जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती है। पाठ्य प्रोग्राम के समस्त विषय परस्पर-सम्बन्धित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार वे बच्चे के अन्त में बच्चों को सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साथ ही उन्हें आधारभूत शिल्प की इतनी अच्छी जानकारी हो जाती है कि उसकी सहायता से वे परोपाजन करने लगते हैं।

बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत (Basic Principles of Basic Education)

(१) जनसाधारण की शिक्षा—गांधी जी का कथन था कि 'जनसाधारण की शिक्षा भारत का पाप और बलरू है अतः उसका अन्त करना आवश्यक है। जब भारत में जनता में प्रणाली की स्थापना की गई तब गांधी जी के चिन्ता की गरिमा का अनुभव किया गया। यह आवश्यक समझा गया कि देश का प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रूप से शिक्षित हो। इस कार्य के लिये बेसिक शिक्षा को उपयुक्त समझा गया। अतः यह शिक्षा सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए रखी गई है और जनसाधारण को इसका द्वारा भ्रान्तता के रूप से बाहर निकास दिया गया।

(२) अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा—गांधी जी का भारत के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा में दृढ़ विश्वास था। पराधीन भारत अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था करने में असफल रहा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत ६ से १४ वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निश्चय किया गया।

(३) हस्त शिल्प की शिक्षा—भारत के लिए नवीन शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गांधी जी ने ३१ जुलाई १९३७ के हरिजन में लिखा था—हस्त शिल्प शिक्षा और श्रम समय से वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता है उठ उठान करने योग्य बनाकर प्रारम्भ करना चाहता है। गांधी जी के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्तशिल्प का

प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है और समस्त विषयों की शिक्षा उसी व माध्यम से दी जाती है।

(४) स्वावलम्बी शिक्षा—नवीन शिक्षा व आधारभूत सिद्धान्त का उत्तम करत हुए गांधी जी का कथन था कि— शिक्षा का स्वावलम्बी होना चाहिए अर्थात् शिक्षा से पूँजी व अतिरिक्त बड़े सब धन मिल जाना चाहिए जो उस प्राप्त करने में व्यय किया गया है। अतः बेसिक शिक्षा में इस स्वावलम्बी पहलू व प्रति बिना ध्यान दिया गया है।

(५) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा— बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। इतिहास हम बताता है कि यदि किसी देश का सृष्टि का मिटाना हो तो उसका साहित्य मिटा देना चाहिए। इसी सिद्धान्त पर विदितिया ने हमारे देश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा। पर बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा व माध्यम से शिक्षा स्वाभाविक रूप तथा स्वतन्त्रता से दी जा सकती है।

(६) शिक्षा में शारीरिक श्रम—बेसिक शिक्षा में शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनमें तीन लाभ होंगे—प्रथम इससे बच्चा की शिक्षा का व्यय निरुक्त आयगा। द्वितीय इनसे उन्हें एक व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त होगी। तृतीय शारीरिक श्रम में बच्चा का आत्म विस्वामी बनाया जा सकेगा और व शारीरिक श्रम से पूँजा नहीं करेगा।

(७) सामाजिक शिक्षा—बेसिक शिक्षा का अन्तिम आधारभूत सिद्धान्त है— प्रत्येक प्राणी में सहानुभूति एवं प्रेम उत्पन्न करना घना और निर्धन व्यक्ति का श्रेष्ठ समाप्त करना और उच्च तथा निम्न वर्गों में समता लाना। इस प्रकार बेसिक शिक्षा का द्वारा एक एक नवान समाज की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है जो धार्मिकविहीन है। जिसका आधार वाय है और जिसका मूलमंत्र अहिंसा तथा सत्य हो।

बेसिक शिक्षा का उद्देश्य

(१) नागरिकता व गुणों का विकास—प्रजापति-शासन-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति शासन व प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य व प्रति उसका कर्तव्य बड़ा बात है। साथ ही उस अनवरत अधिकार भी प्राप्त है। वह इन कर्तव्यों तथा अधिकारों का निर्वाह समाज के लिये करता है। जब यह इनका प्रति समझता है। हमने नियमों की शिक्षा को आवश्यकता है जो उसमें नागरिकता व गुणों का विकास करे। नागरिकता में नागरिकता का भाव गुण गुण धन निहित है।

(२) नैतिक विकास—आधुनिक समाज का उत्तरोत्तर नैतिक पतन होता जा रहा है। समाज की इस पतनी-मुख्य दशा का देखकर गांधी जी ने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य—व्यक्ति में नैतिकता की समाविष्ट करना बताया। वैश्व शिक्षा में नैतिक विद्या की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है।

(३) सांस्कृतिक उद्देश्य—प्रचलित शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य दोष यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति का पाठ न पढ़ाया जाकर बच्चा को पाश्चात्य रंग में रंगा जाता है। वे अपना परम्परागत संस्कृति से दूर हो जाते हैं। अतः गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में अधिक महत्व शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू को दिया। इसीलिए वैश्व शिक्षा में भारतीय संस्कृति का ध्यान दिया गया है और शिक्षा को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।

(४) त्रिविध विकास—प्रचलित शिक्षा प्रणाली में केवल बुद्धि के विकास पर ध्यान दिया जाता है और शारीरिक तथा आत्मिक विकास की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। अतः इस प्रकार व्यक्ति का केवल एकांगी विकास होता है पूर्ण विकास नहीं। वैश्व शिक्षा में मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास की ओर पूरा ध्यान दिया गया है।

(५) आर्थिक उद्देश्य—वैश्व शिक्षा में आर्थिक उद्देश्य के दो अभिप्राय हैं प्रथम बच्चा द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालय के व्यय की आदिश्व पूर्ति करना। द्वितीय वैश्व शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् बालक का वह हाथ जिससे उद्योग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

(६) सर्वोदय समाज—आज का भौतिकवादी समाज स्वायत्त निधि की नीति की नींव पर खड़ा है। समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित है—धनपति और धनहीन। दोनों ही वर्ग विद्वत् हैं। एक की विकृति का कारण धन की अभिवृद्धि है और दूसरे की विकृति का कारण धन का अभाव। वैश्व शिक्षा का उद्देश्य—इस विद्वत् समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। सर्वोदय समाज में स्वायत्त का स्थान परमार्थ सत्य की वृत्ति का स्थान त्याग की वृत्ति और दायित्व का स्थान सेवा होगी। इस समाज में धन की महत्ता होगी परन्तु नहीं और सहयोग तथा स्नेह का भावनाएँ हागी ईर्ष्या और द्वेष की नहीं। इस समाज के निर्माण के लिए वैश्व शिक्षा बच्चा में त्याग आत्मविश्वास समाज-सेवा प्रेम आदि की उच्च भावनाओं को बूझ-बूझ कर भरने का प्रयत्न करती है।

**वैश्व शिक्षा की विशेषताएँ**

(१) मनोवैज्ञानिक आधार—वैश्व शिक्षा-प्रणाली का आधार मानवता है कि बालक इसमें पाठ्य विषयों की आशा प्राप्त की प्रभावना में जाना

है। बालक का प्राकृतिक विकास विना बाध के द्वारा होना चाहता है। इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बेमिक् शिक्षा में हस्तशिल्प का प्रमुखता दी गई है।

(२) सामाजिक आधार—बसिक् शिक्षा प्रणाली का आधार सामाजिक है क्योंकि इसमें बालक के सामाजिक गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। हस्तशिल्प द्वारा उनमें आत्म-समयमान आना पाने सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास किया जाता है।

(३) धार्मिक आधार—बसिक् शिक्षा प्रणाली का आधार धार्मिक है। इसमें पक्ष में दो तर्क उपस्थित किए जा सकते हैं। प्रथम बेमिक् विद्यालयों में छात्रों का किसी शिक्षक की शिक्षा दी जाती है। उनमें द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बचकर विद्यालय और शिक्षा का व्यय यदि पूर्ण रूप में नहीं तो आंशिक रूप से अवश्य निकल आता है। नितोय बालक हस्तशिल्प का सामग्र्य और इसमें प्रयुक्तता प्राप्त कर स्वयंसे रूप में जीविकोपार्जन कर सकते हैं।

(४) हस्त-श्रम का महत्व—बसिक् शिक्षा में बालक हाथ से काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान का दृष्टि में देखते हैं और हस्तश्रम का महत्व समझते हैं। इससे दश में मानविक श्रम और श्रम का काम निरूपण समझ आता है। इस प्रकार के विचार और धैर्यमान आत्मिकता के नये प्रजातन्त्रवादी वातावरण में नहीं चल सकते हैं और प्रजातन्त्रवादी सम्प्रदाय की वृद्धि और विकास में बाधा डालते हैं। इसी बात का ध्यान रखकर बेमिक् शिक्षा प्रणाली में हाथ के काम का अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

(५) विद्यालय, गृह और समाज के जीवन में सामंजस्य—वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारे द्वारा विद्यालय गृह और समाज के जीवन में सामंजस्य नहीं उपस्थित किया जाता है। बसिक् शिक्षा प्रणाली इस दोष का निवारण करती है। हस्तशिल्प का शिक्षा प्राप्त कर बालक के व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है और वह अपने को विद्यालय गृह और समाज में समान वातावरण में पाता है।

(६) सहसम्बद्ध शिक्षण—बालक शिक्षा में अनायास ही विद्यालय विधि विधि रूप में प्रवृत्त तथा आधुनिकता है। इस विधि में बालक की समग्र शिक्षा का माध्यम कोई हस्तशिल्प प्रयुक्त किया है। यदि बनाई-बुनाई, मरम्मत, मिनी अथवा चमक के काम आदि में बालक एक कार्य का करने करने को कहा है। तब बालक को उस कार्य में उपस्थित और ज्ञान प्राप्त होता है।



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

(७) **ज्ञान एक अमिन्न धन** समष्टि—H R Bhatia के अनुसार वैदिक शिक्षा में ज्ञान एक अमिन्न धन समष्टि है और उसका अर्थ अक्षय और बर्द्ध शर शरस्वर अमिन्नजित विषया में विभाजन निषिद्ध है। प्रचलित गिणा प्रणाली के अनुसार बालकों की जिन विभिन्न विषयों की गिना ली जाती है वे प्रायः एक-दूसरे में असम्बद्ध होते हैं। जगत बालक जिस ज्ञान का उपार्जन करता है वह एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में न होकर विभिन्न मध्या तथा विषया का मरतन मात्र होता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में सभी विषयों का ज्ञान किसी उपयोगी हस्तक्षिप्त के द्वारा बताया जाता है।

(८) **बालक-प्रधान शिक्षा**—वैदिक शिक्षा बालक प्रधान है। उसका एक मात्र विषय बालक है। गिना बालक को प्राप्त करती है। अतएव उसे सपन और सार्थक बनाने के लिये यह प्रयास किया जाता है कि विद्यालय के प्रत्येक कार्य तथा प्रयास में बालक पूर्ण रूचि से और उन्मत्त बुद्धि से भाग ले। H R Bhatia के शब्दों में वैदिक प्रणाली में बालक का विद्या का प्राहक समझा जाता है जिसका आवश्यकताका अध्ययन किया जाना और समझना जिनकी व्यवस्था करना और जिनको पूर्ण करना आवश्यक होता है।

(९) **क्रिया-प्रधान शिक्षा**—वैदिक शिक्षा क्रिया-प्रधान है। इसमें सम्पूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना गया है। इस अनुभव को प्राप्त करने का माध्यम कोई हस्तक्षिप्त होता है। बालक इन से द्रष्टृ हस्तक्षिप्त के धन में सक्रिय रहते हुए और भी सम्बन्धित अनुभवों का श्रान करता है। हस्तक्षिप्त में लगे हुए बालक बौद्धिक ज्ञान अथवा मानसिक अनुभव भी प्राप्त करता है। शिक्षा में यह मिथ्या नहीं करी और सीखा (Do and Learn) कहा जाता है।

(१०) **शिक्षा का माध्यम** आधारभूत शिक्षा वैदिक शिक्षा का माध्यम कोई आधारभूत शिक्षा होता है। यही 'गुरु' सभी विषयों के अध्ययन का माध्यम होता है। आधुनिक युग में सभी शिक्षा विशेषज्ञ इन बात का स्थापना करते हैं कि बालक को किसी उत्पादन कार्य में गिरा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इन प्रकार की शिक्षा जीवन में वास्तविक सम्बन्ध स्थापित करती है।

(११) **स्वतन्त्रता-प्रधान प्रणाली**—वैदिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक तथा छात्रों को कार्य करने का अधिक स्वतन्त्रता रहती है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि उनमें आत्म-प्रदर्शन तथा रचनात्मक कार्य सम्भव नहीं है क्योंकि उनमें केवल पढ़ाई में उत्तम होने के गुरु-निर्देश सत्य से रहने तथा निष्ठा अर्थ में सच्चाई पर न ध्यान देकर न पढ़ा जाता है।

वैश्व शिक्षा में छात्रों को काम करने का कार्य मजबूत बनाने और काम करने सामर्थ्य ज्ञान के अर्जन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है ।

वैश्व शिक्षा में अध्यापकों को भी पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है । उन्हें न तो कोई अटल पाठ्य-ग्रन्थ ही पढ़ाना पड़ता है और न कोई नियमबद्ध पाठ ही पढ़ाना पड़ता है । उन्हें न तो पुस्तक को समाप्त करने की चिन्ता होती है और न उन्हें परीक्षाओं का भय होता है । वे अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग तथा परीक्षण कर सकते हैं और ऐसा विधि-तत्त्व उपायों पर विचार कर सकते हैं तथा उन्हें काम में ला सकते हैं जो छात्रों के भविष्य तथा योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें स्थान की आवश्यकताओं में पूरा हो सके ।

### वैश्व शिक्षा के दोष

- १ यह योजना शिक्षण रूप से प्रामाणिक सिद्ध है न कि नगरों के लिए ।
- २ इस योजना में उत्पादितता सिद्धांत (Principle of Productivity) की अति है । अतः इसका अनुसरण करने में वैश्व शिक्षा विद्यालय कुटीर उद्योगों में परिणत हो जायेंगे ।
- ३ उत्पादितता सिद्धांत से अध्यापकों का नितर पतन हो जायगा क्योंकि वे विद्यार्थियों को पकड़वाएँ एवं विद्यार्थियों को घनोपाजन करने के माध्यम समझने लगेंगे ।
- ४ यह युग वायुमयता एवं समाज का और विज्ञानों की अति तीव्र गति में प्रगति हो रही है । ऐसे युग में बर्तमान और सुनाई के गद्यान माध्यम वालीन उद्योगों के प्रयोग का उपदेश करके भारत को औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हो जायगी ।
- ५ आधारभूत शिक्षा द्वारा समस्त शिक्षा की शिक्षा दी जानी एवं समग्रता प्राप्त है ।
- ६ आधारभूत शिक्षा की सहायता से न तो अधिकांश समाजवादी विकास करना सम्भव होगा और न उन्हें सामाजिक शिक्षा ही से जागरणीय क्योंकि वर्षा शिक्षा योजना में व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा में उच्च मनुष्यता का अभाव है ।
- ७ तत्कालीन द्वारा बर्तमान पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है । क्योंकि इस कार्य द्वारा अधिक उत्पादन होना सम्भव नहीं है अतः इसमें विद्यार्थियों का समय नष्ट होगा और उच्च शिक्षा में अग्रणी पड़ेगी ।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

- ८ वर्षा शिक्षा योजना में भारतीय मस्तिष्क को सुरक्षित रखने की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है पर धर्म को शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया है।
- ९ Jhingran and Sharma के शब्दों में— यह योजना काल्पनिक है एक अनावश्यक विश्वास है एक मन सृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है। इस योजना में एक सुस्थिर शिक्षा-दर्शन की अपेक्षा भावुकता अधिक है। इसे गाँधी जी की महानता में प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश ही स्वीकार किया है।'

### उपसंहार

बालिक शिक्षा योजना व उपयुक्त गुण-दोषों के विवेचन के आधार पर हमें यह स्वीकार करने में मकोष नहीं करना चाहिये कि भारत जैसे निधन देश व लिये वर्षा शिक्षा योजना अत्यधिक कल्याणकारी सिद्ध होगी। वस्तुतः हमारे देश के नियम इससे अधिक उत्तम शिक्षा-योजना की कल्पना करना ही असम्भव है। इस योजना की महानता देन है— उत्पादक क्रिया का गिदाल। यह योजना गाँधी जी की दूरदर्शिता का प्रतीक और उनकी देश सेवा तथा तपस्या का अनुपम पत्र है। हम हृदय विस्वांग हैं कि जिस प्रकार उनकी राज नीति व यात्राओं में हम देश की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने व लिये अद्वितीय शक्ति विद्यमान रहती थी उसी प्रकार उनकी वर्षा शिक्षा योजना में भारत की समस्त शिक्षा समस्याओं को हल करने की पूर्ण क्षमता है।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Describe in detail the fundamental features of the Basic Education explaining the implications of a basic craft and self-supporting aspect of the education
- 2 Write a reasoned criticism of the Wardha Scheme
- 3 The present system of education does not meet the requirements of the country in any shape or form. In what respects does the Wardha Scheme meet the requirements of this country?

## सार्जेंट-योजना, १९४४ (Sargent Scheme, 1944)

### विषय प्रवेश

प्रथम विश्व युद्ध के दुःशान्त अग्रिम का अन्त होने पर भारतीय जीवन का विभिन्न पक्षों के सुदृढीकरण विकास की योजनाओं का निर्माण-कार्य की ओर रुख बदलना शुरू हो गया। इन योजनाओं में शिक्षा का भी स्थान मिला। अतः 'वाल्मसेय की प्रबन्धनशैली की शिक्षा का पुनर्निर्माण समिति' ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सम्पादन पर सर जॉन सार्जेंट (Sir John Sargent) को भारत में सुदृढीकरण शिक्षा विकास पर एक स्मृति-पत्र (Memorandum) तैयार करने का आदेश दिया। सार्जेंट ने १९४४ में अपना रिपोर्ट 'राष्ट्रीय शिक्षा सम्पादन' के रूप में सरकार को सौंपा। इस रिपोर्ट की सार्जेंट योजना का नाम से पुकारा जाता है।

### सार्जेंट योजना की सिफारिशें (Recommendations of Sargent Scheme)

सार्जेंट योजना में भारत की सम्पूर्ण शिक्षा को १२ अध्यापकों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संश्लेषित शिक्षण पाठ्येक है —

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

१ **पुनः प्रारम्भिक शिक्षा**—से ६ वर्ष तक की अवस्था वाले शिशुओं के लिये शिक्षा-मस्याएँ स्थापित की जाय। ये समस्याएँ समस्त शिक्षण साधनों और सुयोग्य शिक्षका से सम्पन्न हों। शिक्षा नि शुल्क हो।

२ **प्राथमिक ग्रथवा वैसिक शिक्षा**—६ से १४ वर्ष तक की अवस्था के गमस्त बच्चों के लिये मावसीमिक निगुत्क एवं अनिवार्य प्राथमिक या वैसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। अपभ्यय को रोचन के लिये शिक्षा को अनिवार्य बनाना आवश्यक है और अनिवार्यता को कार्यान्वित करने के लिये 'उपस्थिति निरीक्षक पदाधिकारी' नियुक्त किये जायें। योजना में वैसिक शिक्षा व भीसिक सिद्धान्तों का समर्पन परन्तु शिक्षा को आरम्भ निर्मांर बनाने का विरोध किया गया। क्या गया कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विनय कठिन है। वैसिक शिक्षा के बाल को दो भागों में विभक्त किया गया—(क) यूनिवर वैसिक (६-११) और (ख) सोनियर वैसिक (११-१४)।

३ **हार्ड-स्कूल शिक्षा**—यह शिक्षा ११ से १७ वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिये होगी। हार्ड स्कूल दो मुख्य प्रकार के होंगे—साहित्यिक और प्राविधिक। दोनों प्रकार के हार्ड स्कूलों में कुछ विषयों की सामान्य रूप से शिक्षा दी जायगी यथा—(१) मातृभाषा (२) अंग्रेजी (३) आधुनिक भाषाएँ (४) भारत एवं विश्व का इतिहास (५) भारत एवं विश्व का भूगोल (६) गणित (७) विज्ञान (८) अर्थशास्त्र (९) कृषि (१०) कला (११) शारीरिक शिक्षा। इन विषयों के अतिरिक्त सांख्यिक हार्ड स्कूलों में प्राच्य भाषाओं और नागरिक शास्त्र की भी शिक्षा दी जायगी। प्राविधिक हार्ड स्कूलों में जिन अर्थ विषयों की शिक्षा की व्यवस्था होगी वे हैं—वाष्ट-कला धातु कला साधारण इंजीनियरिंग डाइज़ल वाणिज्य सम्बन्धी विषय बुक-कीपिंग टाईट हैण्ड टाइप राइजिंग तथा टैक्सी व्यापार पद्धति इत्यादि। बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होगी।

४ **विश्वविद्यालय शिक्षा**—विश्वविद्यालय का भी ए० की उपाधि पाने के लिये न्यूनतम अवधि ३ वर्ष होनी चाहिये। अतः साजेंट योजना में यह मिश्रण की गई की इंटरमीडिएट बना को भंग कर दिया जाय और उसकी १२ वीं बना की विश्वविद्यालय में तथा ११ वीं बना की हार्ड-स्कूल के अन्तर्गत कर लिया जाय। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के नियमों में कठोरता कर दी जाय।

५ **प्राविधिक वाणिज्य एवं कला शिक्षा**—इस प्रकार की शिक्षा के लिए पूर्णतानिक तथा अग्रशानिक विद्यालय स्थापित किये जायें। भारतीय कलाओं

तथा उद्योगों के लिए निम्नलिखित चार प्रकार के कार्यक्रमों का आवश्यकता है—

- (क) उच्च स्तर—इस श्रेणी में उच्च शिक्षा के मुख्य कार्यक्रमों का अनुमोदन आता है। इस श्रेणी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी टेक्निकल हाई स्कूल का पाठ्यक्रम समाप्त करने के उपरान्त किसी विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक (Technological) विभाग या किसी अन्य पूरक शिक्षा टेक्निकल संस्था में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करेंगे।
- (ख) निम्न स्तर—इस श्रेणी के अन्तर्गत निम्न वर्गीयकारी फोरमन आदि आते हैं। इस श्रेणी के उद्योगों का शिक्षा तथा टेक्निकल हाई स्कूल का कार्य होगा।
- (ग) कुशल शिक्षा—कुशल शिक्षाकारों में उन छात्रों को भरती किया जाएगा जो टेक्निकल हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होंगे।
- (घ) अर्द्ध कुशल एवं अकुशल कार्यगार—इन कार्यगारों में सीनियर हाई स्कूल शिक्षित स्त्रियां या शिक्षा प्राप्त करने वाले व छात्र भरती हो सकेंगे, जिन्होंने किसी शिक्षा का अध्ययन किया होगा।

१ प्रौढ़ शिक्षा—प्रौढ़ों का शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। बालकों पुनर्शिक्षा, पुण्यो और शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय की व्यवस्था की जाय। प्रौढ़-शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए विश्व मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट सिस्टम को प्रयोग में लेंगे। पुनर्शिक्षा एवं वापस आने का आश्वासन दिया जाय।

७ अध्यापकों का प्रशिक्षण—माजेंट-योजना को सफल बनाने के लिए अध्यापकों की एक बहुत बड़ी संख्या आवश्यक है। इन बड़े पैमाने पर अध्यापकों का प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना आवश्यक होगा। इसके अनिवार्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा हाई स्कूल शिक्षा का होना के बिना प्रत्येक प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण करना अनिवार्य है।

८ छात्रों का स्वास्थ्य—६, ११ एवं १४ वर्ष के आयु में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण स्वास्थ्य के द्वारा किया जाय। छात्रों का स्वास्थ्य अभिलेख (Medical Record) रखा जाय। स्वास्थ्य छात्रों की निरन्तर परीक्षा की जाय। रक्त में सामान्य रोग तथा पाचन तंत्र का विकार का प्रबन्ध किया जाय। प्रौद्योगिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाय।

९ विकलांग छात्रों की शिक्षा—विकलांग (Handicapped) छात्रों में निरक्षर स्त्रियों को शिक्षा का जाय और उन्हें दिया शिक्षा दी जाय शिक्षा के लिए उद्योगों काय करने अन्तर्गत जीवन का निर्वाह कर सकें।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

१० विधोवात्मक तथा सामाजिक क्रियाएँ—प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की आयु व अनुसार अप्रतिष्ठित क्रियायां न से जा उचित हों उनका ध्यान रिया जाय—बागवानी सोहनरथ शारीरिक व्यायाम कूनियर रेड-क्रास ग्रुप अभिनय बालघर बाद विवाद अन्तर्विद्यालय प्रतियोगिताएँ स्वाउटिंग मुक्क आन्तेलन ।

११ सेवा योजनालय—सेवा योजनालया की स्थापना की जाय—जो सीनियर वैसिक कूनियर टेकनिकल और हाई स्कूना के छात्रो को व्यवताम धुनन म सहायता दें । विवविद्यालयों के अपने स्वयं के सेवा-योजनालय होने चाहिए ।

१२ शिक्षा का प्रशासन—शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था व लिए मुख्य इकाई प्रात हो । परन्तु विश्वविद्यालय तथा उच्च टेकनिकल शिक्षा का प्रबंध तथा समन्वय अधिस भारतीय पमाने पर किया जाय । राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना व मिये केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारा के बीच अधिक निकट सहयोग होना चाहिए ।

## सार्जेंट-योजना का मूल्यांकन (Estimate of Sargent Scheme)

१८५४ के कुछ के घोषणा पत्र के पश्चात् अनेक समितियां एवं आयोगों की नियुक्ति की गई थी और भारतीय शिक्षा के विराम तथा विस्तार के लिये बहुत से सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किये जा चुके थे परन्तु न तो उनका इंटिरोल ही व्यापक था और न उनके विचार ही स्पष्ट थे । इनके विपरीत सार्जेंट शिक्षा-योजना एक ऐसा व्यापक प्रयास था जिसमें शिक्षा के सभी पक्षों का सूक्ष्म परीक्षण करके उनकी समुपलब्ध करने के लिये बहुसूत्र्य शुभाप प्रस्तुत किये गये । परन्तु कुछ शिक्षाविदों ने इस योजना पर भारी आरोप लगाये हैं और इनको बा-पनिश अरापीय विभ्रमकारी और गम्भीरी कहकर भारत के निर्जन देश के पिय अनुपयुक्त ठहराया है । पर वास्तविकता यह है कि योजना निर्माण के समय में सरकार अब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को न तो उप हीना न मुक्त किया जा सका है जिनका सम्मन योजना में किया गया है और न उन गुणा में मुक्त किया गया है जो योजना में विद्यमान हैं । आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली अपने पूर्ण रूप में कनी जा रही है । यदि हमने योजना को विगन्नेषर्त न करके और आलोचना करने के अपने अभ्यास का परिणाम करके योजना को विमार्गित कर दिया होता तो आज भारतीय शिक्षा की रूप रेखा ही कुछ और हुनी ।

UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Explain the importance of the Sargent Report and summarize its main recommendations
- 2 Write a reasoned criticism of the Sargent Plan as Scheme of National Education



## अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का सिंहावलोकन (Review of the British Educational Policy)

### विषय प्रवेश

इससे पूर्व कि हम स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का विवरण प्रारम्भ करें यह युक्ति-गगत प्रतीत होता है कि हम अंग्रेजी शासन-काल में शिक्षा का सिंहावलोकन करें। भारतीय नेताओं एवं शिक्षा विद्वानों का मत है कि अंग्रेजों की शिक्षा-नीति तथा अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति भारत के लिये सर्वथा अनुपयुक्त अहितकर एवं क्षराष्टीय थी। इसके विपरीत भारत के अंग्रेज शासकों का कथन है कि अंग्रेजी शिक्षा स्वयम्भूत भारत के लिये एक ऐसा श्रेष्ठ वरदान है जो इस देश के शिक्षा के इतिहास में बेनाइ है। इन्हीं दोनों विचारधाराओं का हम अध्ययन करना है।

### अंग्रेजी शिक्षा के साम

(१) वाच्यताय ज्ञान एवं विज्ञान से सम्पर्क—अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों का वाच्यताय ज्ञान एवं विज्ञान में सम्पर्क स्थापित हो गया। यह सम्पर्क ऐसे समय में स्थापित हुआ जब भारतीय अपनी प्राचीन सम्पत्ति और संस्कृति को बिस्मृत करके पतनोन्मुख हो रहे थे।

(२) भारतीय समाज का आधुनिकरण—जित समय भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई उस समय यहाँ के समाज की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। इसमें अनेक हानिप्रद कुरीतियाँ प्रचलित थी और उनसे देश का भय पतन हो रहा था। अंग्रेजों की शिक्षा से प्रभावित होकर भारतीय विचारकों ने इन सामाजिक दुपलायों के विरुद्ध आन्दोलन किया और भारतीय समाज को एक नवीन रूप प्रदान किया।

(३) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति—भारत में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति करने का कार्य अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्त है। अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने भारत के सुप्त गौरव का प्रामाणिक परिचय दिये समस्त उपस्थित किया। अपने साहित्य तथा संस्कृति की जिन बातों का हम विस्मृत कर चुके थे उनका हमने अंग्रेजों भाषा के द्वारा समझा।

(४) धार्मिक उन्नति—ब्रिटिश शासन की स्थापना के उपरान्त जब अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप भारत में नवजागरण प्रारम्भ हुआ तब रामा राममोहन राम आदि महात्मा ने यह अनुभव किया कि पश्चिम के अमृतपूत्र प्रगति का एक प्रमुख कारण—विज्ञान का उन्नति है। अतः उन्होंने अंग्रेजी के द्वारा भारतीयों का बर्णानिर्णय की शिक्षा नये ज्ञान की माँग की। इस शिक्षा की सुविधा मिल जाने पर अंग्रेजों ने विज्ञान के अर्थ में बहुत प्रगति की।

(५) सतिन कलाओं का पुनरुत्थान—भारत के सतिन कलाओं के पुनरुत्थान का कार्य अंग्रेजों की प्राप्त है। पर्युमन ने अनेक चित्रकारों को प्रेरित किया और भारत की वास्तुशिल्प कला का अन्वेषण किया। अतः सतिन कलाओं का प्रति माताओं की रचित की पुन जागरुत किया।

(६) लोकप्रिय राजनीतिक संस्थाओं का विकास—अंग्रेजी शिक्षा के एक स्वरूप ही भारत में लोकप्रिय राजनीतिक संस्थाओं की वृद्धि एवं विकास हुआ। उदाहरणार्थ—अंग्रेजों शिक्षा प्राप्त करके ही भारतीयों के हृदय में लोकतन्त्रवादी विचारधाराएँ रुढ़ हुईं और अंग्रेजों के संस्थाओं का प्रचलन विकास हुआ गया।

(७) शिक्षा प्रसार के नवीन साधन—शिक्षा प्रसार के नवीन साधन भी अंग्रेजों की देन है। उन्होंने अनेक शिक्षा प्रणालियों के अन्तर्गत मुद्रापत्रों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, रेडियो, चमचिन्ता आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। स्वयं भारत ने इनकी शिक्षा प्रसार के साधनों में स्थान दिया है और इनकी

सहायता से शिक्षण तथा निरक्षरता के निवारण का कार्य रिया जा रहा है।

(८) भारतीय पुनर्जागरण—भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण अंग्रेजी की शिक्षा है। स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में विचारों तथा दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन कर दिया। परिणामस्वरूप इस देश में उसी प्रकार की विद्यालय मानसिक प्रगति हुई जसी कि यूरोप में पाँचवी तथा सोमहवी शताब्दियों में पुनर्जागरण के समय में हुई थी।

### अंग्रेजी शिक्षा की हानियाँ

(१) अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली—देश के वातावरण के प्रतिकूल—विदेशियों द्वारा आयोजित की जाने वाली कारण अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली इस देश के वातावरण के प्रतिकूल थी। M R Paranjpe का कथन है कि—यह एक विदेशी वृक्ष का जो भारत भूमि में उचित प्रकार से पल्लवित नहीं हो सकता था।'

(२) राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश—M R Paranjpe का मत है कि—अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—भारत की राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश करना और यहाँ के निवासियों को भारतीय होने हुए भी पसन्द, व्यवहार तथा विचार में अंग्रेज बनाना था।'

(३) अंग्रेजी शिक्षा का निष्पक्ष ध्येय—अंग्रेजों द्वारा १८३५ में जिस शिक्षा-नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसका १८५४ में अनुसरण किया गया और जिस पर १८८२ में यत्न दिया गया उसका एक मात्र ध्येय अंग्रेजी दफतरों के लिए बाबू वर्ग को तैयार करना था।

(४) अंग्रेजी माध्यम के दुष्परिणाम—M R. Paranjpe ने लिखा है कि—'भारतवासियों को अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षा दी गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनके अपने साहित्य तथा भाषाओं का समुचित ज्ञान न प्राप्त हो सका। साथ ही भारतीय भाषाओं एवं भारतीय मतिधर्म का विनाश अवश्य हो गया।

(५) धर्महीनता एवं भक्ति पतन—M R. Paranjpe ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि—अंग्रेजी विद्यालयों में भारतीयों के धर्म की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। शिक्षा को पूँजीवादी शैक्षणिक बना दिया गया। धार्मिक शिक्षा के अभाव में व्यक्तियों में न केवल धर्महीनता की वृद्धि

हई धर्मिणु धर्म के अभाव में उनका नविक पतन भी होना प्रारम्भ हो गया ।”

(६) शिक्षा का मन्द विकास—अंग्रेजों पर एक दोषारोपण यह भी किया जाता है कि उन्होंने शिक्षा का प्रसार करने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया । परन्तु शिक्षा के विकास की गति अत्यन्त मन्द रही । लगभग १५० वर्षों में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली द्वारा केवल १५ प्रतिशत भारतीयों को शिक्षित बनाया जा सका ।

## राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में असफलता

(Failure to Develop a National System of Education)

अंग्रेज भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण एवं विकास करने में पूर्णतः असफल रहे । इस असफलता के प्रमुख कारणों को और हम नीचे संकेत कर रहे हैं —

(१) प्राच्य तथा पश्चात्त्य आदर्शों का समन्वय न करना—अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रमुख दोष यह था कि वह प्राच्य तथा पश्चात्त्य आदर्शों का समन्वय करने में असफल रही । भारत और इस्लाम के सामाजिक सांस्कृतिक आदिम एवं नविक आदर्शों में बिना प्रचार का साम्य नहीं था । एवं आध्यात्मिकता में विश्वास करता था उस दूसरा मौलिकवादिता में ।

(२) साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण—अंग्रेज भारत का अपने साम्राज्य का एक अविच्छिन्न अङ्ग समझने से और प्रत्यक्ष सम्भव नीति से इस पर अपने प्रभुत्व को बनाये रखना चाहते थे । उन्होंने इस बात की कक्षा बरूपना ही नहीं की कि भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करके सम्मानित एवं भाग दिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में उनका लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण की बात गोपनीय विन्दुस असम्भव था ।

(३) शिक्षा का उद्देश्य में अस्थिरता—भारतीय शिक्षा का उद्देश्यों के सम्बन्ध में अंग्रेज प्रशासकों के विचारों में बड़ी स्थिरता नहीं रहता । उद्देश्यों का रूप समय-समय तथा अवसर के अनुसार सदैव परिवर्तित होता रहा । १८१९ के आशा-पत्र में प्राच्य साहित्य तथा ज्ञान का प्रसारण करने का आदेश दिया गया । १८५४ के पाण्डेय पत्र में शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करने के माध्यम-माध्यम अंग्रेज शिक्षा द्वारा एक स्थिति को उत्पन्न करना बताया गया जो राज्य को मुक्त बना सके । १८९९ के सरकारी प्रस्ताव में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण निर्धारित किया गया ।

(४) शिक्षा-प्रसार की दोषपूर्ण विधियाँ—यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा प्रसार की जितनी विधियाँ का अनुसरण किया वे सभी दोषपूर्ण थीं। निस्सन्देह सिद्धान्त शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों को प्रतिष्ठित करना माध्यमिक स्कूला एव कॉलेजों में अंग्रेजों की शिक्षा की प्रधानता देना एवं भारतीय भाषाओं की अवहेलना करना, शिक्षा प्रसार की दोषपूर्ण विधियों के कुछ ज्वलन्त उदाहरण हैं।

(५) शिक्षा विभाग की अवहेलना—अंग्रेजों ने जिनका ध्यान अन्य विभागों की ओर दिया उसका सातवाँ भी शिक्षा विभाग की ओर नहीं दिया। जिस प्रकार के सुपाय एव कुशल मनुष्यों का अंग्रेज विभागों में कार्य करने के लिए इंग्लैंड से भारत भेजा गया उस प्रकार के मनुष्यों को भारतीय शिक्षा विभाग में नियुक्त नहीं किया गया। जो व्यक्ति आय भी उनमें इतनी कार्य-क्षमता नहीं थी कि वे इस देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बना सकते।

### निष्कर्ष

उपरिसंक्षिप्त ब्रिटिश कालीन शिक्षा एवं अंग्रेजों शिक्षा प्रणाली के मामूली-हानियाँ अथवा गुण दोषों पर दृष्टि डालने से सहमा यही विचार उत्पन्न होता है कि अंग्रेजों ने अपनी भाषा और शिक्षा-पद्धति को परबल भारत पर लादकर एक ऐसा जपजप अपराध किया है जिसके लिए वे अक्षम्य हैं। पर यदि हम अपनी मायुक्तता के बशीर्ष न होकर निष्पक्ष एवं सदस्य रूप से विचार करें तो हम यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए एक अद्वितीय वरदान बनकर आई। अंग्रेजों के अध्ययन से ही हमारे देश में पिछले सौ वर्षों में मुगलतर हुआ है। इसका योगदान उस समय हुआ जब हमने ज्ञान एवं प्रकाश के लिए अपना मुँह पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर मोड़ा।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Discuss critically the view that the British totally failed to evolve a National System of Education for India
2. 'The British Educational Administration did several good things which India will always acknowledge  
Elucidate and comment

**विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग**  
**(University Education Commission)**  
**राधाकृष्णन् कमीशन**  
**(Radhakrishnan Commission)**  
**[1948-1949]**

**विषय प्रवेश**

स्वातन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालयों और उनमें शिक्षा प्रदत्त करने वाले छात्रों की समस्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई। परन्तु विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रसार की शिक्षा प्रदान की जा रही थी, उससे जनसाधारण में अध्ययन अवसरों का अभाव अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा-परिषद (Inter University Board of Education) और केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education) ने सरकार से एक अलग भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान विमुक्त करने की सिफारिश की। एक स्वतन्त्र भारत सरकार ने ४ नवम्बर १९४८ को डा० एन० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नियुक्ति की।

नियुक्ति के उद्देश्य—आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य—‘भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट’ प्रस्तुत करना और उन सुधारों तथा विस्तारों के विषय में सुझाव देना था, जो देश की वर्तमान तथा आगामी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिए आवश्यक हों सकें।’

## आयोग के विचार तथा सुझाव

(Views & Recommendations of the Commission)

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए और उनमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए। हम इनका बख़्त नोट कर रहे हैं :—

### १ विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य (Aims of University Education)

- १ स्मृत-व्रता प्राचिन के पश्चात् हमारे विश्वविद्यालयों में कल कल से सदा दायिरों में घुट्टि हो गई है। अब उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो राजनीतिक प्रशासकीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकें।
- २ विश्वविद्यालय समाज सुधार में सहस्रकपूर्व योग दे सकते हैं। अतः उनका उद्देश्य ऐसा नेताओं को जन्म देना होना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा साहसी हों।
- ३ विश्वविद्यालयों को ऐसे विवेकी व्यक्तियों का जन्म देना चाहिए जो प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार कर सकें।
- ४ शिक्षा का उद्देश्य—जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना है। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालयों में जो विषय पढ़ाये जायें वे राष्ट्रीय-क्रम के अन्तर्गत हों।
- ५ विश्वविद्यालय देश की सम्पत्ति तथा संस्कृति के पोषक हैं। अतः विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य—नवयुवकों में इन तत्वों का पोषण करना होना चाहिए।
- ६ स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। अतः विश्वविद्यालयों में छात्रों के न केवल मानसिक विकास अपितु शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाय।

### २ अध्यापक बल (Teaching Staff)

- १ अध्यापकों का प्राविष्ट प्रणाली की अधीन उत्तम सुविधा दी जाय। इससे सिद्ध अध्यापक और विश्वविद्यालय—दोनों आठ-आठ प्रतिफल दें।

२. विश्वविद्यालय के समीप ही अध्यापकों के निवास की व्यवस्था की जाय।
३. अध्यापक अपने घर पर ६० वर्ष की आयु तक रहें और यदि उनकी स्वास्थ्य अवस्था है तो वे ६४ वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं।
४. अध्यापकों को अध्ययन के लिए एक बार में १ वर्ष का अवकाश, और अपने सम्पूर्ण सेवा काल में ३ वर्ष का अवकाश मिलना चाहिए।
५. अध्यापकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक १८ घण्टे (Periods) का अध्यापन कार्य दिया जाय।

### ३. अध्यापन के स्तर (Standards of Teaching)

१. शिक्षण विश्वविद्यालय की कक्षा एवं विज्ञान कक्षाओं में ३००० और सम्बद्ध कमिटी में १४०० से अधिक छात्र न रहे जायें।
२. परीक्षा दिवसों को छोड़कर कार्य करने के दिन एक वर्ष में कम से कम १८० हों।
३. शिक्षा के व्यापक परिश्रम से तयार किये जायें शैक्षणिक कक्षाओं का व्यवस्था की जाय और पुस्तकालय में अध्ययन तथा लिखित कार्य पर ध्यान दिया जाय।
४. शिक्षा का कक्षा के नियम वास्तविक निश्चित न किया जाय।
५. स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को व्याख्याता में उन्नति होने के लिए बाध्य न किया जाय।
६. स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न गोष्ठियों (Seminars) को प्रोत्साहित किया जाय।
७. छात्रों का १८ वर्ष की आयु से पूर्व विश्वविद्यालय में प्रवेश न दिया जाय, क्योंकि इस आयु के पूर्व उनका नैतिक परिपक्व नहीं हो पाता है।
८. छात्रों को ३२, ४४ और ६० प्रतिशत अंका पर लचीली नियाय तथा प्रथम श्रेणी न दी जाकर ४०, ४५ और ७० प्रतिशत पर दी जाय।

### ४. पाठ्य-क्रम (Courses of Study)

१. स्नातक का उपाधि प्राप्त करने का अवधि ३ वर्ष है।
२. स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के ३ वर्ष पाठ्य और स्नातक करने के ३ वर्ष उन्नत प्रशिक्षण की जाय।



- १ विद्वद्विद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों में सामान्य शिक्षा के सिद्धान्तों तथा प्रयोगों का शिक्षण अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय।
- ४ सामान्य शिक्षा तथा विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाय।
- ५ स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान (Post Graduate Training and Research)
  - १ स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन एवं अनुसन्धान की विधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाना चाहिए।
  - २ पी० एच डी० के छात्रों का अखिल भारतीय स्तर पर निर्वाचित किया जाय।
  - ३ पी० एच डी० एवं अन्य अनुसन्धान कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा अभिवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  - ४ डी० लिट० एवं डी० एस-सी० की उपाधियाँ कबल उच्च काटि की शैक्षिक कृतियों पर प्रदान की जायें।

## ६ व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)

(i) कृषि (Agriculture)—कृषि शिक्षा में सम्बन्ध में आयोग ने निम्ना द्रष्टव्य सिफारिशों की —

- १ प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- २ कृषि शिक्षा की समस्याएँ यथासम्भव ग्रामीण छात्रों में होनी चाहिए।
- ३ सर्वमान कृषि कलियाँ को पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर अधिक साधन-सम्पन्न बनाया जाय।
- ४ सर्वान कृषि-कलियाँ को यथासम्भव मजदूर ग्रामीण विद्वद्विद्यालयों से सम्बद्ध रखा जाय।
- ५ केंद्रीय और राज्य-सरकारों द्वारा प्रयोगात्मक कामें शासित जायें।

(ii) वाणिज्य (Commerce)—आयोग ने वाणिज्य की शिक्षा विषय में निम्नलिखित सुझाव दिये—

- १ विद्वद्विद्यालय में वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की ३ या ४ विभिन्न प्रकार की प्रमों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाय।
- २ स्नातक-परादा प्राप्त करने के पश्चात् छात्रों को किसी विद्यालयात्ता में विशेषज्ञ बनने का परामर्श दिया जाय।

(iii) शिक्षा-व्यवसाय (Teaching Profession)—शिक्षा-व्यवसाय में सुधार करने के उद्देश्य से आयोग ने अधोलिखित सिफारिशों की—

1. प्रशिक्षण-सम्पादना के पाठ्य-क्रम में सुधार किया जाय। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा विद्यालयों में अध्यापन के अभ्यास की अधिक महत्त्व दिया जाय।
2. प्रशिक्षण विद्यालयों में अधिकांश अध्यापक वे हों, जो स्कूला में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हों।
3. शिक्षा-सिद्धान्त (Theory of Education) के पाठ्य-क्रम लचीले और स्थानीय वातावरण के अनुकूल हों।
4. एम० एड० डिग्री के लिये उन्हीं व्यक्तियों की प्रोत्साहित किया जाय जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण का अनुभव हो।

(iv) इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (Engineering & Technology)—इस शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नावि हैं—

1. फोरमेन इण्टरमेन और आउरसियरा का शिक्षा देने वाले इंजीनियरिंग स्कूला की शिक्षा में सुधार की जाय।
2. इंजीनियरिंग स्कूला और कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों को कारखानों में कार्य करने के व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाय।
3. रेल व विभिन्न उद्योगों की सीमा का ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम को विस्तृत किया जाय।
4. उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजिकल मैसाजों का दीर्घावधि निर्माण किया जाय।

(v) कानून (Law)—कानून की शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. छात्रों को कानून की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति तभी दी जाय जब वे 1 वर्ष का सामान्य शिक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करें।
2. कानून के विशेष विभाग के पाठ्य-क्रम 2 वर्षों का हो।
3. कानून के छात्रों का अध्ययन-काल में अन्य विद्यार्थियों के समान होने की अनुमति कबल विद्यार्थी परिस्थिति में दी जाय।

(vi) चिकित्सा (Medicine)—चिकित्सा-शिक्षा के विषय में आयोग ने जो विचार प्रकट किए, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

- १ किसी भी मेडिकल कॉलेज में १०० से अधिक छात्रों की प्रवृत्ति न ली जाय।
- २ कॉलेज में प्रवृत्ति लेने वाले प्रत्येक छात्र के लिए १० बेडों का होना चाहिए।
- ३ स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर बच्चाओं के छात्रों की प्रवृत्ति क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाय।
- ४ दृष्टा चिकित्सा प्रणालियाँ में अनुसंधान-कार्य के लिये विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायें।

### ७ धार्मिक शिक्षा (Religious Education)

- १ सभी शिक्षा-संस्थाएँ कुछ मिनट के मौन चिन्तन के पश्चात् अपना दैनिक कार्य प्रारम्भ करें।
- २ द्वितीय भाग में प्रथम वर्ष में विश्व के महान् धार्मिक नेताओं—बुद्ध, कनफूसियस, मुकरात, ईसा, डॉक्टर रामानुज, माधव, मुहम्मद, कबीर, नानक गान्धी—की जीवनियाँ पढ़ाई जायें।
- ३ द्वितीय वर्ष में विश्व के धार्मिक ग्रन्थों में से सांख्यिकीय महत्त्व के चुने हुए भाग पढ़ाये जायें।
- ४ तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया जाय।

### ८ शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)

- १ उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासंभव अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग प्रारम्भ किया जाय।
- २ उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाय—प्रादेशिक भाषा (मातृभाषा), स्थानीय भाषा (राष्ट्रभाषा) और अंग्रेजी।
- ३ उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा (Regional Language) हो परन्तु राष्ट्रभाषा को एक या अधिक विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है।
- ४ राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्तर पर द्वितीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सभी बच्चाओं में स्थानीय भाषा की शिक्षा की व्यवस्था करें।
- ५ सर्वोच्च ज्ञान के सम्पर्क में रहने के लिये स्त्रियों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का अध्ययन यथापूर्व रखा जाय।

### ९ परीक्षाएँ (Examinations)

- १ प्रत्येक विश्वविद्यालय में तीन समस्या का एक पूर्वाभासी बोर्ड स्थापित किया जाय। इस बोर्ड के दो प्रमुख कार्य हों—

- (i) विश्वविद्यालय अधिका कमिज व अध्यापका को वस्तुगत परीक्षा (Objective Tests) की नवीन योजनाएँ बनाने में परामर्श देना और पाठ्य-क्रम में संशोधन के लिए सामग्री देना ।
- (ii) सम्बद्ध करिजा के छात्रों का समय-मय पर प्रगति परीक्षा (Progressive Tests) द्वारा परीक्षा करना ।

२. वक्षा में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वषार्षीय वस्तुगत प्रगति-परीक्षा (Objective Progressive Tests) का एक कुल (Set) विकसित किया जाय ।
३. तीन वर्ष के द्वितीय पाठ्य-क्रम की परीक्षा तीन वर्ष उपरान्त ले ली जाय अर्थात् प्रत्येक वर्ष के क्रम में स्वतः पूर्ण इकाइयाँ (Self contained Units) में परीक्षा ली जाय और विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में प्राप्त हुना आवश्यक हो ।
४. परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा करने के लिये प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिये न्यूनतम अंक क्रमशः ७०, ५५, और ४० प्रतिशत निर्धारित किये जायें ।

## १० छात्र, उनके कार्य तथा उनका कल्याण (Students their Activities and Welfare)

१. प्रवेश के समय और तदुपरान्त वर्ष में एक बार प्रत्येक छात्र और छात्रा का निम्न स्वस्थ परीक्षा की जाय ।
२. प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिये अस्पताल हो ।
३. मध्याह्न के समय उचित मूल्य पर छात्रों को पोषक भोजन दिया जाय ।
४. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक 'काउन्सलर ऑफ विट्डीकल एड्युकेशन' की नियुक्ति की जाय ।
५. छात्रों के नैतिक-वैयक्तिक आदि की ठाणुल व्यवस्था की जाय ।
६. सभी शिक्षा-अध्यापका में एन० छा० बी० की स्थापना की जाय ।
७. विश्वविद्यालय में छात्रावासों की उचित व्यवस्था की जाय । एक छात्रावास में २० से अधिक विद्यार्थी न हों ।
८. छात्रों की उन्नत प्रशिक्षण में वृद्धि उन्नत की जाय और प्रत्येक 'प्रोक्शनल सिस्टम' (Proctorial System) का विकास किया जाय ।
९. विश्वविद्यालय में छात्र-कल्याण परामर्श-मंडल (Advisory Board of Student Welfare) की स्थापना की जाय ।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें

### ११ स्त्री शिक्षा (Women's Education)

- १ स्त्रियाँ की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे कि वे सुमाता और सुशिक्षित बन सकें।
- २ स्त्रियों की शिक्षा-सुविधाओं में विस्तार किया जाय।
- ३ शिक्षा प्राप्त करने में स्त्रियाँ पुरुषों का अनुकरण न करें अपितु स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करें।
- ४ शिक्षा-संस्थाओं का पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिए जिससे स्त्रियाँ सामान्य समाज में अपना सामान्य स्थान ग्रहण कर सकें।
- ५ गृह-अर्थशास्त्र (Home Economics) और गृह-प्रबंध (Home Management) की शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्त्रियों को प्रेरणा दी जाय।

### १२ ग्रामीण विश्वविद्यालय (Rural Universities)

भारत एक खेतिहर देश है। अतः उसकी उन्नति और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ग्रामीण कृषि तथा विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। हमें देना है कार्य प्रारम्भ करना राष्ट्रीय है। हम उद्देश्य की पूर्ति के लिये —

- १ छोटे-छोटे गावांसिक स्नातक पूर्व कृषि स्थापित किये जायें। उनमें
- २ कृषि में पढ़ने वाले छात्रों की सरासरी संख्या ३०० हो और समस्त कृषिजों तथा विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या २५०० से अधिक न हो।
- ३ सभी कृषिजों में पृथक् अध्यापक और शिक्षण की सुविधा हो। परन्तु जहाँ तक पुस्तकालयों प्रयोगशालाओं आदि का प्रश्न है वे सब कृषिजों के लिये एक ही स्थान पर हो सकते हैं।
- ४ इन कृषिजों का प्रमुख ध्येय—छात्रों को सामान्य शिक्षा देना और उनकी व्यक्तिगत रुचियाँ का विकास करना होना चाहिए।
- ५ त्रिगुणमय मान स्नातक-पूर्व बनाई अध्ययन कर रहे हों उन्हें विश्वविद्यालय या व्यावसायिक स्कूल में किसी पाठ्य-क्रम को अध्ययन करने की सुविधा हानी चाहिए।
- ६ इन प्रकार की सुविधा में उनका अधिक विकास सम्भव हो सकेगा और वे पुनः-पुनः शिक्षा के माध्यम-माध्यम किसी विषय की विशेष शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे।

- ७ स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कठोर विभाजन नहीं होना चाहिए जिससे कि एक विद्यार्थी कुछ विषयों की स्नातक-पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हुए भी स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण कर सके।

### राधाकृष्णनन् कमीशन का मूल्यांकन (Estimate of Radhakrishnan Commission)

आज तक विश्वविद्यालय शिक्षा का परीक्षण करने के लिये जिनने भी आयोग और समितियाँ की गयी हैं उन सब में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सबसे बड़ी स्थिति प्रमुख है। यदि आयोग की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर लिया गया तो हमारे विश्वविद्यालयों की रूप रेखा द्रुततया परिवर्तित हो जायगी और वे सामान्य में राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हो जायेंगे। महात्मा गांधीजी ने २० राजद्वय प्रमाण में आयोग के कार्यों की मराहती करने हुए लिखा था— आयोग ने हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति पर अत्यन्त सम्मोहकपूर्ण विचार करके एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और साथ ही अति अमूल्य प्रस्ताव तथा सुझाव भी दिए हैं।” (‘The Commission has submitted a very valuable report containing a review of the achievements of our University Education and also suggestions and recommendations which are of a far reaching character’)

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. What reforms have been suggested in the University Education in this country by the Radhakrishnan Commission?
2. Comment upon the view that the Indian Universities as they exist today despite many admirable features do not fully satisfy the requirements of a National System of Education. How far do you think the implementations of the recommendations of the University Commission of 1948 can fulfil the needs of the country?

# माध्यमिक शिक्षा-आयोग (Secondary Education Commission)

मुदालियर कमीशन  
(Mudalliar Commission)  
[1952-1953]

## विषय प्रवेश

स्वतन्त्र भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा था। अतः उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। १९४८ में 'केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय बोर्ड' ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा को जाँच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाय। १९४९ में बोर्ड ने अपनी माँग का विवर दोहराया। फलस्वरूप भारत सरकार ने २३ मिनम्बर १९४९ को डा० सहमण्डलामो मुन्नामियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसी को मुन्नामियर कमीशन' भी कहा जाता है।

नियुक्ति के उद्देश्य—इस आयोग का नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य ये —

- १ इसमें प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जाँच करना । ( To examine the prevailing system of Secondary Education in the country )
- २ इस शिक्षा प्रणाली के पुनर्र्गठन और सुधार के विषये सुझाव देना । ( 'To suggest measures for its reorganisation and improvement ' )

### आयोग के विचार एवं सुझाव

(Views & Recommendations of the Commission)

माध्यमिक शिक्षा का विभिन्न अवयवों एवं उनमें सम्मिलित समस्याओं का विषय में आयोग द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए और जो सुझाव दिए गये उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है —

#### १ माध्यमिक शिक्षा के दोष (Defects of Secondary Education)

- १ माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।
- २ अध्ययन की रीतियाँ परम्परागत हैं और वे छात्रों को प्रभावित करने में असमर्थ हैं ।

माध्यमिक शिक्षा एक परीक्षा एक प्रणाली है और छात्रों की रुचि के अनुरूप नहीं है ।

- ४ अंग्रेजी भाषा, शिक्षा का माध्यम एक अध्ययन का अनिवार्य विषय है । अतः जिन छात्रों को इस भाषा का समुचित ज्ञान नहीं होना है वे इसके अध्ययन में बड़ी परिश्रम करके अन्त में समझ तथा गति को नष्ट करते हैं ।

- ५ वर्तमान शिक्षा में छात्रों का चरित्र निर्माण का और नैतिक भावना नहीं दिया जाता है ।

- ६ परीक्षा प्रणाली आवश्यक दोषपूर्ण है ।

#### २ माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Secondary Education)

(१) लोकतन्त्रात्मक भागीदारी का विकास (Development of Democratic Citizenship)—भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है और उसका उद्देश्य सर्व निम्नलिखित वर्गों को सम्मानित करना है । अतः शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिये जो कि भारत के अनेक भागों के



भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

अनुसूत हों। दूसरे शब्दों में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य—सोक्त-त्रात्मक नागरिकता का विकास करना होना चाहिए।

(२) व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि (Improvement of Vocational Efficiency)—माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य—नागरिकता में व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करना है। अने छात्रों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है।

(३) व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality)—शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—नागरिकता के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे छात्रों का साहित्यिक सांस्कृतिक एवं शारीरिक विकास हो सके।

(४) नेतृत्व का विकास (Development of Leadership)—प्रजातन्त्र की नींव में मजबूती के लिए कार्य कर सकता है जब कि उसका प्रत्येक नागरिक नेतृत्व में शिक्षा प्राप्त कर चुका हो। अतः माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य—छात्रों को अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व की भी शिक्षा प्रदान करना है।

३. माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन (New Organisational Pattern of Secondary Education)

१. माध्यमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष की होनी चाहिए।

२. यह शिक्षा ११ से १७ वर्ष तक की आयु के बालकों तथा बालिकाओं के लिये होनी चाहिए।

३. शिक्षा ताल दो भागों में विभाजित किया जाय —

(i) ३ वर्ष की पूर्वियर माध्यमिक (Junior Secondary) शिक्षा।

(ii) ४ वर्ष की उत्तरतर माध्यमिक (Higher Secondary) शिक्षा।

४. वर्तमान इष्टरमाइण्ट कक्षा को ताब दिया जाय।

५. द्वितीय कोर्स ३ वर्ष का कर दिया जाय।

६. बहु उद्देशीय (Multi purpose) स्कूलों की स्थापना की जाय।

७. बहन बहो मध्याम प्राविधिक स्कूलों (Technical Schools) की स्थापना की जाय।

८. बड़े शहरों में व-शेय औद्योगिक संस्थानों (Technological Institutions) का निर्माण किया जाय।

९. उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर (Industrial Education Cess) लगाया जाय और इससे प्राप्त धन को प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में व्यय किया जाय।

१०. बानिकाबा बा गृह विज्ञान (Domestic Science) क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाय ।

#### ४ भाषाओं का अध्ययन (Study of Languages)

१. हिन्दी की विद्यालया के पाठ्य-क्रम में अनिवार्य विषय बना दिया जाय ।
२. एत गमय पाठ्य-क्रम में अष्टदा एव अनिवार्य विषय है और इसको अविव्य में इसी स्थान पर रखना पड़ेगा ।
३. विद्यालया के पाठ्य-क्रम में संस्कृत का सम्मिलित किया जाना आवश्यक है ।
४. माध्यमिक विद्यालया में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अपना छात्रीय भाषा हानी चाहिये ।
५. मिडिल स्कूला में प्रत्येक छात्र को कम से कम दो भाषाओं में निपार्य जानी चाहिये ।
६. हायर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाय । इनमें से एक मातृभाषा हो और दूसरा छात्राय भाषा ।

#### ५ माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्य क्रम (Curriculum in Secondary Schools)

१. पाठ्य-क्रम में विविधता तथा लचीलापन होना चाहिये जिससे कि उस छात्र की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुकूल बनाया जा सक ।
२. पाठ्य-क्रम का सामाजिक जीवन में घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिये ।
३. पाठ्य-क्रम में ऐस विषय नहीं होन चाहिये, जिनका एव-दुमरा में कोई सम्बन्ध न हो ।

#### ६ पाठ्य-क्रम के विषय (Curriculum)

(क) मिडिल और सीनियर सेतिव स्कूल—(१) भाषाएँ (Languages), (२) समाज विज्ञान (Social Studies) (३) सामान्य विज्ञान (General Science) (४) गणित (Mathematics) (५) कला एवं कला (Art & Music) (६) शिल्प (Craft) (७) पारान्त्रिक शिक्षा (Physical Education) ।

(ख) हाई क हायर सेकेंडरी स्कूल—इन स्कूला में पाठ्य-क्रम में विविधता (Diversification) का आवश्यकता है जिसमें कला का अभिरुचि तथा

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

योग्यता का विकास किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्य-क्रम में निम्नलिखित विषय होंगे —

### १—आन्तरिक विषय (Core Subjects)

अ—(१) मातृभाषा अथवा प्रादेशिक (Regional) भाषा अथवा मातृभाषा तथा एक शास्त्रीय भाषा (Classical Language) का नियत पाठ्य-क्रम।

(२) निम्नांकित में से चुनी जाने वाली एक अन्य भाषा —

(i) हिन्दी (जिसकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)।

(ii) प्रारम्भिक अंग्रेजी (जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है)।

(iii) उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने पहिले अंग्रेजी का अध्ययन किया है)।

(iv) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा।

(v) अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा।

(vi) एक शास्त्रीय भाषा (Classical Language)।

ब—(१) समाज विज्ञान का सामान्य पाठ्य-क्रम (केवल प्रथम दो वर्षों के लिए)।

(२) गणित सहित सामान्य विज्ञान का सामान्य पाठ्य-क्रम (केवल प्रथम दो वर्षों के लिये)।

स—निम्नलिखित में से एक शिल्प (Craft) —

(१) बरतई एवं कुनाई (२) लकड़ी का काम (३) धातु का काम (४) बरतई एवं कुनाई (५) दर्जी का काम (६) मुद्रण का काम (७) कमछाता का काम (८) माँहल बनाने का काम (९) निसाई के दस्तकारी।

### २—वैकल्पिक विषय (Optional Subjects)

अ—निम्नलिखित समूहों में से किसी एक समूह के तीन विषय —

समूह १—मानव विज्ञान (Humanities) समूह २—विज्ञान (Science) समूह ३—प्राविधिक (Technical) समूह ४—वाणिज्य (Commercial) समूह ५—कृषि (Agriculture) समूह ६—संज्ञित कलाएँ (Fine Arts) समूह ७—गृह विज्ञान (Domestic Science)।

ब—पाठ्य पुस्तकें (Text Books)

१ निर्धारित पाठ्य-पुस्तक का स्तर का ऊँचा उठाने के लिए एक सर्वोच्च पाठ्य-पुस्तक समिति (High Power Text book Committee) का निर्माण किया जाय।

- २ राष्ट्रीय सरकार पुस्तक वितरण का प्रविष्टि देने के लिए एक नई मर्यादा की स्थापना करे।
- ३ शिक्षा की विषय के लिए एक पाठ्य-पुस्तक निर्धारित न की जाय अपितु उस स्तर की पुस्तकें पर्याप्त संख्या में निर्दिष्ट की जायें।
- ४ पाठ्य-पुस्तक में छोटे-छोटे समय के उपरांत परिवर्तन न किया जाय।

#### ८ शिक्षण की प्रायोगिक विधियाँ (Dynamic Methods of Teaching)

- १ विद्यालयों में शिक्षण विधियाँ का उद्देश्य बच्चों की कुशलता पूर्वक जान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए अपितु छात्रों में उपयुक्त मूल्य (Desirable Values) उचित दृष्टिकोणों (Proper Attitudes) एवं कार्य करने की भावना का भी समावेश करना चाहिए।
- २ शिक्षण में मौखिक भाषा (Verbalism) एवं वक्तव्य करने का क्रिया (Memorization) पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, शिक्षण ऐसी परिस्थितियों के माध्यम द्वारा किया जाना चाहिए जो साधनात्मक (Purposeful), मूल (Concrete) एवं वास्तविक हों। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण विधियाँ में क्रिया-पद्धति (Activity Method) और योजना-पद्धति (Project Method) को स्थान देना चाहिए।

#### ९ धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा (Religious & Moral Instruction)

- १ धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है।
- २ यह शिक्षा विद्यालय में अध्ययन के समय न हो अपितु उसमें पूर्व या उसके उपरान्त दी जाय।
- ३ इस शिक्षा को प्रवृत्त करने के लिए शिक्षा छात्रों का वास्तविक न किया जाय।

#### १० चरित्र निर्माण की शिक्षा (Education of Character)

- १ छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी अध्ययन के विषय उत्तरदायित्व है। अतः स्कूल के प्रत्येक कार्य-क्रम में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाना चाहिए।
- २ उत्तम अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्रों में अतिरिक्त सम्पर्क स्थापित किया जाय।
- ३ अतिरिक्त पाठ्य क्रियाएँ (Extra-curricular Activities) की विद्यालयों में दी जान वाली शिक्षा का अतिरिक्त अर्थ समझ जान।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

- ४ सब स्कूलों में एन० सी० सी० फस्ट-एड और कूनिमर रड प्राप्त कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### ११ माग प्रदर्शन एवं समुपदेशन (Guidance & Counselling)

- १ यह आवश्यक है कि छात्र उद्योगों के विभिन्न व्यवसायों के क्षम प्रवृत्ति एवं महत्व की जानकारी प्राप्त करें। अतः विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित कार्यों के फिल्म तैयार किए जायें और उन्हें छात्रों को दिखाया जाय। साथ ही छात्रों को विभिन्न उद्योगों के कल-कारखानों में भेजा जाय।
- २ विद्यालयों में प्रचलित माग प्रदर्शन अधिकारियों (Guidance Officers) और आविकोपार्जन शिक्षकों (Career Masters) की नियुक्ति की जाय।

### १२ छात्रों का शारीरिक कल्याण (Physical Welfare of Students)

- १ सब स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा (School Medical Service) को उचित रूप से सज्जित किया जाय।
- २ विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सब छात्रों की प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से स्वास्थ्य-परीक्षा की जाय।
- ३ सभी रोगी छात्रों की विद्यालय-स्वास्थ्य-अधिकारी (School Health Officer) द्वारा निरीक्षा की जाय।
- ४ छात्रावास और निवास विद्यालयों (Residential Schools) में समुचित एवं पोष्टिक आहार की व्यवस्था की जाय।

### १३ परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्यांकन (Examination and Educational Evaluation)

- १ बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाय।
- २ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ढंग में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि परीक्षा निष्पक्षतापूर्ण ढंग की न रहे जाय।
- ३ छात्रों के काम का अन्तिम मूल्यांकन करते समय आन्तरिक परीक्षाओं (Internal Examinations) के साथ-साथ नियतकालिक परीक्षाओं (Periodical Tests) और विद्यालय-अभिलेख (School Records) की भी उचित महत्व प्रदान किया जाय।
- ४ बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षाओं में छात्रों के काम का मूल्यांकन संकाय में न किया जाकर प्रतीकमय (Symbolic) होना चाहिए।

## १४ अध्यापकों की उत्पत्ति (Improvement of Teachers)

- 1 अध्यापक का पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है। अतः विशिष्ट समितियाँ को नियुक्ति का काम, जो इस बात का सुझाव दें कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों को कितना वेतन दिया जाना चाहिए।  
अध्यापक को अपनी और अपने माधित सम्बन्धियों की विमताओं से मुक्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में त्रिमुखी साम-आजना कार्य नित की जानी चाहिए। इसके अन्तर्गत अध्यापकों को वेतन प्राविष्टेण्ड कण्ड और आबन-जोमा को सुविधाएँ दी जाएँ।
- 2 अध्यापक व बच्चा को नि-गुम्ब शिक्षा दी जाय विद्यालयों व समाज उनके निवास का व्यवस्था की जाय स्वास्थ्य वृद्ध व स्थाना-कम्पा शिक्षा-अध्ययन का भाग म जान व लिए उह विराये म रियायत और छुट्टी दी जाय तथा बिक्रिमासयो म सुपन इमाज की सुविधा भी जाय।

### उपसंहार

मुनासियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा व पुनर्गठन व मर्याद में जो सुझाव दिए हैं उनको प्रायः सभी शिक्षा विचारकों ने स्वागतार्थक और सामान्य माना है। उनका कथन है कि आयोग व अधिकांश सुझाव अति महत्वपूर्ण और इलायमीय हैं। यदि उनके अनुसार हमारा माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन कर दिया जाय तो हमारा रूप पूरुत परिवर्तित हो जायगा और देश व मर्यादा का हित बरक अलगाव का रूप का बन्धन बरगी। आयोग व अधिकांश सुझावों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार करके कार्यान्वयन कर दिया गया है।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Critically examine the recommendations of the Mudaliar Commission for the reorganization of Secondary Education in India
- 2 Discuss the pattern of Secondary Education as recommended in the Report of the Secondary Education Commission

## पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा (Education Under The Five Year Plans)

### विषय-प्रवेश

सतानिया स परतग्नता की श्रुतसाओ मे बन्दी भारत अगस्त १९४७ मे मुक्त हुआ । परन्तु विगत दो महायुद्धों की घोषण-नीति तथा देश के विभाजन न राष्ट्र क समस्त अति बटस समस्यायें उपस्थित कर दीं । उन समस्याओं का निवारण एवं देश की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितिया का पुनर्मकुटन करके ही स्वाधीनता के बरम लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव थी । अतः विश्व क अनेक समृद्ध तथा सम्य देशों के समान भारत न भी अपनी बिसारी हुई सतिया को एकत्र करने एक निश्चित दिशा मे अवसर होने और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का पूर्ण विचात करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त १९५१ मे अरनो प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यान्विता की । इसमें अन्य विषया के साथ साथ शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया ।

## प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा

### शिक्षा की दशा

१९५१ में भारतीय शिक्षा की स्थिति अति दायनीय थी। अनेक दोषों से युक्त होने के अतिरिक्त देश में साक्षरता का प्रतिशत बस १७.५ था। इससे स्पष्ट है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं। वस्तुतः ६-११ वर्ष की आयु के कुल ४० प्रतिशत ११-१७ वर्ष की आयु के कुल १० प्रतिशत और १७-२१ वर्ष की आयु के ०.६ प्रतिशत व्यक्तियों को ही शिक्षा का सुविधाय प्राप्त थी जब कि योरोप और अमेरिका में देशों में ८० से लेकर १०० प्रतिशत तक बालक-बालिकायें शिक्षा से लाभ उठा रहे थे। इससे अतिरिक्त उच्च शिक्षा को अनावश्यक अधिक महत्व प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव नगरा एवं ग्रामीण शिक्षा सुविधाओं की असमानता स्त्री शिक्षा की उपजा और प्रशिक्षण अभ्यासों की कमी आदि कुछ ऐसे बात थे जिनका निवारण अनिवार्य था। अतः भारतीय शिक्षा को जनतन्त्र का आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये शिक्षा का पुनर्गठन अति आवश्यक था। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में इस दिशा में प्रियारम्भ दृढ़ उठाया गया।

### शिक्षा-पुनर्गठन

योजना-आयोज (Planning Commission) ने भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन के सम्बन्ध में अघोषित निम्नलिखित मुख्य सिद्ध —

१. वैश्व एक समान शिक्षा के क्षेत्रों का प्रसार करना।
२. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का मबान रूप दक्ष सुम्बन्धित करना।
३. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा का देश की आवश्यकताओं के अनुसार मवीन रूप प्रदान करना।
४. स्त्री शिक्षा का विस्तार करना और सामील करना में स्त्री शिक्षा का अधिक से अधिक प्राप्ताह करना।
५. अभ्यास के प्रशिक्षण का समुचित व्यवस्था करना।
६. अभ्यास के शर्तों और उनके सेवा शर्तिका (Conditions of Service) में सुधार करना।
७. शिक्षा में विदेश दृष्टिकोणों का उपाय मन्त्रालय अनुदान कर के शिक्षा विकास एवं विस्तार करना।



## शिक्षा पर व्यय

अनुमान लगाया गया कि प्रथम योजना-काल में ६ १४ वर्ष की आयु के लड़के प्रतिशत बच्चों की शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने के लिये लगभग ४०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त २०० करोड़ रुपये वैज्ञानिक और हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा २७२ करोड़ रुपये स्कूलों के लिये अपने को असमर्थ पाया और योजना काल में १६६ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इन धन में से ४४ करोड़ केंद्रों द्वारा और १२५ करोड़ राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया गया। यह धनराशि इतनी अल्प थी कि इससे देश की समस्त शिक्षा सम्पत्ति आवश्यकताओं पूर्ण नहीं हो सकती थी। अतः सरकार ने जनता से अपील की कि वह धन घर-घर से जमा करके इस योजना के लक्ष्य

योजना आयोग की आशा थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक निम्नान्वित लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे —

- १ १९५६ से पूर्व ही ६ ११ वर्ष की आयु के ६० प्रतिशत बालकों को शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त हो जायेंगी।
- २ विद्यालयों में ६ ११ वर्ष तक की आयु वाली बालिकाओं की संख्या ४० प्रतिशत हो जायगी।
- ३ स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के लिये योग्य आयु के बच्चों की संख्या १५ प्रतिशत तक पहुँच जायगी और इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने वाला बालिकाओं की संख्या भी बढ़कर १० प्रतिशत हो जायगी।
- ४ सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में १४ ४० वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुषों को व्यावसायिक अर्थों में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की शिक्षा दी जायगी। इनमें भाग लेने वाले स्त्री एवं पुरुषों की संख्या कम से कम प्रत्येक १ और २० प्रतिशत होगी।

इन योजनाओं में विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

## समालोचना

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत मास्टर शिक्षा के विकास विस्तार एवं पुनर्गठन के लिए एक योजना का निर्माण करने अप्रैल १९५१ में उच्च

कार्यान्वित पर लिया गया। इस योजना में गुणों के माप-माप पाया जा प्रभाव ही नहीं प्रयुक्त हमने अनर्थ भी अनेक एमी बातें थीं जो दोषपूर्ण थीं। प्रथम योजना में शिक्षा के जो मन्त्र निर्धारित किए गए थे उन्हें प्राप्त करने में सफलता न मिली। द्वितीय हमने अग्रजों द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली के शोष का स्पष्ट चलेस करके भी उनके निवारण के लिये कोई रचनात्मक पद नहीं उठाया। तृतीय, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर रचनात्मक की ध्यान नहीं लिया गया। चतुर्थ योजना-आयोग ने शिक्षा का अर्थनायकत्व चिन्तिता प्रति सहानुभूति ध्यात करके भी उनके आर्थिक हित तथा सामाजिक सम्मान के लिये जो प्रयास किये, वे प्रायः नगण्य ही रहे जा सकते हैं। पञ्चम सावजनिक शिक्षा को साक्षरता के लिये आवश्यक बता कर भी आयाज न पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये हमने अन्य धनसहित लिये दिन की जा मजदूरी की बात कहा जा सकता है। अन्तिम हमारा उद्देश्य मुबारक रूप में नहीं लिया गया। साक्षात् रूपों का दुर्लभता किया गया। शिक्षा-सम्बन्धी अनेक कार्य उन्मादपूर्वक प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् तन्निष्ठ सी बाधा उपस्थित होान पर स्थगित कर लिये गये जिससे धन और शक्ति का भयकर नाश हुआ।

उपरिलिखित दोषों के बावजूद भी भारतीय जनता के हितों में शिक्षा के निर्माण का यह प्रथम प्रयास था। अनुभव अनुष्ण का सर्वोत्तम शिक्षा है। योजनाकारों ने शिक्षा-योजना के दोषों तथा त्रुटियों से एक नवान पाठ सीखा और अगले आधार पर द्वितीय योजना में उनमें सुधार कर शिक्षा के प्रकार एवं पुनगठन का दृढ़ संकल्प लिया। पञ्चवर्षीय यह प्रथम योजना की अन्तिम द्वितीय योजना में अधिक सफलता हस्तगत हो रहा है।

## द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा

### शिक्षा-पुनगठन

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का उद्देश्य—शिक्षा का साक्षरता के व्यवस्थापन में अनुष्ठान बनाना और भागीय शिक्षा प्रणाली में निर्माण के उद्देश्य के अनुसार करना था। इस प्रयास में बहुत अर्थिक व्यय हुआ प्राप्त हुई। योजना में जो अभाव था उसकी ओर रखा गया और आत्मसुख में आत्मकारिक भाषा में कहा था—‘संसार में कुछ धर्म था है और धर्म का हाना स्वाभाविक ही है क्योंकि संसार बहुत बड़ा बन रहा है।’ प्रथम योजना-काल में शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी। हमी बात का ध्यान में रखकर द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा के पुनगठन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। हमने शिक्षा-निर्माण के उद्देश्य निवारण किया गया —

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

- १ वैश्व तथा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना ।
- २ माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाकर उसका रूप परिवर्तन करना ।
- ३ कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर में सुधार करके उसको ऊँचा करना ।
- ४ प्राविधिक प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करना ।
- ५ समाज शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास के कार्य प्रमो को कार्यान्वित करना ।

## शिक्षा पर व्यय

प्रथम योजना में शिक्षा पर १६६ करोड़ रुपये व्यय किए गये थे । द्वितीय योजना में ३०७ करोड़ व्यय करने की व्यवस्था की गई । दोनों योजनाओं में व्यय का विभाजन निम्नोक्त तालिका से स्पष्ट है —

शिक्षा का स्तर	व्यय (करोड़ रुपयों में)	
	प्रथम योजना (१९५१—५६)	द्वितीय योजना (१९५६—६१)
प्राथमिक शिक्षा	८३	८६
माध्यमिक शिक्षा	२०	५१
विश्वविद्यालय शिक्षा	१५	५७
प्रौद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा	२३	४८
समाज शिक्षा	५	५
प्रशासन व विविध	११	५७
योग	१६६	३७७

## योजना के लक्ष्य

प्रथम योजना में शिक्षा के विविध क्षेत्रों में जितनी उपलब्धि हुई और द्वितीय योजना का बना मन्त्र या इगला विवरण अर्थात् जितना तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

विवरण

(क) विभिन्न वय-वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएँ—

१ (६-११) वय-वर्ग का प्रतिपात

२ (११-१४)

३ (१४-१७)

(ख) सहाय्य—

१ प्राथमिक बेसिक

२ पूरक बेसिक

३ मिडिल बेसिक

४ उच्चतर बेसिक

५ हाई—हायर सेकेंडरी

६ बहुउद्देशीय

७ हायर सेकेंडरी बना दिने जाने वाले हाई—स्कूल

८ विद्वत्विद्यालय

(ग) इ बीनियरियल विद्यालय—

१ डिप्लो देने वाले

२ डिप्लोमा देने वाले

(घ) टेक्नोलॉजी के विद्यालय—

१ डिप्लो देने वाले

२ डिप्लोमा देने वाले

१९५०-५१  
योजना में पूर्व

१९५५-५६  
प्रथम योजना

१९६०-६१  
तृतीय योजना

४२०

५१०

६२७

१३६

१६२

२२५

६४

६४

११७

२०६६७१

२७४०२८

३२६८००

१,४००

८३६०

१३८००

१३५६६

१६७७०

२२७२५

३५१

१,६४५

४५७१

७७८

१०६००

१२१७५

—

२५०

११८७

—

४७

११६७

२६

३१

३८

४१

४५

५४

६४

८१

१०४

२४

७५

२८

३६

३६

३७

## समालोचना

भारत-संस्कार न इस यात्रना की अवधि के लिए शिक्षा-मन्त्रालय अनेक रायप्रम निश्चित किये जिनको राष्ट्र के भविष्य के लिये सम्पन्न किया जाना था। देश के औद्योगिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये शिक्षा का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक था परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका। अमेरिका के समान हमारी यात्रना क अभिप्राय को न तो स्पष्ट रूप से समझा गया और न उसके कार्यक्रमों को ही निर्धारित किया जा सका। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें कोई निश्चित योजना नहीं थी। केवल कुछ छ विद्यालयों की स्थापना करने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने पाठ्य प्रमा में अधिक विषयों का समावेश करने और कुछ स्थानों पर शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान करने से शिक्षा को न तो पुनर्गठन किया जा सकता था और न इन कार्यों को योजना की राह ही दी जा सकती थी। तथ्य यह है कि योजनाकारों ने शिक्षा के विकास एवं विस्तार क अर्थ को रख मान भी नहीं समझा। फिर आर्थिक विकास को पूर्ण रूप से जनता की भलाई का गणन बनाने के लिए शिक्षा क कार्यक्रमों को आर्थिक योजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं दी गई। आर्थिक यात्रनाओं का स्थान सर्वोपरि था और शिक्षा-मन्त्रालय योजनाओं को गौण स्थान प्रदान किया गया। देश क सभी कुशल कार्य-कर्ताओं का ध्यान आर्थिक विकास पर केन्द्रित था। शिक्षा क क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे उनमें न तो पर्याप्त कार्य-क्षमता थी और न कार्य-यत्नता ही थी। ऐसी दशा में शिक्षा क कार्यक्रमों का असफल होना कोई आश्चर्य का बात नहीं थी।

आमापन ने कुछ अन्य दावा भी सत किया है। उनका कथन है कि शिरीय योजना में जन शिक्षा का निरन्तर करके माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को प्रगतिष्ठित एवं प्रदान किया गया। यही कारण है कि सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा क व्यय का ६३ करोड़ में घाट ८६ करोड़ कर दिया गया जब कि माध्यमिक शिक्षा क व्यय का २२ करोड़ से बढ़ाकर ३१ करोड़ और विस्तारित माध्यमिक शिक्षा क व्यय का ११ करोड़ से बढ़ाकर २७ करोड़ कर दिया गया।

योजना का एक अन्य दाव यह भी था कि प्रशासन पर होने वाला व्यय १७ करोड़ निरूपित किया गया था जब कि प्रथम योजना में यह व्यय कम ११ करोड़ था। प्रथम और शिरीय योजनाओं में शिक्षा पर होने वाला कुल

अधम प्रमाण १६६ करोड़ और २०७ करोड़ था, अर्थात् शिक्षा योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा १३८ करोड़ रुपया अधिक व्यय किया जा रहा था। इस धन में से लगभग आधा रुपया प्रशासन पर व्यय किया गया। यह बात बुद्धि का समझ से पर है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया ?

योजना आयोग ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि शिक्षा प्रणाली का मफल बनाने का नियम अध्यापकों के वजन में बुद्धि और उनके सेवा प्रतिबन्धों में सुधार किया जाना अति आवश्यक था। परन्तु वेद का विषय है कि अध्यापकों का नियम कुछ भी नहीं किया गया। शिक्षा-योजना पर एक अन्य दोषान्वेषण यह किया गया है कि हममें निरक्षरता का नाश करने का नियम कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया।

अन्त में हम यह कहना है कि कानि कानि बातें तो शिक्षा में नियोजना की आवश्यकता की पुष्टि सुनकर भी भारत-सरकार इन और पूर्णतया उपाधीन रही।

## तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

### शिक्षा-युनसूचक

प्रथम योजना प्रारम्भ होने का क्षण से शिक्षा की सुविधाओं में सभी स्तरों पर प्रगतिशील विचार हुआ है। परन्तु जब दृष्टि एक समस्या की विनामता, देश की जनशक्ति का विकास करने और ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न करने की आवश्यकता पर जाती है तब तब भी सोच कर देना आवश्यक प्रतीत होने लगता है। अब तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक यह है कि शिक्षा प्रसार कार्यक्रम का विस्तार करके हम प्रत्येक घर तक पहुँचाना है ताकि शिक्षा राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक शाखा में आयोजित विभागों को सम्बन्धित बन जाय। इसके निम्ने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

१. १ से ११ वर्ष तक के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा देना।
२. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में सुधार करना।
३. गुरुकुलों के शिक्षण का प्रसारण देना।
४. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

## शिक्षा पर व्यय

नीचे दी गई सारिणी में प्रथम द्वितीय और तृतीय योजनाओं में सामान्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये निर्धारित व्यय का अलग अलग ह्योरा दिया गया है।

शिक्षा का स्तर	व्यय (रुपये करोड़ में)		
	प्रथम योजना (१९५१-५६)	द्वितीय योजना (१९५६-६१)	तृतीय योजना (१९६१-६६)
१ प्राथमिक शिक्षा	८५	८७	२०६
माध्यमिक शिक्षा	२०	६८	८८
३ विश्वविद्यालय शिक्षा	१४	६५	८२
४ अन्य काय प्रोग्राम—			
गणित शिक्षा	—	४	६
सार्वजनिक शिक्षा पर युवक प्रयोग	१६	१०	१२
५ अन्य		१	११
योग	१	२०६	४०८
६ निर्धारित काय प्रोग्राम	०	४	१०
कुल योग	१३	२०	४१८

० प्रथम योजना में सार्वजनिक काय प्रोग्राम पर होने वाला व्यय अन्य काय प्रोग्राम में सम्मिलित कर दिया गया था।

### योजना के लक्ष्य

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में शिक्षा व विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों उत्पन्न हुई थीं। तृतीय योजना का क्या लक्ष्य है इसका विवरण नीचे की सारणी से स्पष्ट हो जाता है —

विवरण	१९२०-२१ योजना में पूर्व	१९२२-२६ प्रथम योजना	१९६०-६१ द्वितीय योजना	१९६२-६६ तृतीय योजना
(क) विभिन्न वय-वर्ग व वर्गों के लिये शिक्षा सुविधाएँ				
१ ६-११ वय वर्ग का प्रतिशत	४.०	४२.६	६१.७	७६.४
२ ११-१४ " "	१.७	२६.५	५.०	५८.६
३ १६-१७ " "	२.३	७.८	११.५	१७.६
(ख) साक्षरता				
१ प्राथमिक व बेसिक	२०६.७१	५७८.१४	१६०.००	६१४.०००
२ अनिवार्य बेसिक	३३.३७६	६२.६७१	१००.०००	१७०.०००
३ मिडिल बेसिक	१३.४६६	२७.७१०	६६.००	२३,७००
४ अनिवार्य बेसिक	३२१	६८४	११.६४०	१६,७००
५ हाई व हायर गैर-बेसिक	७५.८८	१०.८	१६.००	१७.०००
६ बटुवर्ग सीधे	—	२५४	२,११४	२,४४६
७ विवाचिकात्मक	२७	३५	४६	३८

### प्राथमिक शिक्षा

तृतीय योजना व अगले लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा की गम्भीर योजना व शिक्षा मंत्रालय ने ही बनाया जा सकता है। ६-११ वय-वर्ग के ७६.४ तथा ११-१४ वय



वर्ग के २८६ प्रतिशत बच्चा को ही शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा मरेगी। एक विचार यह है कि ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों की नियम पूर्वक विद्यालय जाने की सुविधाओं में शिक्षा को आगे भी जारी रख सकने के व्यवहारों की पर्याप्त वृद्धि कर दी जाय। इससे अतिरिक्त, थम एव नियोजन मंत्रालय भी एक ऐसी योजना तयार कर रहा है जिससे ११ वर्ष तक की आयु के शिक्षित बालकों को सरल ढंग का प्राविधिक प्रशिक्षण दिया जा सके। माना है कि चौथी और पाँचवी योजनाओं के समय ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को निरुत्तर एव अनिवार्य शिक्षा देने के लक्ष्य पूर्ण करने के उपाय किये जा सकेंगे और तब सावधान के एक निर्देश की पूर्ति हो जायगी।

प्रथम दो योजनाओं के समान तृतीय योजना में भी प्राथमिक विद्यालयों की वैश्विक प्रणाली से सम्बद्ध किया जा रहा है। किन्तु इसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता प्रशिक्षित शिक्षकों की है। अतः तृतीय योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। आजकल एक बड़ी समस्या में शिक्षकों की वैश्विक अध्ययन प्रणाली सिखाई जा रही है। जहाँ तक सम्भव होगा वहाँ तक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार वर्तमान संस्थाओं की सुधार कर किया जायगा तथा तृतीय योजना के अन्त तक विद्यालयों में सगे हुए कम से कम ८० प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित हो चुकेंगे शेष के लिये प्रशिक्षण के कम समय के क्रम प्रियादिन किये जायेंगे। एक विचार यह भी है कि तृतीय योजना के समय प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का समय बढ़ाकर गभीर रूप से २ वर्ष कर लिया जाय।

### माध्यमिक शिक्षा

तृतीय योजना में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इन तीन शिक्षाओं में किया जायगा — (१) विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि की जायगी, (२) तृतीय योजना के समय जो बहुउद्देश्य विद्यालय खुले थे उन्हें सुधारा जायगा तथा कुछ नवीन विद्यालय भी खोल जायेंगे, और (३) उच्चतर माध्यमिक प्रकार के कुछ नवीन विद्यालय खोल जायेंगे तथा वर्तमान माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर लिया जायगा।

तृतीय योजना की समाप्ति पर १६०० माध्यमिक विद्यालयों में से ११५०० में विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हो गईं थी। तृतीय योजना के अन्त तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर १८००० हो जाने की आशा है। मध्य यह कहा गया है कि प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के नियम

विशेष सहायता देकर तथा शिक्षा की प्रशिक्षित करके इन सभी विद्यालयों में सामान्य शिक्षा की शिक्षा प्रारम्भ कर दी जाय।

शिक्षा योजना की अवधि में १५५० माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देश्य विद्यालय बना दिये गये। इन विद्यालयों को प्रशिक्षित शिक्षक मिलने, विशेष कर हाथ के काम के विषय पढ़ाने वाले शिक्षक मिलने में कठिनाई होती है। अतः निम्नलिखित किया गया है कि कुछ पाठ्य-सहित बहुउद्देश्य विद्यालय खोलने के अतिरिक्त तृतीय योजना में विशेष बल पहिले से मुक्त हुए विद्यालयों को सुधारने तथा उत्तम करने और उनमें शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करने पर दिया जायगा। शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिये चार प्राथमिक प्रशिक्षण कनिष्ठ खोलने का निश्चय किया जा चुका है।

### विश्वविद्यालय शिक्षा

तृतीय योजना का एक महान् कार्य विज्ञान पढ़ाने की सुविधाओं का विस्तार करना होगा। तब यह रहता गया है कि इस योजना के अन्तर्गत विज्ञान के छात्रों का अनुपात लगभग ४० प्रतिशत हो जाय। विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षकों, दलीयकारी तथा अन्य प्राविधिक सरक्षाओं में छात्रों की उन्नति में वायव्यताओं आदि का बढ़ना इस माँग का पूर्ति करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है। यह सब सभी पूरा हो सकता है जब प्रयोगशालाओं की सुविधाओं में वृद्धि करने तथा अध्यापन के लिये योग्य व्यक्ति खोजने के प्रयत्न तीव्र हो आरम्भ कर दिये जायें। विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग इन समस्याओं का हल करने की ओर विशेष ध्यान दे रहा है।

इस योजना में जो नवीन कार्य-क्रम प्रारम्भ किए जायेंगे उनमें विज्ञान पढ़ाने की सुविधाओं में वृद्धि शिक्षकों की वृत्त-दूर-वृद्धि प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का सुधार, स्नातकोत्तर अध्ययनों तथा अनुसंधानों के लिये धन की व्यवस्था छात्रवृत्तियों एवं श्रद्धा देना छात्रावासों तथा शिक्षा के विशाल स्थान बनवाने के लिये सहायता देना प्रायोगिक सम्पादने सामान्य माध्यमिक विद्यालयों के लिये वन-अध्ययन द्वारा पढ़ाई की सुविधा करना और प्रयोग के लिये अनेक नवीन परियोजनाओं का आरम्भ करना आदि सम्मिलित है।

### प्राविधिक शिक्षा

तृतीय योजना के समय ४५ ००० स्नातक तथा ८० ००० डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता पड़ने का सम्भावना है। यह सब पूर्ण हो जाएगा। डिप्लोमा धारियों की आ मांगी क्या होगी, उन पूरा करा के फिर तृतीय योजना के आरम्भ में ही व्यवस्थित अभिहित वि-संगु-व्यापक का व्यवस्था का व्यवस्था।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

तृतीय योजना की अवधि में द्वितीय सत्र वाले छात्रों के वार्षिक प्रवेश में ६००० की वृद्धि कर देने का विचार है—५००० तो इजीनियरिंग कॉलेजों में प्रविष्ट करके तथा १००० का आंशिक समय में अथवा पत्र-व्यवहार द्वारा पढ़ा कर। जब वार्षिक दाखिला की संख्या १९६१ में १३२०० से बढ़कर १९६६ में १९२०० हो जायगी। इस प्रकार चौथी योजना के समय ७५००० इजीनियर स्नातकों की सम्भावित माँग इजीनियरिंग कॉलेजों से निकले हुए और आंशिक समय में अथवा पत्र-व्यवहार द्वारा पढ़े हुए स्नातकों को मिला कर पूरी हो जायगी।

इसी प्रकार डिप्लोमा लेने वाले छात्रों के वार्षिक दाखिलों की संख्या में १५०० की वृद्धि कर देने का विचार है—१००० को पोलिटेक्नीकों में प्रविष्ट करके तथा ५००० का आंशिक समय में अथवा पत्र-व्यवहार द्वारा पढ़ा कर। तब वार्षिक दाखिलों की संख्या जो द्वितीय योजना के अन्त में २५०० थी वह तृतीय योजना के अन्त तक बढ़कर ३६००० हो जायगी। इससे चौथी योजना के समय डिप्लोमाधारियों की सब माँग पूरी हो जायगी।

### सामाजिक शिक्षा तथा वयस्क साक्षरता

द्वितीय योजना में भारत-भरवार् में सामाजिक शिक्षा का विस्तार करने का आभोजन दिया है। अतः सरकार ने निम्नलिखित किया है कि सामाजिक शिक्षा तथा वयस्क गणगना का विभाग शिक्षा में यात्रा विधायक रूप से ग्राम के स्कूलों तथा ग्रामों एवं स्वयंसेवा समितियों में मिल जुनकर भी जाने वाली विस्तार कर पाइया कि रूप में किया जाना चाहिये। मोटे तौर पर यह सत्य होना चाहिये कि जहाँ एक बड़ा क लिये पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्षर होना चाहते हैं उनमें लिये प्रयास करना। एक शिक्षा उपकरणों के रूप में सब सुविधायें हमें प्राप्त होने का वयस्क अध्ययन का इस प्रयास में योग देना चाहिये। ग्राम पंचायतों और अन्य अभिन्नताओं का इस कार्य में पूरा योग देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा-मण्डलकर्त्ताओं का लक्ष्य शिक्षा-अधिकारियों और निजी शिक्षा संस्थाओं की मदद से मिल जुनकर आवश्यक स्थानीय संस्थाओं और निजी शिक्षा संस्थाओं को दना चाहिए। पत्र-व्यवहार में समितियों को ग्राम-पंचायतों और स्वयंसेवा संस्थाओं की मदद से शिक्षा एवं गणगना का करना आवश्यकताओं और अवस्थाओं के अनुसार निरन्तर विभाग बनाए रखना चाहिए। पत्र-व्यवहार का करना आवश्यकताओं और अवस्थाओं के अनुसार निरन्तर विभाग बनाए रखना चाहिए। पत्र-व्यवहार का करना आवश्यकताओं और अवस्थाओं के अनुसार निरन्तर विभाग बनाए रखना चाहिए।

वर्त्ताओं का योग प्राप्त किया जाय। बयस् साक्षरता व एक व्यापक कार्यक्रम व मुभावों पर आजकन विचार हो रहा है और आशा है कि तृतीय योजना की अवधि में इसमें उन्नतभनीय प्रगति होगी।

## समाप्तिचर्चा

पूराय योजना में शिक्षा के जिन कार्य-क्रमों का गल पृष्ठा में विवरण दिया गया है उसमें यह बात स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में आज शिक्षा के सभी अवस्था का सुव्यवस्थित करने का नया मोड़ है। हमारे देश में शिक्षा प्रयत्नशील है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने शिक्षा के जिन कार्य-क्रमों का निर्माण किया है वह असाध्यनीय है। इन कार्य-क्रमों में प्रमुख हैं — ६ व ११ वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था प्राथमिक तथा विद्वत्विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में विस्तार एवं सुधार प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा का विस्तार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के प्रगतिशील की सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार छात्रवृत्तियों की शिक्षा तथा अन्य सहायताओं में वृद्धि। इनके अनिवार्य कार्यावली की शिक्षा के अतिरिक्त उच्चतम व्यवस्था में जायगी और उनका अध्ययन की अन्य सुविधाओं प्रदान की जायगी। इस समय हमारे सभी कार्यावली के शिक्षा-मंत्रालय में जो कार्य है उसको हम किया जायगा। सभी प्राथमिक विद्यालय बन्दित स्तरों में परिवर्तित किए जायेंगे। विद्वत्विद्यालयों में छात्र-वर्षीय दिनों को भी पूर्ण रूप में प्रयोजित किया जायगा तथा स्नातकोत्तर और अनुसंधान सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार किया जायगा। इन सभी कार्यक्रमों की सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए पूराय योजना में शिक्षा पर निर्य जान बान व्यय की तृतीय योजना में कुल में अतिरिक्त तथा प्रथम योजना से तिगुने से अतिरिक्त कर दिया गया है। यह सभी कार्य शिक्षा में भारत-सरकार की प्रथम दृष्टि का प्रभाव है।

## उपसंहार

नहीं कहा जा सकता है। ६ से ११ और ११ से १४ और १४ से १७ वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या अभी क्रमशः ६१, २६ और १२ प्रतिशत है। जब इस वचन की कि—शिक्षा प्रजातन्त्र का प्रमुख आधार है और प्रजातन्त्र की सफलता बच्चों का शिक्षा पर जो देश के भावी नागरिक हैं निर्भर है—एक लक्ष्य साधे स्वीकार किया जाता है तो हम यह समते हैं कि सरकार ने जन जन के लिए शिक्षा का सुखम न बनाकर अपने दायित्व का पालन नहीं किया है।

### UNIVERSITY QUESTIONS

1. Write a critical note on "Education in India under the First and Second Five year Plans"
2. Discuss briefly the achievements in the following fields of education under the Third Five year Plan —
  - (a) Primary Education
  - (b) Social Education
  - (c) Secondary Education
  - (d) University Education and
  - (e) Technical Education

## नव-भारत में शिक्षा (Education in New India) (1947-1965)

### विषय प्रवेश

स्वातन्त्र्योत्तर काल में प्राथमिक माध्यमिक एवं विनवविद्यालय शिक्षा व अनिरित शिक्षा व अग्न्य क्षेत्रों में भी आगातान प्रगति हुई है और सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। इस प्रकार शिक्षा परिरक्षण नीचे दे रहे हैं।

### प्राथमिक शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा व प्रकार का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। १ जुलाई १९४७ का स्थापित की गई अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् (All India Council for Elementary Education) समझौता तथा राज्य-सरकारों को प्राथमिक शिक्षा व विकास एवं अनिवार्य निम्न प्राथमिक शिक्षा व समझौता में समझौता स्वरूप समझौता काय कर रही है। इससे समझौता स्वरूपता व उत्तरदायित्व का प्राथमिक शिक्षा व प्रगति की अखिल भारतीय मंत्रालय में जाना जा सकता है —

मान्यता प्राप्त

गान्धिका प्राथमिक शिक्षा की प्रगति —				
वर्ष	मान्यता प्राप्त स्कूला की संख्या	गान्धिका की संख्या	सिखावा का संख्या	धन्य (बराह रूपका में)
१९१०/११	६	६७१	५२६३६६७	३७ ६१८
१९११/१२	२	७८	१३१/२	६१६७
१९१२/१३	२	६६	७	६१ २४६
१९१३/१४	२	६६	७	६१ १०९ ६६६ ७ १५ १७७

गान्धिका प्राथमिक शिक्षा की प्रगति (Planning Commission)

योजना आयोग (Planning Commission) की शिक्षा पैनल (Panel)  
7 राज्य-निर्देशित निम्न एक अंशवाय शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया निर्धारित  
अविष्य को दो समान मंत्रालय करने का सुझाव रखा है (१) ६ न ११  
बचत कर बच्चों के लिये प्राथमिक और (२) १५ स १८ पर तक बच्चों  
के लिये माध्यमिक। प्रथम क्रम का ₹३६० ९ तक पूर्ण करने का प्रयास  
किया जा रहा है। साक्षरता निश्चित एक अभिवाय शिक्षा व कार्य-क्रम का  
संपन्न तथा व्यापक रूप प्रदान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने द्वितीय  
पंचवर्षीय योजना का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अध्यापकों का तालिम मध्याह्न  
उपलब्ध करने की एक योजना बनाई है। इस योजना में अनुसार वर्तमान प्रति  
क्षण संस्थाओं की सामर्थ्य बढ़ाई जायेगी और साथ ही महाविद्यालय नवीन संस्थाओं  
का विभागात्मक विकास कायमा। प्रतिष्ठान का सुविधाओं का विकास के लिये  
विभिन्न अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उपाय सरकार राज्य  
को शान्तिपूर्ण आधार पर अनुदान देती है।  
बैतिक शिक्षा

तृतीय योजना में १७७६० प्राथमिक विद्यालयों का वसति स्त्रुता में परिवर्धित करने कायान विद्यालयों का वसति हाँव न उग पर मान मभा प्रशिक्षण स्यादा का वसति प्रमाणों न आधार पर पुनर्गठन करने नगर क्षेत्र में वैकल्पिक स्त्रुता वास्तव और वैकल्पिक शिक्षा का हर स्थानीय अनुपात न विकास कार्यो स सम्बन्ध करने की व्यवस्था है।  
वसति शिक्षा के क्षेत्र में अहम

यदि विश्वास न हो तो अब तो आप्रवास ही है उम्मीद बिना





# भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

## स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा की प्रगति —

वर्ष	मायता प्रा.न. स्कूलों की संख्या	पढ़ाई की गयी शिक्षा का समय	अध्यय (बराबर रूप में)
१९१०-११	६,६७,११८	२३,६७,७७७	३६,६६
१९११-१२	७,७७,१३२	६,७६,७७७	५३,७७
१९१२-१३	८,८८,१४६	७,८७,७७७	६४,८८

योजना आयोग (Planning Commission) की शिक्षा पैनल (Panel) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। (१) ६ म ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक और (२) ११ म १६ वर्ष तक के बच्चों के लिए माध्यमिक। प्रथम क्रम में १९६५-६६ तक पूर्ण करने का प्रयाग किया जा रहा है। सावजनिक शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम का सफल तथा व्यापक रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने तुनीय पंचवर्षीय योजना का अर्वाय में प्राणित अध्यापकों का पालन करना एवं उपलब्ध करने की एक योजना बनाई है। इन योजना के अनुसार वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखकर आवश्यक जावगी और साव हो सहाय्य नवान सन्ध्याओं का विचार किया जायगा। प्रगति का सुविधाओं के विकास के लिए को धन प्रगति का आधार पर अनुदान मिले है।

### बैसिक शिक्षा

तुनीय योजना में १९७७-७८ प्राथमिक शिक्षा का बसिक स्कूलों में परिचालित करने के समान विद्यालयों का बसिक ढांचे के रूप में समान प्रगति मन्त्रालय का बसिक प्रगति के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए मन्त्रालय के समान और बसिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय मन्त्रालय के विभाग कावों से सम्बन्ध करने की व्यवस्था है।

बसिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक आ प्रगति हुई है उम्मीद है कि यह विभाग

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद वैश्व शिक्षा की प्रगति —

वर्ष	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
स्कूलों की संख्या :			
प्रिमरी शिक्षा	३३ ३७६	६ ६७१	५६ १६७
सीनियर प्रिमरी	५१	६६७	८४४
छात्रों की संख्या			
प्रिमरी शिक्षा	२८ ६- ८०	३ ६ ६	४३ ८० १६५
प्रिमरी शिक्षा	६६ ६८२	२६ ७ ८	२ १० १०६
व्यय करोड़ रुपये में			
प्रिमरी शिक्षा	३ ६६	११	१२ १८
सीनियर प्रिमरी	२१	४०	७३२५

केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षा का प्रगति में विशेष रूप से योग दिया जा रहा है। जो राज्य वैश्व शिक्षा का प्रचार करता था, उनका केंद्रीय सरकार किए जाने वाले व्यय का ५० प्रतिशत बांटा जाता है। उनका केंद्रीय में होता है। जो राज्य प्राथमिक शिक्षा को वैश्व प्राथमिक शिक्षा का रूप देना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सरकार कुछ व्यय का ७५ प्रतिशत देती है। नवीन वैश्व शिक्षा को स्थापना में दिए गए व्यय का ५ प्रतिशत भार केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केंद्रीय सरकार में वैश्व शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक स्थायी समिति (Standing Committee of the Central Advisory Board of Education on Basic Education) का है।

माध्यमिक शिक्षा

केंद्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा में पुनर्गठन एवं उद्यम गुंथार करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचारित अनुसार सरकार ने १९५५ में अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद (All India Council for Secondary Education) की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का प्रचार करना और इस शिक्षा के सम्बन्ध में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सम्पर्क स्थापना है। माध्यमिक विद्यालयों के प्रगति के लिए शिक्षा में अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति (Central Institute of Education) को विस्तृत किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों की पालन-पोषण में सहायक के निमित्त शिक्षा में केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो (Central Bureau of Text Books Research) का स्थापना का है। इस अनुसंधान ब्यूरो द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रचार किया जा रहा है।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

Institute of English) स्थापित किया गया। इस सस्था में अँग्रेजी शिक्षण क सम्बन्ध में अनुसंधान काय और शिक्षकों का प्रतिशोध किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने प्रास्ताविक के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा में जो प्रगति है उसका अनुमान नीचे की तालिका में लगाया जा सकता है —

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	व्यय (करोड़ रुपये में)
१९२०-२१	२० ८८४	५२ ३२० ६	२ १२ ०००	३० ७४
१९४५-४६	३२ ५६८	८५,२६ ५ ६	३,३८,३३३	५३ ०२
१९५८-५९	५३ ३०२	१ ४० ७८ ३३४	४ ७१ २०७	८१ ६३

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन भारत समय एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर सामने रखा गया है कि इसका क्रियाकालित चिन्तन तथा व्यावहारिक शिक्षा की ओर कर दिया जाय। इसमें लिये ० उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्यक्ष शिक्षण मिलाना और सब बहुत उद्देशीय विद्यालयों में कारखानों के काम करवाना आरम्भ किया जा चुका है। हमारे देशों में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन और विकास का काम-सम पूरा किया गया है उनका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य का विस्तार करना और इसे शिक्षा क्रम का अन्तगमन एक पूर्ण इकाई बनाना है। इसमें लिये जो कदम उठाये गये हैं वे हैं हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलना बहुत उद्देशीय स्कूलों का विकास जिनमें कई वैशिष्ट्य विषय पढ़ाने की व्यवस्था है। विज्ञान पढ़ाने की सुविधाओं का विस्तार और सुधार और व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी निर्देशन की व्यवस्था परीक्षा और प्रवेशन प्रणाली में सुधार व्यावहारिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, बालिकाओं और विद्यार्थी जातिवर्ग की शिक्षा-सुविधाओं में विस्तार योग्य छात्रों की छात्रवृत्तियों द्वारा प्रोत्साहन इत्यादि।

## विश्वविद्यालय शिक्षा

वर्तमान प्राप्ति का उदरान विश्वविद्यालयों की संख्या में स्थापनाय कृति हुई है। देश का विभाजन से पूर्व भारत में २१ विश्वविद्यालय थे परन्तु उक्त उदरान १६ रहे गये। उस समय में सरकार आज तक २१ नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। इस प्रकार अब हमारे देश में ४० विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान भारत में हम शिक्षा की प्रगति का अनुमान अंग्रेजों की शिक्षा से लगाया जा सकता है —

विश्वभारत में शिक्षा की प्रगति

नव भारत में शिक्षा

१०१

वर्ष	वर्ष प्रमाण	१ व प्रमाण	विश्व शिक्षा	मध्यम शिक्षा और उच्चतर शिक्षा	उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा	विश्व शिक्षा	अध्ययक	वर्ष (करोड़ रुपया में)
१९१०-११	२७	१८	१२	२०८	११८	४०३/१६	७४ १२३	१७६८
१९११-१२	२७	१४	११२	३३६	७१२	६८१/७६	७८६५	२६७१
१९१८-१९	१०	१४	११२	४२८	८७३	८६५/६६६	४५५३१	६२८१

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त विन्धविद्यालयों एवं कालेजों में छात्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। १९५८-५९ में इनकी संख्या ८६५ ६९६ थी, जबकि १९५०-५१ में ४०३ ५१९ ही थी। इन आँकड़ों से ज्ञान होता है कि हम क्षत्र में जितनी क्षमता व्यर्थ जा रही है। विश्वविद्यालय एवं कालेजों की शिक्षा के प्रकार को उन्नत करने एवं अपभ्रष्ट को गौर्नने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ उपाय कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा में विविधतायुक्त शिक्षा के प्रवर्तन में कठिनाई कमिजों से छात्रों की भीड़ कुछ कम हो जाय। यह भी प्रश्न उपायगत हुआ है कि गार्जनिंग महाशाला में भागों को टाटा में किसी सीमा तक हिस्से पर निर्भर किया जाय या बिना कुल ही न किया जाय? इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति विचार कर रही है। विश्वविद्यालयों के छात्रों का बलिष्ठ जिनमें से अनेक से मानविक अमलौषजनक है एवं और महत्वपूर्ण समस्या उपस्थित करने के और केन्द्रीय सरकार इस पर भी विचार कर रही है। यह बात निश्चित है कि माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय परिवर्तन में विन्धविद्यालय की शिक्षा का वृहत्तर उद्देश्य अपेक्षित प्राप्ति होगी और इस प्रकार राष्ट्रीय नियामक अधिक गहराई तक विनयेगी।

ग्रामीण उच्च शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान सर्वप्रथम १९४९ के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने आवृत्ति किया। आयोग के सुझाव के अनुसार भारत सरकार ने अक्टूबर १९५१ में ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति (Rural Higher Education Committee) का स्थापना की। समिति ने ग्रामीण शिक्षा में परिवर्तन करने वाली महाशाला की स्थापना इन्स्टीट्यूट्स (Rural Institutes) में परिवर्तन करने का विचारण की और इनके राष्ट्रीय स्तर के विषय में निर्माणात्मक सुझाव दिए।

१. ग्रामीण महाशाला के लिए ३ वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम।
२. शिक्षण डिप्लोमा (Teaching Diploma) के लिए १ वर्ष का कार्यक्रम।
३. शिक्षण सर्टिफिकेट (Teaching Certificate) के लिए १ वर्ष का कार्यक्रम।
४. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Rural Health Workers—Women) के लिए २ वर्ष का सर्टिफिकेट कार्यक्रम।
५. औद्योगिक के लिए २ वर्ष का सर्टिफिकेट कार्यक्रम।
६. दूरि विज्ञान के लिए २ वर्ष का सर्टिफिकेट-कार्य।

समिति की सिफारिशों के अनुसार १० गस्त्याओं की 'रूम इस्टाब्लिशमेंट' में परिवर्तित कर दिया गया है और उताने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है। ग्राम-सेवाओं के डिप्लोमा की विनियमितता का मध्यप्रदेश विधायक सभा ने मान्यता प्रदान हो चुकी है। रूम इस्टाब्लिशमेंट का ७३,०५८५२ साक्षर स्तर का अनुमान की एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ७०८ विद्यालयों के लिए ३०५०४५१ साक्षर स्तर की छात्रवृत्ति के लिए जान की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। ग्रामीण उच्च शिक्षा का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन (Ford Foundation) ने मान्य सरकार का ८१८१ लाख रुपये लिए हैं।

### स्त्री शिक्षा

केंद्रीय सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई ददाभुस का अध्यक्षता में गई ६५८ में स्त्री शिक्षा का राष्ट्रीय समिति (The National Committee of Women's Education) का नियुक्ति की। समिति का उद्देश्य स्त्री शिक्षा में सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर अपने सुझाव देना था। समिति ने जनवरी १९५६ में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निम्न मुख्य सुझाव शामिल हैं:

१. स्त्री शिक्षा का स्तर का सम्बन्धों में प्रमुख स्थान प्रदान किया जाना चाहिये।  
पुरुषों जैसे शिक्षा में भी आवश्यकता है उस सामान्यीकरण को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये। शाला की शिक्षा में स्थायी स्थापित करना सरकार का कर्तव्य है।  
राष्ट्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा का पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए और स्त्री शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए एक योजना बनाई जाए जिससे समस्त में पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके।
२. केंद्रीय सरकार समस्त राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित कर और उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों की अधिक सहायता दे।
३. स्त्री शिक्षा के विकास में स्त्री शिक्षा का एक पूर्ण विभाग स्थापित किया जाना चाहिये।
४. प्रत्येक राज्य में स्त्री शिक्षा के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को स्त्री शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार देना चाहिए।
५. सामान्य शिक्षा में स्त्री शिक्षा के समावेश और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास का पूर्ण ध्यान सरकार को देना चाहिए।

८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना धन स्त्री शिक्षा के लिये निर्धारित किया गया है उसके अतिरिक्त १० करोड़ रुपये और खर्च किये जाय।

१९५६-६० में बालिकाओं की शिक्षा व विभिन्न क्रमा तथा वयस्क स्त्रियाँ की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार की परामर्श देने के लिये महिला शिक्षा की एक राष्ट्रीय परिषद् स्थापित की गई है। शिक्षा मन्त्रालय ने महिलाओं की शिक्षा के लिये एक विशेष व्यवस्था का है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायगी। राज्य-सरकारों की परामर्श लिया गया है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग में एक उप निदेशक अथवा समुक्त निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये जिसका कार्य—बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा में सम्बन्धित विशेष कार्य-क्रम बनाना और कार्यान्वित करना होगा। १९५६-६० के बजट में बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार तथा प्रारम्भिक स्तर पर अध्यापिकाओं व प्रशिक्षण के लिये बजट द्वारा आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत ७०५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें अतिरिक्त, बालिकाओं तथा वयस्क महिलाओं की शिक्षा के एक विशेष कार्य-क्रम के लिये 'राष्ट्रीय परिषद्' की सिफारिशों का अमल में लाने के लिये शिक्षा मन्त्रालय द्वारा एक विशेष व्यवस्था किया जाने का विचार है। यह विशेष व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना का अंश होगी।

## विवेकशून्यता की शिक्षा

(Education of the Handicapped)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में विवेकशून्यता की शिक्षा की बहुत कम व्यवस्था थी। अर्थात् की शिक्षा के लिये कलकत्ता में २ विभाग में २, बम्बई में ४ मध्यप्रदेश में १ मद्रास में ६ पंजाब में २ उत्तर प्रदेश में ६ अजमेर में १ और गुजरातवाण ( सिन्धी ) में १ स्कूल था। इनके अनिश्चित भूगोलों और बहुरा के लिये ३३ मानसिक दुबलता वाला के लिये २ और कोटियों के लिये २ स्कूल थे। १३ सुधार-गृह (Reformatories) भी थे। इन स्कूलों में विवेकशून्यता का माध्यमतायुक्त बुद्धि के बालों के लिये काम करती बनाने आदि की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात् की ब्रैल लिपि (Braille Code) द्वारा क्रिया आदिमात्र १९४१ में ही शुरू था। मिशनरी पढ़ने का भी शिक्षा दी जाती थी। पन्ना के अर्धों के स्कूल में टाइप राईटिंग की शिक्षा की व्यवस्था थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राज्यों के शिक्षा मन्त्रालयों एवं शिक्षा विभागों ने विवेकशून्यता की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया। मई मास १९५२

में भारतीय बाल कल्याण परिषद् (Indian Council of Child Welfare) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बाल-कल्याण व छत्र में अनुसंधान करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था समाज-कल्याण बोर्ड (Social Welfare Board) है। यह बिगोर अपराधिया विकलांग एवं बाल-कल्याण के कार्यों की देखभाल करता है। मार्च १९५५ तक बाङ्ग ने देश की विभिन्न बाल कल्याण संस्थाओं को १५ लाख रुपये दिये।

एक राष्ट्रीय परामर्श परिषद् सरकार का विकास की शिक्षा प्रणिाल एवं नियोजन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है। उच्चतर शिक्षा अधिकाधिक अधिकाधिक व्यावसायिक प्रणिाल व नियमों के अन्तर्गत एवं विकास छात्रों की छात्रवृत्तियों को जानी है।

देहरादून व अन्य (श्री) प्रणिाल वन्द में लगभग १५० व्यक्तियों को स्नानार्थी प्रणिाल दिया जाता है। अन्य व्यक्तियों व लिये एर वामदिनाङ्क स्नानर कुर्सी १९५४ से मद्रास में कार्य कर रहा है।

अक्टूबर १९५० में देहरादून में स्थापित केन्द्रीय वन्द मुन्नालय द्वारा भारतीय भाषाओं में वन्द ग्राह्य प्रकाशित किया जाता है। अन्धे वामक भाषिकों व लिये जनवरी १९५६ में स्थापित एक स्कूल में शिक्षणार्थ एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अन्तर्गतका इसकी धार्मिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

१९५५-५६ में भारत में ५३४ स्कूल विकलांग व लिये के दिन पर २३६६ वन्द माग न्याय व्यय किया जा रहा था।

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. The idea of Rural Universities has recently gained much favour with the Indian leaders. Bearing in mind the recommendations of the Radhakrishnan Commission outline a scheme to make the idea a real success in the country.
2. Write a brief account of the progress of Women's Education from 1947 to 1963.
3. Write a note on The National Committee on Women's Education.
4. Describe briefly the progress of Primary Secondary and University Education in free India.





**भारतीय शिक्षा को समस्याएँ**  
**(Problems of Indian Education)**



## प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

### विषय प्रवेश

अपने युग के महान् अंग्रेज लेखक रस्किन (Ruskin) के अप्रतिष्ठित एक शिक्षा ज्ञान का मर्मक आलापन करने रहेंगे। शिक्षा का अभिप्राय व्यक्तिगतता का उन बातों की शिक्षा ज्ञान नहीं है जिन्हें वे नहीं जानते हैं। शिक्षा का अभिप्राय है उनको सग प्रचार का व्यवहार करने की शिक्षा देना जगा कि वे नहीं करते हैं।<sup>1</sup> हम अपने ही अपने को प्रगतिशील आधुनिक तथा सम्यक कहें परन्तु हमारे मूलिक आत्मा में बड़ी परिवर्तन नहीं हुआ है। आज का मानव उसी प्रचार की समस्या उपस्थित करता है जैसा कि प्राचीन मानव करता था। हमने अपने बाह्य आचरण का परिवर्तन कर लिया है परन्तु हमारा स्वभाव वही है। वह अधिक सुन्दर और आकर्षक करने पारस करता है परन्तु फिर भी वह प्राचीन मानव से भिन्न नहीं है। अपनी साम्यता का चरम धाम पर पारसाल देना व सुरक्षा के लक्ष्य का निश्चय पुष्टा में ऐसे अवश्य अन्तर्गत किए

1 Education does not mean teaching people to know what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. —John Ruskin Quoted by Sir Richard Livingstone S. — Talk for F24 June p 24

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

हैं जिनकी समानता इतिहास में प्राप्त होना असम्भव है।<sup>1</sup> अतः आज के प्रजातन्त्रीय युग में सब महान् आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया जाय और उसे प्रजातन्त्र राज्य का सुयोग्य नागरिक बनाया जाय। एक उत्तम नागरिक के रूप में उसे दूसरा के साथ रहना और उनका अधिकारा तथा भावनाओं का आदर करना सीखना है। उसे समाज की प्रगति में योग देना है अथवा समाज का जीवित रहना असम्भव है। समाज के विनाश में हमारा विनाश भी अवश्यम्भावी है।

आज हमारा देश भा एक प्रजातन्त्र राज्य है और उसको सफल बनाने के लिए उत्तम एक आत्मा नागरिकता की शिक्षा देना अनिवार्य है। इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत की केवल २३.७% जनसंख्या साक्षर है।<sup>2</sup> भारतीयों को एक विपक्ष स्तर तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दी उन्हें देश में योग्य नागरिक बनाने की आशा की जा सकती है और भारत को सफल प्रजातन्त्र बनाने का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय मन्त्रिमण्डल में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत इस राष्ट्रियान के कार्यान्वित किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु का पूर्ण नहीं कर लेते निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।<sup>3</sup> यह शिक्षा वैश्विक प्रसार की होगी। इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का मन्त्र निर्मित किया जाएगा। हमारी सरकार इस शिक्षा में मन्त्रिय पग उठा रही है। इसकी पुष्टि इस बात में होती है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ६ से ११ वर्ष वाले बच्चों (Age Group) के बस ३० प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे परन्तु तत्पश्चात् पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन वर्ग के ७६.८ प्रतिशत तथा ११ से १४ वर्ष वाले बच्चों के ६ प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।<sup>4</sup>

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को प्रेरित कर रही है। जो राज्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उनका।

- 1 In the last years the West at the height of its civilization has seen human nature guilty of crimes to which history has no parallel.—Sir Richard Livingstone op cit p 27
- 2 First Year Book of Education p 913
- 3 The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for the free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.—Article 51 of the Constitution of India
- 4 Third Five Year Plan p 574

केंद्रीय सरकार किए जाने वाले काम का व्यय का ३० प्रतिशत प्राथमिक महाविद्यालय अनुदान के रूप में देती है। अन्य प्राथमिक शिक्षा में प्रगति का अध्ययन हुई है परन्तु उस उपायकक्ष के नहीं कहा जा सकता है। मगर प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से अनेकों समस्याएँ बाधाएँ और कठिनाइयाँ हैं, जिनकी उत्तरस्थिति में शिक्षा का समय तथा व्यक्ति प्रसार कठिन ही नहीं अपितु असम्भव प्रतीत होता है। इस प्राथमिक शिक्षा की इन समस्याओं और उनके समाधान पर माथे प्रकाश डाल रहे हैं।

## समस्याएँ और उनका समाधान

(Problems and Their Solutions)

### १. समस्या - सरकार की दोषपूर्ण नीति (Faulty Policy of Government)

१९२० में स्वतंत्र भारत के संविधान में घोषित किया गया था कि १० वर्ष की अवधि में ६ से १४ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जायगा। परन्तु यह बात विषय है कि सरकार द्वारा इस शिक्षा में अभी तक अति ग़ुन ग़ुन सफलता प्राप्त की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ६ से ११ वर्ष के बच्चों के ३० प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वर्ष १९६६ के अन्त तक यह प्रतिशत ७६.४ हो जायगा और १९ से १४ वर्ष के बच्चों के ८६ प्रतिशत बच्चे के लिए शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो जायगा। ये दोनों ही बातें इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि सरकार घोषित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार का नीति आदर्शवाद पर आधारित है। शैक्षिक शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। इसी व्यवस्था में प्रारंभ होकर प्राथमिक शिक्षा को शैक्षिक स्तर पर परिचित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु मगर इन शिक्षा व्यवस्था के अन्त में अभी तक का प्राथमिक अभाव है शैक्षिक स्तर का अध्ययन योजना को क्रियात्मक करना दुष्कर है। सरकार ने जो इस समस्या को दूर करने का अनुमान करके यह बात स्वीकार कर ली है कि ग़ुनग़ुनी बात में कुछ ही समय में शैक्षिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वयन करना सम्भव नहीं है। परन्तु फिर भी सरकार प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिए जाने वाले काम के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक शिक्षा पर ध्यान कर रही है। एकीकृत शिक्षा में हम बचने नहीं चाहते हैं कि सरकार की नीति अब भी आदर्शवाद पर आधारित है और वह स्तर स्तर शिक्षा के अन्त में प्राथमिक शिक्षा के अन्त में कि शैक्षिक व्यवस्था में



भा उमा पर है। फिर शिक्षा के प्रति सरकार का उदासीनता का कारण समझ में आना कुछ कठिन प्रतीत होता है। यदि सरकार इन राजनैतिक रूढ़ियों की उपस्थिति में देश के औद्योगिकरण आवागमन व भाषा के प्रसार आदि कार्य का कर सक्ता है तो शिक्षा के कार्य से उम्मेद क्या है? कारण जैसा कि सपेदन में लिखा है यह समझ में आता है भारत के राजनैतिक स्थिति अनिवार्य शिक्षा-योजना का कार्यान्वयन पीछे डी पाहूनी है परन्तु राजनीति हमारे लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं है। इस आवागमन से व समा मुक्त हो सकता है जब व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के प्रति अपना पूर्ण ध्यान दे।

### ३. समस्या—दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन (Faulty Administration of Education)

भारत के अधिकांश राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका तथा जिला परिषदों पर है। जब यह कार्य उम्मेद सौंपा गया था तब यह आशा की गई थी कि समय शिक्षा का प्रसार अधिक तीव्र गति में होगा। परन्तु समय की गति ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ। साधारणतः इन स्थानों में स्थानीय समस्याओं में काम लगाने की प्रवृत्ति तथा धन का अभाव है। वे अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य बहन करने के लिए स्थानाधिकार दे सकती हैं परन्तु उमा करने में पर्याप्त मध्यम आधारा निर्वाचन में अपना पक्ष रखा करने के विचार में संतुष्ट हो उठा है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सभी अधिनियम समयानुक्रम में लागू प्रारंभ हो गए हैं। फिर ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो स्थानीय समस्याओं का उद्देश्य कार्यान्वयन करने के लिए कार्य करे। ऐसा स्थिति में व अधिनियम बल में नहीं आ पाए हैं। इससे अनिश्चित प्राथमिक विद्यालयों का संख्या में भी वृद्धि हो गई है परन्तु उनमें अनुपात में शिक्षा निशिक्षा का वृद्धि नहीं हो गई है। शिक्षा प्रशासन के ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था अनेकानेक शिक्षा के माध्यम में सन्तुष्ट बाधक सिद्ध हो रहा है।

### समाधान—शिक्षा प्रशासन में सुधार (Reform in Administration of Education)

इस समय प्राथमिक शिक्षा का भारत में स्थानीय समस्याओं के कारण है परन्तु इन समस्याओं की उदासीनता तथा अगम्यता के कारण प्राथमिक शिक्षा के प्रसार



भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ  
है। नागरिक

का गति अत्यंत मन्द है। नागरिका को शिक्षित करने का भार रास्ट के ऊपर होता है। अब यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के पुनोद्धार का भार सरकार स्वयं अपने ऊपर ले। यदि बिन्ही कारणा का सरकार इस उत्तरदायित्व का नया सम्भाल सकती है तो उसे एक तभी प्रगतिशील राष्ट्रीय सम्था स्थापित कर लनी चाहिये जो एक निश्चित अवधि में शिक्षा परिषदा तथा नगर पालिकाओं का अपने क्षेत्त्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का नियम बाध्य करे।

४. समस्या—शिक्षकों का अभाव।

४ समस्या—शिक्षकों का अभाव (Dearth of Teachers)

प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य बनान में शिक्षकों की वांछित सम्पत्ति उपलब्ध न होने व कारण सरकार व समक्ष तन्त्र अति जटिल समस्या उपस्थित है। अनुमान लगाया गया है कि शिक्षा की अनिवार्य बनान के लिये २८ लाख शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु इनमें से १९५८-५९ में केवल ९५५ २४० शिक्षक ही उपलब्ध थे। १९५१-५६ में प्रति शिक्षक के पास औसत रूप में शिक्षा देने के लिये ३ छात्र थे। नगर विद्यालयों की अपेक्षा ग्राम विद्यालयों में शिक्षकों का अधिक अभाव है। शिक्षकों की वांछित सम्पत्ति न होने तथा विद्यालयों में उनका अभाव होने का प्रमुख कारण यह है कि नव युवकों के लिये अध्यापन कार्य आकर्षक नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन इतना निम्न है कि किसी योग्य तथा सुविद्यित नवयुवक का ध्यान उधर आकृष्ट हो नही होता है। नगरों में तो उनको घनोपाजन के अर्थ साधन प्राप्त रहते हैं परन्तु ग्रामों में इस बात की जाणा करना अशक्य है। इस प्रकार ग्रामों में अध्यापन का अभाव है। इन्हीं सब बातों का विचार करके मुझे अध्यापन प्रवर्धन योजना का अभाव नगरों में सुगम जीवन व्यतीत करने के अर्थ उत्तम साधन उपलब्ध होना है। इन्हीं सब बातों का विचार ही नहीं करती है जब तक एक ग्राम विद्यालयों में कार्य नहीं करना पड़ता है। जहाँ नगर विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है वहीं ग्रामों में न हो जिससे कि ग्रामों में शिक्षा का अभाव होता है। इस अभाव की उपस्थिति में प्राथमिक शिक्षा का अभाव होता है। इस अभाव की उपस्थिति में प्राथमिक शिक्षा का अभाव होता है।

1 First Year Book of Education, p 935  
2 Education in India 1955-56 p 71

First Year Book of Education, p  
2 Educ in India 1955 56 p 71

## समाधान—अध्यापकों की पूर्ति (Supply of Teachers)

शिक्षा की अनिवार्य बनाने के नियम शिक्षकों की याचिका मर्यादा उत्पन्न । नही है परन्तु इस समस्या का समाधान किया जा सकता है । प्रारम्भ में न्यूनतम स्तर पर आवश्यक योग्यताओं के शिक्षकों को बना जा सकता है । बाद में अप्रतिष्ठित हो गया न हो । उनमें से प्रतिवर्ष एक निश्चित मर्यादा का विद्यापत्र बनने अपना योग्यताओं का प्रमाण के नियम प्रामाणिक किया जा सकता है । अथवा उन्हें राज्य स्तर पर प्रशिक्षण विद्यालयों में भी । प्राप्त करने के लिए भेजा जा सकता है । अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक कि उचित शिक्षा । उचित सहायता उपलब्ध न हो जाय विवरणों का कार्य नहीं किया जा सकता है । सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों का अधिक बर्तन और सुविधायक तथा अधिक सम्मान प्रदान करके अध्यापन कार्य के प्रति आकर्षित किया जाय ।

## ५ समस्या—शिक्षण का निम्न स्तर (Low Standard of Teaching)

प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण अध्यापकों की स्थिति है । १९६०-६१ में विद्यालयों में ६ १०००० व्यक्ति अध्यापन कार्य कर रहे थे जिनमें से ५ ६१ ५०० अध्यापक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित थे । शेष शिक्षक अध्यापक शिक्षण विधियाँ में परिवर्तित नहीं हो पाये हैं । समस्या शिक्षकों में से ५ प्रशिक्षित में भी कम हाईस्कूल अथवा मिडिल स्तर । उल्लेख है । एक मंत्री प्राथमिक स्तर पर शिक्षित है । घनाभाव के कारण प्राथमिक विद्यालय शिक्षण के उपकरणों का प्रयोग न । का वाम है । जब समस्या का कारण व समस्या के शिक्षा अवरुद्ध तथा निम्न स्तर पर है । अतः वह प्रकृति तथा अन्य आसपास की आवाज करने में प्रयत्न रहती है ।

## समाधान—अध्यापक प्रशिक्षण एवं सहायता अनुदान (Teachers Training and Grant-in-Aid)

शिक्षा के स्तर का उच्च उठाने के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम शिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्ति की जाय । इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिक शिक्षकों में शिक्षण विद्यालयों का स्थापना का जाय । इस बात का ध्यान रखा जाय कि न प्रशिक्षित विद्यालयों में गरीबों में ही नियुक्ति न किया जाय । अतिशुद्धताओं तथा मरीजों के लिए यह कार्य जिनमें सहायकों की स्थिति के लिए एक पाठ्य ग्रन्थ लिखी उनमें कम

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

धन व्यय करके दाखिल हो सकें। उत्तम तो यही होगा कि छात्राध्यापका के ममत्त प्रशिक्षण का व्यय भार सरकार या स्थानीय परिषदों अपने ऊपर लें। पर यह विचार कि बचन प्रशिक्षित अध्यापका की नियुक्ति में ही शिक्षण का स्तर पर्याप्त ऊँचा हो जायगा कारी कल्पना से अधिक और कुछ न होगा। आवश्यकता इस बात की भी है कि प्राथमिक विद्यालयों का मुक्त हस्त में शिक्षण उपकरणों को खय करना व लिये सहायता अनुदान दिया जाय। शिक्षा के मापना के अभाव में उसाही और प्रशिक्षित अध्यापक भी अपने शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने में असमर्थ पावेंगे।

### ६ समस्या—धनभाव (Dearth of Money)

प्राथमिक विद्यालयों का समस्त आर्थिक समस्या अति विकराल रूप में उपस्थित रहती है। हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तर दायित्व नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों पर है। सरकार न ऐसा व्यय पूर्ण दायित्व तो उन पर रख दिया परन्तु उनका लिय धन की कोई व्यवस्था नहीं की। उनका खय के आय-साधन सीमित है जिनसे वे प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाकर उसका व्यय भार वहन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। ब्रिटिश शासन-काल में प्राथमिक शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय का ३० प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाता था। स्वतन्त्र भारत में इस धन राशि को ३३ प्रतिशत कर दिया गया है।<sup>१</sup> सरकार द्वारा दो जान वाली इस स्थूल आर्थिक सहायता का शिक्षा का अनिवार्य बनाने में लिये किंगी प्रकार उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः देश में नागरिका का शिक्षित करने का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है न कि स्थानीय मस्याओं पर। फिर यदि आर्थिक समस्या में यमिन स्थानाव मस्याओं शिक्षा का अनिवार्य बनाने का विचार नहीं करते हैं तो इनका लिय उन पर दोषारोपण करना तबका अनुचित है।

### समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

धनभाव का कारण अनिवार्य शिक्षा का प्रकार अभाव गति से नहीं हो रहा है। यदि सम्पूर्ण देश में अनिवार्य शैक्षिक शिक्षा को योजना की ६ से १८ वर्ष तक का आयु के समस्त बच्चों का लिय प्रियायित कर दिया जाय तो प्रतिवर्ष २६६४ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। शिक्षा पर होने वाला व्यय करना इस निर्णय दश का लक्ष्य में पर का बात है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर ६३ करोड़ रुपये खय किया गया परन्तु अत्र

1. Education in India 1952-53 Vol. I p 27  
2. Ibid 1953-54 Vol. I p 116

विकास कार्यों के लिये धन की आवश्यकता होने के कारण द्वितीय योजना में इस राशि को घटाकर ८६ करोड़ कर दिया गया।<sup>१</sup> धनाभाव की ऐसी स्थिति में हमारा ध्येय प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि पर नहीं होना चाहिये अतः हम इस बात का प्रयास करना चाहिये कि कम धन व्यय करके अधिक से अधिक बच्चा को शिक्षित किया जा सके जिससे वे अज्ञानता के भाग में न पड़ें। इस सम्बन्ध में मोतीलाल नेहरू ने यहाँ उल्लेखनीय हैं। उन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अक्षिण का नाश करना है। शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि महत्वपूर्ण अवश्य है, पर उस पर अभी जल दिया जाना चाहिये जब अज्ञानता का विनाश हो जाय।<sup>२</sup> हम बचपन में निर्विद्या मनुष्य का ध्यान में रखकर जायें धन प्राथमिक विद्यालयों को बेमिह स्कूलों में परिवर्तित करना में व्यय किया जा रहा है। उसे पूर्ण रूप से तो नहीं, पर अधिकांश रूप से समाप्त कर देना वांछनीय होगा। सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा पर न कि धर्मिक शिक्षा का रूप में अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये। कुछ भारतीय शिक्षाविदों का मत है कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थिक का हल करने की राह को कम किया जा सकता है। आधुनिक जर्मनी जापान सिंगापूर और हमें प्राथमिक शिक्षा की अवधि को हल करने का जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार किया।<sup>३</sup> गार्डर का सुझाव है कि अनिवार्य शिक्षा के व्यय को कम करने के लिये धनो व्यक्तियों के बच्चा में शुल्क लिया जाय और व्यक्तिगत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चा में शुल्क धन की अनुमति दे दी जाय। यदि इन सभी सुझावों का सरकार द्वारा मायका प्रदान कर दी जाय तो अनिवार्य शिक्षा का आर्थिक समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है।

### ७ समस्या—विद्यालय-स्थापना एवं विद्यालय भवन (Establishment & Buildings of Schools)

अनिवार्य शिक्षा का ध्यान में रख कर हमें ब्रिटिश विद्यालयों का स्थापना है। नगरों में तो नहीं परन्तु ग्रामीणों में ब्रिटिश विद्यालयों का स्थापना करना दुर्लभ प्रमाण होता है। भारत का मायका नहीं है परन्तु दा निगई का मायका<sup>४</sup> जिसमें विद्यालय नहीं है। १८७१ की जनगणना के अनुसार भारत में

१ द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना पृष्ठ ८६८

२ Primary purpose of mass education is to banish illiteracy. The quality of education is a matter of importance but comes only after illiteracy has been abolished.

—Gokhale Speeches p. 64

३ Dinker Datta Primary Education in India pp. 31-32

## भारतीय गिरी और उसकी समस्याएँ

५ १८०८८ ग्राम हैं। इनमें से ३ ००२० ग्राम ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ५०० से कम है।<sup>१</sup> गिरी का अनिवार्य बनाने के लिये लगभग ४ लाख ग्रामों में जिनमें ५० से कम जनसंख्या वाले भी ग्राम सम्मिलित हैं प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना आवश्यक है। परन्तु इतने विद्यालयों के निर्माण के लिये एकत्रित करना मरस नहीं है। फिर ५०० से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में विद्यालय निर्मित करना अधिक बालक की शिक्षा के लिये हिनकर मिष्ट नहीं होगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसे ग्रेग व प्रसामिका तथा शिक्षा विभाग के समस्त एक जतिन प्रश्न उपस्थित कर दिया है।

विद्यालय भवनों का एक अन्य समस्या है। आज हमारे देश में केवल ३० प्रतिशत विद्यालय भवन ही ऐसे हैं जिन्हें उपयुक्त कहा जा सकता है। बाकी सभी विद्यालय बिना किसी मरिदा बनी व्यवस्था के ठूढ़ा अध्यापक के निवास स्थाना आदि में चल रह हैं। इनमें जगह का अभाव है और छात्रों व बटन तथा खेलन के लिये उचित व्यवस्था नहीं है। अनेकों विद्यालय कोता हलपूर्ण जपवा अवाछनीय वातावरण में स्थित हैं तथा उनके भवनों में धूप एवं वायु का प्रवेश न हो सकन व कारण छात्रों व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि गिरी को अनिवार्य कर दिया जाय तो शिक्षा की वृद्धि कर दी जाय तो उह शिक्षा कहाँ दी जाय ? निम्नगृह उत्तर होगा कि नवीन भवनों का निर्माण किया जाय। पर इसके लिये धन जुगना - जगा कि हम ऊपर लिख चुके आधुनिक

### समाधान कुछ सुझाव (Some Suggestions)

(१) प्राथमिक शिक्षा में विद्यालयों की समस्या अनि जतिन है। नये विद्यालयों के निर्माण के लिये धन का अभाव है। फिर अनेकों ग्राम दूर-दूर तथा छोटे हैं। प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण के लिये धन प्राप्त हो सकता है ता उन्हें ऐसे ग्रामों में पश्चिम निर्मित किया जाय जहाँ उनको आवश्यकता अधिक है। जो ग्राम छोटे हैं उनमें मध्य में विद्यालय निर्माण के लिये ऐसे ग्रामों को पुनः जो सभी ग्रामों का बचका व लिये सुविधाजनक हो। परन्तु यदि धन उपलब्ध नहीं है तो अनिवार्य गिरी का कार्य हमलिय स्थिति नहीं कर देना चाहिये कि शिक्षा व लिये विद्यालयों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बचका को जब निर्मित हो किया जाना है तो मरिदा समजिना समसामाजिक

१ भारत १९६० पु० ११ (१९६१ की जनगणना के अनुसार ये छात्रों उपलब्ध नहीं हैं।)



में वही अधिक छात्र थे। उदाहरणार्थ—१९२२ तक इंग्लैण्ड में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या ६० तक थी और १९३२ तक इटली में भी वही संख्या थी। गण्ट मध ने चीन में प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं की संख्या ६० छात्रों की मर्यादा की थी। अतः जिन भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक एक ही कक्षा की विद्याभ्यास की शिक्षा देता है वही छात्रों की संख्या में निश्चय ही संतुष्टि की बात बनती है। हाँ जिन विद्यालयों में एक अध्यापक एक से अधिक कक्षा का एक ही समय में शिक्षा देता है वही इस योजना की श्रियाचिन करना उचित नहीं होगा।

#### ८ समस्या—अनुपयुक्त पाठ्यक्रम (Unsuitable Curriculum)

प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम मकान तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। इसमें पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता है और छात्रों को अपनी स्थानीयता से दूर का विकास करने तथा कार्य करने की शक्ति व सिद्धान्त की अवगतता की जाती है। पाठ्य-क्रम के इन दोषों का निवारण करने में नियम गण्ट ने प्राथमिक शिक्षा की वैमिशिक्षा का रूप प्रदान करने का निश्चय किया है। इसमें पाठ्य-क्रम में दोष तो अनिवार्य रूप से दूर हो जायेंगे परन्तु अतिशय शिक्षा की व्यवस्था योजना का सम्पूर्ण देश में एक साथ न हो श्रियाचिन किया जा सकता है और न किया जा सके।

#### समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम एक मार्गिक तथा अन्विकर है। स्थानीय पर्यावरण में सम्बन्धित न होने का कारण उसमें किसी प्रकार की उपाययोजना नहीं है। यह ठीक है कि सरकार वैमिशिक्षा का पाठ्यक्रम श्रियाचिन करके शिक्षा का शोध बनाने का प्रयास कर रही है परन्तु इन कार्य में अति दीर्घ समय लगता है। अतः उस समय तक कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा समा-कीर्ण की शिक्षा दी जाय। इससे बच्चे की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और वे अपने अज्ञित ज्ञान में कुछ लाभ भी उठा सकेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि इस कीर्ण की शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षा तथा प्रशिक्षित अध्यापक हो गया जाय। इन कार्य के लिये किसी भी स्थानीय तथा अनुसंधान व्यक्ति का सेवाका में साथ उठाया जा सकता है।

#### ९ समस्या—अपव्यय तथा अवरोधन (Wastage and Stagnation)

प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन (Wastage) एवं अवरोधन (Stagnation) है। प्रथम १०० छात्रों में से जो १९३२-३३ में

कक्षा १ में से कक्षा ४ : छात्र १९५५-५६ में कक्षा ४ में पहुँचें ।<sup>१</sup> इस प्रकार १७ प्रतिशत छात्र परीक्षाओं में अग्रगण्य होने अवकाश करने अभिभावकों का वाय करके तथा मनोपार्जन करने मृत्युना देने के लिये विद्यालयों में अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे । दुर्भाग्य से विद्यालयों की उपकरण शक्तों प्रबोधनीय स्थिति तथा आकर्षण रहित भवन—उनको सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिय प्रलोभित न कर सके । इस बात की परम आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा में 'अपभ्रम' तथा 'अवरोधन' की रोका जाय अथवा अनिवार्य शिक्षा-यात्रना अवकाश शिक्षा प्रसार की अन्य किसी भी योजना का सफल होना अगम्य है ।

समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

अपभ्रम एवं अवरोधन निवारण के कुछ उपाय अधिलिखित हो सकते हैं —

- (१) शिक्षा-अवस्था में सुधार किया जाय { } शिक्षा में बर्तमान की मनोपार्जन बनाया जाय (२) उत्तम विद्यालय भवन का निर्माण किया जाय (३) विद्यालय में अन्दर और बाहर के वातावरण में सुधार किया जाय (४) पाठ्यक्रम में सुधार किया जाय (५) परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय (६) छात्रों की स्वास्थ्य उन्नति की जाय (७) अभिभावकों का निम्नित किया जाय, और (८) सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाय ।

(विद्युत अभ्यसन के लिये अपभ्रम एवं अवरोधन <sup>५५१५</sup> अग्रगण्य देखिये ।)

१० समस्या—प्राकृतिक बाधाएँ (Natural Obstacles)

अनिवार्य शिक्षा का प्रसार में भौगोलिक कठिनाइयाँ अग्रगण्य बाधाएँ गिनी हो रही हैं । हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, मद्रास और अरुणाचल आदि पर्वतीय राज्यों में जनसंख्या कम होने के कारण ग्राम दूर-दूर पर स्थित हैं । यही बात राजस्थान के रेगान प्रदेश के सम्बन्ध में भी कहा जा सकती है । फिर मध्य प्रदेश मध्य भारत तथा दक्षिण में ऐसा अनेक क्षेत्र हैं जो जंगलों से ढके हुए हैं और जहाँ की जनसंख्या छोटी एक मुहूर घाटों में बितरित हुई है । उत्तरीय सभी प्रदेशों में आवागमन के साधनों का अभाव है और सीधे उष्णता अथवा भारी वर्षा—घाटा के भागों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं । क्योंकि भारत के प्रायः सभी में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं अतः इन कठिनाइयों पर विचार प्राप्त करके हमने ग्राम-विद्यालयों में ऐसा आचार्य करने के लिये जाना जिसका सामाजिक जीवन में कोई सम्बन्ध नहीं है छात्र एवं उनके अभिभावकों द्वारा बुद्धिमानों का काम नहीं सम्पन्न होता है ।



भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ  
प्रश्न (S)

समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

जिन प्राकृतिक बाधाओं का उल्लेख उपर किया गया है उन पर भारत  
ऐसे विचार देना में विजय प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य  
है। पर स्वतंत्रता के उपरान्त ये बाधाएँ विस्मृति के गर्त में समाती जान पड़ने  
सगी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवागमन के साधनों में स्थापनीय  
वृद्धि हुई है। अनेकों सुदूर ग्रामों में सड़को का निर्माण हो गया है। पर अज  
भी अनेको स्थान ऐसे हैं जहाँ प्राकृतिक बाधाएँ बासकों तथा दालिकात्रा की  
गिरावट अवरोध उपस्थित करती हैं। ऐसे स्थानों पर यदि वहाँ के बच्चों की  
गिरावट का भार किसी स्थानीय व्यक्ति को सौंप दिया जाय तो उनके आवागमन  
का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

११ समस्या—सामाजिक कुरीतियाँ (Social Evils)

सामाजिक कुरीतियाँ (Social Evils)

धर्मापता अथर्विवाह अहिंसा तथा प्राचीन परम्पराओं में आस्था रखने के परिणामस्वरूप भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये निवासी नाना प्रकार की सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त न हो। उदाहरणार्थ—बाल विवाह असंख्यता पर्व प्रथा धार्मिक सिद्धान्त आदि ऐसी ओषधियाँ हैं जिन्होंने अनिवार्य विद्या के माध्यम से भी चिन्ता न करके आज भी हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम की चिन्ता न करके आज भी प्राचीन विषयों के अनेक व्यक्ति बालकों तथा धार्मिकों का अल्प आयु में विवाह करते उन्हें गिरा से बचत कर देते हैं। विद्या द्वारा सभी नागरिकों का समान अधिकार मिले जाने पर भी आज अनेक हरिजन छात्रों को विद्या न गिरा ब्रह्मण में विद्यालयों में प्रवेश करने से निषेध कर दिया जाता है। आज भी अनेक शिक्षार्थी तथा युगसमान का हड़ विवाह है जिन्होंने अनेकों को या तो गिरा ही ही नहीं जानी चाहिए या यदि भी जय तो अति गिरा। पर्व प्रथा का कारण आज भी ऐसे व्यक्तियों का अभाव है जो प्राथमिक विद्यालय में भी गिरा शिक्षा का विरोधी हैं। अब जनता का हितोद्योग होगा है जब शिक्षा की अनिवार्य बनाना निम्नलिखित एक सम्पदा है।

समाधान कुछ सुझाव (Some Suggestions)

समाधान के लिए

गुप्त सुभाष (Some Suggestions)

गामा'त्र करारिता व जगुम म पंथे हृष्ट भारत को मुक्ति सि्ताने व मिये  
व वत कु' हो उगामा वा मुमभ सिता जा गवता है । प्रथम सिता वा प्रगार  
'र' वाज वरा'ि मायात्रि हुरी'नद' म 'गा व वारण हो परपस्थित होनी  
? । सिता वनर व मभित्त को विवगित करनी है और उगको तप-शक्ति

प्रदान करती है। ऐसी दशा में सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन सरलता पूर्वक हो जायगा। द्वितीय सरकार और समाज भवका ब. द्वारा बलविता का प्रयोग करके व्याख्यान देकर ब. और सामाजिक कुरीतियों की हानियों का उदाहरण देकर भरपूर प्रचार किया जाय। तृतीय शिक्षित नवयुवक और नव युवतियाँ यह धीका उगा में कि वे अपने गृहों परामा सम्बन्धियों और परिचित व्यक्तियों को सामाजिक कुरीतियों का अनुसरण नहीं करने देंगे।

## १२ समस्या—भाषा (Language)

अनिवार्य शिक्षा की अन्तिम समस्या भाषा का है। १९६१ की जनगणना के अनुसार २१ म. ८४७ भाषाएँ अवका बोलियाँ बोली जाती हैं।<sup>१</sup> देश के प्रान्तों के समान समस्या यह है कि इनकी विभिन्न भाषाएँ जानने वाले बच्चों का शिक्षा किस भाषा के माध्यम द्वारा दी जाय? भारतीय संविधान में जिन १४ भाषाओं का उल्लेख किया गया है वे ऐसी हैं जिनको शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है परन्तु ऐसी अनार भाषाएँ हैं जिनको हम पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—ऐसी अनेकों अनुसूचित तथा आदिम जातियाँ (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) हैं जिनका न तो कोई मातृभाषा है और न कोई बोलभाषा। फिर उनका क्या भाषा भी उ. उ. करार है।<sup>२</sup> इनके प्रतिष्ठित ४० लाख निरक्षरगृहित आदिम जातीय लोग (Denotified Tribes) और हैं।<sup>३</sup> इन विपरीत हुई जातियों में अभी तक अनिवार्य शिक्षा का प्रयोग नहीं हो सका हो पाया है।

## समाधान—विशेष विद्यालय (Special Schools)

उन भाषों में जो आदिम अनुसूचित तथा विपरीत हुई जातियों निवास करता है विशेष विद्यालयों का स्थापना आवश्यक है। स्वतन्त्र भारत में हम बार परीक्षा प्राप्त किया जा रहा है। सरकार इन जातियों के लोगों के विषे विशेष विद्यालयों का स्थापना कर रहा है और उन्हें निम्न स्तर पर शिक्षा देकर। मूल्य सामान्य आदिम का संविधान दे रहा है।<sup>४</sup> जिस पर उपकरणों काटना का प्रश्न है

1. *Ibid* 1962, p 23

2. *Ibid* p 129

3. *Ibid*

4. *Ibid*, p 135

आदिम जातीय क्षेत्रों में ३ १८७ और अनुसूचित जातियों के लिये ६ ००० स्कूल और छात्रावास स्थापित करने का मक्य रखा गया। तृतीय योजना में उनकी शिक्षा पर ४२ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया है।<sup>१</sup> प्रयत्न साराहनीय हैं, परन्तु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि अनुसूचित तथा आदिम जातियों की संख्या क्रमशः ५ १३ करोड़ तथा २ २१ करोड़ है तो हमें कुछ निराशा प्रतीत होने लगती है। शिक्षा द्वारा शताब्दियों के पद दलित इन जातियों की शिक्षा का भार केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिये अपितु जनता को भी इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहिये।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Discuss the special difficulties that have stood in the way of the adoption of Compulsory Primary Education in India
- 2 What, in your opinion, are the major problems of Compulsory Primary Education in India? What suggestions can you offer to tackle them?
- 3 Describe the system of Compulsory Primary Education which has been adopted in your state
- 4 Discuss the causes of slow progress in the spread of Primary Education in India. How could these be removed?

---

1 Third Five-Year Plan, p. 702.

## माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

### विषय-प्रवेश

बहुत समय पूर्व तक माध्यमिक शिक्षा को हमारी शिक्षा-व्यवस्था में कुछ ही निर्देश कही सम्मिलित जाता था। लगभग एक सताष्टी तक हमारा देश के शिक्षा विद्या की माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा के कारण अव्यवस्थित था। इसी के फलस्वरूप मामूली और प्रायोगिक की नियुक्तियों की गई जिन्होंने कि वे हमारे देशों और निवासस्थानों का समीक्षा करें। १८१४ का कुछ का प्रयोग पर १८८० का हर्टर समीक्षण १८१७-१८ का समस्तता विश्वविद्यालय समीक्षण, १८४४ की मार्जेंट घोषणा और १८४८-४९ का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग—सभी इस बात से सहमत थे कि माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था का आधार मूल दोन यह था कि वह माध्यमिक था और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए छात्रों की तैयारी करती थी।

१८४८-४९ के विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग ने यह बात स्पष्ट कर दी कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण किन किन विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करता सम्भव है। इसी के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा-आयोग की नियुक्ति हुई जिन्होंने इस शिक्षा के सम्बन्ध में अपना बहुमूल्य सुझाव दिये जिसका

भारत-सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। (हम माध्यमिक शिक्षा आयोग का वर्णन पिछले अध्याय में कर चुके हैं।)

माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप (Pattern of Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा की शृङ्खला में बीच की कड़ी कहा जाता है। इस कड़ी में एक ओर प्राथमिक और दूसरी ओर उच्च शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा की सामान्य अवधि ७ वर्ष की है। इसकी दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) ११-१४ बय-वर्ग के बच्चों के लिये ४ वर्ष की निम्नतर माध्यमिक (Lower Secondary) या मिडिल या सीनियर सेकेंडरी या जूनियर माध्यमिक शिक्षा।

(ख) १४-१७ बय-वर्ग के बच्चों के लिये ३ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक (Higher Secondary) शिक्षा।

यहाँ यह बताना बड़ा आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में दोनो स्तरों की शिक्षा का अवधि विभिन्न है। यह भी लिख देना अत्यन्त न होना कि कुछ राज्यों में निम्नतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का अङ्ग है। कुछ राज्यों में अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाये हैं कि निम्नतर माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का अङ्ग है या उच्चतर शिक्षा का। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ हाई स्कूलों में स्थान में हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इनका अध्ययन काल ४ बय का है।

माध्यमिक शिक्षा का विकास (Growth of Secondary Education)

स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास अति द्रुत गति में हुआ है। इसकी पुष्टि निम्नांकित आँकड़ों से हो जाती है—

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार\*

वर्ष	स्कूल संख्या	छात्र संख्या	व्यय (करोड़ रुपये)
१९४६-४७	६६८२	१०,४४,४१६	२०
१९४७-४८	६४१४	१६,०४,८६६	३१
१९४८-४९	१४,१२४	२४,७८,११२	४२

1. M. T. Vyas Secondary Education in Administration of Education in India pp 195-196

2. Review of Education in India p 940

## समस्याएँ और उनके समाधान (Problems & Their Solutions)

स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक सिन्धार उज्जा है। इसमें सुधार करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। परन्तु का विषय है कि अभी तक शिक्षा की गरवना में हमका महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की जाड़ने वाली यह कड़ी अभी तक निरम हो बनी हुई है। आज माध्यमिक शिक्षा में इसकी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं कि यदि उनका समाधान नहीं किया गया तो समग्र रूप से भारतीय शिक्षा का उन्नयन असम्भव होगा। हम इन समस्याओं की ओर नाचे की पंक्ति में गरव कर रहे हैं।

### १. समस्या उद्देश्य विहीनता (Aimlessness)

हमारी माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य विहीन है। यह कहना अनुचित न होगा कि स्वतंत्र भारत में भी हम शिक्षा का उद्देश्य क्या है जो परवर्तमान भारत में था। शिक्षा कबल हम उद्देश्य से प्राप्त की जाती है कि मातो काई कीकरा मिल जाय या उच्च शिक्षा के किसी विद्यालय में प्रवेश प्रिष्ठका अन्तिम उद्देश्य का बही है जो माध्यमिक शिक्षा का है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र दिन रात पुस्तकों का अध्ययन करके अपने स्वाध्याय और गुण का वर्णन करते हैं और उनका माता पिता तथा सरदारक अनक याचनाओं का भेदन हुए भी उनका ऊपर धन व्यय करने हैं। पर जब अन्तर्गतका छात्रों का भरा उद्देश्य का प्राप्ति में असफलता मिलती है तो उनमें हृदय के स्थान में विषाद अधिर हुआ है।

### समाधान—निश्चित उद्देश्य (Definite Aims)

माध्यमिक शिक्षा का मध्यम और मध्यम बनान के लिए उनका उद्देश्य का निर्धारित करना आवश्यक है। अब तक हम शिक्षा के निश्चित उद्देश्य नहीं है कि तक तक हमकी उपायगिता मशयुर्ग रही। पर प्रश्न यह है कि ये उद्देश्य हान क्या चाहिए? इसका लिए सबसेपहले आवश्यकता हम जान की है कि माध्यमिक शिक्षा का उच्च शिक्षा का पूरक न समझकर एक स्वायत्त इकाई बना दिया जाय। उपायगिता माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जायें —

१. शिक्षा-मार्गों के उन्नयन छात्रों की विद्या कर्म के लिए कृष्ण बनाया।
२. उनकी स्वतंत्र रूप से कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करना।
३. उनकी स्वायत्तता के लिए उपायगिता कर्मों में कृष्ण करना।

माध्यमिक शिक्षा-आयोग (Secondary Education Commission) ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किये हैं वे भी प्रासंगिक हैं यथा—

- १ लोकतन्त्रात्मक नागरिकता का विकास
- २ व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि
- ३ व्यक्तित्व का विकास
- ४ नेतृत्व का विकास।

२ समस्या—अनुपयुक्त पाठ्यक्रम (Unsuitable Curriculum)

माध्यमिक शिक्षासंस्था का पाठ्य-क्रम एक मार्गीय (Single Track) है। सभी विद्यार्थियों को एक पूर्व निर्धारित पाठ्य-क्रम का अध्ययन करना पड़ता है। छात्रा को अपनी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषयों के चयन का अवसर नहीं प्राप्त होता है जिसका परिणाम यह होता है कि उनके मौलिक विचारों एवं मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। साथ ही पाठ्य-क्रम का विद्यार्थियों के वातावरण और वास्तविक एवं व्यावहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है फलतः जीवन-दान में पड़ापण करने पर वे अपने को एक ऐसी विषम स्थिति में पाते हैं कि वे सामाजिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं।<sup>१</sup>

समाधान—रोचक और विभिन्न पाठ्यक्रम (Interesting & Diversified Curriculum)

आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्य-क्रम का विस्तार किया जाय और उसमें विभिन्न उद्योग व्यवसायों तथा कृषि सम्बन्धी विषयों का समावेश किया जाय और छात्रा को उनकी रुचियों के अनुसार विषयों को चुनने में विशेषज्ञता द्वारा सहायता दी जाय। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य-क्रम की विविधता (Diversification of Courses) को सत-बल करते हुए निर्माजित मुद्दाक दिये हैं —

- १ पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिये जिससे छात्रा को विभिन्न वास्तविक एवं क्षमताओं का विकास किया जा सके।

<sup>१</sup> The education given in our schools is isolated from life. The curriculum as formulated and as presented through the traditional methods of teaching does not give the students insight into the everyday world in which they are living. When they pass out of school they feel ill adjusted and can not take their place confidently and competently in the community. — Report of the Secondary Education Commission p 22





## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

अतिरिक्त भदे चतुर्विधों नामोद्दीपक फिल्मों गानों एवं जातीय पक्षपात ने भी छात्रों की अनुशासनहीनता में अत्यधिक योगदान दिया है। अतः यदि हम इस दशावस्था की अनुशासनहीनता का निराकरण करने का इच्छु हैं तो हम उपयुक्त सभी दोषों के निवारण की ओर समुचित ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही छात्रों को जीवन में अनुशासन का महत्त्व बताकर उनके अन्दर में अनुशासन के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को जागृत करना होगा। यह कार्य सभी सम्पन्न किया जा सकेगा जब सगृहार जनता और अभिभावक एक निश्चय करके इस शिक्षा में एक साथ क्रियात्मक पग उठाएँ।

### ४ समस्या—व्यक्तिगत स्कूलों की अवांछनीय वृद्धि (Undesirable Growth of Private Schools)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा प्रसार के नाम पर माध्यमिक शिक्षा सदा की सख्या में अमापारण वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि अवांछनीय होने के साथ-साथ छात्रों अध्यापकों एवं अन्त में देग के लिये अभिघात सिद्ध हुई है। इनमें से अधिकांश स्कूल किसी जाति विशेष राजनीतिक दल या सेठ साहूकार की निजी सम्पत्ति हैं जिनमें जातिवाद का ताण्डव नृत्य होता है जिन्हें राजनीतिक रंगमंच में परिणत कर लिया गया है और जो प्रवचन की भाव के निश्चय साधन हो गये हैं। अध्यापक का अल्प वेतन पर नियुक्त किया जाता है उनका वेतन में से कटौती की जाती है और छोमावकाश में उनसे श्राव्य पत्र ल लिया जाता है। ऐसे स्कूलों में अनुशासन शिक्षा-न्तर एक गिरावो और छात्रों में चरित्र का अनुमान सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। स्कूल निरीक्षक भी ऐसे स्कूलों के प्रति या तो स्वयमव उदासीन हो जाते हैं या कोई बड़ा कार्यवाही करने की इच्छा करने पर भी अग्रण के असमर्थ पान हैं क्योंकि उनमें स्कूल प्रवचन का छ लोहा लने की शक्ति नहीं होती है।

### समाधान—व्यक्तिगत स्कूलों की समाप्ति (Abolition of Private Schools)

व्यक्तिगत स्कूल माध्यमिक शिक्षा के भाग पर ऐसे बलब बिंदु हैं जिनको सामाजिकीय या दालना आवश्यक है। यह कार्य करने का सामर्थ्य बलब गर कार में है और बलब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र उपाय है। शब्द का विषय है कि अभी तक बनका राज्या में हम आर कोई कदम नहीं उठाया गया है और व्यक्तिगत स्कूल राज्य सरकारों से सहायता अनुदान लेकर उठी की दण्डाया में परिवर्तित होकर माध्यमिक शिक्षा का नामा पाट रहे हैं।

५ तमस्या—निक्षा वा निम्न स्तर (Low Standard of Teaching)

माध्यमिक शिक्षा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यह है कि शिक्षा का स्तर निम्न है। इसमें निम्न मुख्य रूप से हमारा सरकार उच्चतम है क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सरकार का ध्यान शिक्षा प्रसार पर ही केंद्रित रहा है और उसकी गुणगमक उद्यमिता की ओर ध्यान भी नहीं गया है। परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं। युद्धजनित भौतिक के कारण सभी देशों के मूल्य में बर्तमान वृद्धि हो गई है परन्तु शिक्षा का स्तर प्रायः वही है जो युद्ध से पूर्व था। सरकार शिक्षा की दशा की ओर पूर्णतः उदासीन रही है जबकि अन्य विभागों में बर्तमान विकास का पर्याप्त ध्यान और महत्त्व दी जा रही है। शिक्षा की दशा स्तर नहीं बढ़ता है कि व अपना दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। ऐसी दशा में उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती और उनके द्वारा काम की उपलब्धि कम हो जाती है। फिर अन्य शिक्षाएँ एक ही दिन के पाठ्यक्रम से घटती हैं कि व उपयुक्त भोजन और पाठ्य सामग्री की आवश्यकता कर ले। इन सभी कारणों से शिक्षा के स्तर पर ध्यान देना आवश्यक होता है और उसका स्तर निम्न हो गया है।

### समाधान पूर्व सुझाव (Some Suggestions)

[illegible]

## ६ समस्या—दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली (Defective System of Examination)

माध्यमिक परीक्षा प्रणाली में एक नहीं अपितु अनेकों दोष भरे हुए हैं। इन प्रणाली में जितने ही दोषों का जल्मेम किया जाय उतने ही कम हैं। बस्तुतः यह भारत की साम्प्रदायिक सामाजिक एवं राजनयिक प्रणाली से भी अधिक बुरी है। 'मेट्रोपुलिटन' परीक्षा का सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर शासन है। एक विद्यालय और उसने गितना तथा छात्रों की छेरठना परीक्षा की कसौटी पर जाँची जाती है। वही विद्यालय उत्तम समझा जाता है जिसका पराधा-यत्न उत्तम होता है। ऐसी परिस्थितियाँ में अध्यापक उत्तम परीक्षाफल देने के लिए अनुचित मायना का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी ज्ञान के अर्जन से वास्तविक लाभ उठाने की ओर ध्यान केवल पुस्तक को पढ़कर रखते हैं जिससे उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। परिणाम यह होता है कि उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास अवलक्षित हो जाता है।

## समाधान—परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन (Change in Examination System)

परीक्षा ही छात्रों के ज्ञान और अध्यापक की कार्य-क्षमता की वास्तविक कसौटी नहीं है। अब यह आवश्यक है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय जिससे छात्र अर्जित ज्ञान से सामाजिक हो सकें और अध्यापक की कार्य-क्षमता को भी जाँचा जा सके। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन के निम्ने माध्यमिक शिक्षा प्रायोग ने जो निम्नलिखित सुझाव दिये हैं वे स्वीकार्य हैं —

- बाह्य परीक्षाएँ (External Examinations) की संख्या में कमी की जाय।
- परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हल में इन प्रकार परिवर्तन किया जाय कि पराधा निबन्ध-प्रकार हल (Essay Type) की ग रह जाय।
- छात्रों का कार्य का अन्तिम मूल्यांकन करने समय आन्तरिक परीक्षाएँ (Internal Examinations) का माध्यम नियन्त्रात्मक परीक्षाएँ (Periodical Tests) और विद्यालय-अभिलेख (School-Records) को भी अधिक महत्त्व प्रदान किया जाय।

- ४ बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षाओं में छात्रों के कार्य का सुव्यवस्थित प्रवृत्ति में न दिया जाए प्रतीकात्मक (Symbolic) होना चाहिए।
- ५ प्रत्येक छात्र का एक विद्यालय अभिनेता रखा जाय त्रिगुण विधित्त छात्रों में उनके द्वारा दिये गये कार्यों एवं उनमें प्राप्त गहनता का उत्पन्न हो।
- ६ गेन-इरी स्कूल का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त ही वेदों एवं सांख्यिक परीक्षा भी आयें।

### ७ समस्या सामुदायिक जीवन का अभाव (Absence of Community Life)

विद्यार्थियों में समुदायिक सामुदायिक जीवन का अभाव है। कारण यह है कि ये न केवल छात्रों के व्यापार तथा विनोदमय एवं सामाजिक विचारों का कोई भी आधार नहीं दिया जाता है जिससे छात्रों में सम्पर्क स्थापित हो और उनमें चर्चा-विमर्श हो। इस प्रकार सामान्य एक छात्रावास स्कूल का फंडी के समान होता है जिसका प्रमुख उद्देश्य—छात्रों का भिन्नानुसंग परीक्षा में उत्तीर्ण करवाना होता है। इस अनिश्चित भी स्कूलों के कुछ और कार्य हैं। उन्हें छात्रों का देश के भाषा सागरों के रूप में समर्थन करना है। अतः जब तक छात्रों को विद्यालय में समुदायिक सामुदायिक जीवन स्थापित करने की जिम्मा नहीं दी जायगी, जब तक वे देश के युवाओं एवं वर्तमान शिक्षा सागरों नहीं बन सकेंगे।

### समाधान—स्कूल सामुदायिक जीवन का केंद्र (School A Centre of Community Life)

शिक्षा साधारण रूप में एक सामाजिक समस्या है। समाज स्कूल का वह कक्षा में होता है कि वह सुबह का प्रयोग तथा उसका वापस-आना इस प्रकार करे कि वे समाज के अति समृद्ध से सम्बन्ध रखते हैं और जीवन के ये समाज के हक से भाग ले सकें। अतः स्कूल में स्कूल का सामुदायिक जीवन के केंद्र (Centre of Community Life) के रूप में स्थापना की जानी चाहिए। सुधारकर्ता समिति ने उद्घोषित किया है स्कूल एक युवा समुदाय के अन्तर्गत एक ही एक समस्या है जिसमें देश की युवाओं का जीवन समाज के अन्तर्गत ही विद्यार्थी प्रवर्धित होना है और स्कूल के रूप में

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

प्रचलित होनी है।<sup>१</sup> वस्तुतः स्कूल सामुदायिक जीवन का एक आदर्श निष्ठा (An idealized epitome) होना है अपितु यह कहना अधिक उचित होगा कि स्कूल ऐसा होना चाहिए जिससे समुदाय की समस्त मुख्य उपयोगी गति निश्चिन्ता व मूल्य प्रतिबिम्बित हो।

यह तो निश्चित है कि व्यक्ति को (स्कूल में) प्रशिक्षित किया जाना चाहिए परन्तु बाहर के बृहत्तर समाज की आवश्यकताओं तथा ओर आदर्शों के प्रयोग और कुछ हद तक उनका निमित्त हो उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और चूंकि समाज के ये तत्वावे हमारा बदन रक्षते हैं बढ़ते रहते हैं और उनमें सुधार होने रहते हैं इसलिए ये आवश्यक है कि स्कूल के बाहर के जीवन के साथ स्कूल का संचालन सम्बन्ध रहे और वह बदलते हुए तथा गति जाते आलावरण के लिए बच्चों का िका हो। राजनीतिक परिवर्तन के कारण हमारे समाज हमारे समुदाय के तत्वावे भी बदल गए हैं अतः यह अनुभव किया गया है कि देश के विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा को उन तत्वावों के अनुकूल बनाया जाय। स्कूलों को सामुदायिक जीवन से घृणित रखकर एक इस मान का भय रहेगा कि एक जड़ औपचारिकता उन पर छा जाय और वर्तमान सामाजिकता का स्थान अज्ञान की प्रतापमाएं लें। अतः सरकार ने घोषित किया है कि हमारा समस्त शिक्षा सम्बन्धी सामुदायिक बनकर हो।<sup>२</sup>

८. समस्या — अपव्यय एवं अवरोधन (Wastage and Stagnation)  
सामाजिक शिक्षा की एक अति अति समस्या है अपव्यय एवं अवरोधन। प्राथमिक स्तर के समस्त स्तर पर भी अपव्यय तथा अवरोधन शिक्षा के समर्थकों को जबरन स्मरण दहते हैं। इनके कारण कितनी भीषण क्षति होती है इसका कुछ अनुमान अर्थात् कितनी क्षति से किया जा सकता है —

1. School is a small community within a large community and that the attitudes, values and modes of behaviour which have currency in national life are bound to be reflected in the schools. — Report of the Secondary Education Commission p. 127

२. सभी शिक्षा की पुनर्रचना पृ. ६३।  
3. All our institutions will be communities at work — Radio Broadcast by Dr Zakir Hussain published in The Future of Education A Symposium

हार्द स्तूत्र एव उभये समान परीक्षाया के परीक्षा फल

वर्ग	पतीला नवे बाप (दाज माया)	उत्तीर्ण हाने बाप (दाज माया)	उत्तीर्ण दाजो वा नित्या
१९५१-५२	५८३ ४७०	२६१ ०५६	४८७
१९५२-५३	७२४ ७६६	३६ ७६०	६६७
१९५३-५४	८१ ७०	३६७ ००२	८८५
१९५४-५५	८३० ००१	८ ०१६	८८
१९५५-५६	६०० ०२६	४ ६४६६	४६७

### समाधान— कुछ सुझाव (Some Suggestions)

[illegible]

#### ६. गणसभा — संगठन (Organization)

[illegible]

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

समाधान—माध्यमिक विद्यालयों की एकरूपता (Uniformity in Secondary Schools)

यह यति आवश्यक है कि सम्पूर्ण देश के माध्यमिक विद्यालय एक समान हो जिससे छात्रा को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के समय विद्यालय में प्रवेश पाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। ऐसा करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों को धीमातिशील कार्यान्वित किया जाय। माध्यमिक शिक्षा केवल दो प्रकार के विद्यालयों में दी जानी चाहिए—(१) यूनिफ़ॉर्म माध्यमिक विद्यालय—जिनमें शिक्षा का लक्ष्य ३ वर्ष का हो और (२) हायर माध्यमिक विद्यालय—जिनमें शिक्षा का लक्ष्य ४ वर्ष का हो। एसी दशा में इन्टरमीडिएट कक्षाओं का भंग करना अनिवार्य हो जायगा।

१० समस्या—माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंध (Management of Secondary Schools)

आज-कल हमारे देश में तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालय शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं—(१) राजकीय स्कूल, (२) निराय स्कूल (District Board and Municipal Schools) और (३) स्वयंचालित स्कूल (Schools run by Private Bodies)। इन विद्यालयों की गवर्ना नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाती है—

माध्यमिक विद्यालयों का विभाजन १९५५-५६<sup>१</sup>

प्रबंध	स्कूल संख्या	कुल विद्यालयों का प्रतिशत
१ राजकीय		
२ निराय स्कूल	६ १७३	२०.२
(i) जिला परिषद		
(ii) नगरपालिका	२ १५४	२८.१
३ स्वायत्त विद्यालय	१ २३६	३८
(i) गृहस्थाश्रम	११ ६३२	३५.७
(ii) गृहस्थाश्रम	३ ६७३	१२.२
योग	३२ ३६८	१००.००

पूर्वादिष्ट तात्त्विक न स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंसेवात्मक विद्यालयों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों की संख्या बड़ी कम है। इसका एक भाग कारण यह है कि सरकार स्वयं शिक्षा पर धन व्यय न करने महाप्रताप अनुमान न रखें में मोह सा धन स्वरूप अतिशय रूप से विद्यालयों की स्थापना की प्रोत्साहित करती है। राजकीय विद्यालयों का तुलना में परिष्कार और निष्ठा का विद्यालयों की दृष्टि भी सोचनीय है। माध्यमिक शिक्षा-आयोग का इन विद्यालयों के विषय में मत है, "यद्यपि हम इनकी कार्य-कुशलता का बारे में कोई अनुचित कृतकर्म नहीं देना चाहते हैं, पर हमारे पास यह सिद्ध करने के लिए काफी प्रमाण है कि इन विद्यालयों में सुधार करने की अवधि आवश्यकता है।"<sup>1</sup>

जहाँ तक स्वयंसेवात्मक विद्यालयों की बात है वे बहुत दूरानगरी के विद्यालयों पर बसाये जाते हैं और प्रबंधका का भाव के निमित्त ग्राह्य हैं। इनसे माध्यमिक शिक्षा का अक्षयताय अहित हो रहा है। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए हैं —  
दुर्भाग्यवश इन विद्यालयों के कारण अनेकानेक विद्यालयों के रूप में न बसाये जाकर व्यावसायिक उद्योगों के रूप में बसाये जाते हैं। अनेकानेक विद्यालयों में व्यक्ति अपनी निजी हेतुओं के लिये या व्यक्तिगत या समूह के लिये भवन या उपकरणों का ध्यान का प्रतीति करने विद्यालयों का समान लगने है जिसमें वे एमो विभिन्न उत्पन्न कर देते हैं कि शिक्षा विभागों के पास विद्यार्थियों के हित के लिए उनका सामर्थ्य देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता है।<sup>2</sup>

1 Though we do not wish to make any unfair generalization about their efficiency we have had enough evidence to show that there is considerable need for the toning up of these institutions — *Report of the Secondary Education Commission* p 196

2 This laxity has unfortunately led to a state of affairs where schools are run more like commercial enterprises

no alternative but to recognise them for the sake of students — *Report of the Secondary Education Commission* pp 197-198



इन सहायता प्राप्त स्वसंचालित विद्यालयों से कहीं तराय दशा गटायता अनुमान न मिलने वाला स्कूला की है ।

समाधान—विद्यालयों का सरकारी प्रबंध (Government Management of Schools)

उपरोक्त समस्या का समाधान उसी दशा में हो सकता है जब सरकार कोई नियम बनाकर सभी घर-सरकारी स्कूलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और उनका प्रबन्ध जो अपने हाथ में ले ले । अथवा इनका कारण माध्यमिक शिक्षा की जो क्षति हो रही है वह दिन-दूनी रात चौगुनी होती पत्ती जायगी और माध्यमिक शिक्षा-सुधार की सभी योजनाएँ विफल हो जायेंगी ।

उपसंहार

हमने ऊपर माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की ओर संकेत किया है । यहाँ पर गहना आवश्यक नहीं है कि इन समस्याओं का घीघ्रानिमीम उन्मूलन आवश्यक है । बिना ऐसा किए उच्च शिक्षा में गुणार और देश की प्रगति की आशा करना व्यर्थ है । इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके हमारे नवयुवक कदापि देश में योग्य नागरिक नहीं बन सकेंगे । विद्यालय ही व स्थान हैं जहाँ छात्रों का चरित्र एवं देश के भावी नागरिकों का निर्माण होता है । अब यह बावश्यक हो जाता है कि हमारे विद्यालय और उनमें प्रदान की जाने वाला शिक्षा पूर्णतः दोष रहित हो । हमारी शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा सबसे दुर्बल मर्यादा (Weakest Spot) है । हमें उसे सबसे शक्तिशाली मर्यादा बनाना है । सभी हम अथ लेगी व साथ ही हमें आगे निरुक्त करेंगे ।

गारादा में हमारी माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र भारत की आकांक्षाएँ एवं आवश्यकताओं व अनुष्ठान हानी चाहिए । इसे भारत का प्रत्यक्ष नवयुवक को प्रतीक के का योग्य नागरिक बनाना चाहिए ।<sup>1</sup>

1 "In short our education must be brought into line with the aspirations and requirements of free India. It should train every young Indian to be a worthy son of his motherland. —Seven Years of Freedom (Ministry of Education), p. 5

# UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Secondary Education is considered to be the weakest link in our educational system. What are its major weaknesses and how are they to be removed ?
- 2 Comment upon the view that the present system of Secondary Education in India is the gift of the British regime and needs drastic changes. What modification would you like to introduce to suit present needs ?
- 3 Secondary Education in India is said to be excessive in quantity and defective in quality. Discuss the reforms that you would like to introduce in Secondary Education.
- 4 What in your opinion are the problems of Secondary Education ? What measures do you suggest to overcome them ?

## उच्च शिक्षा (Higher Education)

### विवरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसका अनुमान नीचे की तालिका से सहज ही लगाया जा सकता है।

### सामान्य उच्च शिक्षा की प्रगति<sup>1</sup>

वर्ष	कनिष्ठों की संख्या	छात्रों की संख्या	विद्यार्थी की संख्या	अर्थ (रुपया में)
१९६६-७०	४६७	२ ६८ ६२२	१३ ६६६	६ १२ ३६ ६०४
१९५४-५५	६१७	५ २६,३७३	२२ ०८७	१० ३६ ४६ ६८३
१९५७-५८	८६७	६ १६ ६६७	२७ ३०७	१४ १६ ५७ ७८४

1 *Review of Education in India* p 949

व्यावसायिक उच्च शिक्षा की प्रगति<sup>१</sup>

वर्ष	कालजा की संख्या	छात्रा की संख्या	गिनका की संख्या	धन (रुपया में)
१९४९-५०	१८६	७९१०१	४२५३	३५६६८४८२
१९५४-५५	२९१	१३४७९७	७४७६	६३१४०,३८०
१९५७-५८	४८९	१८१५६४	११०४८	८८४८६५८९

उपरोक्त आंकड़ा व आधार पर काँ ब्यक्ति यह कह देगा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का प्रसार अति स्थिति मति से हुआ है पर कोई भी गम्भार विचार वास्तव्य व्यक्ति इसकी सराहना करने में सकोष का अनुभव करेगा। कारण यह कि उच्च शिक्षा का विकास देश की नवीन आवश्यकताओं एवं अभिव्यक्ति की ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। सरकार की नीति रही है उच्च शिक्षा के विस्तार की संख्या में वृद्धि करना न कि हम शिक्षा को गहनता व नागरिकों के लिये उपयोगी बनाना। इससे अतिरिक्त उच्च शिक्षा-सम्बन्धी ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जिनका मुसम्मान व निम्न सरकार ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। हम इनमें से प्रमुख समस्याओं पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं।

## समस्याएँ और उनके समाधान

(Problems and Their Solutions)

## १. समस्या—उद्देश्यविहीनता (Aimlessness)

उच्च शिक्षा की उद्देश्यविहीनता के विषय में अनेक बातें हो सकती हैं। आप यदि छात्रों या उनका अभिभावकों से पूछें कि (विद्यार्थी) किस उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आकर ६६% यही उत्तर मिलेगा कि— 'अभी तो अध्ययन कर रहे हैं।' या 'हेतु शिक्षा समाप्त करने के बाद जीवन की नौकरी मिलनी है। उच्च शिक्षा के कामकाज में अध्ययन करने वाले छात्र स्वतन्त्र रूप से समाज में विकसित करने हैं और उनका माता पिता बड़ी-बड़ा भाग्य लेकर उन पर आनी पाई। समाज का पैसा खर्च रहे है। पर अब वे बी० ए० या एम० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और सरकार पर नौकरी की शोख में टकरा मारकर भी विराम के लक्ष्य में गिर पड़ते हैं। तब वे स्वयं को समाज

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

अवस्थीर्ण होकर यथार्थता के अगत भ पदापण करते हैं और ठण्डी सास लहर सोचने हैं कि यदि उच्च शिक्षा पर इतना धन समय और स्वास्थ्य नष्ट न किया होता तो अधिक उत्तम होता। पर जिस रास्ते को तय करने के आग्र निरुप नुते हैं उससे वापिस आना असम्भव होता है। परिणाम होता है वहीं वषर्षी या स्प्रिंकोपरो करने अपने भाग्य को जोसना या ईस्वर भ विश्वास करने उसस मनुष्ट होना। साधारणत होना भी यही है कशकि भारतीयो के ममान भाग्य और भगवान् पर भरोसा करने वाल व्यक्ति जो अपने को सम्य कहने का दावा कर रखते हैं बहुत कम हैं।

समाधान—उद्देश्यों में परिवर्तन (Change in Aims)

भारत की उच्च शिक्षा-सत्वाभा को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना होगा। पर प्रश्न यह है कि ये उद्देश्य हा क्या? १८५२ में विद्वविद्यालय गिना का उद्देश्य बताते हुए न्यूमन (Newman) ने लिखा था— यदि विद्व विद्यालय की शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि यह समाज के उत्तम नागरिका का प्रतिष्ठित करना है।<sup>१</sup> एक राष्ट्र के विद्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर वहाँ के निवासियों के औद्यिक नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर का मानदण्ड है। देश का समस्त विद्वविद्यालयों से सम्बन्धित होगा है। दूषित विद्वविद्यालय सम्पूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं।<sup>२</sup> विद्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य न केवल बुद्धिमान नागरिका का अपितु सुयोग्य व्यक्तियों का भी निर्माण करना है। विद्वविद्यालय शिक्षा आयोग<sup>३</sup> ने भारत के विभिन्न विद्वविद्यालयों का भ्रमण करते समय इस बात का अनुभव किया कि सभी व्यक्ति राष्ट्रीय कल्याण के लिये विद्वविद्यालय शिक्षा का महत्त्व से अवगत थे परन्तु वे वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था को अपर्याप्तता से दग्ध थे। भावी नागरिका का निर्माण करने वाल विद्वविद्यालय शिक्षा की प्राचीन पद्धति से बाध नहीं रह सकते हैं। समाज की अभिवृद्धि जटिलता तथा परिवर्तनशील रूप का कारण यह आवश्यक हो गया है कि यदि हमारा राष्ट्रीय जीवन में

1 If a practical end must be assigned to a university course then I say it is training of good members of society  
—Cardinal Newman *The Scope and Nature of University Education* Discourse 6

2 The prosperity of the country is linked up with the university  
A vicious university is like a contaminated fountain which is bound to imperil the health of those who drink from it  
—R. A. Singh *Our Universities* p 9

प्रभावपूर्ण रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो य ध्यान उद्देश्य तथा विधिमा म  
परिचित करे ।<sup>१</sup>

विश्वविद्यालय गिर्गा आयोग' ने उच्च गिर्गा के अनेकों उत्कृष्ट निर्धारित किये हैं । ( इनका वर्णन विद्यन सम्प्रदाय में किया जा चुका है । ) जो प्रदत्तनाय है पर इनमें से अधिकांश आदर्शवाद पर आधारित हैं और उनकी न तो सत्ता प्राप्त मनु १९६६ अब तक हो पाई है और न कभी हो पाएगी ।

२ समस्या—अपव्यय (Wastage)

उच्च शिक्षा में अव्ययता आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा प्रायोग ने अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया है। सावधानता पन का प्रतिफल महान् अवश्य हो रहा है परन्तु हमारे भी अतिरिक्त दुसरे भी मानते हैं कि सावधानता पन की सम्पूर्ण हानि के प्रति उनकी ही उदासीनता है जिनकी शिक्षा और उच्च अभिव्यक्ति का समय सक्ति और पाठ्य सामग्री तथा उनकी जागरूकता और क्षमताओं पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।<sup>12</sup> विश्वविद्यालय शिक्षा में होने वाले अव्ययता का अनुमान अग्रजिन सामान्य में लगाया जा सकता है —

1 "We were everywhere struck by a deep general awareness  
of the importance of higher education for national welfare  
and as such, it was

effectively in our national life — Report of the University  
Education Commission, pp. 3-6

2 A deplorable wastage of public funds goes on year after year but what is worse there is an unconcerned complacency about this serious loss of public funds on the one hand and waste of time, energy and funds of students and their parents, besides terrible frustration of their hopes and aspirations on the other.—Report of the University

विभिन्न परीक्षाओं के फल (१९५५—५६)<sup>१</sup>

परीक्षा	सम्मिलित होने वाले छात्र	उत्तीर्ण होने वाले छात्र	प्रतिशत
एन्टर			
बी०ए०	३,०० ५२३	१ २१ ७३६	४८०
बी एम सी०	७६ ६२०	३७ ६६२	४७५
एम० ए०	३२ ६६७	१५ ६६७	४६०
एम० एम-सी०	१३ २१५	६ ३१३	७०५
व्यावसायिक	३ १५२	२,४५६	७८२
विषय	४८,४५०	३५ ७७२	७३८

## समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

इस अपेक्ष्य को राखने के लिये यह आवश्यक है कि केवल योग्य छात्रों को ही विन्विद्यालय में प्रवेश दिया जाय। सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार हार्ड स्लूट परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों में से १५ में से केवल १ को प्रवेश दिया जाय।<sup>२</sup> इससे अतिरिक्त पाठ्यक्रम में इस प्रकार सुधार किया जाय कि वह साहित्यिक न रहकर व्यावहारिक हो जाय अथवा अनुत्तीर्ण छात्रों की समस्या में बची न हो सकेगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और अग्रजों का शिक्षा के माध्यम व पर से हटाना भी आवश्यक है। सभी उच्च शिक्षा के अपेक्ष्य को कम किया जा सकेगा।

## ३. समस्या—दोषपूर्ण पाठ्य-क्रम (Faulty Curriculum)

हमारी उच्च शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्य-क्रम एवं नहीं अपने दावा में परिपूर्ण हैं। अधिकांश कनिष्ठा में वही पित पित विषय मिलते हैं। जिस स्थान व उत्साही अथवा धन-मोक्षु व्यावसायिक विचारों के व्यक्तियों ने एक ईट की दीवार तहो करने छन को पूँछ या टीन से ढक किया और इतिहास राजनीतिशास्त्र तथा अध्यात्म व विज्ञान की व्यवस्था कर ली व उनका विन्विद्यालय से मायका प्राप्त हो गई। सीनिए उस स्थान पर उच्च शिक्षा का जितना सुन्दर प्रकल्प हो गया। अब वहाँ व छात्रों का बाहर रहकर अध्ययन पर धन व्यय नहीं करना पड़ेगा। एवं यिनि तब इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करके शिक्षा का बिलाल करना अनुपेक्षनीय है। पर ध्यान के भारत व निम्न इस प्रकार का पाठ्य-क्रम छात्रों और दण व नियम विष

१. Education in India (1955-56), p. 197  
 २. Sargent Report p. 32

की योजना से कम नहीं है। कारण यह है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के छात्रों की क्षमताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। परन्तु हम उनका मानविक विकास अवगुह हो जाता है।

### समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

इन समस्या का समाधान करने का उपाय है। हमारे विद्य विद्यालयों के पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के छात्रों की क्षमताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। परन्तु हम उनका मानविक विकास अवगुह हो जाता है। इस दोष का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि विद्य विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार की विविधता आयेगी जो आम जनता की क्षमताओं के अनुरूप न होकर विद्य विद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित की है। विद्य विद्यालयों के पाठ्यक्रम का मूलाधार होना आवश्यक है किन्तु उसकी परिवर्तनशीलता समाज की परिस्थितियों और उसका विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। विद्य विद्यालयों का निर्माण कुछ समय के लिए न कि स्थायी के लिए किया जाता है। मानव की शिक्षा देने की कोई स्थायी विधि नहीं है। जो पाठ्यक्रम यदि हमें पुनर्गठन के पुनर्गठन में उपयुक्त या उसे २०वीं शताब्दी के विद्य विद्य विद्यालयों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।<sup>1</sup> अतः हम आवश्यक है कि हमारे विद्य विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मर्यादीत सुधार किया जाय।

### ४ समस्या—शिक्षा में विशेषीकरण (Specialisation in Education)

विद्य विद्यालयों में शिक्षा का एक गहरा समस्या यह है कि विभिन्न विद्यालयों में विशेषीकरण पर बल दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि विद्य विद्यालयों में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्रों की विद्य विद्य विद्यालयों में ही समाप्त हो जाती है परन्तु उनका दृष्टिकोण अनुभूति रहता है और वे पूर्णतया शिक्षा भ्रष्ट नहीं बन जाते हैं।<sup>2</sup> अतः हमें उचित शिक्षा है "विशेषीकरण में एक प्रकार का स्वीकार्य एक आवश्यकता होती है

1 Educational systems are built for a time and not for all time. There are no classless ways of education of human nature. A curriculum which had vitality in the Vedic period or the Renaissance cannot continue unaltered in the 20th Century. —Report of the United Nations Educational Commission p 41.



भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

जिसका परिणाम यह होता है कि विज्ञान के छात्रों को कला और कविता तथा सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है और छात्रों को विद्यापिया का इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियाँ न उस संसार का जितना वे निवास करते हैं वित्त प्रसार परिवर्तित कर दिया है ।

समाधान— सामान्य शिक्षा की व्यवस्था (Provision for General Education)

यह आवश्यक है कि ज्ञान को विभिन्न शाखाओं एवं अनुभवों में अन्तर्मुख एवं सामंजस्य हो । जब तक छात्र ज्ञान तथा अनुभव की एकता का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनके मस्तिष्क का समुचित विकास सम्भव नहीं होगा । विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में कला एवं विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षा (General Education) की भी व्यवस्था की जाय जिससे कला एवं साहित्य व छात्र विज्ञान के विषयों का और विज्ञान के छात्र कला एवं साहित्य व विषयों का ज्ञान अर्जित कर सकें । इस प्रकार सामान्य शिक्षा तथा विशेषीकृत शिक्षा (Specialization) में सामंजस्य स्थापति करके समुचित विनिष्टता को दूर किया जा सकेगा । साथ ही छात्रों के व्यक्तिगत विकास का उपयुक्त विकास हो सकेगा और वे सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे । सामान्य शिक्षा का वास्तविक विकास तथा वास्तविक-वस्तु विनिष्टता का अनुभव होने चाहिए । इस का विषय है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में स्थान दिया जाय । सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालयों व वास्तविक-वस्तु

५. समस्या मार्ग-प्रदर्शन एवं समर्थन का अभाव (Want of Guidance and Counselling)

हमारे उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का पथ प्रदर्शन करने और उनकी परामर्श देने की कोई व्यवस्था नहीं है । इस अभाव में छात्र स्वयं अपनी पथों में या गिरी अनुभवहीन व्यक्ति व परामर्श से वास्तविक-वस्तु के विषयों का

There is a certain narrow unimaginative type of specialisation which results in the science students being complacently ignorant of art and poetry and art students having no appreciation of how science and the scientific technique have transformed the world in which they are living — A. G. Sanyal Education Culture and Social Order p 163

घटन करते हैं। परिणाम यह होता है कि अनेक छात्र ऐसे विषयों का चुनाव कर लेते हैं जो या तो उनकी प्रवृत्ति व प्रवृत्तियों से हैं या जिनका अध्ययन करने की उनमें समझ नहीं होती है। जब उन्हें इस बात का ज्ञान होता है तब इतना विलम्ब हो जाता है कि वे अपने को कुछ करने में असमर्थ पाते हैं। फलतः उन्हें छात्र जीवन में असफलता और अन्य असफलता व परिणामस्वरूप व्यावहारिक जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है।

**समाधान—**साथ प्रवर्धन एवं समुपदेशन की व्यवस्था (Provision for Guidance and Counselling)

इस बात का आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा व विद्यालयों में आदि से लेकर अन्त तक छात्रों को अनुसूची तथा प्रवर्धित स्थितियों का पर्याप्त एवं परामर्श प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था मुक्तानियत समाधान व माध्यमों विद्यालयों व छात्रों के लिए की है वही ही व्यवस्था विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा व विद्यालयों व छात्रों के लिए भी की जानी चाहिए।

**६. समस्या—शिक्षा का निम्न स्तर (Low Standard of Teaching)**

हमारे कनिष्ठों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर पर्याप्त निम्न है। आर्यभट्ट ने उचित ही लिखा है— हमारे ज्ञान और शिक्षा का स्तर बहुत कम ही था जो कि बहुत कम ही था। परन्तु अब वह प्रति स्तरिता में नीचे की ओर जा रहा है।<sup>1</sup> इसका अनेक कारण प्रस्तुत किए जाते हैं। एक बात स्पष्ट है कि कनिष्ठों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर कार्य का भार अधिक है। कमसंख्या के अपने व्याख्याताओं की पूर्ण क्षमता में तैयार करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। कक्षाओं में इतने अधिक छात्र होते हैं कि उनमें और अध्यापकों में व्यक्तिगत सम्पर्क असम्भव होता है। ट्यूटोरियल पद्धति विदेशी शिक्षाओं और पुस्तकालय में अध्ययन करने की प्रथा का पूर्ण अभाव है। फिर अध्यापकों का ध्यान इस बात से है कि उन्हें अपने कार्य में रुचि लेने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। साथ ही छात्रों की प्रवृत्ति इन सब बातों में अध्ययन करना पड़ता है कि कुछ घटा व पढ़ाया सब कुछ अपने हाथ में उठा लिये और बिना प्रयोग के न सता है।

1 Our standards whether in scholarship or teaching are very high or exacting are now fast sinking to the bottom."  
—A.R.S. Iyengar, A New Deal for Our Universities p. 29

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

अध्यापन के स्तर की ऊँचा उठाने के लिये अनेक सुझाव दिये जा सकते हैं जिनमें से प्रमुख हैं—अध्यापकों की वेतन-वृद्धि उनके द्वारा सप्ताह में १८ घंटे अध्यापन-कार्य उनके सेवा प्रतिबंधों में सुधार ट्यूटोरियल कक्षाओं की व्यवस्था पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का सुसज्जन एवं विमर्श-गोष्ठियाँ को प्रोत्साहन ।

७ समस्या—शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी (English as Medium of Instruction)

हमारे देश को स्वतंत्र हुए आज १८ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर अब भी उच्च शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम के रूप पर अंग्रेजी भाषा प्रचलित है । हमारी दीर्घकालीन दासता ने हम में अंग्रेजी के प्रति इतना मोह उत्पन्न कर दिया है कि हम अब भी उसका आचल पकड़े हुए हैं । परन्तु इतने हमारे नवयुवकों का कितना अहित हो रहा है इस बात को हमने अभी ध्यान में नहीं लाया है । इस सम्बन्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मत था— विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है । इनके अतिरिक्त गांधी जी का मत था— हमने अपने जनसाधारण से वृष्ण कर दिया है । हमने शिक्षा को आवश्यक रूप से महंगा बना दिया है ।

समाधान—शिक्षा का माध्यम संघीय भाषा (Federal Language as Medium of Instruction)

यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अंग्रेजी की दीर्घातिशील शिक्षा के माध्यम का रूप से हटा लिया जाय । विश्वविद्यालय आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रादेशिक भाषा या संघीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाय । अधिक उपयुक्त यह होगा कि संघीय भाषा की शिक्षा का माध्यम बनाया जाय जिससे देश के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त के माध्यम स्थापित करने और अतिसार भारतीय सेवाओं की परीक्षा करने में सुविधा हो ।

८. समस्या—दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली (Defective System of Examination)

हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षा-प्रणाली अनेक दोषों से युक्त है । भारत का 'जननी मा भूमिनिषा' एवं आयोग नियुक्त किये गए हैं उन सब में इन दोषों का दूरण । The imposition of a foreign medium has sapped the energy of the nation. It has shortened the lives of the people. It has estranged them from the masses, it has made education unnecessarily expensive.

दाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। १९०२ के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का बयन था— भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि शिक्षण परीक्षा के आधेन है न कि परीक्षा शिक्षण के।<sup>१</sup> १९४६ के विश्वविद्यालय आयोग का मत था— यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा के केवल एक विषय में सुधार का सुझाव दें, तो वह परीक्षाओं के सम्बन्ध में होना चाहिए।

### समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं—बैज्ञानिक पद्धति का परीक्षा-पद्धति में प्रियामित करना, छात्रों का प्रगति-परीक्षाओं द्वारा परीक्षा करना सम्पूर्ण प्रगति-परीक्षाओं का कुल तैयार करना और प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के लिए प्रमाण ७०, ५५ और ४० प्रतिशत अंक निर्धारित करना।

### ६ समस्या—अनुशासनहीनता (Ladiscipline)

माध्यमिक शिक्षा के समान उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर भी छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या है। कमरता विश्वविद्यालय के उद्घोषणा प्रोग्राम पर एन० के० मिश्रा ने उच्च शिक्षा संस्थाओं के छात्रों का अनुशासन हीनता के अनेक विभिन्न प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया है<sup>२</sup> यथा—

- १ धन-सम्बन्धी अनियमितता (Financial Irregularity)
- २ गायारण दुर्व्यवहार (Minor Misconduct)
- ३ उच्छ गम व्यवहार (Disorderly Conduct)
- ४ यौन-सम्बन्धी दुर्व्यवहार (Sex Misconduct)
- ५ चोरी और गैरमारी (Theft and Burglary)
- ६ प्राधिकारों का दुरुपयोग (Misuse of Privileges)
- ७ परीक्षा में धूर्तता (Cheating in Examination)

१ The greatest evil from which university education in India suffers is that teaching is subordinated to examination and not examination to teaching. —Report of the Indian University Commission

२ If we are to suggest one single reform in university education it should be that of examination —Report of the University Education Commission, p. 225

३ N. K. Saha : The Problem of Discipline in Indian Universities, p. 4

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ित होती जा रही है। 'उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन बनाय रखने की समस्या प्रतिदिन प्रचिन्न महत्वपूर्ण होती जा रही है।'

### समाधान—कुछ सुझाव (Some Suggestions)

अनुशासनहीनता की समस्या का उपशमन करने के लिये प्रोफ़ेसर सिद्धान्त ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्येक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता के प्रकार के आँकड़े रखे जाय।
2. अपराध करने वाले छात्र के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन और जहाँ उसने पढ़ित अध्ययन किया है वहाँ के अधिकारियों का अध्ययन किया जाए।
3. छात्रक अपराध के कारण की खोज की जाय।
4. अपराधी छात्र से एक विशेषज्ञ के द्वारा छात्रावस्था किया जाय और वह छात्र से अपराध की गम्भीरता और उसका द्वारा दाने वाली दानि पर विचार विमर्श करके उसको यह समझाने का प्रयत्न करे कि उसका काम उचित नहीं है।

उपरोक्त सुझाव तो उत्तम हैं ही पर इनके अतिरिक्त कुछ और उपायों की भी काम में लाया जा सकता है यथा—पसलू छात्रावस्था में सामुदायिक जीवन योजनायों का छात्रों द्वारा प्रवर्धन का विज्ञान और गोष्ठियाँ। पर इस बात की अपेक्षा आवश्यक है कि इन कार्यो में शिक्षक अग्रणी हों।

### 10. समस्या—छात्र-समितियाँ (Student Societies)

उच्च शिक्षा-मण्डलों में छात्र समितियों की समस्या अति प्रबल है। इस सम्बन्ध में डॉ॰ ए॰ आर॰ बी॰ राय (B. K. R. Rao) ने अपने विचार

1. 'The problem of maintaining discipline in the seats of higher education is assuming greater importance every day' —Indian Univerity Administration p 98
2. N. K. Sidhanta op cit pp 6-7
3. The best way of solving the problem of indiscipline is to divert the activities of your students into healthy channels including sports games & co-operative living in hostels self management of messes debates and symposia. However the lead in all these matters should be given by the teachers themselves —Indian Univerity Administration p 98

एक प्रकार का एक विषय है। 'छात्र समितियाँ' के अन्तर्गत मैं अपने सहयोगियों व विचार अथवा विचार व अनुसूच बनाने व सिद्ध विचार रूप में चिन्तित हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में इन प्रकार की समितियों की अति विरागता मर्यादा है जिनमें से अनेक सशक्त नहीं हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि उनको अपने पर बड़ी मर्यादा मिलती है या वे उनको किस प्रकार व्यय करती हैं। मैं यह समझता हूँ कि कभी-कभी चिन्तित पर इन बातों विचार विवेचन के अन्तर्गत उनको मिल जाते हैं। मेरा विचार है कि अनेक ऐसी समितियाँ की उपस्थिति के कारण ही छात्र गतिविधियों का निर्माण होता है।<sup>1</sup>

इन छात्र समितियों में जो हानियाँ होती हैं व गतिविधियाँ हैं। छात्र काय कला कलित व अथवा काय में हानि हो सकती है। य व कलित व गतिविधियों में प्रविष्टता या प्रवृत्ति काई तरह कार्य करने है जो उनको हानि व प्रविष्टता होता है। वे उनका विरोध करते हैं। इनका हा नब कुछ नहीं है। य जानते हैं कि कलित व अथवा काय की निर्मुक्तियाँ उनके अथवा काय एवं कलित से सम्बन्धित सभी मामलों का प्रविष्टता उनका परामर्श से किया जाय। ऐसी दशा में य समितियों कलित व निम्न अथवा काय मिष्टता है।

### समाधान—छात्र-समितियों का पंजीकरण (Registration of Student Societies)

भारतीय शिक्षा विभाग छात्र-समितियों का विरोध नहीं है। इसका विरोध व जानते हैं कि इन प्रकार की समितियों का संगठन किया जाय व या उनको अपनी मानसिक क्षमताओं व प्रवृत्ति का अवसर मिले। उनमें मनुष्य व गुणों का विकास करता है और उनका मानसिक सम्बन्ध का विकास करती है। पर शायद य समितियों अनुचित ढंग में कार्य करती मर्यादा है। उन्मुखता—उनका उद्देश्य कि वे शिक्षकों व गुरुओं को स्थापित करने हैं कि वे उनका का

1 'There is the question of student societies on which I am particularly anxious to canvass the opinion of my colleagues. We have a large number of societies in our universities of which many are not even registered. We do not know how they get their funds nor how they disburse them. Sometimes if I may say so for a fund of a disbursement large may make get involved. Indeed talking of student politics I think they emerge because of the existence of many such organisations. —*Indian University Association* by K. P. V. Rao Speeches on the Indian University Students pp 104-105

योजनाएँ बनाने हैं और विश्वों में धन प्राप्त करते हैं। इन सब बातों का राज्य-समुदाय पर अति दूषित प्रभाव पड़ता है। अतः इनका रोक जाना आवश्यक है।<sup>1</sup> हमें लिये वी० के० आर० वी० राव (V. K. R. V Rao) का मुझाव है कि सब विश्वविद्यालय या कॉलेज-समितियों के लिये एक कानून बना लिया जिसके अनुसार उन्हें अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाय, और जिससे वे अपने समासदा के निर्वाचन के समय कुछ नियमों का पालन करें और अपने आय-व्यय तथा अन्य बातों को रख-बंद करें।<sup>2</sup>

### उपसंहार

उपरिखणित प्रायः सभी समस्याओं की ओर विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ है और उसने उनका समाधान के लिये अपने प्रतिबन्धन में अनेक उपचारों का प्रस्ताव किया है जिसमें से अधिकांश का सरकार द्वारा स्वीकार करवा जाया-वत कर दिया गया है। हम आशा है कि उच्च शिक्षा अपनी वर्तमान समस्याओं से मुक्त होकर भारत के नवयुवकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के साथ-साथ उनकी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्तियों को भी विकसित करके उन्हें देश के वांछ्य नागरिक बनावेगी।

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. What are the present developments in Higher Education in India? Write a critical essay giving your views on the reorganization of Higher Education
2. Summarise briefly the problems of Higher Education and suggest their remedies

1. Unfortunately we have in our universities certain very undesirable elements many of whom are in contact with embassies, ... money from outside sources ... effect on the student ... —Indian University Administration V. K. R. V Rao's Speech on Problems Affecting University Students p 105
2. "I should like to suggest that legislation be introduced for the registration of all university or college societies to ensure that they observe certain rules for elections methods of keeping accounts and similar other things —Ibid p 105

२७

## समाज (प्रौढ़) शिक्षा (Social Adult Education)

### प्रौढ़ अवस्था समाज शिक्षा का इतिहास (History of Adult or Social Education)

समाज शिक्षा व इतिहास पर दृष्टि डालने से पूर्व हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि १९४६ में—जिसे हम समाज शिक्षा कहते हैं—उसे उस समय से पूर्ण प्रौढ़ शिक्षा की संज्ञा दी जाती थी।

बीसवीं शताब्दी के उदात्त नाम में आंग्लो-संस्कृत ने एक नवीन युग में प्रवेश किया था। राष्ट्रीय आन्दोलन में जन-जन के अन्दर से स्वदेश प्रेम की भावना को प्रोत्साहित कर दिया था। देश के समस्त नेताओं ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने न केवल स्वदेशी शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने न केवल स्वदेशी शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने न केवल स्वदेशी शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने न केवल स्वदेशी शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे थे।

२१६



## १९२१ से पूर्व प्रौढ़ शिक्षा

१९२१ से पूर्व प्रौढ़ शिक्षा का लिये किये गये प्रयास प्रायः नगण्य थे। निम्न-देह शुद्ध रात्रि विद्यालयों का देश के विभिन्न भागों में निर्माण किया गया था परन्तु इनका उद्देश्य—फैक्टिया आदि में कार्य करने वाले उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना था जिन्हें दिन में अध्ययन करने के लिये समय नहीं मिलता था। शुद्ध बयस्क भी उनमें शिक्षा ग्रहण करते थे परन्तु विद्यालयों का प्रमुख ध्येय—उन्हें शिक्षा देना नहीं था।

✓ 'भारतीय शिक्षा-आयोग' (Indian Education Commission) की रिपोर्ट के अनुसार बम्बई प्रान्त में १८८१-८२ में १३४ वर्गवृत्तलय रात्रि विद्यालय थे। इनके अतिरिक्त 'दिवा विद्यालयों' (Day Schools) से सम्बद्ध २२३ रात्रि विद्यालय थे। इन बयस्क विद्यालयों में छापाखाना सिराना पढ़ना और भक्षणित की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों की लोकप्रियता एक माँग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। इनकी सफलता देखकर आयोग ने सुझाव दिया कि देश में सभी सम्भव स्थानों पर रात्रि विद्यालयों का संचालन किया जाय। परन्तु दुर्भाग्यवश इस ओर रस मात्र भी व्यक्त नहीं किया गया और बयस्क छात्रों की प्रगति न हो सकी।

१९०१-०२ में बेचन महान बम्बई और बंगाल में रात्रि विद्यालय संचालित थे जिनमें प्रौढ़ शिक्षा का प्रवेश था। परन्तु सरकार की उपेक्षा के फलस्वरूप वे परिणामहीन न हो गए और १९१७ तक इनका सन्नाह में निरन्तर संचालन होता चला गया।

१९१९ के 'भारत-सरकार अधिनियम' (Government of India Act) द्वारा भारतीयों को अति विनाश जनकता में मनदान का अधिकार प्राप्त हो गया। अतः प्रौढ़ शिक्षा में जन-साधारणों की रुचि उत्पन्न हुई। सामाजिक या व्यक्तिगत अनुभव किया गया कि शिक्षा के अभाव में भारतीय जनता महाविचार का अधिक उपयोग नहीं कर सकेगी। इस परिबर्तित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देश में बयस्क साक्षरता के लिये विचार-मंच पनपने लगे। सरकार ने भी धार्मिक सहायता के रूप में पुनः कार्य में योग दिया। परिणामस्वरूप गुरुकुल प्रायः पंचाशत् बम्बई मध्य प्रायः बंगाल और मद्रास में रात्रि विद्यालयों तथा रात्रि-विद्यालयों का अन्वयन किया गया।

## १९२१ से १९३७ तक

इस काल की एक प्रमुख विद्यमान थी—प्रौढ़ शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना। इसका श्रेष्ठ भारतीय महिलाओं को था जिन्होंने भारतीय शिक्षा का

इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया। यद्यपि उनका प्रयास अनिश्चित एवं व्यर्थान्त था, फिर भी उन्होंने अपने देशवासियों और सरकार को एक सच में कार्य करने के लिए अनुप्राणित किया जो शिक्षा प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता थी।

१८२१ में भारत-सरकार-अधिकारों का वर्गीकरण कर दिया गया और हस्तान्तरित विषयों को जनप्रिय संग्रहालयों में रखा गया और सौंप दिया गया। शिक्षा भी एक हस्तान्तरित विषय था। भारतीय अधिकारों ने ग्रीक शिक्षा की समस्या में अत्यधिक रुचि व्यक्त की। परम्परागत भारत के विभिन्न प्रांतों में व्यवस्था-साधारण को सांख्यिक दत्तों के लिए अनवरत परिश्रम किया जाने लगा। परन्तु ग्रीक शिक्षा ने समस्त पराक्रम पर आता अभियान प्रारम्भ किया ही था कि १८२७ के विचारणीय अधिनियम ने ३३४ माह को १२५५ पर दिया। यथासार में व्यवस्था-साधारण का पार में सरकार और जनता—दोनों में मुक्त भाव लिया। परन्तु ग्रीक विद्यालयों का संख्या धारा होना बना रहा। १८३७ में इन प्रकार के पुराने विद्यालयों की संख्या २०१६ और नवी विद्यालयों की ११ रह गई।

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट हो जाता है कि १८७७ तक ग्रीक शिक्षा के सिधे जो चेष्टाओं की गईं उनका कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। परन्तु यह बात सचमुच है कि उन चेष्टाओं का व्यवस्था शिक्षा की नींव डालना और उसी नींव पर उद्युक्त परिधिपरिधि के उत्पन्न हो जाने पर ग्रीक शिक्षा का भवन का निर्माण किया गया।

### १८३७ से १८४७ तक

१८३७ में कायदा परिवर्तन के द्वारा में व्यापक ज्ञान की बगलोर का जाने में जन शिक्षा का भाव ने पाला लगा। शिक्षा प्रसार के आने कायदा के अन्तर्गत ब्रिटिश अधिकारियों ने ग्रीक शिक्षा का समर्थन पर शुरू किया। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने भी १८३८ में बंगाल शिक्षा-अधिकारों की नियुक्ति करके प्रथम बार बंगाल शिक्षा में अपना रुचि व्यक्त की।

ब्रिटिश अधिकारों ने विभिन्न प्रांतों में भी जो ज्ञान दान के लिए या दान के लिए दत्तों की पर परिश्रम साध किया जा रहा है —

प्रथम—इस प्रकार में बंगालों का सरकार दत्तों का कार्य शिक्षा-विभाग की नींव डाला। यह विभाग ने जो कार्य दत्त बंगालों का सरकार के सामने एवं सरकारों के उत्तरदायी शिक्षा का व्यवस्था की।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

**बंगाल**—इस प्रांत में सरकार ने ग्राम-सभाओं द्वारा संचालित प्रौढ़ पाठशालाओं को विकसित करने तथा अधिक सहायता देकर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की।

**बिहार**—इस प्रांत में प्रौढ़ शिक्षा का सबसे अधिक विस्तार हुआ। यहाँ अपना गृह सागर बनाओ—(Make your home literate) नामक आन्दोलन प्रारम्भ किया गया और हजारों ग्रामों में पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये।

**बम्बई**—यहाँ १९३७ में एक प्रांतीय प्रौढ़ शिक्षा-परिषद् संगठित की गई जिसके तत्वावधान में बम्बई नगर में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया। यह योजना इतनी अधिक सफल हुई कि बम्बई नगर में व्यवस्था को साक्षर बनाने के उद्देश्य से बम्बई नगर व्यवस्था शिक्षा-समिति का निर्माण किया गया।

१९३८ में बम्बई सरकार ने एक एड होक एड्युकेशन एडवाइजरी बोर्ड (Ad Hoc Education Advisory Board) नियुक्त किया। इस बोर्ड ने एस आर भगत (S R Bhagat) को अध्यक्षता में निरक्षरता में निवारण के विषये प्रांतीय कार्य किया।

**उड़ीसा**—इस प्रांत में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के कार्य काल में व्यवस्था शिक्षा का कार्य अति तीव्र गति से आगे बढ़ा परन्तु मंत्रियों के बदलाव करते ही इस कार्य का प्रवाह मन्द होकर शीघ्र होना चला गया।

**पंजाब**—इस प्रांत में गैर-नरनारी मंत्रिमण्डल होने के कारण प्रौढ़ साक्षरता का कार्य कम किया गया। परन्तु फिर भी सरकार ने व्यवस्था में हजारों पुस्तकों का बिना कोई भ्रूय सिधे वितरण किया।

**उत्तर प्रदेश**—इस प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में स्तुत्य योगदान दिया। स्वान-स्थान पर प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये गये और व्यक्तियों के नियुक्तों का प्रचार किया गया।

१९४७ से १९६५ तक

स्वतन्त्र भारत में प्रौढ़ शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। १९४६ में प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) को सामाजिक शिक्षा (Social Education) का नाम देकर उग्ररे रूप का अधिकारित तथा परिचालित किया गया। यह निश्चय किया गया कि निरक्षर व्यवस्था का सागर बनाने में माध्यम मापदण्डों की शिक्षा भी प्रणाली का कार्य है। इस प्रकार सामाजिक शिक्षा का





स्पष्ट मय का दारुण की अनुमति दे ता मैं कहूँ कि वेवल राजनीति स्वतंत्रता विभी भी समाज या राष्ट्र का सिय उत्तम जीवा' (Good Life) का आनन्द नहीं दे सकता है। हम सभी प्रकार जानते हैं कि कनेका राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होत हुए भी अथ श्रद्धासाधक आरुह है आ उहे उत्तम जीवन की ओर अग्रसर नहीं हो देती हैं क्योंकि इस प्रकार का जीवन बहुत पश्चिम तथा समाजवादी कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में जब तक जनता निरन्तर सतर्कता (Eternal Vigilance) का रूप में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का मुख्य ध्यान का नियम ठहरा नहीं, तब तक वह हम स्वतंत्रता की भी सुरक्षा नहीं रख सकती है और हम उत कता के लिए उचित नागरिक तथा सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता है। यदि हमारा लक्ष्य केवल है और हम अपनी राजनीतिक स्वातंत्रता के सुरक्षित सामाजिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक आनन्द का लक्ष्य तो पहुँचना चाहता है तो स्पष्टता हम जनसाधारण का नियम नहीं अथि उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होगी। नहो गो लक्ष्य हम मान का मय रहता है बहुत परन्तु वर्तमान हम अथवा व्यक्ति अपने निरुद्ध उद्देश्य का पूर्ति का नियम तत्कालिन् स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाएँगे। इसी कारण मैं सरासरी तथा बहु पक्षों पर प्रोफ़ शिक्षा (Adult Education) का आन्दोलन प्रारम्भ करने का राजनीतिक अधिकार का आधार कहूँगा।<sup>1</sup>

इन सब में शिक्षा-सामर्थ्य लक्ष्य न राष्ट्रीय जीवन में समाज शिक्षा का स्थान तथा मध्य का अद्वितीय शिक्षा है। — 1. राजनीतिक स्वातंत्रता की सुरक्षा का नियम निरन्तर आकाश का और सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य तथा पक्ष का नियम जनसाधारण का उच्च शिक्षा की आवश्यकता उर्ध्व है एवं इन दोनों की पूर्ण करने का नियम प्रोफ़ शिक्षा का आनन्दन पर धन दिया है। भारत में प्रोफ़ शिक्षा का बहुत आनन्दन नियम प्रकार शिक्षा जा रहा है इस — 1. जन का स्वतंत्रता की शिक्षा प्रोफ़ है इन स्वतंत्रता का मार्ग में जीवन का शिक्षा है। इन का शिक्षा का नियम प्रकार दूर शिक्षा जा सकता है? — 2. तथा इन का स्वतंत्रता का पर विचार करना ही प्रोफ़ पाठ की शिक्षा-समर्थ है। परन्तु हम सामर्थ्य का प्रोफ़ीकरण में प्रोफ़ शिक्षा तथा समाज शिक्षा शिक्षा का लक्ष्य का लक्ष्य-लक्ष्य करना अधिक सुविधुन प्रोफ़ है।

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

### प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Adult Education)

प्रौढ़ शिक्षा' के अर्थ की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। जहाँ कि प्रौढ़ शिक्षा शब्द से व्यक्त होता है। इसका अर्थ है—निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ना सिखाना अर्थात् कुछ लिखित चिह्नों को उनकी ध्वनि तथा अर्थ के रूप में पहचानना सिखाना। परन्तु वास्तविकता में प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ इससे बहीं अधिक व्यापक है। इसको स्पष्ट करते हुए एस० एन० मुन्शी ने लिखा है प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो पहलू हैं (१) प्रौढ़ साक्षरता अर्थात् उन प्रौढ़ों की शिक्षा—जिनको विद्यालयों में कभी भी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और (२) साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा।<sup>१</sup> समय-समय पर प्रौढ़ शिक्षा में राजनीतिक और नागरिक तथा नैतिक शिक्षा भी सम्मिलित हैं।<sup>२</sup>

### प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा (New Concept of Adult Education)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समय पूर्व ही भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरान्त देश के नेताओं ने राष्ट्रीय जीवन में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। उन्हें यह पूर्ण रूप से आभास हो गया कि यदि इस मनुष्य तथा प्राचीन देश को जीवित रहना है तो इस देश में निरक्षर व्यक्तियों को कबल साक्षर ही नहीं बनाना है, बल्कि उनका शैक्षिक सामाजिक तथा नैतिक उन्नयन भी करना है। इसी विचारधारा से अनुप्राणित होकर देश के राजनीतिक दल पक्षों ने प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) को एक नवीन रूप प्रदान कर उसको बलिष्ठ आधार बनाया और उसको समाज शिक्षा' (Social Education)

1. Adult education may be defined very broadly so as to include all instruction formal or informal imparted to adults. In India adult education has two aspects (i) Adult literacy i.e. education of those adults who never had any schooling and (ii) Continuation education of the literate.—S. N. Mukerji, Education in India—Today and Tomorrow, pp. 344-45.

2. Adult education includes political and civic as well as moral education.—K. S. Sanyal, op. cit. p. 243.

का नया जामा पहिनाया। जनवरी १९८६ में इसाहबान में होने वाला केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education) के पाठ्यक्रमों अधिदेशन में भाग लेने के लिए श्रीमानों प्रमुख वसुधाय आजाद ने प्रोफ़ेसरों व प्रति भाग्य-सम्पन्न में नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रोफ़ेसरों का उद्देश्य समय-समय पर नवीन ज्ञान को ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु हमारे अन्दर 'उम' शिक्षा का भी समावेश करना चाहिए जो मानव व प्रत्यक्ष ज्ञान के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक है। उनी समय में प्रोफ़ेसरों का ध्यान से परिपूर्ण होना और उनी 'महाविद्यालय' में नए नए परिवर्तन आने लगे।

प्रौढ शिक्षा तथा समाज शिक्षा में अन्तर

(Difference Between Adult & Social Education)

प्रौढ़ गिणा तथा समाज गिणा व जनता की एक प्रकार का विद्या या सज्जता है। प्रौढ़ गिणा को गन्तुल्यमा से आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। मान्यता व अरुण छोटे दायरे में निबल कर बड़े सामाजिक गिणा का व्यापक रूप धारण कर चुकी है। पश्चिम उत्तरा आधुनिक व कम औपचारिक या और व्यक्ति को माहिर बनाकर और उसमें विश्वास बढ़ा बहुत पढ़ने लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं और बतलाने की विधा समझ लेनी पड़े। अब हमका लक्ष्य प्रौढ़ों की इस प्रकार की गिणा देना हो गया है (जिसमें १. व्यक्ति व रूप में और समाज व एक भूत व रूप में चयन। अभाव दान देना व उत्तर उत्तर पश्चिम में अधिक सम्पन्न और प्रगल्भ जीवन व्यतीत कर सकें) ।

ममाज्ज निदा। वा अथ एव वदि नापा

### **(Meaning & Definition of Social Education)**

समाज जिन्हा व अर्थ की स्पष्ट करी हूँ सोमाना बहुत बलवान आवाज  
ने दुनियाँ परिभाषा इन हाथों में की समाज जिन्हा में हमारा तात्पर्य है—  
पूर्ण मानव की जिन्हा । यह उसका मातृभूत प्रदान करता जिसमें कि विरह का  
ज्ञान उसे उसमें ही मर । यह उसका ब्यापक कि वह अन्तर प्रान्त पर  
करता मे अनुक्रमित कि प्रकाश कर और जिन्हा प्राकृतिक दशाभा में वह निवास  
करता है उनका सर्वोत्तम प्रयोग कि प्रकाश कर । इसका अन्तर्गत उस उसमें

[illegible]



कृषा बोधना तथा उत्पादन का विधियों की शिक्षा देना है, जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति का प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज—दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धान्तों की शिक्षा देना भी है जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके। इस शिक्षा को हम नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं जिससे कि उसे सशर की बातों का कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय और वह अपना सरकार को उन निएयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शान्ति तथा प्रगति में योग्य प्रदान करें।<sup>1</sup>

समाज शिक्षा का परिभाषा करते हुए हमारे कबोर ने लिखा है समाज शिक्षा का अध्ययन व हर प्रकार के पाठ्यक्रम का रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य—व्यक्तियों में नागरिकता की जतना का उदय और उनमें सामाजिक सम्बन्ध का उत्थान करना है। समाज शिक्षा निरन्तर बसती है समाजता का प्रसार करके जो समुष्टि बना होती है अर्थात् जन साधारण में शिक्षित मस्तिष्क के निर्माण का अपना लक्ष्य बनाती है। स्वाभाविक उपसर्ग के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति में व्यक्तिगत तथा समाज के सदस्यों के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयास करती है।<sup>2</sup>

1 By Social Education we mean an education for the complete man. It will give him literacy so that knowledge of the world may become accessible to him. It will teach him how to harmonise himself with his environment and make the best use of the physical conditions in which he subsists. It is intended to teach him improved crafts and modes of production so that he can achieve economic betterment. It also aims at teaching him the rudiments of hygiene both for the individual and the community so that our domestic life may be healthy and prosperous. The last but not the least this education should give him training in citizenship so that he obtains some insight into the affairs of the world and can help his Government to take decisions which will make for peace and progress. —Abul Kalam Azad's Inaugural Address to the UNESCO Seminar on Rural Adult Education held in December 1949 in Mysore

2. "Social Education may be defined as a course of study directed towards the production of consciousness of citizenship among the people and the promotion of social solidarity among them. It is not content with the introduction of literacy among the grown up illiterate but aims at the production of an educated mind among the

पूर्वोक्तलिखित परिभाषाओं के आधार पर हम समाज शिक्षा के अर्थ का निर्धारण रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं —

‘समाज शिक्षा एक नियंत्रित अनुभव है जो व्यक्ति की सामूहिक जागीर में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। समाज शिक्षा नागरिकता का उचित मूल्यांकन करने का चतन्य एवं नायना का ज्ञान देती है व्यक्तियों के स्वतन्त्रता तथा अधिकारों का स्थापना करने के और यह शिक्षा देती है कि वे अपने सामाजिक नायना पर अवलम्बित होकर ही भी किसी विषय का अनुमरण करके अपनी जाय में वृद्धि कर सकते हैं।

### समाज शिक्षा का पंचमुखी पाय क्रम

(Five Point Programme of Social Education)

भारत-सरकार द्वारा समाज शिक्षा की योजना धारणा के अन्तर्गत न केवल साक्षरता के महत्त्व का स्वीकार किया गया है अपितु यह भी स्वीकार किया गया है कि बचपन का विभिन्न अधिकारियों का विश्रुत करने का प्रयास किया जाय। अतः सरकार ने समाज शिक्षा के निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम का निर्माण किया है<sup>१</sup> —

१. साक्षरता का प्रसार।
२. स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान के विषयों की शिक्षा।  
बच्चों की शारीरिक शिक्षा के लिए उद्योग चलाये जायें।
४. बचपन में अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति पर्याप्त जागरूकता का साथ साथ नागरिकता का भावना का विकास।
५. धर्म एवं समाज के आवश्यकताओं के अनुकूल मनोरंजन के स्वस्थ माध्यामों की व्यवस्था।

समाज शिक्षा का यह पंचमुखी कार्यक्रम अति विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें अन्तर्गत न केवल वे सभी की योजना है बल्कि साक्षरता, श्रमिक उद्योग, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक शिक्षा में शिक्षा आगम और इस प्रकार उनके जीवन का महाद्वैतीय विश्रुत शिक्षा आगम शिक्षा सामाजिक मानवता विकसित है हर मनुष्य की शक्तों का विकास करना है।

महत्त्व। As a natural corollary it is to inculcate in them a lively sense of rights and duties of citizenship both as individuals and members of the community.”

—Hukumdas R. P. Social Education, p. 112

## समाज शिक्षा के लक्ष्य (Aims of Social Education)

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही यह अनुभव किया जाने लगा कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना तथा स्थिरता के लिए जनता को शिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। अतः स्वतंत्र भारत के नवनिर्मित तथा प्रथम शिक्षा-मन्त्रालय ने समाज की शिक्षा को अपने कार्य-क्रम में प्रमुख स्थान दिया। अतः १९४६ में धा माहनेसात सक्तेना की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया और उसे व्यवस्थापन शिक्षा के प्रकार पर परामर्श देने का आदेश दिया गया। समिति ने व्यवस्थापन शिक्षा के उद्देश्यों की अति संकुचित पावर रेखांकन की। यह परामर्श दिया कि एक शिक्षा का समाज शिक्षा की मज्जा में हो जाय। सरकार द्वारा समिति का यह परामर्श स्वीकार कर लिया गया। इस समिति ने समाज शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए —

१. नागरिकों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और उनमें समाज-सेवा की भावना का विकास करना।
२. उनमें जनतंत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा उन्हें जनतंत्रीय सरकार की शासन विधि की शिक्षा देना।
३. उनका दण्ड तथा बिद्वत् के समस्त उपस्थित समस्याओं से अवगत कराना।
४. उनमें इतिहास, भूगोल तथा सांस्कृतिक शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना।
५. उनको गायन, नृत्य, कविता तथा नाटक के द्वारा सांस्कृतिक परिपक्व तथा मानव के अवगत प्रदान करना।
६. उनको सामूहिक बाल विवाद तथा पठन-पाठन के माध्यम से विशिष्ट नैतिक प्रेरणा से अवगत कराना।
७. उनको मित्र-पत्र तथा माध्यमों के माध्यम से उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना एक ज्ञान के प्रसार के प्रति प्रोत्साहन देना।
८. उनको दण्डकारी के आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने व्यवसाय के करनी आर्थिक प्रगति के लिए उपयोग करने के लिए शिक्षा देना।
९. उनमें युक्तिसंगत विवाद-मोर्चियों, शिक्षा-समिति, तथा जनता महासंघों द्वारा शिक्षा के क्रम को बनाए रखना।
१०. उनमें महासंघों का भावना का विकास करना।



वास प्रमुख रोगों को रोकने और पोषक आहार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षण का समुचित प्रबंध करना ।

#### ४. व्यक्तियों की सामाजिक कुशलता (Social Skill) का विकास

व्यक्तियों की सामाजिक कुशलता का विकास करने के लिये उन्हें अपने मायियों व मध्य निवास करने जावन में प्रगति करने पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने और आपुनिक जटिल मयार में अपने प्रशिक्षण तथा कृत्यों की शिक्षा प्रदान करना ।

#### ५. व्यक्तियों का सांस्कृतिक (Cultural) विकास

व्यक्तियों का सांस्कृतिक विकास करने के लिये तथा उन्हें अपने देश के प्राचीन तथा प्रचलित सांस्कृतिक कानों से अवगत कराने के लिये मनोरंजन नृत्य तथा सौन्दर्य गीत तथा गीत-गीत व्याख्यान भाषणों का वि की उपयुक्त व्यवस्था करना ।

#### ६. व्यक्तियों का आत्म विकास (Self-development)

व्यक्तियों का आत्म विकास करने के लिये उनकी परिस्थितिया तथा आप व्यवस्थाओं के अनुकूल निवास विविध ज्ञान की प्राप्ति, जीवन विधानों के निर्माण अथवा निगी कसा व अनुसरण व लिये सुविधा प्रदान करना ।

### (ब) समाजगत उद्देश्य (Social Purposes)

हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि व्यवस्था शिक्षा की प्राचीन धारणा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है और उसकी समाज शिक्षा की गता दे दी गई है । वर्तमान समाज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—व्यक्ति की सर्वांगीण उपनि करना है परन्तु हमारे माय ही उमे समाज का उचितान तथा सामग्रद सांस्थ भी बनाना है जिससे कि न केवल उसका अपितु उमक सांस्थान में समाज का भी उधान हो सके । हम उद्देश्य की पूर्ति के लिये समाज शिक्षा—व्यक्तियों के मयन विभिन्न मयन की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को प्रस्तुत करती है । यह उनका विचार करने की विधिया तथा मयन में सामाज्य समस्याओं के समाधान की शिक्षा देती है । यह उनका हम मात को समर्थन की शिक्षा देती है कि न समूह मयन परिवार अथवा भारत और उमके भी मयन परिवार अथवा विश्व का निर्माण करने व निर निर प्रकार परम्पर मायन है और

उत्तर समग्र भारत व भाग्य निर्माण तथा विरह-युद्ध व तिर्य अनवरत प्रयास एवं कार्य करने का आदर्श उपस्थित करती है ।<sup>१</sup>

इस ध्याना के आधार पर समाजगत दृष्टिकोण से समाज-निष्ठा व निम्नांकित चार उद्देश्य हैं —

## १ सामाजिक एकता का प्रचार (Promoting Social Cohesion)

आधुनिक समाज की हर प्रमुख विशेषता है—व्यक्तिता व शक्ति का पारस्परिक गणप । समाज को हम गणप में सुरक्षित रखन व तिर्य सामान्य बनना के निर्माण का आवश्यकता होता<sup>२</sup> । यह न बनन कभी के पारस्परिक द्वेषों की दूर बनन व तिर्य अतिरिक्त व्यक्तिता तथा व्यक्तिता शीघ्र समूह तथा समूहों व मध्य निरन्तर बढ़ता हुआ पक्षपक्ष का या हमारे नागरिक तथा हमारे सामाजिक समाज का भाग बन विनाय सम्मान है । प्रत्येक करने व तिर्य भी आवश्यक है । तिर्य विनाय व हम पक्षपक्ष का एकता (Solitude) बनन परिभाषित किया है । हम समाज की 'एकता' विभिन्न भाग भागी समूहों, सामाजिक समूहों, सामाजिक तथा अन्तर्गत समूहों, निमित्तों तथा अन्तर्गत प्रतिक्रिया तथा सामान्य व्यक्तिता व आधुनिक तथा व्यक्तिता अन्तर्गत तथा वि विविध युद्ध तथा तिर्य तथा निमित्त व्यक्तिता व मध्य विद्यमान है । समाज निष्ठा का उद्देश्य है—हम एकता को अन्तर्गत बन बनन और एक सामान्य साधन का निर्माण करना तिर्य दाय व समय साधन सत्य भाग में रहें ।<sup>३</sup>

## २ राष्ट्रीय साधनों की सुरक्षा तथा उन्नति (Conservation & Improvement of National Resources)

समाज निष्ठा व्यक्तिता का एक भाग निम्नांकित है (१ व भाग की प्रवृत्ति द्वारा तिर्य एक उद्देश्य तथा दाय व निमित्त का उद्देश्य साधन समर्थ तिर्य)

1 It places before the people the needs and problems of various groups. It teaches them the way of thinking and solving the common problems in groups. It teaches them to see how these groups are knit together to form the great family that is India and the greater family that is world and holds before them the ideal of sustained effort and work as their offering to the destiny of India and the service of the world.—Te. has H. S. S. S. of Social Education—pp. 21-22.

2 It is the purpose of Social Education to reduce these divisions as far as possible and to create a common culture in which all national elements can participate.—[4] p. 22.

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

महायत्ता से हम देश के समस्त प्राणियों के लिए जीवन के एक उचित स्तर का निर्माण करना सम्भव है। य माधन दो प्रकार के हैं—(१) भौतिक तथा (२) मानवीय।

विद्युत् हुए राष्ट्रा क समस्त एक कठिनतम कार्य है—अपने प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा तथा उत्पत्ति। उपाहरणार्थ—भारत में हमारे समस्त हमारी भूमि तथा वना व क्षय की समस्याएँ हैं। यह आवश्यक है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इन समस्याओं से अवगत हो और वह न बलम उनकी सुरक्षा अपितु उनका उत्पत्ति में भी अपना योग प्रदान करे।

प्राकृतिक साधना से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय साधन हैं। हमारे विद्यालयों तथा शिक्षा का उच्च गम्भीरता का बलव्य है कि व इन मानवीय साधनों की उत्पत्ति करें। हमारे देश की अधिकांश जनता को विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए वे साहित्यिक तथा अन्य आवश्यक योग्यताओं का विकास नहीं कर सके हैं। यही कारण है कि समाज निर्माण में हमारे देश के निवासियों को साक्षरता तथा उन्नत योग्यताओं के समान आधारभूत ज्ञानों का निर्माण प्रदान करने का भार अपने ऊपर लिया है।

लनिन (Lenin) का मत था कि निरक्षर जनता व आधार पर समाजवाद (Socialism) का निर्माण केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक निरक्षर मनुष्य राजनीति व शेष से बाहर होता है। यही बात किसी भी वास्तविक जनतात्मिक समाज व सम्प्रदाय में कही जा सकती है। एक अनिश्चित व्यक्ति में हितों तथा मूल्यों को वृद्धि विचारना नहीं होनी है जो स्वस्थ राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है।

अन्त में हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है—व्यक्तिगत की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि करना और इस कार्य का तब तक सम्पन्न नहीं किया जा सकता है जब तक जनता अनिश्चित है। साक्षरता तथा शिक्षा के अभाव में उत्पादन में एक निश्चित सीमा तक वृद्धि की जा सकती है उमर आगे नहीं।

३ सहकारी समुदायों तथा संस्थाओं का संगठन (Building Co-operative Groups and Institutions)

विभिन्न समूहों का संस्थापना की वम करना और राष्ट्रीय साधनों की सुरक्षा तथा उत्पत्ति प्रारम्भिक कार्य है। समाज निर्माण की मनुष्य की ऐसी गुणवत्ताओं की शिक्षा देनी है जो उसे समूहों व निर्माण के लिए आवश्यक है।

जा इन सामान्य का समीचन हित के लिये प्रयोग करने के लिये योग्य तथा इच्छुत है।<sup>१</sup> इन गुणसमाधायक अन्तर्गत तीन बातों का समावेश है —

(१) समूहों के समान उपस्थित समस्याओं का सामूहिक अध्ययन, (२) उनका समाधान करने के लिये सामूहिक तथा सहकारी कार्य और (३) इन कार्यों के परिणामों का सामूहिक मूल्यांकन।

अतः समाज शिक्षा का सत्य है — उन विधियों का निर्माण करना जिनसे उत्पत्तिस्थित समूहों का निर्माण इन प्रकार किया जाय (अ) व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता तथा सम्मान में बचिन न हो सके (ब) जिससे नेता साध बिना बल का प्रयोग किए समूहों का नेतृत्व कर सकें (ग) जिससे अधिकतम व्यक्तिगत गुण का सामाजिक प्रगति से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, (द) जिससे उन साधारण समाधायक समस्याओं की रचना की जा सके जो व्यक्ति के बलपूर्वक का गहन अध्ययन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है और (ए) जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इन समस्याओं के विचार तथा व्यापार में योग दे सके।<sup>२</sup>

#### ४ सामाजिक आदर्श का समावेश (Inculcating Social Ideology)

समाज शिक्षा का एक प्रधान लक्ष्य है — लोगों को करने व्यक्तिगत अध्ययन की अपन समूह अथवा समाज और अपने देश के अध्ययन के लिए प्रेरित करने और इन कामों का प्रगतिशीलता करने के लिए उत्प्रेरित करना।<sup>३</sup> इन दृष्टिकोण को एक प्रगति अर्थ समझ के साथ। य इन प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यदि हम सब जानते हैं तो सब बिगड़ते हैं, यदि हमने सब का सम्मान है तो जीवन बचता है।<sup>४</sup> समाज के जीवन में महानुत्तम व्यक्ति का योग भी जीवन होता है। फिर भी उनके जीवन का सम्मान हम सब का होता जाता है कि उनमें मानव जाति का प्रगति में क्या योगदान किया है।

1. Social Education has to lead on to teach men the skills which are necessary for building up groups qualified and willing to use the resources for the good of all.

—Teachers H. L. L. & C. of Social Education, p. 23

2. One of the most important functions of Social Education is to prepare the people to subordinate their private welfare to the welfare of their group, their community and their country and to do this joyfully.—Teachers H. L. L. & C. of Social Education, p. 23

3. Who dies if England lives who lives if England dies—



समाज शिक्षा का सत्य है—निम्नतम भारतीय में इस भावना का समावेश कर देना कि वह मानव-जाति की प्रगति में योग प्रदान करने के कार्य को अपना धार्मिक समझे।

## समाज शिक्षा की आवश्यकता (Need of Social Education)

समाज शिक्षा के उपरिर्वाहित उद्देश्यों तथा सत्यों का निर्धारण किसी आकस्मिक घटना के परिणामस्वरूप न होकर, व्यक्ति समाज तथा देश की कतिपय आवश्यकताओं पर गम्भीर विचार करने के उपरान्त किया गया है। इन्हीं आवश्यकताओं के फलस्वरूप समाज शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया गया। हम इनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

### १ अशिक्षित वयस्कों की आवश्यकता (Need of Illiterate Adults)

हमारे देश में अभी तक अनिर्वाह शिक्षा का पूरा रूप से प्रसार नहीं हो पाया है। फलस्वरूप अनेक बच्चे शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वयस्क होने पर भा-उ-हैं मिलने पड़ने तथा सामान्य गणित का कोई ज्ञान नहीं होता है, जिससे उनका मानसिक विकास तदर्थ के लिए ध्वस्त हो जाता है। उनका स्थान समाज में निम्न स्तर होता है और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा उनका अनेक प्रकार से हाथ धुँसाया जाता है। भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता तथा स्वतन्त्रता के समान अधिकार प्रदान किये हैं परन्तु अशिक्षित वयस्क उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अशिक्षित वयस्कों की इस सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समाज शिक्षा का व्यवस्था की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य निरक्षर वयस्कों को सागर बनाना है।

### २ अर्ध-शिक्षित वयस्कों की आवश्यकता (Need of Half Literates)

भारत में अनेकों वयस्क ऐसे भी हैं, जिन्हें वास्तविक में अधिक कठिनाई तथा कष्ट बिना कारगरता अपना ज्ञान को स्थिति करना पड़ा था। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इन अर्ध-शिक्षित वयस्कों को शिक्षित करने उनका मानसिक दृष्टिकोण का विस्तार किया जाय जिससे कि वे देश के उत्तम नागरिक बन सकें और साथ ही अपने व्यवसाय में अधिक सफल हो सकें।

### ३ पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता (Need of Complete Education)

विद्यार्थियों तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षा प्रदान की जाती है उनको पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह व्यक्तियों को जीवन के समस्त क्षणों में सम्पन्नतापूर्वक कार्य करने को योग्य नहीं प्रदान करती है। हमारे

शिक्षातन्त्र की शिक्षा के प्रमुख दोष ये हैं कि वह स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन तथा अवकाश के समुदाय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती है। जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति अनुभव करता है कि उसे हम प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समाज शिक्षा व्यक्तियों को इस आवश्यकता को पूरा करती है।

#### ४ मनोरंजन की आवश्यकता (Need of Recreation)

आधुनिक युग में अत्यंत देशवासीयों के समान भारतीयों की आवश्यकता में भी कृति हुई है। यद्यपि आवश्यकताओं की पूर्ण वरदान के लिए प्रत्येक देश में सत्तर सामान्यतः एक विधि में विना विधि से धन का अवनयन करने में व्यस्त रहते हैं। फिर भी यह एक बहुत परिश्रम के उपरान्त व्यक्तियों में विना में विनी मनास्वजन द्वारा स्वयं की आनन्ति करने की शक्ति का अर्थ होगा। अन्तर्गत है। जहाँ तक नगरों का प्रश्न है वहाँ मनास्वजन के साधनों का अभाव नहीं गटवता है परन्तु सामान्य में उनका संख्या अभाव है। समाज विज्ञान में सामान्यतः एक विधि प्रसार के मनास्वजन की व्यस्तता करने का भार अपने ऊपर लिया है।

५ राजनैतिक आवश्यकता (Political Need)

आज का समय हमारे देश के लिए पुनर्निर्माण एवं पुनर्विर्माण का उपाय एवं विभाग का समय है। हमने अपने देश में सर्वोत्तम कल्याणकारी नीतिगत की स्थापना की है। हम उस मुद्दे पर प्रतिबद्ध हैं कि हमारी आर्थिकता ही मुद्दा एवं चालीवला न हो। और यह आधार दिया है—हम देश की बहुत कमरा जलना बिगड़ ऊपर कि आज राज्य-भारदार का मुख्य निर्वाचन निर्देश है तथा समूचे राष्ट्र के समक्ष एक स्वच्छ का निर्धारण अवसरमिति है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है—उस निम्न का भार अत्यन्त करने वाली जन जन की उपस्थिति निम्न एवं उपस्थिति माहित। अनुरूप जिस प्रकार हम अपने बातचीत-मात्रिका तथा सुख-सुखिया का निम्न शाखा उनका निर्मित माहित की आवश्यकता एवं माहित के व्यवस्थापन निर्माण पर बन देते हैं। उगा प्रचार हमें अपने प्रौढ़ भाई-बहनो का जिज्ञासा और उनके लिए उपस्थिति एवं व्यवस्थापन विधि के माहित के सूजन की बिम्बा भी करनी होती है।

1. सन्ततिप लिता-मन्त्रा वसन्तपत्र विराट्। "मन्त्रास्तोत्रमोक्षोपाय  
विमर्श-मोक्षोपाय। श्री गान्धर्व के प्राध्यापक से—'सन्ततिप' विमर्श उपर  
पृष्ठ १६३८।

इस चिन्ता का भार समाज शिक्षा ने पूरा रूप से अपने ऊपर ले लिया है।

#### ६ सामाजिक आवश्यकता (Social Need)

समाज तुलनात्मक दृष्टि से सब से अधिक स्थायी समूह है जो कि सामाय स्वार्थ सामाय मू भाग सामाय प्रकार का रहल-राहन और सामाय पारस्परिक सहयोग या अपन-य की भावना रखता है।<sup>1</sup> समाज की इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि समाज का एक आवश्यक तत्व सहयोग है। समाज का सम्पूर्ण ढाँचा सहयोग की नींव पर ही खड़ा है। इन सहयोग से ही समाज की रक्षा हो सकती है और उनका निर्माण हो सकता है। समाज में जितनी भी समस्याएँ समितियाँ और संगठन होते हैं उन सभी का अस्तित्व सहयोग पर निर्भर है। सहयोग प्राप्त करने ही से समाज को प्रगतिशील बनाने में सफल हो सकते हैं। भारतीय समाज में सहयोग की भावना पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। विभिन्न समूहों में समस्याओं और वर्गों में महान् संघर्ष है जो समाज को एकता में मिला रहा है। फलस्वरूप हमारा समाज जड़ तक हिल गया है। ऐसे समाज की एकता में मूल में आघात करने की आवश्यकता का अनुभव करते ही समाज शिक्षा के कार्यक्रम को त्रिवारित किया जा रहा है।

#### ७ आर्थिक आवश्यकता (Economic Need)

भारत की अधिकांश जनता निर्धन है। नगर-निवासियों की अपेक्षा ग्राम बागियों की रूपा अधिक दयनीय है। उन्हें तन डगने के लिये पर्याप्त वस्त्र और के भरणे के लिये पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है। हमारा देश एक मरतक पर विधनता की जा बचक कामिमा लगी है। उसकी बिना पाण हम प्रगति कीम बहमाने के अधिकांश नहीं हैं। इसी विचार से उत्प्रेरित होकर भारत सरकार ने बड़ा निधन देखासिया की आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान दिया है और इसी आवश्यकता की दृष्टि से सरकार समाज शिक्षा द्वारा उनको विविध प्रकार के वर्गों में प्रशिक्षित करके उनका आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने का निश्चय किया है।

#### ८ देश की आवश्यकता (Need of the Country)

यदि एक देश की व्यक्ति निर्धन नहीं है तो उस देश का त्रिवारित शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। शक्ति-गणय तथा शक्ति

1 "Society is the far est relatively permanent group (of human beings) who share common interests common territory a common mode of life and a common group of ideas or belongings"—J Gullin *The Ways of Men* p 340

व युग उत्पन्न व नियम निष्ठा की महान् आवश्यकता है। एक अतिमि  
मिति का एक मान का ध्यान मनी होना <sup>१</sup> कि उन्म कौन मो दक्षिणी निहित  
है और व उत्पन्न उपयोग विम प्रकार वर गहना है। भारत व सम्पत्ति  
म व मान प्रत्यक्ष मध्य है। एक विनाम देन की अन-सक्ति का उचित उप  
योग मनी हो रहा है। इसी आवश्यकता की ध्यान में रखकर समाज निष्ठा  
का आयाजन किया गया है।

समाज निष्ठा द्वारा हमारे देशवासियों समा देन का जो बलवान् हाथ  
उठाया जाय, वकार व इन दानों में अहित किया जा सकता है "निहित  
अहित अधिर उत्तमान् म मान देन और हम प्रकार उपयोग तथा व्यक्तमान  
दानों की अति उत्पत्ति होगी। यह उत्पत्ति वक्त व्यक्तमान तक ही सीमित  
नहीं रहना। अधिर निष्ठा के समग्र रूप राष्ट्रीय सन्धिति में वृद्धि हागा और  
आवश्यक समाज-सेवाका का विस्तार होगा। स्वयं निष्ठा ही हमारे देशवासि  
व जीवन के स्तर में उत्पत्ति करने व नियम-आधारित आधार का निर्माण कर  
सकती है। निष्ठा ही सन्धित तथा धरित के प्रणिता की विमम धरित  
आने अवकाश का निर्माणकारी प्रयोग कर सकेंगे आवश्यक मान है। इन  
प्रकार वक्त समाज निष्ठा ही वर आधार है विम वर स्वयं भारत वक्तान  
कारी राज्य का निर्माण कर सकता है जो वक्तान स्वयंभवा तथा सामाजिक  
गुरदा की मान को स्वीकार करेगा। <sup>१</sup>

## समस्याएँ और उनके समाधान

(Problems and their Solutions)

समाज निष्ठा की समस्याएँ निम्न व वक्तान वक्तान की समस्याका म अधिर  
अतिम और अधिर वक्तान भी हैं। व अधिर अतिम हमारे हैं। वीरि निम्न

1. Educated workers would make for increased production and thus make for increased growth for both industry and trade. The benefits would not however be confined to business alone. Increased education would lead to an addition in the national wealth and create the basis for an expansion of necessary social services. Education alone can create the rational basis for an improvement in the standard of life of our people. It is also the necessary condition for the training of mind & character which will permit the people to make a creative use of their leisure. Social education is thus the foundation on which alone the structure of human welfare stands which will receive the claims of both the individual and the social group. —Humayun Kabir

शिक्षा का उद्देश्य—उन बयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को शिक्षित करना है जो शिक्षा प्राप्त करने की आयु को पार कर चुके हैं। वे अधिकतर हमलिए हैं क्योंकि हम इनको वास्तविकता की अपना कम शिक्षा देनी है।

भारत में समाज शिक्षा की समस्याएँ प्रगतिशील देशों की समस्याओं से भिन्न हैं। अन्य देशों में उन बयस्कों के लिए शिक्षा की योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं जो अपने बाल्यकाल में अनिवाय शिक्षा से लाभ उठाकर कुछ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। भारत में मुख्य रूप से उन बयस्कों को शिक्षित किया जाता है जो किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त न करने के कारण पूर्ण रूप से निरक्षर हैं। हमने अतिरिक्त भारत में जो एक विविध विधेयता पाई जानी है वह यह है कि यहाँ के बयस्क निरक्षर होते हुए भी अनिश्चित नहीं हैं। यद्यपि भारतीय ग्रामवासी निरक्षर हैं पर इसलिये वह अनिश्चित नहीं हैं। वह एक अन्य भी शिक्षित हैं। हमारी स्मृति विस्मरण है जिसमें उसने अपने देश के प्राचीन ज्ञान का सचय कर रखा है।<sup>1</sup>

उपयुक्त तथ्यों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप समाज शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य अपेक्षाएँ समस्याओं का परिणाम किया जा सकता है जिनका संक्षिप्त वर्णन और समाधान निम्नांकित है —

### १. समस्या—निरक्षरता (Illiteracy)

संसार के सबसे घनी जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ४३ ६४ २४ ४२६ थी। इस विभाजन जनसंख्या के अनुसार २३ ७ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत ३३ ६ और स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत १२ ८ है।<sup>2</sup> नागरिक शिक्षा की अपना प्रामाण्य शिक्षा में यह साक्षरता घट्ट कम है।<sup>3</sup>

इन आँकों में गिड़ हो जाता है कि हमारे देश में ७६ ३ प्रतिशत व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में अपना मार्ग खोज रहे हैं। इन अज्ञानता की उपस्थिति में किसी प्रकार की सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति की अपेक्षा

1 Although the Indian villager is illiterate he is not therefore uneducated. He is educated in a sense he has a tremendous memory in which he carries a vast amount of folk lore — N. A. Toth, *The Vaishnavas of Gujarat* p. 180

2 *India*, 1962, p. 16

3 *First Year Book of Education* p. 913

4 *संसार के बयस्कों का शिक्षण* पृष्ठ ४८२।



## भारतीय गिदा और उसकी समस्याएँ

का ज्ञान करा गया। प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पढ़ना सीखा लिया था चाट लेकर अपने परिवार के सदस्य तथा पड़ोसियों को पढ़ाने के लिये भेजा गया। पाँच वर्ष में 'सानाव' (Lanao) प्रान्त के १५०,००० व्यक्ति में से ७०,००० का न केवल पढ़ने अपितु लिखने का भी ज्ञान करा दिया गया।<sup>१</sup>

डा० सॉडक ने १९३५, १९३७ तथा १९३८ में भारत पघार कर मराठी तलश बगना हिन्दी, तमिल और गुजराती भाषाओं की अपनी विधि के द्वारा गिदा देने के माग का प्रदर्शन किया। पञ्जाब में भोगा के मिशनरियों ने इस विधि को अपना कर पर्याप्त सफलता प्राप्त की। दुसरे हैं कि इस विधि का परीक्षण भारत में अन्य भाषा में नहीं किया गया। हमें विश्वास है कि यदि भारत सरकार डा० सॉडक द्वारा निमित्त विधि का अनुसरण करे, तो अल्प समय में ही भारत के जन-जन को साक्षर बनाया जा सकता है।

अभी तक सरकार ने व्यक्ति की गिदा का प्रसार की दिशा में कोई ठोस कृपा नहीं उठाया है। सयदान (Sayidain) ने उचित ही लिखा है "जो कुछ हम अभी तक नहीं कर पाते हैं उसमें सबसे पहले तो यह स्पष्ट तथ्य हमारे सामने है कि मात्रा की दृष्टि में अभी तक जी कुछ बिगड़ गया है यह बहुत ही बुरा है। हमारे लगभग ८४% दसवांसी न तो धरी हुई पुस्तक का एक भी पृष्ठ पढ़ सकते हैं न वे मनदान की पर्ची पर समझौते के साथ गिदान लगा सकते हैं और न ही राखमरी का धाटे-छोटे हिस्सा लगा सकते हैं। अगर साक्षर का एक ऐसा मानचित्र बनाया जाय जिनमें गागरता की स्थिति दिखाई जाय और पृष्ठी का निरक्षर हमारा को बासा रखा जाय तो भारत उस मानचित्र में एक अग्रगण्य पूर्ण महात्तीय जैसा गिदाई देगा और यह हमारे लिये बड़ी सज्जा की बात है।<sup>२</sup> स्पष्ट रूप से निरक्षरता का उन्मूलन करो का आर्थिक सरकार पर है। आ यह आवश्यक है कि सरकार या तो डा० सॉडक की गणन विधि का अपना किसी अन्य उपाय को अपनाकर देश का जनता को निरक्षरता के गर्त में निजामे।

## २. समस्या—पाठ्य-क्रम (Curriculum)

समाज गिदा की दूसरी समस्या है—पाठ्य-क्रम की। व्यक्तियों के लिये उचित पाठ्यक्रम न होना कारण समाज गिदा का कार्य में भारी बाधक बन रहा है। अभी तक हम बात पर मनबन्ता नहीं हो सके हैं कि व्यक्ति का

1 T N Siquia & Co. in Ind. in Education p. 162.  
२ के जी० ए०-१७ शिक्षा की पुनर्रचना पृ० १८४।

निम्नलिखित प्रकार का पाठ्य-क्रम सबसे अधिक उचित माना जाता है। जिन पाठ्य-क्रम का वास्तविकी की शिक्षा का विषय प्रयोग किया जाता है उसे प्रौढ़। ५ विषय प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसी अभिव्यक्ति को आवश्यकताओं और जीवन का प्रति उनसे हृदयबोधन निम्नलिखित मित्र है। 'पर समस्त प्रौढ़ों के लिये भी समान पाठ्य-क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनमें कुछ विस्तृत निश्चय है जिनके लिए पहिले प्रसार गान की व्यवस्था आवश्यक है, कुछ अल्प निमित्त समस्त है जिनके लिए पुनः विविध शिक्षा का निम्नलिखित आवश्यकता है और कुछ नवता (Neo-literate) प्रौढ़ हैं जो वास्तविकी का पढ़ाई लिखाई जानते हैं तथा जिनमें वास्तविकता की भावना का विकास करना के लिये साम्यता संस्कृति इतिहास भ्रमण नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है।'<sup>13</sup>

[illegible]

पाठ्यक्रम के निर्धारण में अतिम बर्तनाई यह है कि क्या म गरीबों के पुत्र भोज सिद्धांत है। तथापि मैं उन कथनों को नहीं मानता जो भोजी की शक्ति से रखा गया है। जिनका चायु १ से २० वर्ष की है। माटे तोर पर वह अनुसार प्रोडा का इस क्रम में रखा गया — (१) १ वर्ष से १० वर्ष तक व प्रोडा ( ) ११ वर्ष से २ वर्ष तक व प्रोडा और (३) २५ वर्ष से अधिक चायु व प्रोडा। स्पष्ट है कि इन तीनों अवस्थाओं में प्रोडा की मात्रा में बहुत ही बड़ी-छोटी अंतरियाएँ हैं। अतः महीने के पाठ्यक्रम निर्धारण में विचार करना उचित न होगा।

इत गह ब' साहू म ग ह'। व मित्र अल्लभ व गल्लन बाव व। त  
व' त गल्लन बा व'। त।

समाधान—उत्पुष्ट पाठ्यक्रम का निर्धारण (Construction of Suitable Curriculum)

उत्तुङ्ग पाठ-वन वा निषेधम् विनाशः अथ मरणम् अथ भयम् ।  
 ३१। अथ विनाशः अथ भयम् अथ मरणम् अथ भयम् अथ मरणम्



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

करने के उपरान्त ही किया जा सकता है क्योंकि समाज शिक्षा का उद्देश्य बचन साक्षरता का प्रसार करना ही नहीं है अपितु ब्यवस्था का सर्वांगीण विकास भी करना है। अतः पाठ्य-क्रम में उन समस्या-विषयों को स्थान देना होगा जिनसे कि उनका राजनैतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास माँहा सार है। विषयों का निर्धारित करके समय-व्यवस्था की अभिवृद्धियों मानसिक प्रवृत्तियों बौद्धिक स्तर तथा पर्यावरण को आवश्यकताओं के अनुकूल एवं सदा अपितु जनक-पाठ्य-क्रम का संगठन करना पड़ेगा जिससे कि सभी वर्गों के ब्यवस्था का जीवन का पूर्ण विकास किया जा सके। यद्यपि पाठ्य-क्रम विभिन्न हाथ पर उनके विषय साधारणतः समान होंगे और ब्यवस्था के बौद्धिक विकास का आधार पर उनका अन्त गहन अथवा विस्तृत अध्ययन आवश्यक

उपरिर्क्षित तत्वा का ध्यान में रखकर शिक्षा प्रसार पाठ्य-क्रम का निर्माण किया जाय और उनमें किन विषयों को स्थान दिया जाय यही इस बात पर विचार कर लेना युक्तिसंगत होगा।

उचित तो यह होगा कि पाठ्य-क्रम का निर्माणकर्त्ता किसी ऐसे देश के पाठ्य-क्रम का अपना आदर्श माने जिसमें विकास करने वाले ब्यवस्था प्रायः उन्हीं परिस्थितियों में ही जिनमें भारतीय हैं। इन दृष्टि से दो देशों के पाठ्य-क्रमों को आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सकता है—डेन्मार्क और चीन।

डेन्मार्क का पीपुल्स हाई स्कूल (People's High School in Denmark) का पाठ्य-क्रम भारत के लिए उपयुक्त होगा क्योंकि हमारा देश डेन्मार्क के समान एक निर्धन तथा दूधि प्रधान देश है। यहाँ पुरुषों की सीत श्रुति के पूर्व माया में और स्त्रियों की श्रम श्रुति में शिक्षा दी जाती है। अध्ययन सामान्य करने पर उन्हें किसी वरीयता में सम्मिलित नहीं माना पड़ता है। श्रमक काल में अध्ययन का समय किसी परम्परागत गीत में प्रारम्भ होता है। श्रम का प्रमुख उद्देश्य—ब्यवस्था की राष्ट्रीय आर्थी से और श्रान करना होता है। प्रथम वर्ष में इतिहास का शिक्षण व्यावहारिक रूप में कि र्विज्ञानिक दृष्टि से किया जाता है। इस विषय का शिक्षण करने समय छात्रों की व्यवस्था तथा देश की परम्पराओं का उन्मूलन किया जाता है। दूसरे वर्ष में व्यापार की व्यवस्था होती है। तीसरे वर्ष में विद्यार्थी शिक्षा से प्रथम प्रवृत्ति है और वह उनके उत्तर देता है। मध्यमाल के भोजन का उत्तरान्त ध्यान गया है और वह उनके उत्तर देता है। मध्यमाल के भोजन का उत्तरान्त ध्यान गया है और वह उनके उत्तर देता है। मध्यमाल के भोजन का उत्तरान्त ध्यान गया है और वह उनके उत्तर देता है।

पर भाग्य दिय जाने हैं। फिर सामूहिक अध्ययन मानमात्रा पर वात विद्या नियंत्रण रखना और व्यक्ति का शिक्षण दिया जाता है।<sup>1</sup>

चीन का पाठ्यक्रम भारत के विद्ये और भी अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि दोनों देशों की आवश्यकताएँ तथा कठिनाईएँ समान हैं। उम्र ११ के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जिसे विद्या की शिक्षा दिया गया है वे हैं सामान्य ज्ञान पढ़ना विद्येता नागरिक शासन व्यक्ति समीप चित्रकला इतिहास भूगोल स्वास्थ्य विज्ञान कृषि इत्यादि योग्य सामग्री तथा राष्ट्रीयता प्रज्ञा तथा और सामाजिक व्यवस्था। इनमें अनिश्चित प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रत्येक सामान्य कृषादीक्षण सहज निर्माण कार्य निर्माण तथा गीतकविता का व्यापक तथा व्यापक की भी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के नये प्रौढ़ शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध तथा उसका पुष्प करने वाली ही नहीं हो गई है। अतः सामाजिक तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना का माध्यम भी हो गई है।<sup>2</sup> प्रौढ़ शिक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम भारत के विद्ये और भी अधिक उपयुक्त होगा।

यदि किसी कारणों से हमारा देश के नये तथा शिक्षाविद् समाज एवं चीन के पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं पर भारतीय व्यवस्था के साथ पाठ्यक्रम का समन्वय करने के लिए उद्यत नहीं है तो यह अवसर उपयुक्त पाठ्यक्रम का सुमात्र प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु यहाँ यह बात स्पष्ट आवश्यक है कि हमारे माध्यमों की पाठ्यक्रम का अध्ययन निश्चित न किया जाय। माध्यमों के साथ शिक्षा का अर्थ है और न प्रारम्भ यह केवल यह माध्यम है—विद्ये द्वारा अनुप्राप्त तथा शिक्षा की शिक्षा दिया जा सकता है।

क्योंकि शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक माध्यम पढ़ने और विज्ञान की शिक्षा दी जाय। जब हमारे देशों के विद्ये ज्ञान उपलब्ध कर लें तब उनसे मिले बहुत माध्यम ज्ञान इतिहास नागरिकशास्त्र अध्ययन व भूगोल कृषि पशुपालन सामान्य विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान नागरिक शासन चित्रकला तथा व्यापक का शिक्षा की आवश्यकता की जाय। व्यापक आवश्यकताओं के अनुसार इन

1 T N Siqueria Op cit pp 164-165

2 "Adult education in China has thus become not only a continuation and completion of elementary education but also a means of social and national re-orientation"  
—T N Siqueria Op cit p 166

3 "Literacy is not the end of education. It is even the beginning. It is only one of the means by which men and women can be educated"—Mahatma G J in Air Mail to the Hail—31 July 1937

विषयों के अनन्तरित कुछ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाए। बच्चों के सामर्थ्य सुनिश्चित व्याख्या द्वारा प्रौढ़ विद्यार्थियों में बचाने के व्यासाया तथा उनमें नियम सामर्थ्य विषयों पर व्याख्यान की आयोजना की जाए। प्रत्येक बच्चे को किसी कला क्षेत्र में अवश्य प्रांगणित कर दिया जाय जिसमें वह उसको अपना आय-सृष्टि का माध्यम बना सके।

### ३ समस्या—शिक्षण पद्धति (Method of Teaching)

बच्चे के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति का निर्धारण भी कुछ कम जटिल समस्या नहीं है। हमका कारण यह है कि जीवन तथा समाज के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण समान नहीं होता है। हम जानें कि बच्चे में भिन्न ज्ञान है। अन्य आयु में दृष्टिकोण का विकास अधिक न होने के कारण प्रायः सभी बच्चे के लिए समान शिक्षण-पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है। बच्चों के लिए ऐसा करना न तो सम्भव है और न उचित है। बच्चे में अल्प की भावना कम ही रूप से विकसित हो जाती है। वे अधिक सामाजिक स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं। उनमें अपने कुछ मिष्टान्त ज्ञान है उनकी अपनी आदतें होती हैं जिनसे बच्चे को बाध नहीं करना चाहते हैं। इन सभी बातों के कारण प्रौढ़ों के लिए ठगवाया शिक्षण पद्धति का सरलता पूर्वक निष्कर्ष करना सम्भव नहीं है। यदि शिक्षण-पद्धति में कोई भी ऐसा तत्त्व है जो उनकी अवधारणा प्रतीत होता है अथवा जो उनकी अल्प की भावना स्वतन्त्रता मिष्टान्त तथा आदतों में टकराता है तो शिक्षण-पद्धति का असफल होना अवश्यभावी है। यही कारण है कि अभी तक किसी एक पद्धति को बदलने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जा सका है।

### समाधान—उपयुक्त शिक्षण-पद्धति (Suitable Method of Teaching)

बदलने के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति का निर्धारण करने में नियम उनका मनोविज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना आवश्यक है। शिक्षण-पद्धति ऐसी हो या उन्हें अधिक प्रतीत हो तथा उनको शिक्षा प्रणाली बनने के लिए आकर्षित कर सके। हमारे देश में शिक्षा विचारों में शिक्षा में पर्याप्त रूप में सन्नित है और उद्देश्य कुछ उपयुक्त शिक्षण-पद्धतियों की ओर खींचा जाता है। हम जानते हैं कि कुछ अन्य पद्धतियों का विकरण निम्नांकित नीतियों में दे रहे हैं।

(१) बच्चे के लिए पद्धति—इस पद्धति में बच्चे के व्यक्तिगत अंतरों का ध्यान रखा जाता है। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में इस पद्धति का प्रचलन है।

(२) बाल्य-पद्धति—इस पद्धति में बच्चों के जीवन का ज्ञान एक साथ रखा जाता है और फिर उनका समुचित रूप में विभिन्न धारणाओं का कर दिया



प्रौढ़।" लिये उपयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ म अग्रगणित होते हैं। वे समाज शिक्षा के उद्देश्य, सभ्यता आकांक्षक साहित्य तथा शिक्षा के उपयोगी साधनों से अवगत नहीं पाते हैं। अतः जब उनको प्रौढ़ शिक्षा का भार सौंप दिया जाता है, तब वे उसका अन्याय-मूलक संघासन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। पनम्बक्य कथक शिक्षा का प्रवाह निर्वाध गति से नहीं हो पाता है।

यद्यपि विद्यालयों में लिये उपयुक्त शिक्षकों के अभाव की समस्या तो है ही, पर इससे भी गुरतर समस्या यह है कि सभ्यापरा की वांछित सभ्यता अपलब्ध नहीं है। निरक्षर बचपन की अधिकांश सभ्यता भारतीय ग्रामों में निवास करती है। शिक्षा की दायी म जीवन की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि आसानी से न हो सकती है। ग्रामीणों की कठिनाइयों का तत्काल समाधान करना पड़ता है। अतः न ग्रामों में स्थित प्रौढ़ शिक्षा के अध्येतृ कार्य करने के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं का और भी अधिक अभाव है क्योंकि वे अपने निवास स्थानों से दूर अपरिचित स्थानों के साथ में रहें वे स्वयं शिक्षित हान के कारण अक्षय और गैर-समर्थ हैं अपने जीवन तथा समय को व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं।

### समाधान—अध्यापकों की पूर्ति (Supply of Teachers)

आवश्यक योग्यताओं-युक्त अध्यापकों की वांछित संख्या प्राप्त करने की समस्या वस्तुतः अति है पर निरन्तर तथा हृदय प्रवाह द्वारा इस समस्या पर विचार प्राप्त का जा सकती है। इस शिक्षा में सर्वप्रथम कार्य यह है कि प्रौढ़ विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक जानें कि अध्यापकों का प्रौढ़ शिक्षा की विधियों और प्रौढ़ों के मनोविज्ञान में पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाय। इनके अतिरिक्त ग्रामों में प्रौढ़ विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक जानें कि शिक्षा की विधि-पद्धतियों का उपयोग उद्योग, प्रारम्भिक विद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, कानून और बुनारी के मनुष्य ज्ञान का दिया जाय ताकि ग्रामीण बचक उस ज्ञान से सामान्यित लिये जा सकें।

प्रौढ़ विद्यालयों के लिये उपयुक्त शिक्षकों की पूर्ति करने में समय लगता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जब तक उपयुक्त शिक्षकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध नहीं हो जाय तब तक समाज शिक्षा के कार्य को स्थगित कर दिया जाए। ऐसा करना बल्लभ और दण्ड के लिये शिक्कर म होना। अतः इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्रामीणों की प्रौढ़ विद्यालयों में अध्यापन-कार्य करने के लिये अक्षय शिक्षा प्राप्त। महारमा लक्ष्मी के पथ प्रदर्शन में अध्यापन शिक्षक के दायी-बायाँ का शिक्षा के कार्य लक्ष्य मंथन द्वारा सुचारु रूप से सम्पन्न

गिया गया था।<sup>१</sup> उस आदर्श की प्रीति को निष्ठा देने में मिले भी अपनाया जा सकता है। यदि निम्न-वर्गों के अध्यापक तथा विद्यार्थी कार्यक्षमता के सम्बन्धी, ए० ग्रा० सी० तथा ए० सी० सा० के मध्य वास्तव तथा मान्यता के आधारों और अन्य निम्नवर्ग समाज-सेवी राष्ट्रपिता और उनके स्वयं सेवकों के उदाहरण से अनुप्राणित होकर हर एक पढ़ाए एवं ' (Each one Teach one) को अपना मिशन बना लें तो प्रीति विद्यार्थियों के विवेक अन्तर्निहित रूप में निम्न भी उत्तम हो जायेगी और अज्ञाना-परायणता का जो धारा बर्गों के मध्य में होकर प्रवाहित हो रही है उसका रूप भी सरलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकेगा।

#### ५. समस्या—उपयुक्त साहित्य (Suitable Literature)

समाज शिक्षा का उत्तरदायित्व करने वाले व्यक्तियों को मान्यता देना ही समाज नहीं हो जाता है। प्रीति को बचाने सिखाया पढ़ना तथा गणना गणित की शिक्षा दे देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम प्रसार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही शिक्षा ग्रहण करने का कार्य समाप्त कर दें तो वे कुछ समय के पश्चात् फिर निरक्षर हो जायेंगे। अतः यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक ज्ञान उपलब्ध करने के बाद भी सवासाक्षरों के विवेक साहित्य हो। 'यदि हमारी समस्त जनता पढ़ना सिखना और जाह-बारी तथा गुणात्मक के सम्बन्ध में सज्जना सीखने में लगे तो हमारे देश का विकास होगा। हमारे समाज में तो वे तथा कार्यक्षमता के पर लक्ष्य करने वाला को उन्हें प्रेरणा देने का अपना ही उपाय बनाया और मिल जायगा। हमारे लक्ष्य तो उनका मान्यता देना होगा न उनकी रचना में सुधार होगा और न उनका जीवन ही समृद्ध होगा। उनकी साहाय्यता ही समाज का सामाजिक बनना में को-ऑरिनेशन नहीं पाने होगी।'<sup>२</sup> हमारे समाज में केवल एक ही साहित्य का आवश्यकता है जो उनमें प्रीति को प्रदान करे। समाज सामाजिकता के लिए तथा सामाजिक भावना का विकास करने में योग दे प्रिय है। वे बनने के क्षमता में प्रीति तथा निष्ठा के साथ ही समाज के लक्ष्य और प्रयत्न के साथ ही समाज के लक्ष्य में मन और बुद्धि के बीच अंतर हो सके।<sup>३</sup> हम प्रसार के साहित्य का निम्न एक समष्टि है।

१. महात्मा गांधी का जन्म २९ सितम्बर और निधन ३० सितम्बर (अनुसूचित दिनांक ३० सितम्बर) १९४८ ई।

२. दे० सी० सी०-न शिक्षा की पुस्तक, १०-२११।

३. वही।

## समाधान—उपयुक्त साहित्य का निर्माण (Production of Suitable Literature)

उपयुक्त साहित्य के अभाव के कारण समाज शिक्षा का कार्य साक्षरता के स्तर पर और अपने व्यापक अर्थ में अति मन्द गति से चल रहा है। अब हम जान ही आवश्यकता है कि एसी पुस्तकें, चार्टों, समाचार-पत्रों, मासिक तथा मासाहिन पत्रिकाओं, चित्रों आदि की व्यवस्था की जाय, जो बयस्क की दृष्टि से अनुकूल हों।<sup>१</sup> इस कार्य को विज्ञान सेवकों की सहायता में पूर्ण किया जा सकता है। इस हेतु उन्हें बयस्क के लिए उपयुक्त पुस्तकें तथा पुत्रिकाओं की रचना करने के लिए प्रत्येक सम्भव विधि में प्रोत्साहित किया जाय। चित्र पूर्ण समाचार-पत्र एवं पाठकारों प्रकाशित की जायें। एवं एसी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाय जिसमें कुछ स्वास्थ्य, कृषि तथा विद्वत् से सम्बन्धित समाचार हों। क्योंकि नवगाढ़ारा के लिये इस प्रकार की पत्रिका की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे देश की प्रायः सभी राज्य-सरकारें इस विषय में प्रिया दीप्त हैं।<sup>२</sup>

प्रौढ़ों तथा नवमानवों के लिये साहित्य निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की नवमानवोपयोगी साहित्य निर्माण गोष्ठी की आस्था<sup>३</sup> में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। उक्त उत्सव किया गया है कि इस साहित्य का निर्माण करत समय पाँच चीजों का ध्यान रखा जाय—(१) समाज शिक्षा के उद्देश्य (२) आयु भेद (३) लिंग भेद (४) क्षेत्र भेद और (५) माँग तथा आवश्यकता।

## ६. समस्या—शिक्षा के साधन (Agencies of Education)

समाज शिक्षा के साधन म साक्षर हैं—वे समूह यद्यपि संस्थाएँ जो समाज शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखती हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करने

1 The work of Social Education is greatly handicapped both—at its literacy stage and in its wider sense—by the paucity of suitable reading materials, graded to appeal to the adults. There is urgent need for producing large number of booklets, folders, charts, journals, news papers, wall papers and other illustrated materials which will capture the adults' interest.—K. G. Salyidin, *Proceedings of the 19th Meeting of the Central Advisory Board of Education in India*, Appendix C (d)

2 *Teachers Handbook of Social Education* p. 18

3 *Report of the Literary Workshop on the Production of Literature for Non-Literates*, 1958

है तथा उनका आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है।<sup>1</sup> श्री शिक्षा व इन मापनों व चयन में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है क्योंकि यदि ये मापन समयों को ज्ञान के प्रति आकृष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे पूर्णतया निरर्थक हो जाते हैं। इन मापनों का विशेषरूप चयन सरस कार्य नहीं है। यही कारण है कि श्री मनोविज्ञान में दण्ड व्यक्ति साधना की समस्याओं को गुप्त करने में व्यस्त है।

**समाधान—शिक्षा के उपयुक्त साधन (Proper Agencies of Education)**

श्री का ज्ञान प्रदान करने व निम्ने विविध प्रकार के उपयुक्त मापनों के गुणों प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की नवजागरण पदांगी साहित्य निर्माण योजना ने जो सुझाव दिये हैं वे अत्यन्त ही—  
(१) वर्णन प्रदान गद्य (२) वाक्य सोपानोपपन्न चरित्रों (३) नाट्य चरित्र एवं गद्यांश, (४) कथा-कहानी (५) पत्र तथा पत्रिका (६) चित्रों द्वारा तथा (७) वाचन।

उपरिस्तिगित शिक्षा-साधना की उपाययोजना पर ध्यान रखी की जा सकती है परन्तु हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन मापनों का प्रमुख उद्देश्य—वेचन व्यवस्था का बौद्धिक विभाग करना है। यदि समाज शिक्षा का कार्य यही ठहर सीमित रहेगा तो चरित्रों व जीवन का सर्वांगीण विभाग करना सम्भव नहीं होगा और सर्वांगीण विभाग करना ही समाज शिक्षा का प्रधान लक्ष्य है। अतः व्यवस्था को शिक्षा इन के लिए अन्य मापनों की भी प्रयोग करना होगा। ज्ञान में जो पर्याप्त रूप में प्रभावकारी शिक्षा हो सकती है वे अत्यन्त ही—  
संयुक्त मापन (Audio-Visual Aids) गद्यांश चित्रों द्वारा नाट्य, गद्य-कहानी तथा अन्य साहित्यिक तथा वाचन-विभाग चरित्रों द्वारा तथा गद्य-कथा-कहानी इत्यादि। केवल शिक्षा-साधन ने सामान्य मापनों के प्रयोग को विशेष रूप से माना है।

**७. समस्या—धनभाष (Lack of Funds)**

१९५१ की जनगणना व अनुमान ध्यान में १० वर्ष में अधिक धन का श्री का ज्ञान सम्मान २१९ कराह है। इनके श्री का उत्तर बनान में

1 By a series of social education is to make the bodies of institutions which deliver the goods which concern the consumers of social education and satisfy its needs.

—T. S. S. H. of Social Education — p. 64

2. Ibid. 1952, p. 70



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

बित्तों घन की आवश्यकता होगी इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक अध्यापक ३० प्रौढ़ों को ६ मास में साक्षर बना सकता है। इस प्रकार वह ६० प्रौढ़ों को १ वर्ष में पढ़ना सिखाना सिखा सकता है। इस हिमाय से २१ ६ करोड़ व्ययस्कों को १ वर्ष में साक्षर बनाने के लिए ३५ लाख से अधिक अध्यापकों तथा प्रौढ़ विद्यालयों की आवश्यकता होगी। यदि एक प्रौढ़ विद्यालय का कम से कम व्यय २५० रुपये मासिक मान लिया जाय, तो ३५ लाख प्रौढ़ विद्यालयों से लिए = ७५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। १९६०-६१ में भारत की राष्ट्रीय आय १४,२०० करोड़ रुपये थी।<sup>१</sup> उपर्युक्त आँकड़ा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए घन की उपलब्धि एक महान् समस्या है।

**समाधान—धनाभाव एक यहाना (Lack of Funds A Pretence)**

प्रायः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे निर्धन देश के पास निरक्षर बचस्व की २१ ६ करोड़ की विज्ञान समस्या को साक्षर बनाने के लिए घन उपलब्ध नहीं हो सकता है। के० जी. उपर्युक्त इस तर्क को निरस्त करते हुए लिखते हैं— वास्तव में केवल एक ही प्रकार की दरिद्रता होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है और वह हानी है— दरिद्रता की दरिद्रता यानि हम गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करें तो अन्य सभी प्रकार की दरिद्रताएँ दूर की जा सकती हैं। यह एक बहुत बिली-पिटी बात है फिर भी मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि इसी निधन देने में एक एस. मुन्डू ने लिए बित्त छोड़ने में उसका कोई हाथ नहीं था कराहा। रुपये साथ कर दिये थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का क्या कारण हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मा. जो धान्ति और मानवीय गुणों का मूल आधार है इतना ही बड़ा प्रयाग न किया जा सके? मरा हृत्किरोरा से नहीं देगना चाहिये। मरी राय में समस्या पर विचार करने का सही तरीका यह नहीं है कि हम एक अश्वि शिक्षा-व्यवस्था का या एक अच्छी स्वास्थ्य नाति बनाने का गर्भ बनाय नहीं कर सकते बल्कि हमें इस तरह सोचना चाहिये कि इन बाधों के बिना क्या हमारा काम चल सकता है? यदि हम बात का स्वाकार किया जाता है कि कोई भी देश बहुत बड़ी हानि का सामना कर रहा है और जाति और सामाजिक दृष्टि में दरिद्र नहीं रह सकता है तो

इसके निचे धन कुशल सरकार वित्त विभाग और राष्ट्रीय अख्यतन की योजना बनाने वालों की जिम्मेदारी है।”

## ८. समस्या—उत्तरदायित्व (Responsibility)

समाज शिक्षा की कौन सी समस्या यह है कि समाज-शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर होता चाहिये—केंद्रीय सरकार पर राज्य-सरकारों पर शिक्षा विभाग पर शिक्षा परिषद पर अथवा मातृशाला शिक्षा-संस्थाओं पर ? केंद्रीय सरकार ने इस उत्तरदायित्व को राज्य-सरकारों पर रखा है और इस प्रकार करने का समाज शिक्षा का भारत में मुक्त चयन का प्रयास किया है। पर हमने समाज शिक्षा की महान् समस्या का समाधान होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

## समाधान—संयुक्त उत्तरदायित्व (Joint Responsibility)

समाज शिक्षा की महान् समस्या का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संस्था पर नहीं रखा जा सकता है। इसका उत्तरदायित्व तो राज्य विभिन्न संस्थाओं तथा इन देश के निवासियों को संयुक्त रूप से अपने ऊपर लेना पड़ेगा—कभी इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। प्रत्यक्ष रूप से यह एक ऐसा उत्तरदायित्व है जिसे न तो शिक्षा विभाग ही पूर्ण कर सकता है और न सम्पूर्ण समाज-अध्यक्ष ही। हमने निचे सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संस्थाओं तथा मजदूरों और व्यापारिक वर्गों को समझाते उन सभी व्यक्तियों के मध्य जो भारत का वर्तमान चाहते हैं यदि प्रत्यक्ष एवं हार्दिक सहयोग आवश्यक है। कभी हमारे समय इतना और इतने विविध प्रकार का कार्य करने का पता है कि जो भी इन सेवा-क्षेत्र में सम्मिलित होता चाहे, उन्हें निचे हमसे श्रद्धा है—एक शिक्षक बनो व्यक्ति राजनयिक नका मतलब धर्मिक शिक्षा व्यावसायिक कार्य करने वाले मनुष्य—कभी के निचे।”

1. “जी. सी. मन्दा शिक्षा की पुनरचना” पृ. १८६ १६०।

2. “It is obviously a responsibility which neither the Education Department nor the Government machinery as a whole can take on by its If it needs the closer and most cordial co-operation of all classes official and non-official and of all individuals of goodwill and social sense who are interested in the welfare of India. There is so much work to be done and it is so varied as to that there is room for everyone who cares to join the crusade of service—students, teachers men of letters political leaders, workers, business craftsmen, professional men—everybody”

—A. C. Senapati of C. S. p 247

उपरिबोधित विषय-वस्तु का पर्यवेक्षण करते हम निस्तब्ध भाव से कह सकते हैं कि समाज शिक्षा की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज शिक्षा के प्रसार के प्रति ईमानवाला या सङ्कुचि न दृष्टिकोण वाला रवैया न अपनाकर उत्साह और आत्मनिश्चय के सहित व महान् अपने उद्देश्य का पूर्ण करने का प्रयास करें।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Trace briefly the history of Social Education Movement in India and indicate the more important phases through which it has passed
- 2 Discuss the need and importance of suitable literature for neo-literates in India
- 3 What should be the main aims of Social Education in a secular democratic society? Discuss with special reference to India
- 4 Discuss the causes of the slow growth of Social Education in India and give suggestions to remove them
- 5 Define Social Education. What are the main causes that have hindered its progress?
- 6 Social Education is the *Panacea* for all social ills. What curriculum would you prescribe for Social Education to fulfil this purpose?
- 7 What do you understand by 'Adult Education'? Discuss its need in India
- 8 Discuss the need and importance of Social Education in the national life of India
- 9 Give a brief account of the purposes and agencies of Social Education
- 10 Why was the term Adult Education changed to Social Education? What is the significance of this change?

## प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा (Technical and Vocational Education)

### विषय-प्रवण

शिक्षा के अन्तर्गत प्रौद्योगिकीय विषयों का समावेश प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए। प्राचीन तथा मध्यकालीन युगों में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य (General) एवं सरकारी (Liberal) शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं था। मोनर विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा में लगभग १० वर्षों में अत्यन्त कम प्रसारण होने के परिणामस्वरूप समाज का हानि पहुँचा हुआ है।<sup>1</sup> व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी—प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख दिशाएँ हैं और इनका प्रगति के मानव जीवन की समस्याओं को परिचित कर देना है और

1 "The sciences which discoveries in physical sciences and technology have taken within the last two hundred years have changed the face of the world" —Quoted from Dr. Rajendra Prasad's Speech at the Joint Meeting of the Inter University Board of India and the Executive Council of the Association of the Universities of the British Commonwealth on December 21, 1931 at the Delhi University

ऐसा प्रतीत होता है कि ये मानव जीवन के स्वामी और आशा हो गये हैं। अतः इस परिवर्तन को देखते हुए स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि क्षिणा को भी परिवर्तित कर देना चाहिये और उसमें विज्ञान तथा प्राविधिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये। इस विचार का समीक्षा में अनुमोदन किया गया है। यही कारण है कि आज सभी प्रगतिशील राष्ट्रा में प्राविधिक विषयों को विद्यालयों में पाठ्य क्रमों में स्थान दिया जा रहा है।

भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

(Need of Technical Education in India)

भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता  
(Need of Technical & Vocational Education in India)

हम ऊपर की पक्तियों में तिस्रें चुके हैं कि आधुनिक युग में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि शिक्षा के पाठ्य क्रमों में प्राविधिक एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश किया जाय। इसका प्रधान कारण यह है कि प्राविधिक शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा है। यह आवश्यकता क्या है ? इसी पर हम यहाँ विचार करेंगे।

हुमायूँ नबीर (Humayun Nabi)

हुमायून् खबीर (Humayun Kabir) का मत है कि किसी देश अपना राष्ट्र की सम्पन्नता का आधार—विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा है। यदि देश में यह शिक्षा सम्पन्नतापूर्वक प्रदान की जा रही है और यदि इस शिक्षा की प्रगति हो रही है तो राष्ट्र की उन्नति अवश्य होगी। समुक्त राज्य अमेरिका सोविट देश का जर्मनी और जापान से उन्नाहरण हमारे समक्ष हैं। लगभग १०० वर्ष पूर्व समुक्त राज्य अमेरिका एक पिछड़ा हुआ देश था परन्तु प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के कारण आज वह इतना धनी हो गया है कि सत्तार के अनेक देश उसके कदमी हैं। १९१८ में जारसाही का अन्त करके रुस में गणतन्त्र की स्थापना की गई। उस समय रुस की गगना सत्तार के प्रगतिशील देशों में नहीं थी परन्तु आज वह संसार का सबसे अधिक धातुआली देश माना जाता है। इसका कारण सबसे यही है कि वहाँ प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष धन दिया गया है। श्रितीय विश्व-युद्ध में जर्मनी तथा जापान की अति

Applied Science and Technology are the most characteristic features of modern civilization and their development has transformed the conditions of human life and appears to have become its mistress and hope. An obvious conclusion is that in keeping with this transformation education should be transformed.—Sir Richard Livingstone  
*Some Tasks for Education* p. 6.

महान् दानि यज्ञो यन्तु प्राविधिर्गणिता यं कारणं आत्र वे पुन भवतो पूर्णं  
 सिद्धिर्ना यज्ञे ब्रह्म प्राप्य कर शुद्ध है ।<sup>1</sup>

आधुनिक युग में एक राष्ट्र का सम्पन्नता के चार आधार माने गए हैं—  
पूँजी बचवा माप, सन्नित्त प्रणाल तथा प्राविधिक शिक्षा। हम यह स्वीकार  
करते हैं कि भारत में पूँजी का अभाव है क्योंकि हमारा विश्वी व्यापार ने  
अपना अर्ध-नीति की दृष्टि से हमारे देश का पूर्ण रूप से घायल किया और  
यहाँ के प्राविधिक मापन की अपने सम्बन्धों के कारण मन्दिर निर्माण।  
परिणामस्वरूप भारत में दुमिन्ना का लोना-जन ग्या और भारतीय जनता निपनता  
के गर्त में डूब गई। परन्तु भारत में बचने माप और सन्नित्त प्रणाली का अभाव  
नहीं है। हमारे देश की पृथ्वी व वन में अब भी लोहा, मन्नीक, तेल आदि  
इतने लोहा, आग्नेय अम्ल इन्धनादि आदि के भण्डार दिये हुए हैं। इनके  
अतिरिक्त विद्युत् व अन्युत्पन्न मापन भी हैं। परन्तु हमारा प्रयोग सभी किया जा  
सकता है जब तक कि प्राविधिक एवं व्यावसायिक विषयों तथा विज्ञानों का पूर्ण  
ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हों। दुर्भाग्यवश हमारा देश अभी इन शिक्षा में पूर्णतः  
अज्ञान नहीं कर पाया है, यद्यपि हमारा राष्ट्रीय सरकार इस कार्य में गमन  
है। प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक एवं व्यावसायिक  
शिक्षा में स्थापनाय उन्नति हुई है और यदि हमारा धन से प्रयत्न हाँकी रहो तो  
आगामी कुछ ही वर्षों में देश का आर्थिक विकास ही आगम्य और निपनता का  
अन्त हो जायगा।

यद्यपि स्वयम्भू भारत के विषे प्राविधिक एव व्यावसायिक शिक्षा प्रधान माना जाता है परन्तु यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टिगत करें, तो हमका ज्ञान होगा कि प्राविधिक क्षेत्र में भारत उन्नति व अति उच्च स्थिति पर था। इस क्षेत्र में अथर्व वेद का कारण के भीरु विद्वत् ब्राह्मण वयं आज विरहमात्रा देता उस शिक्षा में बदल हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें प्राविधिक एव व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि बनानी पड़ेगी।

प्राचिन शास्त्र में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

[illegible]

1. Noel F. Sugarman & Ted J. Fennell - "Art by  
Harrison Kahr in The London: People's Day Supp-  
lement 1953



अगर जी राज्य में प्राविधित एव व्यावसायिक नि १

### भारतीय उद्योगों का विनाश

भारत में परम्परागत रूप में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देने की जा प्रणाली चल रही थी और जिसके सम्प्लक्ष्ण यहाँ के उद्योग धंधे अरु उद्योग घर से उभरा गया था। व्यापारी संघर्षों ने जो शिक्षा परिणामों यहाँ के सम्प्ल उद्योग धंधे खोद डी गये । अष्टादश स व्यावसायिक रूप में १९११ में माध्यामिक में अपना प्रथम उत्तरागत स्थापित किया । व्यापारी के मुँह के विज्ञान के उत्तरागत १९१२ में जनको राजनीति के धर्म प्रदान ई । उक्त समय में लक्ष १९४७ तक उत्तरागत भारत पर अत्यन्त सामन किया । इस काल के पूर्व और अन्य में इन देश और इनके निवासियों की कक्षा दशा था । इसका अनुमान गत है । अर्थात् शिक्षा उत्तरागत न सहायता प्राप्त है । मन् १७०० के भारत का वर्तन काल का प्रणाली यात्रा करनियर (Bencher) मिलता है । यह शिक्षागत एक उमा अवकाश गच्छा है जिसमें समाज का अधिकार होता और भी । यहाँ लक्ष के अर्थ कायता में आभार प्रदाता है और जिसका बाहर शिक्षा का उक्त एवं भी शक्ति नहीं मिलता है । २ की लक्ष्यी के प्रारम्भ में भारत का उमा का वर्तन विविध शिक्षा (William Dugby) ने इन का । म किया है । बागरी का । के मुँह के काल १० करोड़ मनुष्य शिक्षा भारत में है । शिक्षा समाज भा वर भर लक्ष नहीं मिल सकता है । इस अर्थ काय की दूसरा शिक्षा इन समय विविध गच्छ और उत्तम शिक्षा देना में वहाँ पर भी शिक्षाई नही । म करता है । इस अध्ययन का कारण था— अष्टादी का समाज निर्धारण में न के अनुसार समाज की प्राधान्य साम-समायता शिक्षा प्रणाली द्वारा और समाज पाठ्यपुस्तक और हस्तका काल के उत्तम उद्योग धंधे का माय कर सामना । ३



अग्रज गवर्नर जनरल लार्ड बेंटिन्क (Lord Bentinck) ने १८३८ में अपनी रिपोर्ट में शिक्षा व्यवसाय व इतिहास में लेव दुमाय का अर्थ उदाहरण बटिनाई से मिलाता है। जुलाहों की हठिहया ने भारत के मदानों को सफेद कर दिया है।<sup>१</sup> ऐसा दसा में भारत में जो प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पिता द्वारा पुत्र को अनेक पीढ़ियाँ से प्रदान की जा रही थी उसका सदेव के लिये अन्त हो जाना स्वाभाविक था। यह दसा अति दीर्घकाल तक चलती रही। उसका उपरान्त स्थिति में धनी दान कुछ परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। इसका अध्ययन हम मुबिया के लिये निम्नलिखित काला में करेंगे —

१८८० से १८८२ तक

यद्यपि इस काल में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) के पतस्वरूप प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था तथापि उक्त देश के सामरा ने अपने पास भारत में इन शिक्षा का प्रचार आवश्यक नहीं समझा। इसकी ओर सरकार का ध्यान सर्वप्रथम १८७७-७८ के दुर्मिश-आयोग (Famine Commission) द्वारा आकर्षित किया गया। फिर भी सरकार ने इस शिक्षा की अवहेलना ही की। हई मिशनरियों ने कुछ कार्य अवश्य किया। उन्होंने थोड़े से औद्योगिक स्कूल स्थापित किये जिनमें भारतीय ईसाई बालक की जाविकापाजन के लिये बर्क और मुहार के कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु इन स्कूलों की औद्योगिक स्कूल न कहकर दस्तकारी के स्कूल (Craft School) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

१८८२ से १९०२ तक

भारत सरकार प्रारम्भ में ही प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की विराधो थी। अग्रज शासकों का विचार था कि यदि भारत में इन शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई तो देश का औद्योगिक विकास प्रारम्भ हो जायगा और इससे इंग्लैण्ड व उद्योगों का आघात पहुँचेगा। इनके विपरीत भारत में राष्ट्रीय नेताओं का विचार था कि देश की नियोजना की दूर करने के लिये प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा अति आवश्यक है। कांफस ने १८८७ में होने वाले अने तीव्र अधिवेशन में सरकार से इन शिक्षा की माँग की और अग्य अधिवेशनों में इन माँग का दाहराती रही।<sup>२</sup> परन्तु निम्न स्थापित भारत की अग्रणी

1. The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton weavers are bleaching the plains of India.
2. Madan Mohan Malviya in Report of the Indian Industrial Commission 1916-18 p 20

सरकार इस माँग को निरन्तर टुकरानी रही। १९०२ में सम्पूर्ण भारत में केवल ८० प्राथमिक तथा प्रौद्योगिक स्कूल थे। इनमें से कुछ ही प्रौद्योगिक विज्ञानय कहमाने के अधिकांश थे।

१९०२ से १९२१ तक

इस काल में श्री भारत सरकार ने प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति बड़ी ध्यान नहीं दिया। हाँ इनका अध्ययन किया कि भारतीय शिक्षा आयोग (Indian Education Commission) को नियुक्ति का स्थापन करके विभिन्न प्रांता में हाई स्कूल व पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दे दिया गया।

१९२१ से १९३७ तक

इस उ्पर निम्न पुष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने निरन्तर प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को माँग कर रही थी, परन्तु सरकार ने इस माँग का स्वागत नहीं किया था। हाँ इनका अध्ययन किया था कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विद्यालयों को छात्र-वृत्तियों में लगे थे। १९०२ में १९१७ तक ११० छात्रों को छात्र-वृत्तियों में लगे थे। सरकार ने इस कार्य में जनता को मनोव नहीं हुआ कि प्राथमिक शिक्षा के अभिभावकों को छात्रों को छात्र-वृत्तियों में लगे हानी थी। इनके अतिरिक्त वे बहुत कम थी और उनमें अध्ययन अधिक होता था। १९१७ में मॉरिसन समिति (Morrison Committee) ने सुझाव दिया कि छात्र-वृत्तियों को छोड़ कर से उन विद्यालयों को ही जाय—जो वस्त्र (Textile) खनिज (Mining) मृत्तव्य (Pottery) चर्म मशीन (Tanning) शिल्प (Mat hies) काँच चीनी केन्द्र और वास्तु के उद्योगों में कार्य करना चाहिए। हाँ, परन्तु हमने कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

१९२१ में प्रांतीय में व्यवसाय का स्थापना व उद्योग जनता ने व्यावसायिक तथा प्राथमिक शिक्षा को माँग का प्रथम किया। यह कहा गया कि इस शिक्षा की आवश्यकता माँग में ही थी जाय। सरकार ने इसका निर्णय करने का कार्य लॉर्ड मिशन (Lyttton) को अन्तर्गत में एक विचार समिति को छोड़ दिया। हमने कि इस में अध्ययन करने का माँग—छात्रों को छात्र-वृत्तियों का अध्ययन किया और उनको दूर करने के लिए सुझाव दिया।

1. Bhagwan Das: *The Development of Modern India* Educ. - p. 43.

2. Committee on Indian Studies Report 1921-22.

का प्रथम महत्त्वपूर्ण सुझाव यह था कि भारत में प्रौद्योगिक प्राविधिक तथा औद्योगिक संस्थाओं का निर्माण किया जाय और उनमें उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय। भारतीयों का अपने देश में ही यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। अब यह आवश्यक है कि इस शिक्षा के विभिन्न अंगों का शास्त्र-अति शास्त्र विभाग किया जाय।<sup>1</sup>

इस शिक्षा के पक्षधर भारत में जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया वे इस प्रकार हैं — (१) हारकीर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट, बालपुर ( ) कलिकाता प्रायः इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी जाम्शेपुर और (२) गवर्नमेन्ट स्कूल ऑफ़ टेक्नोलॉजी मद्रास। १९३७ में सम्पूर्ण भारत में ५३५ प्रौद्योगिक प्राविधिक तथा औद्योगिक विद्यालय थे।

१९३७ से १९४७ तक

अब तक प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को अवहेलना की गई थी, परन्तु इस अवधि में इसका अत्यधिक प्रसार हुआ। इसके तीन प्रमुख कारण थे — (१) विश्वयुद्ध के कारण ऐसे व्यक्तियों की माँग में वृद्धि होगई थी जो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। (२) युद्ध-सामग्री का उत्पादन करने के लिए भारत में नवीन उद्योगों का स्थापना हो गई था और उनमें प्राविधिक शिक्षा प्राप्त मनुष्यों की आवश्यकता थी। (३) केंद्राध्यक्ष प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाई गई युद्धोत्तर विकास योजनाओं का प्रियोगित करने के लिये प्राविधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की माँग बढ़ी। अब प्राविधिक शिक्षा का विस्तार होना स्वाभाविक था। परन्तु उसका गन्तव्यजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि १९४१-४२ में केवल २०४ स्नातक प्राविधिक शिक्षा और २० स्नातक शास्त्रात्मक प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।<sup>2</sup>

स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक-

१। शिक्षा का प्रति दृष्टिकोण

जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं परन्तु भारत में शिक्षा का प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा था और ये विभिन्न सरकारों से इस शिक्षा की निरन्तर माँग कर रहे थे। इससे पक्षधर शिक्षा पर प्राविधिक प्रभाव पड़ा था परन्तु उम्र प्रति अलग ही

1 The Report of the Committee on Indian Students in England  
Para 84

2 Oxford Pamphlets on Indian Affairs No 15 p 54

बहुत आसानी है। स्वयं भारत में हम प्रभाव में निम्नतर मृष्टि होती जा रही है। हमारा मध्य प्रधान कारण है—प्राविधिक शिक्षा का अभाव तथा निवायिका का परिवर्तित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण क्या परिवर्तित हो रहा है इसका और हम निम्नोक्तिन विधियाँ में मध्यम कर रहे हैं।

१. विभाग एक ऐसी प्रक्रिया है— जिसमें निम्नलिखित चरणों की पूर्ति का विद्यमान समाज के साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना होता है। यथासाध्य कुछ प्रवृत्ति का द्वारा लिये हुए होते हैं परन्तु इनकी मधीन यथानिष्ठ उपयोगों और ज्ञान के प्रयोग द्वारा उद्योग किया जा सकता है और यह किया जाता है। हम दृष्टि में बनामिष्ठ उद्योग और ज्ञान का मुख्य पूरा निर्माण की ओर भी ध्यान है। जिससे भी अन्य उद्योगिकीय अर्थ-व्यवस्था में प्रवृत्ति द्वारा लिये हुए साधनों का पूरा ज्ञान नहीं होता है और उनको उद्योग ज्ञान का लिये नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण का प्रयोग करना पड़ता है। भारत में इन साधनों की कमी और इनका उपयोग अधिकाधिक अवस्था में है। आवश्यक यथानिष्ठ विधियाँ का ज्ञान भी अधूरा है। हम कारण ज्ञान साधन का उपयोग करने का लिये भी उन पर यथानिष्ठ विधियाँ का प्रयोग करना सारम मता है। हमें सत्य का स्तर की विचार और अधिक ऊँचा उठान का लिये न केवल ज्ञान साधन का अधिक सारम उपयोग की अपितु ज्ञान यथानिष्ठ विधियों के भी अधिक उद्योग प्रयोग की आवश्यकता पानी है। हमारे लिये नए-नए साधनों की निम्नतर मात्र करने रहना और नवीन उद्योगिक विधियों का विकास करना आवश्यक होता है।

मैं कहना अनुचितपूर्ण न होगा कि हमें का अधिक विकास अधिक हीमा में करने के लिये जिस तरह हमें का साधन और ज्ञान अधिक है वह उपयोग का प्रक्रिया में अनुचित प्राविधिक विधियों का प्रयोग करने का लिये समाज का इच्छा और सकारण है। हमें लक्ष्य में नवीन प्रवृत्ति अति साधन हो रही है और उद्योग प्रयोग में नवीन साधन और साधन के लिये अनुचित अधिक नवीन साधनिक दृष्टिकोण में लक्ष्य प्रदान का हम करने में भी सकारण है। विकास में साधन का ज्ञान का कारण प्राविधिक विधियों में नवीन उद्योगिक कर सकता होता है और हम अनुचित उद्योगिक कारण—विशेष साधन का साधनिक और नवीन यथानिष्ठ दृष्टिकोण की है। यदि हम दृष्टिकोणिका में अधिक कर सकते हैं तो हमें भी अधिक विधियों में उद्योग करने साधन में विकास की लक्ष्य में हो सकता है। जिससे—यदि कौटोन्ध साधन का साधनिक दृष्टिकोण में होता है न कुछ साधन में भी रहता है। अनुचित के

या मध्यम महत्त्वपूर्ण सुभाव यह था कि भारत में प्रौद्योगिक, प्राविधिक तथा औद्योगिक संस्थाओं का निर्माण किया जाय और उनमें उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय। भारतीयों को अपने देश में ही यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। अब यह आवश्यक है कि इस शिक्षा के विभिन्न अंगों का दोघ प्रति पात्र विराम किया जाय।<sup>१</sup>

इस विचारों के फलस्वरूप भारत में जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया वे इस प्रकार हैं — (१) हारबोर्ट मटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट बामबुर ( ) बॉम्बे और इन्डोनिशियन एण्ड टेक्नोलॉजी जादवपुर, और (२) गवर्नमेंट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। १९३७ में सम्पूर्ण भारत में २३५ प्रौद्योगिक प्राविधिक तथा औद्योगिक विद्यालय थे।

१९३७ से १९४७ तक

अब तक प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की अग्रगण्य की गई थी, परन्तु इस अवधि में इसका अर्थविक प्रसार हुआ। इसके तीन प्रमुख कारण थे — (१) बिजनेस के कारण ऐसे व्यक्तियों की माँग में वृद्धि होगई थी जो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। (२) युद्ध-सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए भारत में नवीन उद्योगों की स्थापना हो गई थी और उनमें प्राविधिक शिक्षा प्राप्त मनुष्यों की आवश्यकता थी। (३) ब्रह्म एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा बनाई गये युद्धोत्तर विकास योजनाओं का प्रसारित करने के लिए प्राविधिक शिक्षा प्राप्त व्यावसायिकों की माँग बढ़ी। अब प्राविधिक शिक्षा का विस्तार होना स्वाभाविक था। परन्तु उसकी संगोपजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि १९६१ ई. में जबकि ४४ स्नातक प्राविधिक शिक्षा और २० स्नातक सामाजिक प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।<sup>२</sup>

स्नातक भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक-

शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

देखा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं परन्तु भारत में साक्षात् प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा था और अब इसे ही सरकार का एक शिक्षा की निम्नतर माँग कर रहे थे। इसके फलस्वरूप शिक्षा पर प्राविधिक प्रभाव पड़ा था परन्तु उक्त प्रति अलग है।

1. The Report of the Committee on Indian Students in England  
Para 84

2. O.S. J. Papers, lists on Indian Affairs No. 15 p. 54

बढ़ा जा सकता है। स्वतंत्र भारत में हम प्रभाव में निम्नतर वृद्धि होती जा रही है। इसका मध्य प्रधान कारण है—प्राविधिक शिक्षा के प्रति देश में नेताओं तथा निवासियों का परिवर्तित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण कभी परिवर्तित हो रहा है इसकी ओर हम निम्नांकित परिचायक में संकेत कर रहे हैं।

१. विभाग एक ऐसी प्रक्रिया है—जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य के मापनों का अधिकाधिक सफलतापूर्वक उपयोग करना होता है। ये मापन कुछ प्रवृत्ति के द्वारा दिये हुए होते हैं परन्तु इनका मूलान व्यक्तित्व उपायों और ज्ञान के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और वह किया जाता है। इस दृष्टि में व्यक्तित्व उपायों और ज्ञान का मुख्य पूजा निर्माण का अंग भी अधिक है। इसी भी अन्य उद्योगों में अर्थ-व्यवस्था में प्रवृत्ति द्वारा किए हुए मापनों का पुनः ज्ञान प्राप्त होता है और उनको अन्य ज्ञान के विवेकीय व्यक्तित्व विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। भारत में इन मापनों की सीमा और इनका उपयोग गंभीर अवस्था में है। व्यवहार्य व्यक्तित्व विधियों का ज्ञान भी अप्रचुर है। इस कारण ज्ञान मापनों का उपयोग करने के विवेकीय भाव और व्यक्तित्व विधियों का प्रयोग करना गरम नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर और अधिक ऊंचा उद्योग के विवेकीय व्यक्तित्व ज्ञान मापनों के अधिक सफल उपयोग का अधिपु ज्ञान व्यक्तित्व विधियों के भी अधिक उत्तम प्रयोग की आवश्यकता होती है। हमारे लिए यह-एक मापनों की निरंतर मात्र करने करना और मूल्य उपायों विधियों का विकास करना करना आवश्यक होता है।

यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि देश का आर्थिक विकास अधिक तीव्रता में करने के लिए जिस एक बहुत बड़ा मापन और ज्ञान अधिक है वह उत्पादन का प्रक्रियाओं में आधुनिक प्राविधिक विधियों का प्रयोग करने के लिए समाज की दृष्टि और लक्ष्यरत है। इस क्षेत्र में मध्यम वर्गीय अर्थी ही हो रही है और उसका प्रयोग में बहुत जल्द जल्द परिवर्तन एक मापन का मापन के लिए अधिक प्राविधिक तथा मापनिक मापन में लक्ष्य करना का हम करने में भी सफल होता है। विकास में ये मापन ज्ञान का कारण अधिक विवेकीय में वर्गीय उद्योगों का विकास होता है और इस अर्थ में उद्योग का कारण—विकास प्राप्त करने का मापनिक और मूल्य उद्योगों के लिए ही है। यह एक व्यक्तित्व तथा व्यक्तित्व परिवर्तन का मापन है जो विकास के लिए करता मापन के विकास का प्रतिफल है। इन दोनों में व्यक्तित्व व्यक्तित्व का विकास विकास के लिए है। यह मापन व्यक्तित्व का विकास के लिए है।

उन प्राविधिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनकी अन्य उनसे दशा में परीक्षा हो चुकी है। परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अद्यतन ज्ञान प्रगति हो चुकी है उससे गाय-साध करने का भी ध्यान रखा जाय। सरासरी यह है कि नए-नए साधनों की खोज, नवानि यन्त्रानि प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक विधियाँ का प्रयोग और उपसम्बन्ध जनसाधन की विज्ञान-कार्यों के लिये आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उपयोग, विज्ञान की नींव का काम देता है।

### स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

स्वतन्त्र भारत के प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जिस परिबर्धित दृष्टिकोण का मूलन हमने ऊपर किया है, उससे परिणामस्वरूप शिक्षा पर प्राविधिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। हम इसका वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत कर रहे हैं

#### १९४७ से १९६५ तक

स्वातन्त्र्यप्राप्त काल में देश के औद्योगिकरण के साथ-साथ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा की भी अभिनन्दनीय प्रगति हुई है। १९४७ में केवल ६,९०० छात्रों की व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा देने का प्रबन्ध था। १९५३ में १२७०० छात्रों के लिये इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। १९५८-५९ में द्वितीयक तथा टैक्नोलॉजी के विद्यार्थियों का आगत ८३ करोड़ तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के १४६ पॉलिटेक्नीक के जिनमें प्रतिवर्ष लगभग १११०० एवं १६,४०० छात्रों का प्रवेश की सुविधा थी। नवानि स्वाकृत परिभाषनाओं के परिणामस्वरूप द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति तक द्वितीय पाठ्यक्रम में ११००० से अधिक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में २५,००० स्थानों का प्रबन्ध कर दिया गया। १९५८-५९ में विभिन्न व्यावसायिक, प्राविधिक एवं द्वितीयक संस्थानों के विभाग के लिये १३६२० साल दरमियाने लिये धन का अनुमान है एवं आगामी वर्ष में १४५३६ साल रुपये की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय एवं तृतीय योजना की परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिये आवश्यक कार्यकर्ताओं का अभाव का दूर करने के विचार से १६ बजट एवं ४१ पॉलिटेक्नीक के विभाग के लिये जुटा गया है जिनमें क्रि. २२९८ द्वितीय स्तर के तथा ३४०० डिप्लोमा स्तर के अतिरिक्त स्थान निर्धारित हैं। १९५८-५९ में अतिरिक्त धनी लिये गये धनों की मर्यादा द्वितीय पाठ्यक्रम में २३७८ एवं तृतीय पाठ्यक्रम में १६७८ थी जबकि १९५३-५९ में अतिरिक्त





## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

पाठ्य-क्रम में श्रुति शिक्षा का उपयुक्त स्थान चाहिए प्रौद्योगिक एवं प्राविधिक स्कूला का कालेज में स्थापन और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये छात्र वृत्तियों प्रदान करने की योजनाओं का निर्माण किया गया। कलाकारों एवं गिल्डकारों को प्रशिक्षण देने की अधिक सुविधाएँ तथा ग्रामों में भी प्रतिगण केन्द्र स्थापन की व्यवस्था की गई।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये गए उपायों का अतिरिक्त शिथिल योजना में व्यावसायिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई माँग के कारण प्रौद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा के विस्तार का विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। इसी उद्देश्य से द्वितीय योजना में व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा के लिये ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि प्रथम योजना में यह धन राशि केवल २३ करोड़ थी। शिथिल योजना के लिये निर्धारित धन का कुछ भाग उन कार्यक्रमों पर व्यय किया जायगा जो प्रथम योजना में प्रारम्भ किये गये थे।

इन कार्यों में इन्जिनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सड़कपुर को स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये पूर्णतया विस्तारित कर दिया जायगा। इस इंस्टीट्यूट में योजना के अनुसार १०० छात्रों के लिये प्राक्-स्नातक, और ६० छात्रों के लिये स्नातकस्तर पर एक साथ की व्यवस्था की जायगी। यहाँ विषयों की शक्ति में बहुत व्यापक विषयों के प्रतिष्ठान की सुविधाएँ हैं जिनमें पदोन्नति निर्माण किल्ड और सामुदायिक इंजीनियरी ईथन और ज्वलन इंजीनियरी निम्नी उद्योगों टेक्नोलॉजी पदार्थों का मानविक प्रणयन श्रुति इंजीनियरी में भी निम्नी नगर के प्राविधिक निर्माण योजनाओं और निर्माण किल्ड।

बंगलौर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक संस्था का विभाग वायु एवं ध्वनि इंजीनियरी इति इंजीनियरी आन्तरिक वस्त्र इंजीनियरी वायु विज्ञान और विद्युत इंजीनियरिंग विषयों को प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए किया गया है।

प्रथम योजना-काल में स्थापित किये गये व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा के प्रथम वर्षों में स्नातकोत्तरकाल में पाठ्य क्रमों एवं इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अनुगमन की व्यवस्था की जायगी। वर्तमान संस्थाओं को द्वितीय और तृतीय पाठ्य क्रमों के लिये विस्तार करने का जो कार्य प्रथम योजना में प्रारम्भ किया गया था उस कार्य में योजना में पूर्ण किया जायगा। शेष धन दत्त

४ पश्चिमी, उत्तरा और दक्षिणी प्रदेशों में उच्चतर व्यावसायिक तथा प्राविधिक मस्थाओं की स्थापना में व्यय किया जायगा। इनमें से दो मस्थाओं का निर्माण बम्बई और कानपुर में किया जायगा। पूर्ण रूप में विकसित हो जाने पर प्रत्येक मस्था में १२०० प्राक्-स्नातक और ६०० स्नातकोत्तर छात्र शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

द्वितीय योजना-कान में 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नीकल मस्था' में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जायगा। इससे अनिश्चित देश के विभिन्न भागों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिये ॥ मस्थायें दिल्ली शहर की ओर २१ मस्थायें डिप्लोमा स्तर की स्थापित की जायेंगी। कारखानों के प्रविष्टियों की योजना की उद्योग-मस्थाओं के सहयोग से त्रि-अक्षरित किया जायगा। छात्रवृत्तियों की संख्या को ६३३ से बढ़ाकर ८०० कर दिया जायगा। प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा-मस्थाओं में वायव्य छात्रा के लिये कुछ नि:शुल्क स्थान सुरक्षित रख जायेंगे। १३००० टेक्निकल छात्रों और ३३०० इनिशियल टेक्निकल स्कूला के विद्यार्थियों के लिये अनिश्चित छात्रा भागा का निर्माण किया जायगा। मुम्बई शहर विस्तार की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मस्था का निर्माण किया जायगा। बनारस के इन्डियन स्कूल ऑफ़ माइंग एण्ड ऐप्लाइड टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जायगा। त्रिगुण स्थान की इंजीनियरिंग एवम् उद्योग मस्थाओं में प्रविष्टियों की सुविधाओं उत्तम रूप हो जायेंगी। धर्म मोहा तथा हरन और देवरे मस्थालय भी टेक्निकल स्कूलों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करना रहे हैं। इन मस्थालयों के समन्वय १९६०-६१ तक प्रविष्टि १७०० स्नातक तथा ६८०० डिप्लोमा छात्रों को उत्तम रूप दूना होंगे। यह मस्था प्रथम योजना के अन्तर्गत् प्रान्त होने का नाम स्नातक तथा डिप्लोमा स्तर की स्थितियों से अथवा दुगुनी और त्रिगुनी होती।

तृतीय पंचवर्षीय योजना ॥ प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

पिछले योजना का अवधि में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत ६३ से बढ़ाकर ८७ और उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत १८८८ से बढ़ाकर २३३६३ हो गई है। पश्चिम के ११ मस्था १९६१ में बढ़ाकर १९७१ में २३३६३ हो गई है। पश्चिम के ११ मस्था १९६१ में बढ़ाकर १९७१ में २३३६३ हो गई है। पश्चिम के ११ मस्था १९६१ में बढ़ाकर १९७१ में २३३६३ हो गई है।

बालों की संख्या १७४८४ से बढ़कर २४०२० हो गई है। स्नातकों की शिक्षा में ५ वर्ष और डिप्लोमाधारियों की शिक्षा में ३ वर्ष लगते हैं। इस कारण प्रतिवर्ष निश्चयने वाले स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की संख्या में वृद्धि इस अनुपात से नहीं हुई। उनकी वार्षिक संख्या प्रथम ४,००० से ८३०० और ४००० से १७००० तक ही पहुँच पाई है। परन्तु इन शिक्षा संस्थाओं का जितना विस्तार अब तक हो चुका है उससे आधार पर भी १९६५ तक वर्तमान इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करके निश्चयने वाले स्नातकों की वार्षिक संख्या ११५०० और पॉलिटेक्नीकों से निश्चयने वालों की संख्या १८६०० हो जायगी।

द्वितीय योजना के समय ४५००० स्नातकों तथा ८०,००० डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता पड़ेगी। सम्भावना है। यह सब पूरा हो जायगी। डिप्लोमा धारियों की जो बोझी बनी रहेगी उसे पूरा करने के लिये द्वितीय योजना के प्रारम्भ में ही मयागोष्ठ अतिरिक्त शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

तृतीय योजना की अवधि में द्वितीय सेने वाले छात्रों के वार्षिक प्रवेश में ६००० की वृद्धि कर देने का विचार है—५००० को इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रविष्ट करने तथा १००० को आंगिक समय में अवकाश पत्र व्यवहार द्वारा पढ़ाकर। अब वार्षिक दाखिला की संख्या १९६१ से १३२०० से बढ़कर १९६६ में ११७०० हो जायगी। इस प्रकार चौथी योजना के समय ७५०० इंजीनियर गणना की सम्भावित माँग इंजीनियरिंग कॉलेजों में निभाने हुए और आंगिक समय में अवकाश पत्र व्यवहार द्वारा पढ़े हुए स्नातकों को मिलाकर पूरी हो जायगी।

इसी प्रकार डिप्लोमा सेने वाले छात्रों के वार्षिक दाखिला की संख्या में १५००० की वृद्धि कर देने का विचार है—१०००० का पॉलिटेक्नीकों में प्रविष्ट करने तथा ५००० को आंगिक समय में अवकाश पत्र व्यवहार द्वारा पढ़ाकर। अब वार्षिक दाखिला की संख्या जो द्वितीय योजना के अन्त में २४००० की थी तृतीय योजना के अन्त तक बढ़कर ५६००० हो जायगी। इस चौथी योजना के समय डिप्लोमाधारियों की सब माँग पूरी हो जायगी। इस प्रकार उम्माग अनुमान १०००० सम्भावित माँग है। सम्भव है कि

योग हमसे भी बढ़ जाय । यदि ऐसा हुआ तो उस पूरा करने के लिये आवश्यक उपाय नियत जायग ।

तत्तीय यात्रना में प्राविधिक विभाग के विभाग कार्य-क्रम का पूर्ण बनने के लिये १५० करोड़ रुपये रगे गये हैं ।<sup>१</sup>

## आधुनिकतम गति विधियाँ

### विज्ञान-मन्दिर

देश के विभिन्न भागों में ३८ विज्ञान मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं । राज्य सृष्टिमात्रा में नाम हुआ है कि ये विज्ञान मंदिर सौकरप्रिय सिद्ध हो गये हैं । सरकार का विश्वास है कि सन्ध्या को बढ़ाकर ३० बजे तक है किमति कि प्रत्येक दिन में एक विज्ञान मंदिर हो जाय । यह विज्ञान मंदिर वर्षावर माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित रहेंगे । सम्भवतः इन ज्ञान मंदिरों के माध्यम से माध्यमिक स्तर भी स्थापित किया जायगा ।

### छात्रवृत्तियाँ

विभिन्न संस्थाओं में ही जाने वाला छात्रवृत्ति के अनिवार्य बर्तानिक अनुसंधान संस्थाओं ने इस वर्ष में योग्यता और माध्यम छात्रवृत्ति कार्यक्रम की है ताकि एक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा को सहायता प्रदान हो सके ।

### अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ

एक वर्ष अनुसंधान छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत १९६६ छात्रवृत्तियों प्रदान की गई । इन छात्रों में से ८०० छात्रवृत्तियों का आकलन है । इन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसंधान समितियों के विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करा गया ।

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें  
प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति

संस्थाओं के प्रकार	१९४६-५०		१९५०-५६	
	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या
१ कृषि कनिष्ठ	१५	४५३८	२६	१०८०१
२ कामगार कनिष्ठ	२१	३२,१०८	३५	६६६१३
३ इंजीनियर कनिष्ठ	२३	१०६०६	५३	३००४६
४ वन शिक्षा के कनिष्ठ	४	३८६	३	५६६
५ वायुन के कनिष्ठ	२०	१०६३३	३२	२४०५५
६ मेडिकल कनिष्ठ	३५	१२८३५	१०६	३२,२४२
७ पारोरीक शिक्षा के कनिष्ठ	५	१६२	१५	७४५
८ शिगक प्रशिक्षण कनिष्ठ	४८	४७६१	२३३	२४४८८
९ टेक्नोलॉजी के कनिष्ठ	३	१२५३	६	४४५७
१० वेटरिनरी कनिष्ठ	१०	१४८६	१७	५७३५
११ वास्तव्य और टेक्निकल स्कूल	२० २८	१६२५३२	३५३३	३४८७५
१२ कृषि स्कूल	३६	१८८२	१०२	७४११
१३ आर्ट और साइंट स्कूल	१३७	६८८७	३७४	१५६६६
१४ कामगार क/स्कूल	४१२	२७६८२	६६६	६८७५४
१५ इंजीनियरिंग स्कूल	१६	३८७०	११८	४७६७७
१६ वन शिक्षा के स्कूल	२	५३	५	२१७
१७ टेक्निकल और इन्जिनियरिंग स्कूल	४८६	३४३२६	८३३	६४५५८
१८ शिगक प्रशिक्षण स्कूल	७२०	६७०४६	६७४	८६,३७६
१९ पारोरीक शिक्षा के स्कूल	१७४	१३,६६६	३८	७३६३६

## मस्यस्यार्थे और उनके समाधान (Problems & Their Solutions)

अब जो सामान्य बात में भारतीय शिक्षा पर प्रौद्योगिक प्रभाव अति अल्प था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ने इस प्रभाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत प्राविधिक एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश हिम जल का प्रयाग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों की शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। सरकार तथा व्यक्तिगत संस्थाएँ इस शिक्षा में वृद्धि कर में व्यस्त हैं पर अभी भारत में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति मंदतर गति में हो रही है। इसका कारण यह है कि अनेक वापस तथा समस्याओं में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रभाव का अभाव कर रहा है। ये वापसों की-तादृशी तथा समस्याएँ क्या हैं? इसी पर हम विचार करेंगे।

### १. समस्या—अनुचित दृष्टिकोण (Wrong Attitude)

भारत में अति प्राचीन काल में मानविक धर्म का बराबर पर प्रतिष्ठित किया गया है और शारीरिक धर्म को हीन दृष्टि में देखा गया है। कार्य अथवा धर्म का आधार पर ही हमारे देश में जाति-व्यवस्था का निर्माण किया गया था। पढ़न-प्राप्त करने का नाम काजगत् की समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया और अध्ययन तथा हस्तकार्य करने का नाम व्यवसाय को उनमें निम्नतर स्थान दिया गया था। महत्वा के प्राचीन जाति-व्यवस्था पर व्यापारिक धर्म विभाजन की ओर हमारा समाज में इतना लक्ष्य गत है कि उनको निम्नता माना रहित है। यही कारण है कि आज का प्रगतिशील युग में भी हस्तकार्य करने वालों का आदर का दृष्टि से कम देखा जाता है। प्राविधिक शिक्षा में हस्तकार्य तथा कोशिका का प्रमुख स्थान है। अब क्या व्यवस्था है भारतीय इस शिक्षा का सम्मान नहीं देता है। इस अनुचित दृष्टिकोण का परिणाम यह है कि उच्च जाति तथा परिवारों के मनुष्यों प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने का अति अकारण्य उन्मील रहता है। यद्यपि इस शिक्षा का उचित विचार नहीं हो रहा है।

### समाधान

इस समाज का समाधान क्या है? यदि हमारा और कार्य समाज के मध्य यह व्यवस्था है कि हमें यह धर्म (वर्ग) देना है कि मानविक

## मातृशिक्षा और उसकी समस्याएँ

धर्म से होना नहीं है तो देश में नवयुवकों को प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में प्रति आकर्षित किया जा सकता है। परन्तु सबसे बड़ा आन्दोलन तो ही काम नहीं चलेगा। इससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन में सहायता अवश्य मिलनी परन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को उन छात्रों को अध्ययन की सुविधाएँ देनी होंगी जो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब यह आवश्यक है कि सरकार उनको छात्रवृत्तियाँ दे, अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त उनके लिये नौकरियाँ सुलभ बनाए और उन्हें अधिक वेतन तथा अन्य सुविधाओं का आश्वासन दे।

### २. समस्या—शिक्षासूचियों का अभाव (Dearth of Institutions)

यद्यपि स्वतन्त्र्योत्तर काल में अनेक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों का स्थापना की गई है, तथापि उनकी संख्या को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। आज की जागरूक भारतीय जनता समझने लगी है कि प्राविधिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों का अविष्य उल्लस है। परन्तु विद्यालयों की ग्यूनता के कारण लगभग ६० प्रतिशत छात्रों को इस शिक्षा की सुविधा में प्राप्त होने में कारण महात् निराशा होनी है। ऐसी स्थिति में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास की आशा करना व्यर्थ है।

#### समाधान

इन कठिनाई पर विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब देश में और अधिक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों की आधारशिला रखी जाय और उगम सभी स्तरों की प्राविधिक शिक्षा की समस्या की जाय जिससे कि विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का बाल छात्र उनमें प्रवेश लेकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की अपनी इच्छा को सन्तुष्ट कर सकें। इस समय भारत में व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालयों की संख्या २६४ है।<sup>१</sup> इनकी शिक्षा जनसंख्या का केवल एक तिहाई विद्यालयों की यह संख्या अति ग्यून है। अब सरकार का कर्तव्य है कि स्वरित गति से नवान प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करे।

### ३. समस्या—सकीर्ण पाठ्य-क्रम (Narrow Curriculum)

हमारे प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों में पाठ्य-क्रम मशीनों के निर्माण के अति प्राथमिक विषयों का ही स्थान दिया गया है। उनमें सामान्य

<sup>१</sup> तुनीय पञ्चवर्षीय योजना (प्रारम्भिक अवस्था) पृष्ठ १०३।

तथा सम्बन्धी शिक्षण (Liberal Education) का कोई स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा प्राप्त करने में नवयुवक उत्पादन कार्य के सामाजिक उत्पन्न तथा मानव-सम्बन्धी का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जनस्वरूप उत्पादन कार्य सुचारु रूप में नहीं चल पाता है। अतः हम यह कहते हैं कि सकारण पाठ्य-क्रम का कारण प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रायः निरर्थक हो जाता है।

पाठ्य-क्रम का इस दोष का निवारण करने के लिए उनमें प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य तथा सरकारी शिक्षण का भी उचित सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। इसके का विषय है कि छात्रों के लिए सरकारी का ज्ञान इस प्रकार आवश्यक है और यह प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्य-क्रमों को विस्तृत करने के लिए सामान्य तथा सरकारी शिक्षण का स्थान दे रही है।

#### ४ समस्या—शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम (Unsuitable Medium of Instruction)

आधुनिक भारत के सभी प्राथमिक शिक्षण में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। राज्या के शिक्षा-अधीन के सम्मेलन में २ दिसम्बर १९५६ का एक परिणत अवलोकन नेहरू ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शिक्षण में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। परन्तु क्या अंग्रेजी के कारण राज्या की शिक्षा का सामना नहीं करना पड़ रहा है? उत्तरार्थ—उत्तर प्रदेश में इन्टरमीडिएट विभाग का शिक्षा का माध्यम शिक्षा है। जब यदि एक छात्र इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त शिक्षा प्रौद्योगिक शिक्षण में प्रवेश करता है तो वह वहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी मिलता है। जब तक कि उनमें शिक्षा में वृद्धि और समझ है परन्तु शिक्षा उन अंग्रेजी में सुविधा देना और शिक्षा है। इस परिणत के कारण शिक्षा ही छात्र का विचार होकर अपना अध्ययन समाप्त कर देता है और शिक्षा ही वह है जो शिक्षा में अनुमीर्ण होने के कारण शिक्षण का त्याग करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तब शिक्षा का शिक्षा इन शिक्षा की शिक्षा पर उनमें परिणत के अध्ययन पर और शिक्षा अध्ययन के लिए यह पर।

#### समाधान

यह शिक्षा है कि इस अध्ययन का शिक्षण करने के लिए शिक्षा के प्रयोगों को करना शिक्षा की शिक्षा का शिक्षण करना शिक्षा शिक्षा का शिक्षा



## भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएँ

विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं को प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ेगा। हमने माना कि इस कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि न तो अभी हमारे पास प्राविधिक विषयों की भारतीय भाषाओं में पुस्तकें ही हैं और न उनकी उपयुक्त सामग्रियाँ ही तैयार हैं। परन्तु इस निश्चय इस कार्य में अवश्य सफलता प्रदान करेगा। अथ दशम उदाहरण हमारे समक्ष है। चीन जापान रूस जर्मनी और ब्रिटेन ही अन्य देशों में यह शिक्षा का माध्यम वहाँ की भाषाएँ हैं न कि अंग्रेजी। यदि उन देशों में यह कार्य सम्भव हो सकता है तो अग्रजों की वास्तविकता से मुक्ति प्राप्त करने अग्रजों की क्षमता की वृद्धि भारत को क्यों पहुँचाई जाय ?

### ५. समस्या—प्रायोगिक शिक्षा का ग़ुन महत्त्व (Less Importance of Practical Education)

हमारे प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों में सैद्धांतिक शिक्षा (Theoretical Education) को प्रायोगिक शिक्षा (Practical Education) की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। परिणाम यह होता है कि प्राविधिक विद्यालयों से निकल हुए स्नातक प्रायोगिक कार्य में दक्ष नहीं होते हैं। यद्यपि वे उन्हें इसी कार्य से अधिक प्रयोजन रहता है। वस्तुतः उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्हें छाया रहित अपने अधीनस्थ और कम शिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। इससे उनके सम्मान की हानि होती है।

समाधान

इस दोष का उन्मूलन करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे प्राविधिक विद्यालय प्रायोगिक शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करें। इस कार्य में उन्हें योद्धा तथा अमेरिका के प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों से पाठ सीखना चाहिए। वहाँ छात्रों को कमपाठों में कठिनाई आने पर अंतरात्मा इतना प्रायोगिक ज्ञान करा दिया जाता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने में असफल होने की शंका नहीं रहती है और वे उन्हें अन्य व्यक्तियों का मुँह ताकना पड़ता है।

### ६. समस्या—उपरान्त शिक्षा का अभाव (Lack of Continuation Education)

प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त अधिकांश विद्यार्थी उदात्त में प्रवेश करते हैं। कुछ समय तक वे उनमें अग्रगण्य स्थिति में रहते हैं परन्तु धीरे-धीरे उनमें स्थिति घटने लगती है।

है। वे अनेक बातें विस्मृत कर देने हैं। फलतः उनसे दक्षता में न्यूनता आ जाती है। जिनका अधिकांश प्रौद्योगिक ज्ञान एक मनुष्य में होगा उतनी ही अधिकांश प्रौद्योगिकीय वह प्राविधिक कार्य को सम्पन्न कर सकेगा। परन्तु यदि ऐसा नहीं है तो वह कुशलता से त्वरसे नीचे गिर जायगा। मायात्मक दक्षता भी ऐसा ही जाना है। इसका प्रधान कारण यह है कि प्राविधिक शिक्षा आज व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत समाविष्ट है और अतः शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

### समाधान

प्राविधिक शिक्षा की इन समस्याओं का निवारण अनेक विधियों द्वारा किया जा सकता है। प्रथम अंग्रेजी शिक्षा (Part time instruction) की व्यवस्था की जाय। परन्तु यदि दिन में किसी समय इन शिक्षा की व्यवस्था की जाय तो कर्मचारियों को उसे प्राप्त करने की सुविधा दी जानी चाहिये। इन शिक्षा में बहुत 'मिडियम' (Theory) को ही स्थान दिया जाय क्योंकि प्रायोगिक कार्य में ही कर्मचारी अपनी कर्मगतमात्रा में ही कार्य करके कुशल हो जाते हैं। द्वितीय कर्मचारियों के लिये 'अभिनव पाठ्यक्रम' (Refresher Courses) की व्यवस्था की जाय। यहाँ यह निश्चित देना चाहिये कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष या दो वर्ष में अवकाश अवकाश का समय मिले और एक बार या दो बार एक निश्चित अवधि में लाभ उठाने के लिए बाध्य किया जाय।

### ७ समस्या— शिक्षकों का अभाव (Dearth of Teachers)

प्राविधिक शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है—उत्तम शिक्षकों का अभाव। प्राविधिक विद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षकों की प्राप्ति करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है। कारण यह है कि शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को इनका अधिकांश ज्ञान और अनुभव ही सुविधाएँ मिलती हैं कि वे प्राविधिक विद्यालयों में शिक्षकों का कार्य कर सकें। बहुत कम लोग ही ऐसा कर सकते हैं। फिर शिक्षकों का अभाव में कोई समाधान नहीं है। हमारे विद्यार्थी किसी उद्योग तथा व्यवसाय में कार्य करने वाले अधिकतर लोग ही हैं जो काम व्यवसाय का अभाव में गिर रहे हैं। प्रथम विद्यालय उत्तम शिक्षा की मांगों में अधिकांश नहीं है। प्रथम इन विद्यालयों का शिक्षा स्तर ही गरीब है।

एक व्यावसायिक विद्यालयों के लिये योग्य शिक्षकों की सेवाओं को सुलभ बनाये। इस कार्य में सरकार को सफलता सभी प्राप्त हो सकता है जब वह प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों के शिक्षकों के भर्तना में वृद्धि करे और उनकी सेवाओं को शर्तों को उत्तम बनाये। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकेगा।

हम हर्ष है कि सरकार इस समस्या का समाधान में व्यस्त है। 'तकनीकी शिक्षा के विस्तार की एक बड़िया समस्या—शिक्षकों की कमी है। हिमाचल लगा कर देना गया है कि आजकल यह कमी छिछो कर्मियों में लगभग ३३ प्रतिशत और डिप्लोमा-अस्थाओं में २५ प्रतिशत है। दूसरी योजना में कुछ यात्राओं लुने हुए इन्जीनियरी कॉलेजों में गिण्टवृत्ति देकर शिक्षक तयार करने को और स्नातक को इस शर्त पर विद्वानी छात्रवृत्तियाँ देनी शुरू की गई थीं कि वे वहाँ से लौटकर भी शिक्षक का कार्य करेंगे। इन्हें तीसरी योजना में भी जारी रखा जायगा। अक्सर भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की है कि तकनीकी विषय पढ़ाने वालों की भर्तन करें ऊँची कर दी जायें। आशा है कि इस सिफारिश का कारण भी कुछ अधिक लाग इस पक्ष की ओर आकृष्ट हान।

## UNIVERSITY QUESTIONS

1. What in your opinion is the importance of Technical and Vocational Education? How has this need been met in Free India?
2. What problems are being faced in the expansion of technical and vocational education? How can they be tackled?

अध्यापक-शिक्षा  
(Teacher Education)

**(Teacher Education)**

विषय प्रयोग

[illegible]

भारताय गिरा और उसकी समस्यायें

जो अन्तिम प्रगति और समर्थ की सम्भावनाओं से आसक्ति है जबकि मात्र मूर्ति स्वर्णयुग में पदार्पण कर रही है । ११

ऐसे पुनीत व्यक्ति व पुनीत कार्य की सुदूर प्राचीन युग में भी अक्षतता नदी की गई और उसने प्रविष्टि की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वह अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सक ।

प्राचीन भारत में अध्यापक शिक्षा

प्राचीन भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि अध्यापक अपने प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देता था । सभी-सभी एक गुरु व पाम विद्या वर्जन के लिये इनके छात्र आ जाने थे कि वह उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता था । अतः वह उच्च जाता व सत्ये अग्रिम छात्र की सहायता और सहयोग प्राप्त करता था । व 'वित्ति आश्रय' (Pitruacharya) कहे जाते थे । वे छात्र व गिराण म गुरु की सहायता करते थे । यदि सभी गुरुजी कुछ समय के लिये वहाँ बन जाते थे ता वे अध्यापन और विद्यालय का समस्त कार्य उनका गौर जाते थे । यह कक्षा-नायकीय पद्धति (Monitorial System) की जगहें बता के कुछ नायक अथवा अग्रिम छात्र विद्यालय-सहायता और शिक्षण का कार्य करते थे । जिन छात्रों को यह कार्य गौरा जाता था वे समय की गति के साथ कुछ न अध्यापक और विद्यालय सहायक हो जाते थे । इन प्रकार प्रगति होकर वे प्रविष्टि में अध्यापन गाय म रत हो जाते थे । यद्यपि इनका शिक्षा सिद्धांत ऐसे विषय की शिक्षा न थी

1 A true teacher is rich without money His wealth is to be reckoned not in terms of bank balance but in the bounteous love and loyalty he has evoked in his pupils He is an emperor whose empire is carved in the grateful minds of his pupils which no power on earth can shake no atom bomb can destroy Teaching is a divinely ordained mission To talk of it in terms of trade union and craft guild is to degrade it to adopt tactics intended to frighten people into ploy is to desecrate it Blessed is he who is a teacher twice blessed is he who is born a teacher in this great land of ours where the preceptor has been loved honoured and lifted to the rank of the gods showing him reverence thrice blessed is he who is teacher here in this glorious dawn which is flushed with the possibilities of unprecedented progress and prosperity when the motherland is on the Threshold of a Golden Era "

—S Bala Krishna Joshi

जाते थे। पर उनकी इतनी प्रियात्मक (Practical) प्रशिक्षण शिक्षा प्राप्त थी कि उनकी अपना कार्य में लगपन हान का प्रश्न उठता ही नहीं था। भारत में 'बालानाथजीय पद्धति' अष्टकों के आगमन तक विद्यमान थी। १७८७ में ऐंड्रयू बेल (Andrew Bell) ने अपने विद्यालय में इस पद्धति का अपनाया। इसी के आधार पर दृगमण्ड में बेम पद्धति का विकास हुआ।

### मुस्लिम-शाला में अध्यापक-शिक्षा

भारत के मुस्लिम शासकों का ख्येय था अपने धर्म का प्रचार करना और मुसलमानों को मुगलमान बनाना। आरंभ में मुस्लिम शासकों के प्रशिक्षण और शिक्षा में भी मुस्लिम शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा दस्ता में अध्यापक शिक्षा का विचार भगिन के मन में आता रहित था।

### अध्यापक शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयास (Early Efforts for Teacher Education)

आधुनिक युग में सबसे पहले बम्बई महाराष्ट्र और बलकला का शिक्षा-परिषद् ने अध्यापकों की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया और उन्होंने मोटे में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की। पर इन केन्द्रों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशिक्षण शिक्षा आता था।

'बम्बई प्रांत का दक्षिण शिक्षा परिषद् (Native Education Society) ने १४ अध्यापकों की प्रशिक्षण दफ्तर में एक विभिन्न भाग में सेवा शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए का कक्षा उठाया था।

१८१६ में बलकला विद्यालय परिषद् (Calcutta School Society) स्थापित की गई। इसने बालानाथजीय पद्धति पर आधारित शिक्षा के प्रशिक्षण का प्रयास किया। १८२२ में ई.ए. हर्बर्ट की स्थापना के संभावना में शिक्षा के लिए का प्रोत्साहित करने के लिए १८००) प्राथमिक महाविद्यालय स्थापित किया।

१८६६ में महाराष्ट्र के बम्बई मुन्सा (Munro) के सुझाव के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र में एक विद्यालय का शिक्षा-परिषद् स्थापित किया।

### गुड का पाठ्य-पत्र एवं अध्यापक शिक्षा (Wood's Dispatch & Teacher Education)

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

प्रशिक्षण विद्यालय निर्मित किये जायें ।<sup>1</sup> औपनिषद् शास्त्र इ जोतिरिग तथा गान्धुन शास्त्रि म भी प्रशिक्षण की व्यवस्था का जाय ।

महासभा ने यह भी आशा प्रकट की कि छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा विभाग को उनका ही आकर्षण बनाया जाय जिनने कि अन्य राजकीय विभाग से ।<sup>2</sup>

बुद्ध व घोषणा-पत्र म कम्पनी के महासभों ने अध्यापक शिक्षा के लिये भी आशा व्यक्त की थी वह पूर्ण न हुई । भारत स्थित कम्पनी के कर्मचारियों ने महासभों के आदेश क प्रति कोई ध्यान नहीं दिया । इसका उल्लेख करते हुए सर्वप्रथम भारत मंत्री (Secretary of State for India) लार्ड स्टनले (Lord Stanley) ने अपने १८५६ के आदेश-पत्र (Despatch) में लिखा—  
कम्पनी व महासभों ने जिन प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना व सम्भाल म आग्रह दिय थे उनकी स्थापना अभी तक नहीं की गई है ।  
१८५६ से १८८२ तक अध्यापक शिक्षा

लार्ड स्टनले ने अपने आदेश-पत्र म इस बात का उल्लेख किया कि अध्यापक व प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । सत्ता हस्तान्तरण के उद्गम्य भारत स्थित अंग्रेज प्रशासकों के लिये भारत मंत्री व आंग्ल की अवज्ञा करना सम्भव नहीं था । अतः उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों व शिक्षकों व प्रशिक्षण के लिये अग्रिम उद्गम्य ने कार्य किया और १८८२ तक प्रत्येक प्रांत म अनेक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हो गये । १८८२ म दसवीं म ७ प्रशिक्षण विद्यालय शुरू किये और १ क्रिया के लिये थे । इनमें अध्यापक बनने वालों की कुल संख्या ५२३ थी । मध्य प्रदेश म ४ प्रशिक्षण विद्यालय थे—३ पुरानों के लिये और १ क्रिया के लिये । इनमें पढ़ने वालों की संख्या १८८ थी । १८६२ म बंगाल म नार्मल स्कूल प्रणाली (Normal School System) प्रारम्भ की गई । इसके अनुसार सभी पाठशालाओं के शिक्षकों या उनके गवर्णियों की नार्मल स्कूल म भेजा जाता था । प्रत्येक शिक्षक को २० मासिक छात्रवृत्ति दी जाती थी । १ वर्ष के प्रशिक्षण के बाद अध्यापक का

"We desire to see the establishment with as little delay as possible of training schools and classes for masters in each Presidency in India  
—Wood & Deitch

"Our wish is that the profession of schoolmaster may for the future afford inducements to the natives of India such as are held out in other branches of the public service  
—Ibid

अपने विद्यालय को सीटना पड़ता था। छात्राध्यापक को शिक्षण-विधि-गणित इतिहास आदि विषयों की शिक्षा हो जानी थी। छात्राध्यापक बाराह नामक स्कूल प्रणाली को विस्तार न दिया जा सका और १८७१ तक बस २४३ नामक स्कूलों की स्थापना हुई। १८७४ में प्रान्त के गवर्नर बम्पटन (Campbell) ने शिक्षक के प्रतिशोध के सिद्ध एक नवीन योजना की रूप रेखा तैयार की। इसके अनुसार १ लाख ६४ हजार रुपये व्यय करके ४६ नामक स्कूलों का निर्माण किया गया। मगध में ३२ प्रतिशोध विद्यालयों के त्रिनम प्रतिशोध प्रान्त बन जाने की गणना ६७ थी। इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रतिशोध का प्रबंध किया गया था। १८८२ में मगध प्रान्त में १०६ नामक स्कूलों के त्रिनम ३८८६ पुस्तकें एवं शिक्षा की प्रतिशोध दिया जा रहा था। इन स्कूलों का वार्षिक व्यय लगभग ८ लाख रुपये था।

१८८२ में अध्यापक शिक्षा की स्थिति (Position of Teacher Education in 1882)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि १८८२ तक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रतिशोध के लिए कुछ कार्य किया गया। नर स्थापित प्रतिशोध विद्यालयों में विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया। प्रारम्भ में इन विद्यालयों में बरतानादधीय पद्धति (Monitorial System) को प्रयोजित किया गया। कुछ समय के उपरान्त उनमें निम्नलिखित प्रणाली (Apprentice System) को अपनाया गया। इस प्रणाली के अनुसार छात्राध्यापक किसी अनुसंधी अध्यापक के साथ एक निश्चित समय तक रह कर शिक्षण-सम्बन्धी विषयों का ज्ञान प्राप्त करता था। बरताना प्रान्त में अरवि तीन वर्ष की थी। छात्राध्यापक का ३। मे २ नर वार्षिक छात्रवृत्ति का मिलती थी।

जहाँ तक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रतिशोध का सम्बन्ध है, इस और गहनतम प्रकाश दिया गया। १८८० तक मगध प्रान्त में बरताना प्रणाली महाविद्यालय के—एक महान्त में शिक्षकों का प्रान्त १८४६ में हुई थी और दूसरा प्रान्त में शिक्षकों के विद्यालय १८८६ में किया गया था। इन महाविद्यालयों में कुल ४१ छात्राध्यापक थे जो ६१११ शिक्षकों की संख्या में पूर्ण करने में असमर्थ थे। इसके प्रतिशोध के विद्यालयों का प्रतिशोध ज्ञान के का था और इसके बाद अध्यापक के विषय में शिक्षकों का प्रतिशोध १८७३ में नहीं दे।



## अध्यापक शिक्षा की नियमित व्यवस्था (Regular Provision for Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा की निश्चित व्यवस्था करने के लिए सबसे पहला क़दम १८८२ में भारतीय शिक्षा-आयोग ने उठाया। उसने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए —

- १ प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाय जहाँ में वे समस्त प्राथमिक पाठशालाओं की स्थानीय माँगों का पूर्ति कर सकें। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम-से-कम एक नाममात्र स्कूल का स्थापना का जाय।<sup>१</sup>
- २ नाममात्र स्कूलों का संकल्प बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक निरीक्षक अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालय में रहें। और उसमें पूर्णतः सन्तुष्टि की व्यवस्था करे।
- ३ प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत धन राशि में से प्रारम्भिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा नाममात्र स्कूलों की स्थापना की उचित व्यवस्था की जाय।<sup>२</sup>
- ४ प्रशिक्षण विद्यालय कुछ स्थानों तक ही मामूली न रहें और समस्त क्षेत्र में फैला दिए जायें।<sup>३</sup>
- ५ ग्नानन एव उन्नतानन — दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम हों और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी पृथक् हो।

वर्तमान—भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझावों के अनुसार अध्यापक शिक्षा की निम्नलिखित व्यवस्था आरम्भ कर दी है। वर्ष १९५१-५२ की योजना में एक अलग तरह

- 1 "We recommend that the supply of Normal Schools, whether Government or aided be so localised as to provide for the local requirements of all primary schools whether Government or aided within the division under each Inspector" —*Indian Education Commission Report*
- 2 "We recommend that the first charges on provincial funds assigned for Primary Education be the cost of the direction and inspection and the provision of an adequate supply of Normal Schools" —*Indian Education Commission Report*
- 3 "It seems to us a matter of the greatest importance not merely that normal schools should be established at a few centres, but they should be widely distributed throughout the country" —*Indian Education Commission Report*



भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ  
(Under-graduates) के लिए २ वर्ष रखी गई और (४) प्रसिदाण-महाविद्या-  
लया के साथ अभ्यासात्मक विद्यालय सत्तम कर दिये गये ।  
शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, १९१३ (Government Resolu-  
tion on Educational Policy 1913)

१९१३ के सरकारी प्रस्ताव में अध्यापक प्रसिदाण के महत्त्व पर बल दिया  
गया और यह घोषित किया गया—  
शिक्षा की आधुनिक व्यवस्था में किसी भी शिक्षक को उस समय तक  
अध्यापन-कार्य में सौंपा जाय जब तक कि उसका पास तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र  
न हो ।<sup>१</sup>

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और अध्यापक शिक्षा  
बमरता विश्वविद्यालय आयोग (१९१७-१९) ने अध्यापक शिक्षा की ओर  
विशेष ध्यान दिया और इस सम्बन्ध में अधोनिम्नित सुझाव दिये—

- १ प्रसिदाित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जाय ।
- २ शिक्षा में छात्र-सम्बन्धी काम को प्रोत्साहन दिया जाय ।
- ३ प्रत्येक प्रसिदाण महाविद्यालय में एक प्रदर्शन विद्यालय (Demon-  
stration School) सत्तम हो जिसमें प्रायोगिक काम किया जा  
सके ।
- ४ पी० ए० एच इंटरमाडिएट कक्षाओं में पाठ्य-क्रम में शिक्षा के विषय  
को स्थान दिया जाय ।
- ५ कलकत्ता एवं बारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना  
की जाय ।

हार्डिंग समिति और अध्यापक शिक्षा

१९०९ की हार्डिंग समिति (Harding Committee) ने प्राथमिक विद्या-  
लयों के अध्यापकों के प्रसिदाण पर अवधि बल दिया और इस सम्बन्ध में  
निम्नलिखित सुझाव दिये—

- १ अध्यापकों के शिक्षा-पत्र को ऊँचा उठाया जाय ।

1 Under modern system of education no teacher should be  
allowed to teach without a certificate that he has qualified  
to do so —Government Resolution on Educational Policy,  
191 Para 51

२. प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया जाय।
३. प्रशिक्षण संस्थाओं में सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाय और उनकी सन्ध्या में वृद्धि का जाय।
४. समय-समय पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये अभिनव न पाठ्य-क्रम (Refresher Courses) की व्यवस्था की जाय।
५. सुयोग्य व्यक्तियों को अध्यापन-कार्य के प्रति आकर्षित करने के लिये अध्यापकों को सेवा-दण्डाभास में सुधार दिया जाय।

### अध्यापक शिक्षा पर विहंगम दृष्टिपात (१८८२-१९४७)

उपरोक्त प्रस्तावों अयोगों और समितिओं के सुझावों के कारण अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं में बर्धन वृद्धि हुई। १९२२ में समस्त देश में १०७२ नार्मल स्कूल थे जिनमें २७००० शिक्षादाता शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। उस वर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या १२ और शिक्षाध्यापकों की संख्या ११६ थी।

१९३७ में देश में ३४९ नार्मल स्कूल थे और उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राध्यापकों की संख्या १६७४२ थी। महिमाभा के लिये १९३१ नार्मल स्कूल थे जिनमें ७९०६ महिमाये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा थी। १९४९ तक भारत में उत्तमस्थ प्रशिक्षण-सुविधाओं का अनुमान नाथे की तानिका में सहायता में सचता है —

### अध्यापक प्रशिक्षण की प्रगति (१९२२-४९)

विवरण	१९३१-३२	१९३९-४०	१९४०-४१
प्रशिक्षण महाविद्यालय	१३	३	७३
छात्र	१३८५	१,७७६	७,२१८
पुनः नार्मल स्कूल	४२३	३४९	३४९
छात्र	२१,८२३	१६,७४२	२७,४१६
महिमा नार्मल स्कूल	१०६	१६९	११९
छात्र	१,६४२	७,९०६	८,८६९

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

प्रशिक्षण संस्थाएँ (Training Institutions)—१९४७ में भारत में निम्न लिखित तीन प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ कार्य कर रही थीं—

(१) सामान्य स्कूल (Normal Schools)—इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता था। इनमें मिटिस पास व्यक्ति प्रवेश पाते थे।

(२) सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल (Secondary Training Schools)—इनमें मिटिस स्कूलों के अध्यापकों को दीक्षित किया जाता था। इनमें मैट्रिकुलेशन पास विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे।

(३) ट्रेनिंग कॉलेज (Training Colleges)—इनमें हाई स्कूलों के विद्यार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें सबसे स्नातक और पर-स्नातक ही प्रवेश पाने के अधिकारी थे।

## स्वतंत्र भारत में प्रशिक्षण सुविधाएँ (Training Facilities in Independent India)

स्वतंत्र भारत में अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार करने के लिये सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। इस दिशा में १९४६ में विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग और १९४९ के 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' ने जो सुझाव दिये हैं, उनको भारत-सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यहाँ इन सुझावों का संक्षिप्त वर्णन बांझनीय जान पड़ता है।

१. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (University Education Commission)—अध्यापक शिक्षा में सम्बन्ध में आयोग ने अधानिहित सिफारिशें कीं—

१. प्रशिक्षण-माध्यमों में पाठ्यक्रम में गंभीर किया जाय। पुस्तकीय ज्ञान की अगुवाई विद्यालय में अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाय।
२. छात्रों के कार्य का सुसंगठित करने में उनके अध्यापन की गणना पर विशेष ध्यान रखा जाय।
३. अध्यापन में अध्यापक के लिये बख्त उपयुक्त विद्यालयों की ही चुना जाय।
४. प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापक अध्यापक के ही जो सुझाव दिये हैं, उनको अनुमति देकर चुने हों।

५. शिक्षा विद्यालय (Theory of Education) व पाठ्यक्रम सभ्य और स्थानीय भाग्यवरण व अनुक्रम है।
६. एम० एड० विद्यो व निचे उही व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाय जिन्हें कुछ वर्ष व शिक्षण का अनुभव है।
७. प्रोत्साहित छात्रा सचचारों द्वारा प्रोत्साहित कार्य अगम भारतीय स्तर पर किया जाय।

(२) माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission)—आयोग व अध्यापकों व प्रशिक्षण व विषय व सीधे निचे सुझाव दिये—

१. प्रशिक्षण विद्यालय केवल दो प्रकार व होंगे चाहिए —(क) प्रथम उत्तर नियम जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति है। इनका प्रशिक्षण-काल दो वर्ष का होना चाहिए (ग) नियाय उत्तर नियम जो स्नातक है। इनका प्रशिक्षण-काल दस समय एक वर्ष रहे परन्तु कुछ समय के परीक्षा का वर्ष कर दिया जाय।
२. छात्राध्यक्ष का एक या अधिक अतिरिक्त पाठ्य विद्याया व प्रशिक्षित किया जाय।
३. प्रशिक्षण विद्यालय व अभिनयन पाठ्य क्रमों (Refresher Courses) विषय विषय व मध्य गहन पाठ्य-क्रम (Short Intensive Courses) और कार्य-काल व व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training in Workshops) का व्यवस्था का जाय।
४. प्रशिक्षण विद्यालय व छात्राध्यक्ष व शिक्षा प्रसार का सुत्र व दिया जाय। एक छात्राध्यक्ष को राज्य का कार्य व उपाय निम्न दृष्टि (Stipends) दो जाय। जो शिक्षक शिक्षा सुत्र व कार्य कर रहे हों उक्त प्रशिक्षण-काल व निचे सुझाव पर लक्ष्य जाय।
५. एक अध्यापिका के अभाव का दृष्टि करने व निचे अध्यापिका प्रशिक्षण पाठ्य क्रमों की व्यवस्था का जाय।

स्वातंत्र्य भारत में अध्यापक-शिक्षा का विस्तार

(Expansion of Teacher Education in Independent India)

उत्तम सुझाव और भारत सरकार की दृष्टि व परामर्श व एक भारत में अध्यापक शिक्षा का व विस्तार दृष्टि है उक्त अध्यापक शिक्षा का व विस्तार व एक भारत में अध्यापक शिक्षा का व विस्तार है —

## अध्यापक-शिक्षा का विस्तार (१९४६-१९५८) १

राज्या का प्रकार	वर्ष	संस्थाओं की संख्या	पत्र एवं छात्राओं की संख्या	धन्य (रुपया में)
प्रशिक्षण	१९४६—५०	४८	४,७६१	३३ ५५,१५६
महाविद्यालय	१९५३—५४	६१	८ ८४८	४३ ५८ ४४२
	१९५८—५९	२३३	२४,४२८	१,१६ ३४,४४१
प्रशिक्षण	१९४६—५०	७२०	६७,०४६	१ ६०,६३,६७२
विद्यालय	१९५३—५४	८०८	७६ ६६३	१ ६८,३७ ७२१
	१९५८—५९	६७४	८६,३७६	२ ५५ ७८,३५०

## वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाएँ

(Present Training Institutions)

इस समय हमारे देश में अद्यतनित ६ प्रकार की अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाएँ कार्य कर रही हैं —

- १ पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र (Pre Primary Training Centres)
- २ नार्मल या प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय (Normal or Primary Training Schools)
- ३ उच्चमाध्यमिक के निचले माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय (Secondary Training Schools for Under-graduates)
- ४ स्नातकोत्तर के निचले प्रशिक्षण महाविद्यालय (Training Colleges for Graduates)
- ५ महिला प्रशिक्षण-संस्थाएँ (Training Institutions for Women Teachers)
- ६ विशेषज्ञ प्रशिक्षण-केन्द्र (Training Centres for Specialists)

# १ पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण-केन्द्र (Pre-Primary Training Centres)

हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभी अपना प्रारम्भिक अवस्था में है। कमजोर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना का प्रशिक्षण व्यवस्था भी अभी अभी है। १९५९ में भारत में २४ पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों के स्तर पर २१ स्वयंसेवक (Private) और ३ राजस्व के हैं। इनमें महिला और अन्य प्राथमिकी पाठ्य सामग्री को १ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण-केंद्रों का पाठ्य-क्रम विभिन्न है। ये केंद्र विभिन्न पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का आवश्यकताओं का पूर्ण करना है जिन — पूर्व प्राथमिक बिहरगार्टन (Kindergarten) एक मोन्टेसरी (Montessori)। इन पर भी पाठ्य-क्रम बहुत कुछ भिन्न है। उदाहरणार्थ—मनो प्रज्ञा का। मनो प्रज्ञा बिहरगार्टन में निर्धारित वस्तुओं का सिद्ध प्रयोगों के द्वारा सिद्ध है। —

१. मनोविज्ञान
२. भारतीय विज्ञान तथा भाषा
३. विज्ञान-प्रयोग
४. शिक्षण-तकनीक
५. मनो या चित्रकला या कवि कर्म और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धारणाएँ।

दूसरी प्रकार पूर्व बुनियादी (Pre Basic) पाठ्यक्रम में अधोस्तरिक विषय हैं —

१. सामुदायिक जीवन का अध्ययन
२. समाज प्रशिक्षण
३. भाषा अध्ययन
४. भाषा शिक्षण का इतिहास
५. पूर्व-बुनियादी शिक्षण का मूल विज्ञान तथा उद्देश्य
६. पूर्व-बुनियादी शिक्षा का पाठ्य विषय
७. कार्य-प्रणाली
८. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
९. शक्ति अध्ययन



- १० भाषा एवं साहित्य (वाणी प्रशिक्षण सहित)  
 ११ संगीत एवं ताल  
 १२ कला एवं चित्र ।

## २ नामल या प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय (Normal or Primary Training Schools)

भारत में दो प्रकार के प्राथमिक विद्यालय हैं (१) बुनियादी (Basic) एवं (२) गैर-बुनियादी (Non Basic) । अतः प्रशिक्षण विद्यालय भी दो प्रकार के हैं । १९५६-५७ में सारे देश में ५८१ बुनियादी एवं ३३५ गैर-बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय थे ।<sup>१</sup> दोनों प्रकार के विद्यालयों की पाठ-चर्चाओं की अवधि दो वर्ष की है ।

दोनों प्रकार के विद्यालयों में दो प्रकार के सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं—(१) जो अपर-ग्राइमरी पास छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं उनको 'जूनियर टीचर्स सर्टिफिकेट' (Junior Teachers' Certificate) प्रदान किया जाता है (२) जो छात्र मट्रिकुलेशन परीक्षा पास करके इन विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको सीनियर टीचर्स सर्टिफिकेट (Senior Teachers Certificate) मिलता है ।

विद्यालयों में बुनियादी एवं गैर बुनियादी प्रशिक्षण की व्यवस्था है और दोनों के पाठ्य-क्रमों में पर्याप्त अन्तर है ।

(१) बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों का पाठ्य-क्रम—यह पाठ्य-क्रम निम्न विधित्त प्रकार का है—

- अ—सिद्धान्त—इसमें ७ प्रश्न-वृत्त होते हैं यथा —
- १ बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त
  - २ प्राथमिक शिक्षा-मनोविज्ञान
  - ३ विद्यालय-व्यवस्था
  - ४ (क) पाठ्य विषयों की शिक्षण विधियाँ (ख) कला तथा शिक्षा की शिक्षण विधियाँ ।
  - ५ स्वास्थ्य विज्ञान मनोरंजन विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की विधियाँ ।

<sup>१</sup> *Education in the States (1956-57)* pp 3-5

<sup>२</sup> कलाप राय (१९६६-६७) का पाठ्य-क्रम ।

६ मानभाषा मूलित एवं सामान्य विज्ञान व शिक्षण का विषय।

७ गुरुमुखी लिपि म पञ्जाबी भाषा।

अ—प्रायोगिक शिक्षण—इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं

१ ३० मध्याह्न पाठ

२ प्रदर्शन गाम्भीर्य का उपयोग

३ दारिद्र्य शिक्षण।

ग—कला और लिखन के व्यावहारिक निपुणता —

(i) अनिवार्य विषय —

१ कृषि (कवल मनुष्या व मित्र) अथवा वित्तार्थ (कवल विद्या व मित्र)

२ कलाई और कुशल

३ उद्योग (Duties) तथा पद का काम।

(ii) ऐच्छिक विषय निम्नलिखित में से एक —

१ लकड़ा का काम

२ कृषि विज्ञान (इसमें गाड़ने बनाना सामग्री बनाना बार बनाना आदि विषय सम्मिलित हैं)।

३ सामाजिक कार्य तथा सामुहिक जीवन। —

१ दा मध्यम का मित्र

प्राथमिक शिक्षण।

(२) हर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों का वास्तविक काम — यह वास्तविक काम निम्नलिखित प्रकार का है : —

अ—शिक्षण इसमें १ प्रश्नोत्तर होता है—

१ प्राथमिक प्रश्नोत्तर का ( शिक्षण पञ्जाबी प्रश्नोत्तर )

२ प्राथमिक प्रश्नोत्तर का शिक्षण विषय।

३ सामान्य ज्ञान (अर्थ—इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान का शिक्षण विषय)

४ वास्तविक जीवन

५ शिक्षण-विज्ञान एवं शिक्षण-समस्याएँ

६ शिक्षण प्रश्नोत्तर का।

ब—कला (1929-30) का वास्तविक काम।

# भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

## ब—प्रायोगिक शिक्षण —

- १ माया त्रयोल कृषि एवं विज्ञान सम्बन्धा मौखिक तथा प्रायोगिक कार्य
- २ पढ़ाने का अभ्यास—३० पाठ
- ३ शिल्प—निम्नलिखित समूहों में से एक —  
 प्रथम समूह—सहरी का काम मिट्टी का काम जिल्दकारी बुनाई  
 मुर्गी पालन एवं चित्रकला ।  
 द्वितीय समूह—टोकरों बनाना चट्टाई बनाना ईंट बनाना साबुन बनाना स्पाही बनाना पट्टे का काम कपड़े की छपाई प्राथमिक चित्ररत्ना एवं बालकरी ।

३ माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय (Secondary Training Schools) इन विद्यालयों में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास छात्रों को प्रवेश दिया जाता है । पाठ्य-क्रम का अवधि बिना राज्य में १ वर्ष है और कियों में २ वर्ष । उत्तीर्ण छात्रों को वि विद्यालय या शिक्षा विभाग द्वारा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जाता है । इन प्रमाण पत्रों के नाम विभिन्न राज्यों में विभिन्न हैं । (जिस नामों की जानकारी से इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं ) इन विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यास मिहिल स्कूलों में अभ्यापन का कार्य करते हैं ।

कुछ राज्यों द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र

स्थान का नाम	प्रशिक्षण-अवधि	प्रमाण-पत्र का नाम
बम्बई	१ वर्ष	T D
बम्बई		S T C
बड़ोदा		T D
गुजरात		T D
कर्नाटक		T D
पुना		T D
नागपुर		T D
छापर	२ वर्ष	Dip T
बिहार		Dip T
मद्रास		CT
मद्रास	१ वर्ष	T S L
उड़ीसा	२ वर्ष	T C
उत्तर-प्रदेश		CT
बंगाल	१ वर्ष	J T C
		L T

विभिन्न राशियों और विभिन्न विषयविद्यालयों द्वारा माध्यमिक शिक्षण विद्यालयों के लिए निर्धारित विषय जाने वाले पाठ्य प्रयोगों में सम्मिलित है पर उनही रूप में प्रायः एक ही है। इन विद्यालयों के पाठ्य-क्रम साधारणतः निम्नलिखित होते हैं—

अ—सिद्धान्त—इसमें अधोनिहित ४ प्रश्न-सूत्र होते हैं—

- १ शिक्षा-मनोविज्ञान
- २ शिक्षा सिद्धान्त
- ३ विद्यालय-संगठन एवं स्वास्थ्य विज्ञान
- ४ शिक्षण विधि।

ब—अध्यापन-अभ्यास—प्रशिक्षण काम में।

#### ४ प्रशिक्षण-महाविद्यालय (Training Colleges)

इन महाविद्यालयों में बचपन से लेकर वयस्कता तक का प्रवेश या सम्बन्ध है। ये प्रशिक्षण-महाविद्यालय दो प्रकार की हैं—(१) बुनियादी (Basic) और (२) उच्च-बुनियादी (Non Basic)। १९३६ ई. में बुनियादी महाविद्यालयों की संख्या ३ और उच्च-बुनियादी महाविद्यालयों की १०० थी। इससे प्रमाण २ ४६६ और १२ ६४० छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। ये संख्या १९४७ ई. में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा कम हो गई है। कुछ राज्यों में अब उच्च प्रमाण में महाविद्यालय शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय—दोनों के द्वारा कराये जाते हैं।

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों की प्रशिक्षण प्रवृत्ति वर्ष १९३६ ई. और उसी वर्ष छात्रों की संख्या १०० ६४० १२ ६४० १२ ६४० १२ ६४० की संख्या प्रदान की जाती है।

(१) बुनियादी पाठ्यक्रम—ये पाठ्यक्रम विभिन्न राज्यों में बुनियादी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ये बुनियादी प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के निर्माण में पाठ्य-क्रम में अनुसंधान स्थानों पर जाने के लिए उच्च शिक्षा विभागों के स्थान पर का सुझाव दिया है।

ब—सिद्धान्त—इसमें निम्नलिखित २ प्रश्न सूत्र होते हैं—

- १ शिक्षा-संगठन एवं शिक्षा-समावेश
- २ शिक्षा-मनोविज्ञान

- ३ शिक्षा प्रशासन एवं निरीक्षण, या प्रायोगिक (Experimental) शिक्षा एवं शिक्षा अनुसंधान का विधि
- ४ शिक्षण की बुनियादी पद्धतियाँ
- ५ हस्त शिल्प की शिक्षा—सिद्धान्त एवं अभ्यास (Practice)

ब—मुख्य बुनियादी शिल्प—निम्नलिखित में से एक —

- १ कृषि एवं पशु पालन
- २ कपड़ा एवं बुनाई
- ३ पट्टे का काम लकड़ा का काम और इनसे सम्बन्धित धातु का काम ।

स—सहायक शिल्प—निम्नलिखित में से एक या अधिक :—

- १ गृह निर्माण
- २ कपड़ा, यदि यह मुख्य शिल्प के रूप में न लिया गया हो
- ३ सज्जी की कामकारी यदि मुख्य शिल्प के रूप में कृषि न लिया गया हो
- ४ जमड़े का काम
- ५ मसू-मसरी पालन
- ६ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ।

द—प्रयोगात्मक कार्य (Practical Work)—छात्राध्ययनों के लिए निम्नलिखित कार्य अनिवार्य बनाए गए हैं —

- १ कार्य-सोचनाओं का निर्माण ।
- २ चुने हुए विषयों में किसी कक्षा के नियत क्षमता परीक्षण (Attainment Tests) का निर्माण ।
- ३ वैयक्तिक (Individual) और सामूहिक परीक्षण (Group-Tests) का परिचालन ।
- ४ पढ़ाव जाने वाले पाठों के लिखा-मापनों का निर्माण ।
- ५ बुनियादी विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ और उच्च माध्यमिक का निर्माण ।

(२) छह बुनियादी पाठ्य-क्रम—छह बुनियादी पाठ्य-क्रम अद्यतन का भाग में समाविष्ट है—

ख—विद्यालय—इसमें १ प्रश्न-पत्र ही है—

- १ शिक्षा विज्ञान
- २ शिक्षा-मनोविज्ञान तथा मानसिकी
- ३ विद्यार्थी-संगठन एवं स्वास्थ्य विज्ञान
- ४ अध्यापन विधि
- ५ शिक्षा का इतिहास एवं शिक्षा की समस्याएँ।

ग—अध्यापन-अभ्यास—छात्राभ्यासों की निर्धारित संख्या में पाठ पढ़ाते होते हैं।

५ शिक्षिका प्रशिक्षण-संस्थाएँ (Training Institutions for Women Teachers)

महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के निम्ने पृथक् विद्यालयों का निर्माण किया गया है। इनका विवरण नीचे की तालिका में गण्य हो जाता है।

शिक्षिका प्रशिक्षण-संस्थाएँ (१९४६-४७)¹

संस्था	संस्थाओं की संख्या	छात्राभ्यापिका-संख्या
बुनियादी कौशल	१	४०७
ए-ए-बुनियादी कौशल	१०	८१२४
बुनियादी स्कूल	१४६	१११९४
ए-ए-बुनियादी स्कूल	१४२	१०१२०

६ विशेषज्ञ प्रशिक्षण केंद्र (Training Centres for Specialists)

इन प्रशिक्षण केंद्रों का अध्यापन विज्ञान में विशेषज्ञ शिक्षा का लक्ष्य है —

(१) शारीरिक शिक्षा (Physical Education)—शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण का लक्ष्य दो प्रकार का है — (१) स्वस्थों के निम्ने और (२) असुखियों के निम्ने। दोनों में प्रशिक्षण अर्थात् १ वर्ष का है। उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में शिक्षक इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। १९४६-४७ में संयुक्त

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

देश में धारीरिक शिक्षा के १५ कॉलेज और ३८ स्कूल थे जिनमें प्रनरा ७८५ एवं ७३ ६३६ पुष्प व स्त्रियाँ प्रविष्टित किये जा रहे थे। अभी तक हमारे देश के किसी भी विश्वविद्यालय ने धारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की है।

केन्द्रीय सरकार के सरकारण में ३० जून, १९५७ को ग्वालियर में सस्मी बोर्ड धारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का गिमाव्याप्त किया गया। इसमें प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष की है और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को डिग्री दी जाती है।

(२) सजित कलाओं की शिक्षा (Aesthetic Education)—अभी तक हमारे देश में सजित कलाओं का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की संख्या अति घुन है। इनमें से प्रमुग संस्थाओं का उन्नत नीचे की पत्तियाँ में किया जा रहा है —

- १ विश्व भारती दानिनिरेन—संगीत, गुरु एवं चित्रकला।
- २ सर जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई—चित्राकृत (Drawing)।
- ३ बहोदा विश्वविद्यालय—मगीत एवं चित्रकला।
- ४ कला राज अहमदा (मद्रास)—नृत्य।
- ५ टीपर्स कलेज ऑफ म्यूजिक मद्रास—संगीत।
- ६ सर्व मेन्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स सनऊ—रसा।
- ७ दमगपूत ऑफ आर्ट्स ऐडुकेशन ग्रामिया मित्रिया स्वामिया दिल्ली— कला एवं हस्तकला।

(३) गृह विज्ञान (Home Science)—गृह विज्ञान की लोचप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। माध्यमिक विद्यालयों में अन्तर्गत छात्राएँ इस विषय का पढन करने लगा है। अतः इन विद्यालयों के विषे अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण की व्यवस्था बई स्थाओं पर कर दी गई है जिनमें से प्रमुत अधोलिखित है—

- १ महा इरविन कॉलेज हिन्दी
- २ बहोदा विश्वविद्यालय
- ३ एम० एन० डी० टी० बीमेग युन०विद्या बम्बई
- ४ डामेटिक माह म दूनिग कलेज हैदराबाद
- ५ गजनदल कलेज ऑफ हाउ माह म गरि बीमन इमाहाबाद।

# समस्याएँ और उनके समाधान

(Problems and Their Solution)

## विषय-प्रवेश

डा० एम० एन० मुखर्जी का कथन है स्नातकोत्तरस्तर में शिक्षक प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है तथापि कमजोर स्थिति अभी पूरान गम्योन्नत प्रद नहीं है। शिक्षा की प्रगति का माप माप अध्यापन का नव पैमाना प्रदान करने हो गया है। १. क्या कहा है? इसका उत्तर व. जी० मदनन का इन शब्दों में दिया जा सकता है — अन्य महात्माव समाजों की तरह ही शिक्षण की प्रगति का माप शिक्षा के मानव शक्ति के प्रपनी सामर्थ्य तथा शक्ति के विविध रूपों का माप दिया है शिक्षा समाज का नव प्रौ जीवन भर लगायी करने की उत्तरदायी है। शिक्षण में अध्यापक माना काम शुरू कर गये दिन से अधिक शिक्षण में तब बड़े अध्यापक का कार्य करता रह रहा प्रशिक्षण का प्रथम योग नहीं होता बल्कि माया अध्यापक का शिक्षण व्यावहारिक माया का प्रयोग करने के लिए उगे इसके लिए तैयार करने में कमिश्नर तथा विद्याविद्यालय भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है। इसका काम प्रशिक्षण कमिश्नरों का उम्र का बेवक प्रशिक्षण माध्यम प्रदान करने पड़ते हैं बकि उम्र एवं उचित शिक्षण तथा उचित दृष्टिकोण भी प्रदान करना पड़ता है। २. गुरु का विषय है कि कमिश्नर विद्याविद्यालय और प्रशिक्षण का ध्यान रखनी जिम्मेवारी का पूरा नहीं कर रहा है। इसीलिए

1. "The present position in relation to teacher education is by no means satisfactory in spite of its rapid progress during recent years. Numerous problems have arisen with this development. — S. N. Mukherji, *Education in India Today and Tomorrow*, pp. 259 & 290

2. "Like the other great Arts through which mankind has built up its cultural and intellectual heritage the Art of Education also requires a lifelong preparation. And this process should be continuous, extending from the first day of work to the end of the teaching career. The colleges and the universities have a part to play in it before the prospective teachers enter the professional world. The training colleges have then to provide not only technical equipment but a proper cultural and intellectual when the teacher enters from there" — A. G. Shukla, *Education of Teachers*, p. 37



कात्र शिक्षण प्रशिक्षण में बहुरंगी समस्याएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। अगली पंक्ति में इन्हीं का अध्ययन करना हमारा ध्येय है —

## १ समस्या—प्रशिक्षण एवं स्कूल कार्य की सम्बन्ध विहीनता (Training not related to School Work)

अध्यापक प्रशिक्षण को एक प्रमुख समस्या यह है कि प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा अध्यापकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका स्कूल में काम करने की वास्तविक परिस्थितियाँ से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अध्यापक अपने दशालिक सिद्धान्तों को व्यवहार में कार्यान्वित करना असम्भव पाते हैं। ब० जी० मयदान का कहना है — उनका सिद्धान्तों का ज्ञान और स्कूल की कक्षा में उनका व्यवहार एक दूसरे की समृद्ध बनाने और एक दूसरे में घुलमिल जाने के बजाय दो विलुप्त अलग अलग चीजें बने रहते हैं।<sup>1</sup> विद्यालय में अध्यापक कार्य प्रारम्भ करने के कुछ ही समय बाद वे शिक्षण की परम्परागत तथा प्रणालीहीन विधियाँ को अपना लेते हैं और उनका विद्यालय सिद्धान्तों का समस्त ज्ञान जो अध्यापक परिश्रम से उन्हें प्रदान किया गया था और जिसे अध्यापक परिश्रम में उन्होंने प्राप्त किया था विलुप्त ध्वंश हो जाता है।

## समाधान—सिद्धान्त एवं व्यवहार में संयोग (No Divorce between Theory and Practice)

प्रशिक्षण में सम्बन्ध में जो कुछ ऊपर कहा गया है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ब० जी० मयदान ने उचित ही लिखा है — सिद्धान्तों का व्यवहार के साथ कोई सम्बन्ध न होना प्रशिक्षण कॉलेजों की पढ़ाई का सबसे बड़ा दोष है और जब तक उसे दूर नहीं किया जायगा तब तक इस पढ़ाई के फलप्रसू होने में शंका ही रहेगी।<sup>2</sup> अब प्रश्न यह उपरिपक्ष होता है कि सिद्धान्त एवं व्यवहार में सम्बन्ध क्यों नहीं है और हमने किस प्रकार स्थापित किया जाय ? कारण खोजना कठिन नहीं है। ऐसे ट्रेनिंग कॉलेज बहुत ही कम हैं जिनमें उचित प्रकार का 'प्रदर्शन विद्यालय' (Demonstration Schools) सम्बद्ध है। फलतः अध्यापक अपने विद्यालयों के हित के लिये

1 "Their knowledge of theory and their school room practice remain confined in two water tight compartments, instead of mutually enriching and interpreting each other"  
—K. G. Salyadein op. cit. p. 312

2 "The divorce of theory from practice is one of the most serious defects of training college education and unless it is removed its effectiveness will continue to be very questionable indeed"  
—ibid. p. 313

गिरा सिद्धान्त और विधिया का निर्धारित नहीं कर पाने हैं। उनको इस बात का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है कि वे अपने सिद्धान्त और प्रणालियों को व्यवहार में परख सकें और समझ सकें। उनका गिरा ॥ जीवन तथा वास्तविकता के उग पुन का अभाव होता है जो कबल मजस व्यवहारिक अनुभव में ही प्राप्त हो सकता है। परिणाम यह होता है कि उनका विचार अपष्ट रहता है और वे अपने को पढ़ाई की निर्दोश शिष्टियों का का म उनकी कल्पना करने में असमर्थ रहते हैं। इसके भी बुरी बात यह है कि प्रायः उनका प्रोग्राम में भी बीजा की स्पष्ट रूप में देवान की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनमें यह गुण तभी उत्पन्न हो सकता है, जब उन्हें अपने सिद्धान्तों को व्यवहार की वर्गीकृत पर परखने का अवसर प्राप्त हो और वे यह मान्य कर सकें कि इन सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है या नहीं।

महामा का समाधान बताने हुए व० जी० मन्दन ने लिखा है : 'व्यवहार तथा सिद्धान्त—दोनों ही की कल्पना विद्यामयान तथा की का म की जानी चाहिए—सिद्धान्त व्यवहार का पथ आलोचन करने और व्यवहार सिद्धान्तों में निहित गुणों का।'<sup>१</sup> का यह प्रतिपादन है कि प्रत्येक टिप्पणी के अर्थों में समस्त व्यवहार साधना से युक्त एक प्रदर्शन रूप' हो जो प्रायोगिक (Experimental) पद्धति का अनुसार समझा जाय और जिसमें व्यावहारिकता का बड़ा ही विविधता और सिद्धान्तों का अनुसार काम किया जाय। यदि व्यावहारिक इन विधियों को व्यवहार में परख सकें और यदि वे इन सिद्धान्तों का अनुसार प्रदर्शन रूप' को समझ सकें तो यह बात सम्भव हो सकती है कि वे विद्या विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने समय सिद्धान्त और व्यवहार का अपने ज्ञान की बीज समस्त विद्या प्रविष्टिमा स्थापित करने में सफल हों।

## २ समस्या—सिद्धान्त पर अनुचित बल (Lodge Emphasis on Theory)

विश्व शिक्षण की एक समस्या यह है कि प्रविष्टि-काल में व्यवहार (Practice) की ओर सिद्धान्त (Theory) पर अधिक बल दिया जाता है। अध्यापकों को अनेकों विषयों का और कुछ में बहुत अध्यापन करना पड़ता है। इनकी अनेक बंधु आभाषना की गई है। बताया यह है कि विद्या विद्या के

1 "Practice and theory must both be visualized as growing entities—theory illuminating practice practice continually modifying theory"—H. G. Sanyal in op cit p 314

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

अध्ययन में वे दिन रात जुटे रहते हैं। उनमें से अधिकांश शास्त्रविक शिक्षण कार्य में उनका लिये किंचित् मान भी सामान्य सिद्ध नहीं होते हैं। वे उनका अध्ययन बस डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के लिये करते हैं। वे तथा उनके प्रोफेसर इस बात को जानते हैं। इसके विपरीत उनको व्यवहार के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। अपने प्रशिक्षण-काल में वे लगभग ५० पाठ पढ़ाते हैं। जमा कि गर्वविहित है। प्रायः प्रत्येक अध्यापक को विद्यालय में प्रतिदिन ७ या ८ पाठ पढ़ाने पड़ते हैं। इस हिमाक से उनके ५० पाठ एक सप्ताह के लिये हुए। दूसरे छात्रों में हम यह सकते हैं कि उनको अपने प्रशिक्षण-काल में क्या पढ़ाने के लिये केवल एक सप्ताह का समय मिलता है जब कि सैद्धान्तिक प्रतीति होनी है किनी विद्यमान पूर्ण। निरपेक्ष विषयों के लिए समय और शक्ति का इतना क्षय और सामग्रद क्या शिक्षण-कार्य के लिए इतनी विरक्ति। समाधान सिद्धान्त-सम्बन्धी पाठ्य-क्रम में सभी (Curriculum of Theoretical Courses)

उपरोक्त समस्या का समाधान उगी दशा में हो सकता है जब सिद्धान्त सम्बन्धी पाठ्य-क्रम का कम कर लिया जाए। छात्राध्यापक का बस १ ही विषय पढ़ाया जाय जो उनके अध्ययन जीवन में बरतुन सामग्रद हो और जिनका उपयोग वे जीवन भर करते रहें। इस बात में तो कोई दुश्मिनी नहीं जान सकती है कि वे अपनी परीक्षा को समाप्त करने के बाद अपनी प्रशिक्षण-मुक्तता और ज्ञान और ज्ञान को अवविदा दे दें। पाठ्य-क्रम को कम करने से पढ़ाई में एक स्वयं कम हो जायेगी। इस सबे हुए समय को शिक्षण-कार्य में व्यय किया जाय। वास्तविक तो यह रहना कि वे सम्पूर्ण प्रशिक्षण-काल में कम समय में या १ घण्टा में शिक्षण कार्य करें जिनमें वे अपने अवकाश के लिए पूर्ण रूप से दक्ष हो जायें।

३. समाधान—मानवीय पहलु की उपेक्षा (Neglect of Human Aspect)

सामान्य शिक्षण की एक अति गम्भीर तथा स्थायी समस्या यह है कि शिक्षण-काल में मानवीय पहलु का उपेक्षा की जाती है और प्राविधिक (Technical) पहलु पर ध्यान केंद्रित रखा जाता है। शिक्षण के दौरान में मानवीय की विषय और सामग्री पर कम धन देना। प्रकृति इतना अधिक (Aims Purposes and Values) में सम्बन्धित समस्याओं का सुमधन में रहना मानवीय पहलु की उपेक्षा करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं।

मेठा है। व कृषी का सी देखने है पर उस बन की नहीं देस पावे है जहाँ के उगे हू है। बि हम बन की बगना नहीं कर पावे है बि बिधा पर बिधि सामाजिक एवं मर्यादित जीवन-व्यवस्था की नीमात्रा के अन्तर एक सामाजिक तथा मर्यादित विधा है। अतः शिक्षा व कारण जगती ऐसी छोटे व बाल और प्राविधिक आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण समाज के साथ स्कूल का सम्बन्ध और उसकी ओरी-आगमी समस्याओं और भगत हटि से ओघन हो गये है।<sup>1</sup>

### समाधान—प्रशिक्षण केन्द्रों में मानव-केन्द्रों में सजीवन (Revision in the Values of Training Centres)

प्रशिक्षण-काम में मानवीय पहलु की उल्लेख तो की जाती है पर शक्ति-संग्रहों करने का हम आरोप का माली नहीं समझती है। उनका कथन है कि उन्हें प्रशिक्षण व सिखे जगता कम समझ लिया जाता है कि वे मानवीय-पहलु व मर्यादित जीवन देने व बिना भी मान को समझने जगता है। हमीन तो सुन्दर है पर है किन्ती निराधार। पर यदि हम हम कहने का स्वरूप कर प्रशिक्षण विद्यार्थी में मानवीय विधि को बनाये जगता है तो वह हम बात का उद्देश्य उपादय होना कि हमें समझ मानवीय में विद्यमान वगैरे है और उनमें सुधार करने का प्रयास नहीं करने है। हमका कथन एक ही उपाय है और वह यह है कि प्रशिक्षण-केंद्रों में मानवीय म आरम्भ हो सम्बन्ध बना प्रारम्भ कर दे। अतः विचार की पूर्ण में हम के० जी० ए० के अन्तिम जगता की उद्देश्य कर सकते हैं — प्रशिक्षण व प्रशिक्षण विधि मानवीय म परिधान कर और दुर्ग म रहने वान समुच्च की उक्त दुर्गमार्ग विधि में बने ओ जाने वारा और व मन्त्राविराम हरे व वकन हमें मने नहीं देव मरणा का काल उतरी हटि उक्त कर्मदूत व वार दावा मने नीमि की।

1. They have failed to visualize education as a social and cultural activity carried on within a pattern of a characteristically social and cultural life. The relation of the school to society and its living problems and issues have been obscured by the concentration on short-sighted technical details and technical results. — K. G. Sanyal, op. cit., p. 318.

भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें

प्राथमिक कार्य की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पश्चात् महत्व नहीं दिया जाता है और इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।”

४ समस्या—स्वतन्त्रता रहित वातावरण (Unfree Environment)

प्रतिशालनास में छात्राध्यापक जिस वातावरण में कार्य करते हैं वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता रहित है। प्रतिशालना-संस्थाओं में नवीन शिक्षा (New Education) और उसकी बहुचर्चीत संरचना में सन्निहित अनेक विचारों और आलोचना की बहुत गरम चर्चा है यथा—स्वतन्त्रता पहलकदमी (Initiative), नेतृत्व सामुदायिक जीवन सामाजिक प्रेरणा इत्यादि। छात्राध्यापक से आशा की जाती है कि वे इन विचारों के सार को बिना प्रक्रिया द्वारा पुस्तकों से ग्रहण कर लें और फिर उनको अपने स्तूनों में वास्तविकता का रूप प्रदान करें। आश्चर्य इस बात का है कि टनिंग कॉलेज ऐसी बात की आशा क्या करते हैं जब कि वे अपने छात्राध्यापक को उन विचारों को करने सीतान का सी बरक सीताने (Learning by Doing) के अपने प्रिय सिद्धान्त को कार्य रूप में पालन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। ५० जी० मर्देन का शब्दों में, स्वतन्त्रता या आत्म प्रिया या सहचारी कार्य उसी (कमी भी महत्वपूर्ण) तथा गारमिष्ठ परिवर्तना का पूरे महत्व को उस समय तक मही समझा जा सकता है जब तक कि इन परिवर्तनाओं में निम्नलिखित परिस्थितियाँ न पायी जा सकें।

वास्तविक अनुभव न प्राप्त किया जाय।

समाधान—स्वतन्त्र वातावरण (Free Environment)

उपरोक्त समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि टनिंग महाशयों को बड़े निम्नों का अध्ययन से और छात्राध्यापक का उनका जीवन एवं उनकी निम्नलिखित पर रण जाने जान नियन्त्रण से मुक्त किया जाय। साथ ही टनिंग

- 1 It is essential for the training colleges to revise their values and avoid the misfortune of the man in the cave who could see nothing of the fascinating vista around because his vision was bounded by the four walls of his prison. There is an inadequate appreciation of the social and cultural background of educational work which must be set right.”—A. G. Sanyal in op cit p 319
- 2 “It is impossible to realize the full significance of any important and pre-nant conception like freedom or self-activity or cooperative work without an actual experience of working under conditions which they postulate.”—A. G. Sanyal in op cit., pp 320-321



## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

(१) प्रायः राज्य व ट्रैनिंग कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायता से अधिक से अधिक पाँच वर्ष में एक बार अपने राज्य का सर्वेक्षण करके यह मासूम करने का राज्य में स्थित समस्त स्कूलों की कितनी शिक्षणों एवं शिक्षिकाओं की आवश्यकता होगी और इसी सम्भावित माँग व आपात पर ध्यान को भरना करने की योजना बनाई जाय।

(२) पुराने तथा अनुभवी अध्यापकों के लिए जो किसी कारणवश ट्रैनिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं अल्पकालीन पाठ्य-क्रमों (Short Term Courses) की व्यवस्था की जाय। प्रशिक्षण प्राप्त करने से अध्यापक अपनी व्यावसायिक कार्य कुशलता में वृद्धि करेंगे अतः पद की उन्नति करेंगे और उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी।

(३) उपरोक्त दृष्टि से पुराने एवं अनुभवा अध्यापकों की प्रशिक्षण-व्यवस्था व उपरान्त कबल उन व्यक्तियों व प्रशिक्षण का प्रश्न रह जाता है जो किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त करने व परवाना ट्रैनिंग कॉलेज में प्रवेश करना चाहते हैं। इनमें से उहाँ व्यक्तियों का चुनाव दिया जाय, जो होनहार तथा योग्य अध्यापक बन सकें।

(४) नये छात्रों को चुनने के जो मोटे मोटे बने बनाय तरीक इर्तमाल निये जाते हैं उनकी भवेदा कई अधिक कारणों एवं पर्याप्त उपाय सोचा जाय। य उपाय ऐसे हों जिनसे अध्यापक बनने की इच्छा रखने वालों व मानसिक एवं नैतिक गुणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(५) अध्यापन-कार्य करने व इच्छुक व्यक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने समय अपने भावी व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें ताकि ऐसा न हो कि वे नाना प्रकार का घुटकर ज्ञान अजिग करके ट्रैनिंग कॉलेज में प्रवेश करें ऐसे ज्ञान का अर्थ न सिर्फ़ उनका भावी व्यवसाय छेदाई गवस्य न हो।

(६) किसी की परीक्षा के लिए शिक्षण पाठ्य को एक वर्षाधिक विषय बना दिया जाय जैसा कि कुछ विश्वविद्यालयों में है।

६ समस्या—कृत्रिमिकी एवं छ १-कृत्रिमिकी पाठ्य-क्रमों की विनिश्चयता (Difference between the Basic and Non-Basic Courses)

इस समय हमारे देश में दो प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालय कार्य कर रहे हैं—कृत्रिमिकी और निर-कृत्रिमिकी। दोनों के पाठ्य-क्रम विभिन्न हैं। इस प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण में ही बाराए भिन्न भिन्न शिक्षाओं में प्रशिक्षण पा रहा है। इस प्रकार पद्धति में कृत्रिमिकी (Activity Method) सामुदायिक जीवन

(Community Life) और सम्बन्ध (Practical) पर बल दिया जाता है। इसका मन्त्रा नर वाद-प्रथम निर्बल है। इसका विवरण और बुनियाद। पद्धति में सम्बन्धित ज्ञान और निम्न विषयों पर बल दिया जाता है। पर इसमें सम्बन्धित वा स्थापन योग्य है। इस प्रकार स्थापना पद्धति में सम्बन्धित विषयों पर बल दिया जाता है।

समाधान—यनियादो एवं एर यनियादो पाश्वर्कमों का एकीकरण  
(Integration of Basic and Non Basic Courses)

भाव-परमा इग जान बा है कि इतिहासी और गुरु-दानव । पद्धति का इग प्रकार सम्मिलन किया जाय कि उनके साथ दूर ही जाय और एक पत्रान मया सन्निवृत्ता पद्धति का निर्माण हो जाय । इसमें विद्या प्रशिक्षण का महत्त्व हीन हुआ । इसी बात का ध्यान में रखकर मुनाय अगिल भारतीय शिक्षण महाविद्यालय सम्मेलन (All India Conference of Training Colleges) ने शानि पद्धति का लक्ष्य-रूप का नियम निर्धारित किया —

१. सामान्य प्रशिक्षण-वादी-ग्राम के मजदूरों को काम सिखा जाय और दुगम का लक्ष्य सुधार दिना जाय ।
२. प्रयोग कार्य (Practical Work) का अधिष्ठान मजदूरों को काम और उसमें इस प्रकार संलग्न कर दिना जाय कि वे सामुदायिक जीवन में भाग ले सकें और समन्वित शिक्षा (Correlated Teaching) का परिणाम दे ।

उपसंहार

[illegible]



## UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Trace briefly the history of Teacher Education during the British period
- 2 What provision has been made for the training of teachers in new India ?
- 3 Give a brief account of the various types of Teacher Education Institutions in India at present
- 4 The present position in relation to Teacher Education is by no means satisfactory in spite of its rapid progress during recent years Discuss
- 5 What, in your opinion are the problems in the training of teachers in India ? What measures can you suggest to solve them ?

## अपव्यय एवं अवरोधन (Wastage and Stagnation)

### विषय प्रवेश

भारत में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्याएँ सिंग के ट्रॉक स्तर पर अपनी अग्रगण्य स्थिति में हैं। कि वर्तमान और निरन्तर प्रविष्टि में इन समस्याओं का पूर्ण स्तर अस्वाभाविक स्वीकार किया गया है। भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सत्रित पथ उठा रही है। प्राथमिक शिक्षा का पुनर्गठन कर रही है और विरहित-विद्यार्थी शिक्षा के वास्तविक में प्रविष्टि-नीति परिवर्तन कर रही है परन्तु फिर भी इन समस्याओं का स्थिर प्रवृत्ति के कारण सरकार शिक्षा के विकास की स्तर को रुक बनाने में अविनियमित सफलता प्राप्त करने में निराशा का आतिथ्य कर रही है। इन समस्याओं का हल क्या है और इनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है—इस प्रश्न का प्रमुख विषय-वस्तु है।

### अपव्यय का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Wastage)

सिंग के ट्रॉक स्तर पर वास्तविक की एक निरन्तर अवस्था है। उदाहरणार्थ- प्राथमिक शिक्षा की अवस्था ४५३ वर्ष प्राथमिक शिक्षा का ९ वर्ष

## भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ

(हाई स्कूल परीक्षा पास करने के लिये) और विश्वविद्यालय शिक्षा की २ वर्ष (जहाँ शिक्षा कोर्स २ वर्ष का है)। जो छात्र बिगो स्तर पर शिक्षा प्राप्त करता है उसमें यह आगा भी जाती है कि वह निश्चित अवधि में अपनी शिक्षा समाप्त कर लेगा। परन्तु व्यावहारिक रूप में हमें ऐसे अनेकों छात्र मिलते हैं जो अति उम्रमाह से शिक्षालयाँ में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार के व परधान शिक्षा मन्त्रालय से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं। इस प्रकार के छात्र अपने पाठ्य-क्रम को समाप्त नहीं करते हैं। अतः इन छात्रों पर समय और शक्ति का अपव्यय होता है। इस प्रकार के अपव्यय (Wastage) से हमारा धर्मिण्य है उन विद्यार्थियों पर व्यवस्था किया हुआ समय धन और शक्ति का बिगो न बिगो कारणवश प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने से पूर्व ही अपना अपव्ययन स्थगित कर देते हैं।

अपव्यय का जो अर्थ हमें ऊपर की पक्षिता में स्पष्ट किया है उससे आपार पर हम अपव्यय की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं :— शिक्षा में अपव्यय छात्र का लक्ष्यार्थ व्यय है—उन छात्रों पर समय धन और शक्ति का अपव्यय जो अपने पाठ्य-क्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करते हैं।

### अवरोधन वा अथ एवं परिभाषा

(Meaning & Definition of Stagnation)

जहाँ कि हम ऊपर सिद्ध करते हैं शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्य-क्रम की एक निश्चित अवधि होनी है। उस स्तर पर अपव्यय करने वाले छात्रों में यह आगा भी जाती है कि वह उस अवधि में अपना पाठ्य-क्रम समाप्त करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे। परन्तु यहाँ सामान्य अनुभव की बात है कि अनेक छात्र एक या एक से अधिक परीक्षा में दो या इसमें भी अधिकांश व्यर्थ व्यर्थ रहते हैं। दूसरे स्तरों में हम कह सकते हैं कि वे प्रवेश करता है प्रतिवर्ष उत्तीर्ण नहीं होते हैं। इस प्रकार के छात्रों में स्थिर (Stagnation) की संज्ञा दी गई है। शिक्षा का निश्चय अपव्यय अवरोधन (Stagnation) की संज्ञा दी गई है। जो हम कह सकते हैं कि अवरोधन वह प्रकार का धर्मिण्य है—एक छात्र वा एक छात्रा में एक न अधिक वर्षों तक जाना।

1. "The most popular use of the word wastage in education means the waste of time and money after those students who do not successfully complete the course of study have taken by them"—John & Pathak

अवरोधन के अर्थ का जो स्पष्टीकरण हम कर चुके हैं उसने आचार पर हम अपराधन का परिभाषा अप्रतिगित शब्दों में कर गये हैं — निम्न में अवरोधन शब्द का सवमाध्य अर्थ है—एक छात्र का उत्तरी छात्रोत्पन्न प्रगति के कारण एक कक्षा में एक से अधिक बच्चे रोना जाना ।<sup>1</sup> Hartog Committee ने अवरोधन' का अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्न है — अवरोधन से हमारा अभिप्राय है एक बच्चे का एक निम्न कक्षा में एक बच्चे से अधिक रोना जाना ।<sup>2</sup>

### अपव्यय एवं अवरोधन—क्षय व दो पहलू (Wastage & Stagnation Two Aspects of Waste)

अपव्यय एवं अवरोधन दो शब्दों को एक साथ कहा जा सकता है । जो छात्र अपना पाठ्य-क्रम पूर्ण करने में पूर्व मरस्यती की का अपराधन में मुक्त माह तक है उन पर समय धन और शक्ति का खर्च कर में प्रभाव होता है । पर जो छात्र एक निश्चित अवधि में अपना पाठ्य-क्रम पूर्ण करके परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं उन पर भी किसी अंग तक समय धन और शक्ति का अपव्यय होता है । अन्तर बचन इतना है कि यह अपव्यय प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है । अतः यह कहा जा सकता है कि अपव्यय में अपव्यय का निहित रहता है ।

बालविरता यह है एक निम्न कक्षा में उच्च कक्षा में छात्रों को मध्य अपवा मुक्तता हाता कक्षा जाती है । इन मुक्तता अपवा हाता के दो शक्ति-शाली कारण हैं—अपव्यय और अवरोधन । इन दोनों कारणों और इन दो शक्ति-शाली कारणों अधिक शक्तिशाली है इन सब में Hartog Committee का विचार उल्लेखनीय है — छात्र-संख्या में यह हाता मुख्य दो कारणों के समन्वय होता है जिसे हम अपव्यय तथा अवरोधन की कक्षा में । उदाहरण के लिए यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक कक्षा में दूसरी कक्षा में छात्र-संख्या में होने वाला यह अन्तिम हाता किन्ना अपव्यय के कारण

1 The most popular use of the word stagnation in education refers to the retention of a student in a class for more than a year on account of his unsatisfactory progress.  
—John & Pathak

2 "By stagnation we mean the retention in a lower class of a child for a period of more than a year."  
—Report of the H. C. Committee

होता है और कितना 'अवरोधन' के कारण। पर हमारे अवेपणों से व्यक्त होता है कि अपव्यय की अपेक्षा 'अवरोधन' कम घातिगासी कारण है।<sup>१</sup>

प्राथमिक शिक्षा में 'अपव्यय' तथा 'अवरोधन'

प्राथमिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन के प्रति सबसे पहिले १९२६ में Hartog Committee का ध्यान आकर्षित हुआ। 'अपव्यय' के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 'हर्टोग समिति' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा—“अपव्यय में हमारा अभिप्राय है—प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बच्चा को विद्यालय की किमी भी बसा से हटा लेना।”<sup>२</sup> समिति ने इसको अपव्यय इसलिए कहा क्योंकि जो शिक्षा इस प्रकार के छात्र प्राप्त करते हैं वह उनको स्थायी रूप से साक्षर बनाने में असफल होती है। इसकी पुष्टि में हम हर्टोग समिति के इन शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं— जब तक प्राथमिक शिक्षा कम से कम साक्षरता में प्रदान कर दे वह व्यर्थ है। सामान्यतः कोई भी बच्चा जिसने कम से कम ४ वर्ष का प्राथमिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम पूर्ण नहीं किया है स्थायी रूप से साक्षरता प्राप्त नहीं कर सकता है।<sup>३</sup>

'अवरोधन' के अर्थ को समिति ने अवसिद्धित शिक्षा में व्यक्त किया— अवरोधन से हमारा अभिप्राय है—एक बच्चे का एक निम्न कक्षा में एक वर्ष में अधिक रोक जाना।<sup>४</sup>

प्राथमिक शिक्षा में कितना अपव्यय और अवरोधन है इसका अनुमान अधोलिखित तालिकाओं से सहज ही लगाया जा सकता है —

- 1 The diminution is mainly due to two causes, which we shall term 'wastage and stagnation'. The figures taken by themselves do not indicate how far the excessive diminution in numbers from class to class is due to 'wastage' and how far is due to 'stagnation' but our enquiries show that by far the more important factor is 'wastage'—*Report of the Hartog Committee* p 47
- 2 By 'wastage' we mean the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of the primary course.—*Ibid* p 47
- 3 "Primary education is ineffective unless it at least produces literacy. On the average no child who has not completed primary course of at least four years will become permanently literate"—*Ibid* p 48
- 4 "By 'stagnation' we mean the retention in a lower class of a child for a period of more than one year.—*Ibid* p 47

तालिका १<sup>१</sup>

राज्य	बालिका की संख्या कक्षा १ (१९४४-४५)	बालिका की संख्या कक्षा ४ (१९४७-४८)	स्थापित मागरीता प्रतिमान (१९४७-४८)	अपम्य प्रतिमान १९४७-४८
आसाम	१२१ ८७६	४४, ८७४	४४ ८	४४ २
बंगाल	८३७ ८४४	१४३ ०२४	१७ २	८२ ८
बिहार	१९४ २०४	११२ ६७३	४८ २	४७ ०
बांग्ला	२७१ ३३०	१७१ ३४१	६० १	३६ ६
मध्य प्रदेश	१२६ ०४७	७६ ४१६	४१ २	४६ १
मणिपुर	६६० ७३४	७३६, १२८	७४ ६	२४ ४
उड़ीसा	४६, ३२२	२० ७७२	४ ०	६४ ८
पञ्जाब	१८६ ३१०	६ ७४१	४४ ४	४७ ६
उत्तर प्रदेश	२०१, १०४	१६६ ६२३	४४ ३	४४ ७
मजमूर भारतवासी	६ ६०४	४४८	३४ ८	४४ २
कुल	३ ७४२	२ १४२	४७ १	४२ ६
दिल्ली	१७ ७६७	७ ८४८	४६ ०	४० ७
कुल संख्या	३ १०८ ४४७	१, २६७ १७४	१० ४	४६ ६

तालिका २<sup>२</sup>

कक्षा	परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत प्रतिशत संख्या	
	१९४७-४८ से १९४९-५०	१९४९-५० से १९५४-५५
१	४८-०२	४१ ८३
२	६६ ०६	६८ ६१
३	६४ ४४	६८ ८७
४	६७ ३०	७० १७
५	४६ ४७	६४ ७०

सांख्यिकीय विभाग में 'अपम्य' तथा 'अवरोधन'

सांख्यिकीय विभाग में होने वाले अपम्य तथा अवरोधन के प्रति भा.  
Hastings Committee का ध्यान आकर्षित हुआ। सांख्यिकीय विभाग के प्रधान  
हम स्तर पर की अपम्य तथा अवरोधन विभाग के कमरा की बरत १९८

1. Review of Education in India pp 905-1007  
2. 1 G Singh and Co. 1959 Education in India p 58

हाम २१ है। इसका कारण जितनी भोग्य शक्ति हो रहा है इतना धामास पावे की शक्ति में हो जाता है —

राष्ट्र स्कूल एवं उमरे समान परीक्षाओं के परीक्षा फल<sup>१</sup>

वर्ष	परीक्षा देने वाले छात्र	उत्तीर्ण होने वाले छात्र	उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत
१९४१-४२	५८३,४७०	२६१,०५६	४४.७
१९४२-४३	७२४,७६६	३३४,७६०	४६.२
१९४३-४४	८१८,६२०	३६७,००७	४८.५
१९४४-४५	८३०,००१	४००,०१४	४८.२
१९४५-४६	६७०,०२६	४२६,४६४	४६.७

विश्वविद्यालय शिक्षा में 'अव्यय' एवं 'अवरोधन'

विश्वविद्यालय शिक्षा में अव्यय अव्यय एवं अवरोधन है। इन कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा में अव्यय और अवरोधन के इन कारणों में व्यक्त किया है। 'मार्चमार्च' एवं वा प्रतिपक्ष में अव्यय हो रहा है परन्तु इनमें भी अव्यय दुर्ग की बात यह है कि मार्चमार्च एवं की सम्मान शक्ति व प्रतिपक्ष हो उगावता है जिससे कि लाना और लाना प्रमितायका के समान शक्ति और एवं व लाना तथा उनकी लानाओं और प्रमितायका पर लाना लुपता पावे व प्रति।<sup>१</sup> विश्वविद्यालय शिक्षा में लाना लाने 'अव्यय' एवं अवरोधन का अनुमान अव्यय शक्ति में लाना लाना है —

1. *Review of Education in India* pp 905-1007

2. "A deplorable wastage of public funds goes on year after year but what is worse there is an unconcerned complacency about this serious loss of public funds on the one hand and waste of time, energy and funds of students and their parents besides terrible frustration of their hopes and aspirations on the other" — *Report of the University Education Commission*, p. 26





अवाधनाय भवन और नीरस तथा उत्साह-हीन वातावरण—दुर्भाग्य से छात्रों की अभ्यसन करते रहने के लिये प्रभावपूर्ण प्रेरणा न प्रदान कर सके।<sup>1</sup>

**उपचार—शिक्षा-व्यवस्था में सुधार (Reform in Administration of Education)**

अपभ्यस्य' एवं अवरोधन' का निराकरण करने के हेतु शिक्षा-व्यवस्था में स्वरित सुधार किया जाना अनिवार्य है। शिक्षासमर्थों के शिक्षा-स्तर को ऊँचा उठाया जाय अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाय शिक्षा-उपकरणों में वृद्धि की जाय स्वस्थ पर्यावरण में शिक्षालय भवनों का निर्माण किया जाय, शिक्षालयों के वातावरण को आकर्षक बनाया जाय और छात्रों के मनोरंजन तथा खेल-कूद की उचित व्यवस्था की जाय। जब तक शिक्षालयों को इस प्रकार से सज्जित नहीं किया जायगा तब तक वे शिक्षा के वास्तविक वैद्य न बन सकेंगे और परिणामतः वे शिक्षा प्रसार का कार्य सफलता पूर्वक न कर सकेंगे।

**२ कारण—दूषित वातावरण (Vicious Environment)**

साधारणतः छात्रों को शिक्षालय और उनसे बाहर दूषित वातावरण में अपना समय व्यतीत करना पड़ता है। बिना भी कक्षा में ऐसे बातों का प्रभाव नहीं होता है जिनकी आदतें व्यवहार, बातचीत का ढङ्ग और अभिप्रायों निर्दोष न हों। इस प्रकार के विद्यार्थी प्रति बचकता में उत्तीर्ण होने का कभी विचार ही नहीं करते हैं और अग्य छात्र भी उनके सम्पर्क में आकर विद्याभ्यसन में भी पुराने भगने हैं।

शिक्षालयों से बाहर का वातावरण—विशेष रूप से नगरों में—प्रति विपात हो गया है। ध्वनिप्रसारक यंत्रों पर गुनाये जाने वाले अस्सीस गीत चलचित्रों के उत्तेजक विज्ञापन चित्ताकर्षक अप्रसन्न भेष-समाये तथा मित्रेमापर चित्रों ही छात्रों के अभ्यसन में बाधक निष्ठ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में अपभ्यस्य' एवं अवरोधन की समस्याओं का भविष्य में और अधिक विवर्धन का कारण बन लेना कोई आश्चर्य की बात न होगी।

कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के भी शान्त हैं जिनमें विद्या-देशी के उपासक बनने की प्रबल आकांक्षा होती है। परन्तु उन्हें अपनी आकांक्षा को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर दुर्लभ हो जाता है। यदि वे निरुद्धे छात्रों के

1 "The educational institutions being ill-equipped poorly housed and with dull and depressing environment unfortunately could not exercise effective counter-acting influence."

निवामी हैं। तो उन्हें अपने परिवार में विद्याध्ययन का क्षांक्षनीय बाजारपरण मुसल नहीं हो पाता है। यदि वे किसी निधन काधारण परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें पारिवारिक व्यय का पूति करने में योग प्रशान करने के बिये प्राण एवं धायबाध बाई कार्य करना पड़ता है।

**उपचार—वातावरण में सुधार (Improvement in Environment)**

छात्रों को शिक्षा देना तथा उनमें धर्म और जिस दूषित क्षात्रों में अना-  
मय क्षात्रों करना पड़ता है। उनमें पशुपति करना आवश्यक है। इन कार्य-  
का कारण अना तथा अश्वपति के मन्त्रित्व में नाम में गंगादिन दिया जा-  
गता है। यदि वे तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्तव्य है।  
जहाँ ता क्षात्रपति का निम्नग्रेष्ठ रूप में पशुपति दिया जा गता है। अर्थात्  
का कर्तव्य यह है कि वह छात्रों को अभिवादन में गमात्र मुखात् कराई  
स्वास्थ्य महापति। छात्रों के गुणों का विचार कर और उनमें निम्न नामात्  
विशिष्टा मन्त्रजन तथा प्रीति शिक्षा की व्यवस्था करे। अर्थात् को एक निम्न  
क्षेत्रों ध्वनि प्रमाण मन्त्र। द्वारा अ तीक्ष्ण भावों के गुणों को ध्वनि के  
उत्पन्न शिक्षात् प्रमाण विषय जानें और एक ही एक का भाग के लक्ष्यों  
को निम्न परों में प्रमाण पान में ध्वनि कर केना पाठिए। अर्थात् का कर्तव्य  
है कि वह छात्रों का इन भावों में महापति प्रमाण करने के विषये तन मन से  
ध्यान करे। जहाँ तब अश्वपति का नामात् है। वे अपने शिक्षात् में लक्ष्यों  
पयोगी क्षात्रपति का निर्माण करके करने कर्तव्य का पालन कर गते हैं।

३. शरणा—प्रभावहीन शिक्षण-पद्धति (Ineffective Method of Teacher)

[illegible]



वास्तव को निर्माणकारी एक सामग्र्य काय करने का आउट्रिफ मनीमारना को मनुष्ट कर मत ।

## ५. कारण—दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली (Defective System of Examination)

सन्मग ५० प्रतिशत मात्र परीक्षाओं में अनुमार्ग रहते हैं । इनमें नियम दोषारोपण परीक्षा प्रणाली पर किया जाता है न कि विद्यार्थियों पर । विद्यार्थी एक वय तक बड़ा म जो काय करन ? उम्र पर रिगो प्रकार का भी विचार उनको उपनि हन व समय की किया जाता है । मनुष्ट वाणिज्य परीक्षा का मापार पर जो मुख्य रूप म छात्रों की स्मरण भयवा देनकी रहत की गति की कमीकी हाती है उनको बना उपनि का नित्य दिया जाता है ।

## उपचार—परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन (Change in Examination System)

प्रयत्न परीक्षा प्रणाली में समीक्षा दूरता का उन्मूलन कर । कि दिव इसमें प्रति छात्र समीक्षण किया जाता चाहिये । छात्रों का उपनि वर्ष व कार्य व मापार पर हा जाना चाहिये न कि वाणिज्य परीक्षा व । माप हा १५ फार नकर (Parulekar) व इस रूपन पर मभारतगूरर मदन करना चाहिये । विद्यार्थियों का ग्यापना इनलिए का जाता है किम दि बन्धा की गिता हा जाय न कि उर परा हा म अनुमार्ग दिया जाय । ' जब मक हम यममान परीक्षा प्रणाली में म्हापन करन वाग्मिकर गता इ गित विद्यार्थी का अनुमार्ग म्हा करन तब तक तन्त्र पर हा म अनुमार्ग हा । रहत और परिणामकक अवरोधन भवन वर्तमान का म प्रयत्न दिव म । पर प्रणाली आधिप्य काय रहता ।

पूर्व काल व ग्राम में पहुँच जाते हैं। जन्म देने वाले बच्चा में से आधे बच्चा भी १० वर्ष की आयु को नहीं प्राप्ति कर पाते हैं।<sup>१</sup> ऐसी दशा में हमारे छात्रों की शारीरिक दुर्बलता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। दुबल तथा अस्वस्थ रहने व कारण व अनवरत रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं और कमस्वस्थ प्रायः एक वर्ष का पाठ्यक्रम दो या अधिक वर्षों में समाप्त करते हैं।

### उपचार—छात्रों की स्वास्थ्य-उन्नति (Improvement in Pupils' Health)

छात्रों के स्वास्थ्य की उन्नति की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना है। आज के वास्तविक—वास्तविक के नागरिक हैं। आज जब कि सगार सताने विरल युद्ध के काले बादला व आच्छादित हो रहा है तब की सुरक्षा के लिये वसिष्ठ सैनिकों की आवश्यकता है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब बालका के स्वास्थ्य के प्रति उनका वास्तविकता से ही ध्यान दिया जाय। अतः सरकार पर यह दायित्व है कि वह अपने लिये पीछे आहार की व्यवस्था करे। आज के ममी प्रगतिशील देश ने छात्रों व नियमित न किसी रूप में पीछे आहार की व्यवस्था कर दी है। यदि भारत की निर्धन जनता के बच्चा के लिये वही ऐसी योजना त्रियायित कर दी जाय तो उनके स्वास्थ्य की अवस्था उन्नति होगी और इस कारण व कमस्वस्थ होने वाला अवरोधन मुक्त हो जायगा।

### ७. कारण—अभिभावकों की अज्ञानता (Illiteracy of Guardians)

बच्चा लाने में किये गये एक गलतीपूर्ण से ज्ञान हुआ है कि पिछड़ी हुई जातियाँ व बच्चा में अविश्व अभ्यास है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन बच्चा के अभिभावकों में गिनना का अभाव है। स्वयं गिनना न होने व कारण के अपने बच्चा की गिनना का भी सङ्कलित एवं सामाजिक मूल्य समझने में विफल रहता है। अतः गिनना का अध्ययन समझ कर व यदि भयान बच्चा का गिनना उन्नत कराने व लिए गिननायका में प्रविष्ट भी करा देता है तो भी कुछ समय उपरान्त व उह वही व फिर उनसे गया भयान ही होगी व

1. India's strength is sapped by the constant ill health of her people. One quarter of all babies die before they are one year old and four out every ten die before they are five. Half the babies born never reach the age of ten. —James H. Cunningham, *What I Saw in the East*, p. 75



वाणिज्य की गिरावट का प्रश्न है उनका अधिक से अधिक अर्थ का जान कराने के उपरांत विद्यालयों से वृषक कर लिया जाता है। ऐसा नियम जाने के समय अभिभावक उचित विचार नहीं करते हैं कि वाणिज्य की गिरावट करने से परिवार का बोर्ड आर्थिक हित नहीं होगा। इसके सिवा धर्मिकता पर दोषारोपण करना व्यर्थ है क्योंकि जिस सामाजिक वातावरण में वे पन और बढ़ हुए हैं उसमें उन्होंने ऐसा ही दाता और गुना है।

**उपचार—व्यक्ति की आय में वृद्धि और मूल्यों पर अधिकार (Increase in Individual's Income & Control on Prices)**

अभिभावकों की आर्थिक कठिनाइयाँ का निवारण जिन आवश्यक है क्योंकि इनके कारण गिरावट में अत्यधिक अपेक्षित एवं अवरोधन हो रहा है। भारत सरकार इस 1971 में प्राण प्रण से चेष्टा कर रही है। देश का औद्योगिकरण किया जा रहा है और अन्न तथा वृद्धि-सम्बन्धी अर्थ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि भी जा रहा है। देश के आर्थिक विकास का जो जनवरण प्रयास किया जा रहा है उसका परिणामस्वरूप प्रायः व्यक्ति की आय में वार्षिक वृद्धि हो गई है। 1955-56 में प्रति व्यक्ति की आय 255 रु. 6 पैसे थी। 1960-61 में यह आय बढ़कर 300 रु. 1 पैसे हो गई है। निम्नलिखित आय की इन वृद्धि से विचारणीय बात यह है कि क्या यह वृद्धि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के अनुसरण में व्यतीत होगी? अथवा वस्तुओं के अभाव में व्यतीत होगी? यदि जीवन में व्यतीत होगी तो जीवन में वृद्धि हो चुकी है। परन्तु वस्तुओं का मूल्य 100 प्रतिशत तक बढ़ी आर्थिक वृद्धि हो चुकी है। परन्तु वस्तुओं का अनुसरण बताया है कि मध्य तथा निम्न वर्गों के व्यक्ति का आर्थिक स्थिति पूर्व की भाँति अधिक गोपनाय हो गई है। क्या इन परिस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य जनता की आर्थिक कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी या नहीं? यदि नहीं तो गिरावट में अत्यधिक लक्ष्य अन्वेषण के समान होन का आशा करना उचित नहीं होगा तथा निराशार है। आर्थिक महत्ता के दुर्भेद का प्रश्न पन होगा—निम्नलिखित वृद्धि हुए मूल्यों पर अधिकार करना। यदि सरकार यह नहीं करती है तो राष्ट्रीय उन्नति तथा वर्धितवर्ग की योजनाओं के बावजूद भी जनसाधारण की आर्थिक समस्या का हल नहीं होगा। कारण और गिरावट में हीन जन आर्थिक तथा अवरोधन माने दयावत्ता का प्रविष्टिमान रूप है।

## ६. कारण—सामाजिक कुुरीतियाँ (Social Fails)

स्वतंत्रता पर आधारित भारतीय समाज अपमय एवं अवरोधन में अनियम योग्य है। आज के आधुनिक युग में भा दल के प्रवेश होने से अनेक हास्यास्पद सामाजिक कुुरीतियाँ का बोध होता है। याला तथा बालिकाओं की सह गिता की संगठित दृष्टि से ऐसा जाना है। समाज यदि एक स्थान पर बालिकाओं का गिता से निवेष्टन सम्पन्न है तो उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है और यदि मोक्षार्थ से शिक्षा विद्यालय में प्रवेश पा चुकी है तो योग्यता भाव अपेक्षा हो जाने पर तो उन्हें सरकारी की आगमना समाज बन व विषय बाध कर दिया जाता है। फिर बाल विद्या की तरफ से दूविष प्रथा हो जा अनेक बालिकाओं का हा नष्ट। अतः कुछ धारणाओं की भी शिक्षा का फल प्रत्यक्ष पूर्ण करने से पूर्व ही उत्पन्न और ग युग मोट होने से लिये अपेक्षा युग आगत दर्ती है। इन कारणों से अपमय का अपमय एवं अवरोधन होता है व अपमय से ही दुःख में तो कम है परमप्य तथा निराशा का हि दुःख और गायिका सुनवाना से अति नावनीय है।

## उपचार—कुुरीतियों का सुधार (Some Suggestions)

जिस प्रकार आदिम कठिनाइयों में 'अपमय एवं अवरोधन' से उत्पन्न गतिरोध उपशान्त कर रखा है उसी प्रकार हमारे समाज का सुधार—ऐसा ही सुवर्ण नियम कि 'प्रमाण के मार्ग का लक्ष्य निवेष्टन' है। 'ऐसा ही सामाजिक आदिम गतिरोध निगमे बाधक सख्तुरा करते हैं अपमय एवं अवरोधन से मोक्ष प्रदान करने वाला एक कारण है। ' इस गतिरोध में केवल बाधक को सख्तुरा करने से ही शीघ्र गतिरोध नष्ट किया जा सकता है। बलवत् अधिकांश पर आधारित हमारे समाज में यह शिक्षा की विद्या भावना बन 'बहादुर तथा मानसिक शक्ति' का जोड़ होता नहीं पाई जाती है कि उनका गहन शक्ति बल शिक्षा में ही मानसिक अपमय एवं अवरोधन का भवन शिक्षा अधिनियम से सम्बन्ध पाती बन पड़ता है। समाज में कुछ शिक्षा शिक्षा में इन समस्याओं का निराकरण के लिए दो ही उपाय हो सकते हैं—(१) दो लो गतिरोध में उत्पन्न गतिरोध गतिरोध से बचना (२) दो समाज में गतिरोध का एक ही गतिरोध गतिरोध शिक्षा गतिरोध। शिक्षा—मार्ग से अधिनियम अपमय गतिरोध से गतिरोध



इसका दायित्व देश से मुक्त युवतियों पर है। यदि वे कमर बसकर इन समस्याओं से मोटा सें तो वे जनता में नवीन चेतना और देश में नवीन युग का सूत्रपात कर सकते हैं। उनके इसी कार्य पर उपयुक्त सामाजिक दुगुणा के फलस्वरूप होने वाले अपेक्षित एवं अवरोधन की इतिथी हो सकती है।

### UNIVERSITY QUESTIONS

- 1 Explain fully what is meant by wastage and 'stagnation' in Primary Education
- 2 How do you account for wastage and stagnation in Primary Education in India? What measures should be taken to overcome them?
- 3 What are the causes of wastage and stagnation in Secondary Education in India? How would you combat them?
- 4 Define 'wastage and stagnation'. To what extent are they present in Higher Education in India?

